(1600/IND/RK)

(प्रश्न 101 और 109)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 101 और 109 को क्लब किया जाता है।

कुंवर दानिश अली जी।

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदय, हम बीएसएनएल पर गर्व करते थे, लेकिन आज बीएसएनएल का मतलब "भाई साहब नहीं लगेगा" हो गया है! प्रधान मंत्री जी ने रेड फोर्ट से कहा था कि छह लाख गांवों में ऑप्टीकल फाइबर बिछाई जाएगी और गांवों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। आज इसकी स्थिति बहुत खराब है। हम दिशा की बैठक में जब रिव्यू करते हैं, तो देखते हैं कि गांवों में अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने बीएसएनएल के एसेट्स का मूल्यांकन किया है? बीबीएनएल ने ऑप्टीकल फाइबर बिछाने का काम किया है, वह कितने परसेंट किया है? क्या आने वाले समय में प्राइवेट प्लेयर्स को ऑप्टीकल फाइबर बिछाने देने की कोई योजना है? आप करीब 30 हजार करोड़ रुपये का टेंडर फ्लोट कर रहे हैं।

श्री अश्वनी वैष्णव : मान्यवर अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने बीएसएनएल के बारे में कुछ कमेंट्स किए हैं। मेरे हिसाब से उसकी जांच करनी चाहिए और यदि कुछ असंसदीय है, तो उसे एक्सपंज किया जाना चाहिए।

महोदय, वर्ष 2004 में जब एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार को बीएसएनएल और एमटीएनएल कम्पनीज सौंपी, तब ये दोनों कैश रेज प्रोफिटेबल कम्पनीज थीं। उसके बाद ये कम्पनीज क्यों ऐसी परिस्थिति में आईं, जो लोग आज उधर बैठे हैं, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए।... (व्यवधान) मैं आपको वही बताता हूं कि सात साल में हमारी सरकार ने क्या किया है। जिस पोजिशन पर यूपीए सरकार बीएसएनएल को छोड़ कर गई थी, उस पोजिशन से आज बीएसएनएल बहुत सिग्निफिकेंटली बैटर स्थिति में है और पहली बार कई वर्षों के बाद बीएसएनएल ने ओपरेटिंग प्रोफिट बनाया है। पहली बार बीएसएनएल और एमटीएनएल बिट ऑफ पॉजिटिव हुई हैं। वर्ष 2019 में जो रिवाइवल पैकज दिया, उस पैकेज के कारण आज दोनों कम्पनियां स्टेबल हो गई हैं। मुझे हर्ष के साथ कहना है कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बजट में बीएसएनएल और एमटीएनएल के फर्दर ग्रोथ के लिए करीब-करीब 45 हजार करोड़ रुपये, एग्जेक्टली 44 हजार 720 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया है।... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत सुधार हो गया है। एनसीआर के हापुड़ में मेरे पास एमपी कनेक्शन है, वह पिछले ढाई साल से काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप देखें कि बीएसएनएल कहां काम कर रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि जो 44 हजार करोड़ रुपये एलोकेट किए गए हैं, सरकार की नीयत कहीं बीएसएनएल को प्राइवेट प्लेयर्स को बेचने की तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो टावर्स लग रहे हैं और ऑप्टीकल फाइबर बिछ रही है, वह सब ठीक-ठाक करके किसी प्राइवेट प्लेयर्स को हैंड ओवर कर दें, जैसे एयर इंडिया के साथ किया है कि सारा पैसा सरकार का लगे और बाद में किसी अडानी, अम्बानी या जिओ को हैंड ओवर कर दें।

(1605/KDS/PS)

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष-2019 में बीएसएनएल का जो रिवाइवल पैकेज किया गया, उसके कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी जरूरतें थीं। देश भर में नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगातार इनवेस्टमेंट करना पड़ता है। अभी जो 44 हजार 720 करोड़ रुपये का एलोकेशन किया गया है, उसका भी प्राइमरिली बीएसएनएल के ज्यादा रिवाइवल तथा कैपिटल इनवेस्टमेंट के लिए उपयोग होगा।

महोदय, भारत में पहली बार 4 जी में एक कम्प्लीट कोर नेटवर्क, कम्प्लीट रेडियो नेटवर्क बना है। दुनिया हिली हुई है। सब लोग देख रहे हैं कि भारत ने 4जी, 5जी बना लिया तथा भारत के इंजीनियर्स का जो टैलेंट है, उसकी प्रसिद्धि दुनिया भर में हो रही है। बीएसएनएल उसी रास्ते में काफी अच्छे से रिवाइव होगा और काफी अच्छे से ग्रो करेगा। आप जब इसे छोड़कर गए थे, तब इसका केवल 7 या 7.5 परसेंट मार्केट शेयर रह गया था। हमारे समय में यह ऑलरेडी 10 परसेंट से अधिक पर आ गया है।

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष तिवारी जी- उपस्थित नहीं।

श्री राहुल रमेश शेवाले।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे संसदीय क्षेत्र में टेलीकॉम फैक्ट्री है, जहां पर प्रोडक्शन का काम किया जाता है। वहां पर स्टाफ और प्रोडक्शन से रिलेटेडे बहुत सारे इश्यूज हैं। ग्रुप-डी का जो स्टाफ है, उनको प्रमोशन न मिलने की वजह से वे ग्रुप-डी की पोस्ट से ही रिटायर हो रहे हैं। जो टेलीकॉम फैक्ट्री के ऑफिसर्स हैं, उनका एजीएम पर प्रमोशन का इश्यू भी पेंडिंग है। प्रोडक्शन के बारे में कहा जाए, तो पीएलबी पाइप की प्रोडक्शन का अगर उनको ऑर्डर मिलेगा तो बीएसएनएल का ऑप्टिकल फाइबर संबंधी बहुत ही बड़ा काम हो सकता है। इसके अलावा वहां टेलीकॉम फैक्ट्री की 22 एकड़ की लैंड पर एनक्रोचमेंट भी हो रहा है, इस वजह से वहां पर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज भी हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे बीएसएनएल के रिन्यूअल का आपने एक मॉडल बताया है, वैसे ही टेलीकॉम फैक्ट्री के लिए आप क्या विचार कर रहे हैं? धन्यवाद।

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से अलग है, फिर भी आईटीआई के रिवाइवल के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। हाल ही में रायबरेली में आईटीआई के 3 नए यूनिट्स का काम शुरु हुआ है। मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट लग गया था, इसलिए कोई फॉर्मल इनॉग्युरेशन नहीं किया गया, लेकिन एक दिन भी आईटीआई को लॉस न हो, इस वजह से वहां पर काम चालू कर दिया गया। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वहां पर बन रहे हैं। तीन-चार अलग-अलग तरह की चीजें भी वहां पर बन रही हैं। साथ ही साथ आईटीआई ने देश की दो स्टेट्स में ऑप्टिकल फाइबर लेइंग का काम भी बहुत बड़े तरीके से किया है।

माननीय अध्यक्ष : श्री मणिक्कम टैगोर जी- उपस्थित नहीं।

श्री अरविंद सावंत जी।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आपका सवाल सही है कि पुरानी सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कल भी इस पर बहस हुई। आदरणीय निर्मला जी को लगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं यह मानता हूं कि आपने अपने 7 सालों में पहला कदम ठीक उठाया। वीआरएस हुई, जिसके तहत लोग रिटायर हुए। लोगों को जो पेंशन या पैसा मिला, वह बात भी मैं मानता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। उसके बाद क्या हुआ? वीआरएस के बाद स्टाफ कम हुआ। जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि इनकी लैंडलाइन मेनटेन नहीं हो रही है। मेरी आपसे यह विनती है कि आपका जो रिवाइवल प्लान चल रहा है, उसमें एमटीएनएल, बीएसएनएल के बारे में जो कदम उठाने चाहिए, वे कदम नहीं उठाए गए हैं। अभी जिस कॉंट्रैक्टर को कॉंट्रैक्ट दिया गया है, उसके बाद उसके पास जो कर्मचारी आए हैं, वे ट्रेंड नहीं हैं। उनको कुछ भी नहीं आता है। केबल ज्वाइन कराना अलग बात है।

महोदय, मैं इन दोनों के रिवाइवल के लिए केवल दो प्रश्न पूछ रहा हूं। BSNL has presence in every nook and corner of the country. यह गांव-गांव में गया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर का काम अगर आप बीएसएनएल को दे देंगे, तो बीएसएनएल की ताकत बढ़ेगी। उसके पास चार पैसे आएंगे। लेइंग केबल ऑलरेडी हो चुका है। The Same thing applies to MTNL also. कल-परसों आपने डाटा सेंटर्स की बात की।

(1610/KDS/SMN)

We are having one of the finest data centres of MTNL in Mumbai. We are not utilizing it up to the fullest extent. मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप जिस ढंग से चल रहे हैं, उस हिसाब से मुझे विश्वास है कि आपके मुंह से अगले छ: महीनों में यह सुनने में आना चाहिए कि both are going in profit. I hope that you will take right steps in that direction.

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, सांसद महोदय का जो सुझाव है, वह बहुत ही अच्छा है कि ऑप्टिकल फाइबल का नेटवर्क, जो करीब 2 लाख किलोमीटर के आसपास बन गया है, उसे बीएसएनएल को सौंप देना चाहिए। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज बीएसएनएल करीब-करीब हर महीने एक लाख घरों तक फाइबर पहुंचा रहा है। टोटल संख्या 20 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। अभी जिस तरीके से बीएसएनएल काम कर रहा है, उससे हमें अंदाजा है कि जब हम थोड़ी और मेहनत करेंगे, तो एक लाख की संख्या डबल भी हो सकती है। हम उसी रास्ते पर मेहनत कर रहे हैं और आपका जो पॉइंट एमटीएनएल के बारे में है, तो मैं बताना चाहूंगा कि बहुत स्टेप बाय स्टेप कदम उठाना पड़ेगा। वे लोग ऐसी बैलेंस शीट छोड़कर गए हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाते-चलाते और मेहनत करते-करते कहीं कुछ हो पाएगा।

प्रो. सौगत राय (दमदम): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा एक बहुत ही जरूरी प्रश्न है। श्री अश्वनी वैष्णव जी एक नए मंत्री हैं। पहले यह आईएएस ऑफिसर थे। इन्होंने वाजपेयी जी के साथ काम किया है, लेकिन आप मैजीशियन तो नहीं हैं। आप बोल रहे हैं कि बीएसएनएल की हालत अच्छी है। उनकी पीड़ा आप समझिए। हजारों की संख्या में बीएसएनएल के कॉंट्रैक्चुअल लेबर्स की छंटाई हुई और बीएसएनएल के 50 परसेंट वर्कर्स को वीआरएस दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, आपका प्रश्न क्या है?

प्रो. सौगत राय (दमदम): अध्यक्ष महोदय, मैं दो छोटे से सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी कृपया बताएं कि बीएसएनएल के गरीब कॉंट्रैक्ट वर्कर्स का लाखों-करोड़ों रुपया बाकी है, उसके लिए क्या आप कुछ करेंगे? अगर आप इसको बचाना ही चाहते हैं तो फिर आप जियो को 5जी क्यों दे रहे हैं? 5जी देना है तो आप बीएसएनएल को दीजिए। अगर जियो को 5जी मिल जाएगा, तो बीएसएनएल कैसे प्रॉफिट में आएगा?

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही रिस्पेक्टेड सांसद महोदय हैं। आपकी छत्रछाया में ही हमारे जैसे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। आपका जो सुझाव है कि बीएसएनएल को 4जी और 5जी देना चाहिए, यह पक्की बात है कि उसे देना चाहिए। 4जी ऑलरेडी दिया गया है और बीएसएनएल को पूरा सपोर्ट दिया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का विजन है, उसमें 5जी के कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क, इक्युपमेंट, हैंडसेट आदि की कम्प्लीट तैयारी हो गई है। बहुत जल्दी ही इसकी प्रोग्रेस भी आप सभी के सामने आएगी और वह भी बीएसएनएल को दिया जाएगा। यह पक्की बात है।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much Speaker Sir.

Sir, these are very important questions – Q. 101 and Q. 109, regarding two prestigious organisations of the Government of India, BSNL and MTNL.

Yesterday also, the Hon. Minister during her intervention suggested that a big amount is being pumped so as to revive MTNL and BSNL. We do agree with it. But the problem is we are all chairing the BSNL Telecom Advisory Committee. The regular complaint which we are receiving is that even 4G has not been provided. In the State of Kerala, even 4G has not been provided. All other private telecom operators are going for 5G.

I have a 'b' part of my question. Why is this Telecom Advisory Committee chaired by the Members of Parliament not being reconstituted after two years of assuming the Office? This is 'b' part of my Question.

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष महोदय, सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है, उसका जवाब आपके पास खुद होना चाहिए। जितनी खराब परिस्थितियों में आप लोग बीएसएनएल को छोड़कर गए हैं, उससे उबरकर आने में समय लगता है।

(1615/CS/SNB)

प्रयास बहुत ज्यादा लगता है। आज की तारीख में, आज की कंडीशन में मैंने जैसे पहले बोला, after many years BSNL and MTNL have come into operating profits. They have become EBITDA-positive after many years. 4G has been given to BSNL. The rollout will happen this year. This is something which all of us are trying. There is no magician जैसा कि सौगत दादा ने बोला, लेकिन हमारी नीयत साफ है, हमारे प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है।… (व्यवधान)

(इति)

(प्रश्न 102)

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो कोटिपल्ली-नरसापुर रेलवे लाइन है, यह हमारे राज्य के लिए स्पेशियली अमलापुरम एरिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वर्ष 2000 में हमारे सदन के पूर्व अध्यक्ष माननीय बालयोगी जी का सपना था और उनके समय में, उनकी मेहनत से यह रेल लाइन सैंक्शन भी हुई। जैसा आप जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट को चलते-चलते 20 साल हो गए हैं और अभी उत्तर में दिया हुआ है कि राज्य सरकार का जो शेयर है, क्योंकि यह कॉस्ट शेयरिंग प्रोजेक्ट है, तो 360 करोड़ रुपये में से उन्होंने लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपये दिए हैं। अभी राज्य सरकार की परिस्थिति ऐसी है कि जो सड़कें हैं, उनके गड्ढों को भी वे अभी ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। यह तो हम करोड़ों रुपयों की बात कर रहे हैं। अगर इस तरह की परिस्थिति राज्य में रहती है तो रेलवे मंत्रालय से क्या सपोर्ट मिलेगा कि हम इस प्रोजेक्ट को ऐसे ही रहने दें या फिर मंत्रालय से अभी इसमें कोई सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : महोदय, यह बात सही है कि यह कोटिपल्ली-नरसापुर प्रोजेक्ट आन्ध्र प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्य ने बताया कि बालयोगी साहब का यह सपना था। यह बात भी सही है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में 2,120 करोड़ रुपये की लागत लगने वाली थी और 25 परसेंट पैसा राज्य सरकार से आना था, लेकिन राज्य सरकार ने अभी पैसा देना बंद कर दिया है। एक ही प्रोजेक्ट पर नहीं, पाँच प्रोजेक्ट्स, जो आन्ध्र प्रदेश में चल रहे हैं, पाँचों के पाँचों प्रोजेक्ट्स को राज्य सरकार ने पैसा देना अभी बंद कर दिया है, इसलिए इस प्रोजेक्ट की प्रगति धीमी है।

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु (श्रीकाकुलम): अब इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जब तक राज्य सरकार पैसे नहीं देगी। मेरा दूसरा सवाल इसी से थोड़ा सा संबंधित है, आन्ध्र प्रदेश के लिए जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन सैंक्शन हुआ है, कोटिपल्ली-नरसापुर आदि ये सब डिविजन उसी जोन में आने हैं। इसको प्रपोज किये हुए अभी तक तीन साल हो गए हैं। इसके लिए अभी आन्ध्र प्रदेश के लोगों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा? यह साउथ कोस्ट रेलवे जोन ऑपरेशन में कब तक आएगा?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सरकार ने इस पर कार्यवाही ऑलरेडी शुरू कर दी है और बहुत ही जल्दी यह काम शुरू हो जाएगा।... (व्यवधान)

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, thank you for giving me this opportunity to raise this supplementary question. I do agree with the point raised by the hon. Member. But I would like to make one point in this regard. There is a lot of revenue deficit on the part of the Government of India.

I would like to request the Government, through you, to revise the cost estimate and the cost has to be borne by the Government of India. The State got bifurcated unscientifically. So, where is the fund with the State Government? So, I request the Government of India and the Ministry of Railways to revise the cost estimate and the entire cost has to be borne by the Government of India. I request my colleague from the TDP to support this particular issue.

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : महोदय, जब तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, उस समय यह तय हुआ था कि वह रास्ता जिस राज्य के अंतर्गत आएगा, जो भी उसकी लागत है, वह उस राज्य को देनी चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): महोदय, मेरा प्रश्न बिहार से संबंधित है।

माननीय अध्यक्ष : यह मूल प्रश्न आन्ध्र प्रदेश का है।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): सर, मेरा प्रश्न उसी तरह का है, सिमिरल प्रश्न है। परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है।

माननीय अध्यक्ष : यह आपकी जानकारी में रहे कि मूल प्रश्न आन्ध्र प्रदेश का है।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): सर, मूल प्रश्न आ गया है। अगर आपकी कृपा होगी तो मैं अपना प्रश्न पूछ लूँगा।

माननीय अध्यक्ष : मुझे याद है कि आप बिहार के हैं।

(1620/KN/RU)

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): महोदय, बिहार में मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र में वर्ष 2007 में बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन की स्वीकृति मिली थी और उसका शिलान्यास भी हुआ था। वर्ष 2007 से 2022 तक न जाने कितनी दफा हम लोगों ने प्रयास किया। माननीय पूर्व रेल मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। प्रधान मंत्री जी से लेकर सब तक गुहार लगाई थी। हालांकि इस बार इस योजना में मात्र 50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं, चूंकि 50 करोड़ रुपये में वह रेलवे लाइन नहीं बिछने वाली है। यह लाइन 122 किलोमीटर है। उसमें चार-चार लोक सभा के क्षेत्र प्रभावित होते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): सर, मेरा प्रश्न यह है कि बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन, जो 122 किलोमीटर है, वह कब प्रारंभ होगी और कब सपना पूरा होगा?

माननीय अध्यक्ष : आगे सपना कहने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही बहुत है।

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन की जो परियोजना है, इसके लिए माननीय सदस्य को अलग से प्रश्न पूछना चाहिए। मैं आपके माध्यम से उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मैं इसकी जानकारी लेकर बता दूंगा।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 103 – श्री ए. गणेशमूर्ति।

(Q. 103)

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): *{Hon. Minister's reply only states about the details of FDI inflows into the country year-wise. I want to know the details of countries from where these FDI inflows have come to India. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Thiru Thalapathy M.K. Stalin has been taking several measures to attract FDI inflows towards Tamil Nadu. At a time when Tamil Nadu is making all efforts, I want to know what is the measure taken by the Union Government to attract FDI inflows towards Tamil Nadu.}

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I missed the first part which you said in Tamil. Which project did you mention in Tamil?

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): Sir, if I ask the question in English, the hon. Minister should reply only in English.

माननीय अध्यक्ष : आप दोबारा से स्पष्ट कर दीजिए।

… (व्यवधान)

SHRI PIYUSH GOYAL: I can answer in Hindi but by the time I got the translation, you had completed. I am asking you to repeat what you said.

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): Sir, the Member has asked his question in Tamil but the Minister is answering in Hindi.

HON. SPEAKER: Hon. Member, please repeat your question.

SHRI PIYUSH GOYAL: Hon. Speaker Sir, I can answer in Hindi and if you desire, it is available for you in translation mode…. (*Interruptions*)

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): When I am asking in Tamil, you want to answer in Hindi. … (*Interruptions*)

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I am allowed to answer in Hindi…. (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माइक खोल रहे थे। आपने एकदम तमिल में प्रश्न पूछा। उनको पता नहीं था कि आप तमिल में प्रश्न पूछेंगे।

… (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Member, please repeat your question.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। आपको किसने मौका दिया? प्लीज बैठ जाइये।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइये।

---

* Original in Tamil

… (व्यवधान)

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): Sir, I have already given notice.

HON. SPEAKER: No problem. Hon. Member, now please repeat your question…. (*Interruptions*)

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): *{Hon. Minister's reply only states about the details of FDI inflows into the country year-wise I want to know the details of countries from where these FDI inflows have come to India. Hon. Chief Minister of Tamil Nadu Thiru Thalapathy M.K. Stalin has been taking several measures to attract FDI inflows towards Tamil Nadu. At the time when Tamil Nadu is making all efforts, I want to know what is the measure taken by the Union Government to attract FDI inflows towards Tamil Nadu.}

श्री पीयूष गोयल : सर, मैं आपसे रूलिंग चाहता हूं कि क्या लोक सभा में ऐसा कोई कानून है कि अगर एक भाषा में प्रश्न पूछा जाए तो उसी भाषा में जवाब देना है? ऐसा नहीं है न। मैं हिन्दी में ही जवाब दूंगा और आप उसका ट्रांसलेशन सुनिए। मैंने भी तमिल का ट्रांसलेशन इसमें सुना है।

HON. SPEAKER: No problem. I am conducting the House in Hindi.

श्री पीयूष गोयल : सर, केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है कि एफडीआई को भारत में और ज्यादा बड़े पैमाने पर लाया जाए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, एक मिनट रुकिये।

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): Sir, I have already given notice.

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं। आप हैडफोन लगा लीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, ठीक है।

… (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please sit down. Hon. Minister, please answer now.

… (*Interruptions*)

(1625/GG/SM)

HON. SPEAKER: I am also conducting in Hindi.

श्री पीयूष गोयल : भरत सरकार प्रतिबद्ध है कि एफडीआई को भारत में और ज्यादा बड़े पैमाने पर लाया जाए।

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): I have already given this notice.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं, आप हेडफोन लगा लीजिए। Please sit down. The Minister is giving the answer.

---

* Original in Tamil

… (*Interruptions*)

श्री पीयूष गोयल : महोदय, भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि भारत में निवेश विश्व से लाया जाए। जो-जो सुविधाएं देनी हैं … (व्यवधान) If you do not want an answer, there is no problem.… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Please address the Chair.

… (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार लगातार इन प्रयासों में लगी हुई है कि भारत में अलग-अलग देशों से निवेश आए। … (व्यवधान) प्रश्न में यह नहीं पूछा गया है कि किस प्रदेश से, किस देश से कितना निवेश आए। लेकिन अगर उनको बहुत उत्साह है, एक-एक देश, जिससे निवेश आता है, उसकी जानकारी चाहिए है, मैं उनको वह भी उपलब्ध करवा सकता हूँ। मुझे इस बात का आनंद है कि तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री श्री एम.के. स्टालिन जी निवेश लाना चाहते हैं और बड़े पैमाने पर एफडीआई को प्रोत्साहित करते हैं तो वास्तव में यह अच्छी बात है। इसका स्वागत करना चाहिए। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, निजी क्षेत्र हो, सरकारी क्षेत्र हो, मैं समझता हूँ कि जो देश हित का काम है, वह हम सबको करना चाहिए। यह भी खुशी की बात है जो टॉप के पांच राज्य हैं, जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट आता है, उसमें से एक राज्य तमिलनाडु भी है। यह दर्शाता है कि लोग उत्साहित हैं कि तमिलनाडु की सरकार और ज्यादा प्रोत्साहन दे। अलग-अलग स्कीम्स लाए, अलग-अलग योजनाओं से देश-विदेश दोनों के उद्योगपतियों को अट्रैक्ट करे कि वहां पर इनवेस्टमेंट करे तो देश का हित होगा। जो उद्यमी है, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, उनको लगातार गाली देने के बजाय, उनको लगातार बदनाम करने के बदले अगर विपक्ष की पार्टियां और विपक्ष की राज्य सरकारें उनको प्रोत्साहन देती हैं तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत स्वागत की बात है।

HON. SPEAKER: Hon. Member, please ask the supplementary Question.

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): Sir, I gave the notice in the Notice Office that I am going to ask my Supplementary Question in Tamil.

HON. SPEAKER: The Minster has given answer to your question. Please ask the Supplementary Question.

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): Sir, I will ask my Supplementary Question in Tamil … (*Interruptions*) I want the answer in Tamil only.

*{In the Ease of Doing Business, India stands at 51st rank among 190 countries. Of course, it has improved its ranking but still lot of efforts need to be made. I would like to know from the Minister, measures taken for single window

* Original in Tamil

clearance and fully integrating multiple application forms for ease of doing business?

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। केंद्र सरकार ने कोविड के समय को अवसर में बदलते हुए दो-ढाई वर्षों में नैशनल सिंगल विंडो सिस्टम का निर्माण किया है। कुछ महीने पहले उसका बीटा वर्ज़न लांच किया गया है। इसमें केंद्र के कई सारे विभाग, लगभग 30-32 विभागों का सहयोग मिला है।

उनके अलग-अलग अप्रूवल्स नैशनल सिंगल विंडो से होते हैं। साथ ही साथ कई राज्य सरकारों ने भी इस काम में अपने आपको जोड़ा है। राज्य सरकारों के अप्रूवल्स को भी हम नैशनल सिंगल विंडो पर लाने में सफल हुए हैं। जो-जो राज्य नहीं जुड़े हैं, सभी माननीय सांसदों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने-अपने राज्यों में राज्य सरकार को कहें कि वे नैशनल सिंगल विंडो सिस्टम में जुड़े।

सर, अगर आपकी अनुमति हो तो सभी माननीय सदस्यों को सुन कर आनंद आएगा कि हमने क्या कॉन्सेप्ट किया है। हमने यह किया है कि एक फॉर्म में सारा बेसिक डेटा डाल दिया, यानि कंपनी का नाम, उसके डायरेक्टर्स हों, जो साधारण जानकारी हर सरकारी एप्लिकेशन में लगती है, जैसे कंपनी का एड्रेस, डायरेक्टर का एड्रेस, टिन नंबर, डिन नंबर, पैन नंबर आदि ये सभी जो कॉमन जानकारियां होती हैं, जो हजारों बार अलग-अलग एप्लिकेशंस में डालनी पड़ती हैं उसके लिए एक सिस्टम बनाया है।

(1630/RV/KKD)

उसके लिए एक कॉमन फॉर्म बनाया और फिर एक-एक विभाग को जो अतिरिक्त जानकारी चाहिए, वह विभाग वह अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है, परन्तु इससे बहुत डुप्लीकेशन कम होगा। लोगों को सभी एप्रूवल्स सरलता से ऑनलाइन मिलेंगे।

मुझे आप सबको सूचित करते हुए आनन्द हो रहा है कि हजारों की संख्या में अब कम्पनीज़ उस वेबसाइट पर जा रही हैं। सैंकड़ों एप्लीकेशन्स आने शुरू हो गए हैं। एप्रूवल्स भी ग्रांट होने शुरू हो गए हैं। सभी राज्य सरकारें, सभी लोकल इकाइयां, जैसे पंचायत या कॉरपोरेशन्स वगैरह जुड़ जाएं, वैसे तो हम केन्द्र के सारे मंत्रालयों को तो इससे जोड़ ही रहे हैं, तो वास्तव में 'Ease of doing business' का लाभ हर उद्योग को, सेवा क्षेत्र के लोगों को, छोटे-बड़े सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों को, सभी को इसका लाभ मिलना शुरू हो सकता है।… (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Member, please sit down.

… (*Interruptions*)

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब, जम्मू-कश्मीर में दो इम्पॉर्टेन्ट सेक्टर्स हैं। एक टूरिज्म का सेक्टर है और दूसरा फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या फूड प्रोसेसिंग में एफ.डी.आई. के लिए कोई प्रयास किया गया है और क्या टूरिज्म में यह किया गया है? अगर किया

गया है तो उसका लाभ क्या हुआ, उसका नतीजा क्या निकला? उसमें कितनी कमिटमेंट्स हो गईं और वे किस स्टेज पर हैं?

श्री पीयूष गोयल : यह बहुत अच्छी बात है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा। यह इससे संबंधित नहीं है, पर मुझे आपको सूचित करते हुए बड़ा आनन्द आता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, माननीय मनोज सिन्हा जी अभी तीन दिन पहले ही दिल्ली में थे, वे मुझसे भी मिलकर गए। जम्मू-कश्मीर में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए हमने जो स्कीम अनाउंस की थी, उससे देश के भीतर भी और देश के बाहर भी बहुत उत्साह जेनरेट हुआ है। कई सारे लोगों ने नई स्कीम के अन्तर्गत उसमें निवेश करने के लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। हमारा अनुमान था कि 25,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। फिर सबका उत्साह देखते हुए ऐसा लगा कि 48,000 करोड़ रुपये का निवेश का अनुमान है। मनोज सिन्हा जी कह रहे थे कि शायद अब लगता है कि जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग क्षेत्रों में करीब 60,000 करोड़ रुपये का निवेश आने का संकेत सामने दिख रहा है। उस स्कीम में जो फण्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं, वे मुझे बता रहे थे कि वे अब कम पड़ेंगे और आपको इसे बढ़ाने की तैयारी करनी पड़ेगी।

मुझे यह बताते हुए आनन्द है कि माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर निवेश आए, बड़े पैमाने पर पर्यटन को प्रोत्साहन मिले। अलग-अलग उद्योग क्षेत्र के लोग वहां आएं। सर्विसेज सेक्टर, आई.टी. सेक्टर में भी लोग आएं। जम्मू-कश्मीर के हमारे युवा-युवतियां आई.टी. सेक्टर में भी अपना योगदान देना चाहते हैं। इन सभी क्षेत्रों में अच्छा उत्साह दिखाई दे रहा है। विदेश से निवेश के लिए, जब मैं स्वयं श्रीनगर में था तो डी.पी. वर्ल्ड नाम की यू.ए.ई. की एक कम्पनी है, उसने जम्मू-कश्मीर के साथ एक बड़ा फूड पार्क बनाने के लिए एक एम.ओ.यू. साइन किया। हाल ही में एल.जी. साहब ने मुझे बताया कि यू.ए.ई. की एक और कम्पनी लगभग 5 लाख फीट का एक बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहती है। देश-विदेश दोनों से अच्छा निवेश आने के संकेत जम्मू-कश्मीर में मिल रहे हैं।

(इति)

(प्रश्न 104)

माननीय अध्यक्ष: क्वैश्चन नम्बर -104; श्री सी.पी. जोशी जी।

श्री गणेश सिंह जी।

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पूरे देश में एम.एस.पी. के माध्यम से जितनी खरीदारी होती है, उसके भंडारण की कमी देखी जाती है और सालों से लाखों मीट्रिक टन अनाज सड़ रहा है। जिस राज्य मध्य प्रदेश से मैं आता हूं, वहां पर राज्य सरकार ने अपने प्रयासों से भंडारण की व्यवस्था की है। एफ.सी.आई. जिस अनुपात में खरीदारी करती है, उस अनुपात में भंडारण की कमी है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो भंडारण की कमी है, इसे कब तक पूरा किया जाएगा और किन-किन राज्यों में कितने-कितने भंडारण की आवश्यकता है?

श्री अश्विनी कुमार चौबे : महोदय, माननीय सदस्य गणेश जी ने जो प्रश्न किया है, यूं तो यह प्रश्न राजस्थान से जुड़ा विशेष प्रश्न है, फिर भी उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में भी बताने को कहा है तो हम उनको जरूर मिलकर बताएंगे।

जहां तक उन्होंने भंडारण की बात की है तो भारत सरकार पूरी तरह से भंडारण की क्षमता को बढ़ाने के लिए लगातार तत्पर रही है।

(1635/MY/RP)

मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2021-22 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम पूरे देश में प्रयास कर रही है। जहाँ तक खाद्यान्नों के भंडारण की बात है, अभी 2199 गोदामों को, जिसमें स्वामित्व वाले और किराये दोनों हैं, इनका प्रचालन करने के लिए सरकार ने प्रयास किया है। उनकी कुल क्षमता 426.98 लाख टन है। उसके अलावा, हमारे राज्यों के पास खाद्यान्न स्टॉक का जो भंडारण है, उसकी क्षमता 365.83 लाख टन है। हमारे पास कुल 792.81 लाख मीट्रिक टन की क्षमता का गोडाउन पूरे देश भर में है।

मध्य प्रदेश के बारे में मैंने पहले ही कह दिया है। उसके बारे में मैं आपको अलग से बता दूँगा।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है। किसानों के लिए 25 प्रतिशत अनुदान के ऊपर जो भी गोडाउन बनाए जाते हैं, उसके लिए जो अनुदान रहता है, वह दो-दो साल तक नहीं मिलता है। किसानों को जल्दी मिलने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई कोशिश की जा रही है?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, माननीय सांसद जी ने सवाल किया है कि पैसे नहीं मिलते हैं। हमारे यहाँ गोडाउन बनाने की पाँच प्रकार की पद्धति है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: पद्धति नहीं, आप प्रश्न का जवाब दीजिए कि उनको पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। अगर माननीय सदस्य मुझे लिख कर देंगे तो हम निश्चित रूप से उनका समाधान कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष: आप लोग संक्षिप्त में सवाल पूछिए और उसका जवाब भी संक्षिप्त में हो।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि भारतीय खाद्य निगम के द्वारा हिन्दुस्तान में एमएसपी पर जो खरीदी होती है, उसके भंडारण का काम करती है। मैं अपने संसदीय क्षेत्र का एक उदाहरण देते हुए कहना चाहता हूँ कि मेरे होशंगाबाद में भंडारण की जो क्षमता है, वह पर्याप्त है। लेकिन, नरसिंहपुर, मण्डला और सिवनी में भंडारण की क्षमता कम है। इसका संतुलन स्थापित करने के लिए मंत्रालय क्या काम करेगी?

इसके साथ ही आप सांसदों की एक समिति बनाते हैं। प्रदेशों में एक परामर्शदात्री समिति बनती है। उसे आपने अगस्त 2010 में बनाया है, लेकिन उसकी कोई मीटिंग नहीं होती है। कहीं पर जन प्रतिनिधियों और एफसीआई के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्या सरकार इस संबंध में अपनी तरफ से कोई मैकेनिजम डेवलप करने का काम करेगी?

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, माननीय उदय जी ने मध्य प्रदेश के अपने क्षेत्र के बारे में प्रश्न किया है। हम उनसे मिलकर जरूर जानकारी दे देंगें।

उन्होंने भंडारण के अंतराल के आकलन के बारे में बताया कि हम स्टोरेज के लिए कैसे निर्माण करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि देश स्तर पर भंडारण निर्माण का जो आधार है, उसमें हमारे खरीदी करने वाले राज्य हैं, जो प्रोक्योरिंग स्टेट हैं, उनके पिछले तीन वर्षों में खाद्यान्न के स्तरों के आधार पर भंडारण किया गया है, यह पहली बात है।

दूसरा, जो उपभोग करने वाले स्टेट हैं, यानी जो कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं। उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और इस प्रकार के अन्य कल्याणकारी स्कीम हैं। उसमें चार माह का आवंटन और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए छह माह का आवंटन का आकलन किया जाता है। इसका जिलेवार आकलन होता है। इसके साथ ही जहाँ पर यह अंतर दिखता है, वहाँ केन्द्र सरकार उसके निर्माण कार्य को करती है या किराये पर लेती है।

माननीय सदस्य ने भारतीय खाद्य निगम के भंडारण की क्षमता के बारे में लगातार बताया है। हमने उसकी निगरानी करने की व्यवस्था भी रखी है। इस प्रकार विशेष रूप से हमारा यह प्रावधान है और उसके गैप को कम करने की पद्धति है।

(इति)

(1640/NKL/CP)

(Q.105)

SUSHRI DIYA KUMARI (RAJSAMAND): Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity.

Sir, through you, I would like to ask a question to the hon. Minister. The Government has taken many steps to make social media a safe and reliable space for the citizens of India by making IT Rules 2021. Can the hon. Minister throw some light on how the Government is ensuring that social media platforms are complying with these regulations?

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, the hon. Member has asked a very important question. Today, social media is prevalent in all our lives. In 2021, to make sure that social media is safe and also to ensure people's trust upon what is written on that, a very self-regulating kind of a regime was published. It is in the form of Social Media Intermediary Guidelines.

Basically, there are two things. First is the institutional structure, and second is the process. The institutional structure has been set by almost all the significant social media intermediaries. All of them are also following the guidelines and publishing their monthly reports. These are the reports which are available on the platforms. They can be downloaded by anybody. So, I think, the compliance has been good. Whatever further steps are needed to make social media accountable, the Government is open to those suggestions.

SUSHRI DIYA KUMARI (RAJSAMAND): Sir, the hon. Minister has actually answered to my second question which is about submitting monthly reports. Are the social media companies submitting those reports timely; if not, what action is taken against them?

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, a significant number of social media intermediaries are submitting their reports which are uploaded directly on their platforms.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, the guidelines are not having any statutory force. Rules are different, and there is a statutory force there. Now,

the question is this. Of course, the freedom of expression and freedom of speech is there. But you see the way the social media is being utilised.

Even as regards the posts of the hon. Prime Minister or the Chief Ministers, sometimes, memes, etc. are made. So, I would like to ask whether the Government is having any proposal to bring any Act restricting, prohibiting or regulating this type of concept or this type of thought of just embarrassing or criticising a person according to one's own choice. So, my question is, whether the Government is proposing to bring any such law and penalise the offenders.

SHRI ASHWINI VAISHNAW: Sir, I would like to clarify that these are not the guidelines; these are rules. First of all, there is a statutory backing of these rules. … (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): But the name says that these are the guidelines. … (*Interruptions*)

SHRI ASHWINI VAISHNAW: The name can have the word 'guidelines' but these are the rules. That is why, I clarified this. Thank you for raising that point.

Sir, the point about social media about where the balance is, has to be carefully debated in a forum like this and also outside this. We have to come to some sort of a consensus. It is because as and when the Government tries to increase accountability and regulation, the question which comes from the civil society is whether we are taking away the freedom of expression. If we do not increase regulation, if we do not make the social media accountable, the safety and trust that the citizens have on this media come under a question mark. So, it is a very fine balance that we have to strike. It is an evolving world. We all have to evolve when we have to mould according to the changes that are happening.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, समस्या यह है कि यह इंटरमीडिएटरी कौन है और पब्लिशर कौन है? यह किसी भी प्लेटफॉर्म पर अभी तक पता नहीं चला पाया है और भारत सरकार भी इसके लिए चिंता कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने 66 ए, आईटी रूल की जो आत्मा थी, उसको हटा दिया। पार्लियामेंट को जो कानून बनाने का अधिकार था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और हम आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। महिलाओं और बच्चों का हमेशा शोषण होता रहता है और जैसा कल्याण बनर्जी साहब कह रहे थे, हम पॉलिटिशियंस का भी शोषण होता रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या 66 ए के स्थान पर हम सोशल मीडिया को या इस तरह के पब्लिशर्स को रोकने के लिए आईटी एक्ट में, सुप्रीम कोर्ट के रूल के खिलाफ कोई कानून बनाने की व्यवस्था करने वाले हैं? यदि करने वाले हैं तो कब तक करेंगे?

(1645/NK/MMN)

श्री अश्विनी वैष्णव: अध्यक्ष जी, मान्यवर सांसद महोदय का जो सुझाव है, यह एक तरह से प्रश्न नहीं, सुझाव ज्यादा है। हम इस सुझाव का स्वागत करते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल डिबेट होनी चाहिए और डिटेल्ड डिबेट से ही इसका सोल्यूशन निकलेगा। (इति)

(प्रश्न 106)

SHRI PRAJWAL REVANNA (HASSAN): Sir, thank you for giving me the chance to ask a supplementary question.

I want to ask about two railway line projects which are still pending in Karnataka. One is Mysore-Kushalnagaram Railway line which was sanctioned in 2018-19. I also want to bring to the notice that this is the only railway line which connects the district, Coorg, and Coorg being a tourist destination, we do not have even one railway connectivity still in that district. My first point is about that.

The second railway line which I want to talk about is Hejjala-Chamrajanagar line which was sanctioned in 1996-97 when Shri H.D. Deve Gowda was the Prime Minister. That was originally sanctioned between Bengaluru and Sathyamangalam which was temporarily suspended due to environmental clearance. So, I request this railway line from Hejjala to Chamrajanagar to be undertaken. So, I would request the hon. Minister to take up these lines and do the progressive reports on these projects. Thank you, Sir.

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आगला से जामनगर के बारे में प्रश्न पूछा है, यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है। मैं इसकी जानकारी लेकर माननीय सदस्य जी को दे दूंगा।

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप सारे डिपार्टमेंट की जानकारी रखा करो, क्वेश्चन भी दक्षिण-मध्य रेलवे का और पूरे जोन का दिया हुआ था।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, part (d) of the Question is regarding under-bridges and over-bridges. I would like to bring to the notice of this Government one thing. I will give a small example. Look at Daund which is in the Solapur Division of Maharashtra. It is just an example that I am taking. There are several over-bridges and under-bridges where the State Governments have paid but there are delays from the Central Government or technical issues are being raised for over four or five years. So, how do you look at it? It is because every State faces this problem. It is not only for my State. I am giving Daund only as an example. I am aware that it is not a part of this. But it is an example since you have talked about the RUBs and the ROBs.

So, if you take this Daund as an example, when the Government has paid for it, under technical reasons from the Railway Department, it is terribly delayed, and the locals are suffering totally. So, what quick intervention will the hon. Minister and his Ministry do to help resolve this? Your GMs have been very helpful. We have had several meetings but we have not been able to come with an amicable solution. So, I urge you to look into it and find a solution. Thank you.

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: अध्यक्ष महोदय, रेलवे में दो प्रकार के ब्रिज होते हैं, एक आरओबी और दूसरा आरयूबी होता है। आरओबी राज्य सरकार की भागीदारी से होता है और आरयूबी रेल मंत्रालय करता है। कई जगह ऐसा हुआ है कि आरओबी को सैंक्शन मिलने के बाद राज्य सरकार का शेयर नहीं मिलने के कारण भी लेट होता है। लेकिन आरयूबी के बारे में अगर माननीय सदस्य का कुछ बोलना है तो मैं उनको बता दूंगा।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I have already said we have paid for it. He has not understood my question. … (*Interruptions*)

(ends)

(Q. 107)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, the Government has registered ONDC, that is, Open Network for Digital Commerce, to democratise e-commerce and end monopolistic practice in India. My question is related to finding out how the ONDC may benefit the sellers and the consumers. It is a non-profit company. I would like to understand whether you have a governing body which has control over the ONDC that has been registered since December, 2021. How much funds have been allocated and utilized for the project so far?

(1650/VR/SK)

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, ONDC has been conceptualized as a network very similar to UPI. The idea is that over the last few years we are observing that very large companies have almost secured a complete stranglehold on the e-commerce business. But there are a number of start-ups initiated by our young boys and girls, who are full of ideas, full of new ways of doing things, and there are a lot of small shops in local areas like Mom & Pop Stores or the local kirana stores, which are also a very important and integral part of the ecosystem which provide retail shopping. These small people, the new start-ups and small retailers do not get equal opportunity to be able to engage with e-commerce, particularly given their weak financials against the strong financial muscle of the large companies.

Therefore, we have conceptualized this as a network which will democratize the entire e-commerce ecosystem. It will provide opportunities for new start-ups to start creating network of sellers to provide service to local areas and increase the competition. It is like Google, which provides support when you google any information and you get a series of options. In the same way, it will be easy for somebody, who wants to procure any product, to get a lot of options.

I will give a small example to understand it in a simple way. Suppose, I want to buy a pen. Today I have to go to a particular network or platform which may be owned by Company ‘A’ or Company ‘B’ or Company ‘C’. Most of the current platforms are owned by large companies. Thus, the products of only those suppliers who are chosen by that platform, will be offered to me. But instead of that, once the ONDC, which is a network, becomes operationalized, I will google in ONDC that I want to buy a pen.

Then, all the various platforms which offer pens will come into that screen and I can choose where I get the best opportunity. This will provide a level playing field for the small retailers and help them also expand their business and stand up in competition despite not having the financial muscle. They will get an equal opportunity to provide their services.

We have been working on this concept for about two and a half years. We have had extensive consultations with all the stakeholders. On the basis of extensive consultations, a steering committee was formed, which comprised mainly of large technology experts who understand this subject, who are able to build up the network that is required to provide level playing field for all companies.

Now, we have formed a Section 8 company. We are in the process of finalizing the governance structure of that company. We have taken a very high-quality technocrat who will help us to create the backend technology for this. He has started working on it. I think in another few months, we will be in a position to do a beta launch, and this is the system through which we ensure that it gives opportunity particularly to small retailers to stand up in competition against the big companies.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I have a second question. These are all forward looking things. The hon. Minister is conversant in relating it when we talk about platforms and the difference between a platform and a network. That needs to be explained in a greater detail to the general public.

In that respect, I would like to know when will the ONDC initiative, which you mentioned is yet to be rolled out and is still in the making, be made fully functional? What is the timeline? Has the Government laid down any criteria and guidelines with regard to listing of products by the sellers on the set platform? This is to help the consumers in a great detail.

(1655/SAN/MK)

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, as I said, we expect that in a few months' time, we will have the basic network ready. Of course, it involves a lot of firewalls, a lot of technology input to ensure the sanctity of the processes, secrecy and safety of data. It is not something very small. Just like UPI over a period of time has matured into a world-class system, we expect ONDC also to be able to establish similar public digital infrastructure which will open up new gateways and new opportunities for our start-ups and small retailers.

Obviously, when such a project is initiated, lot of protocols will be set up and these protocols would standardise operations like cataloguing, inventory management, order management and order fulfilment, but ultimately we are only going to be a net-world. Each individual platform will be providing the goods or service and will be ensuring the sanctity of quality, the warranties, the goods return strategy – all of that will be of the platform. Then, the network provides an opportunity for different platforms to come on board. Then, ONDC can set up some basic service standards, but the detailing will have to be of each platform individually, similar to UPI. On UPI, you have the State Bank of India; you have the ICICI Bank also; you have Paytm also; you have other public and private banks, other NBFCs and other payment systems. They all vie for the business. They all compete with their practices, their service. Similarly on this, everybody will get a fair chance to compete.

(ends)

(pp. 22 – 30)

(Q.108)

SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI): Hon. Speaker, Sir, in Tamil Nadu, there are many textile industries and Sankarankoil in Tenkasi District is one of them. Cotton sarees and towels produced in Sankarankoil are very famous and the products are distributed all over the country. In this context, I would like to know from the hon. Minister the steps taken to set up export centres at Sankarankoil in Tenkasi to boost exports.

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, Tamil Nadu has played a very important role when it comes to the promotion of textiles, and different parts of Tamil Nadu like Tenkasi, Coimbatore, Tiruppur are all contributing in a big way in the textile industry. We had set up in the past Special Textile Parks, small parks, under a scheme called Scheme for Integrated Textile Parks, SITP. Almost 27 textile parks have been completed under this scheme and 29 more parks are at different stages of implementation. All of these small parks help to promote the ecosystem of textiles.

Learning from this experience, we have now decided to come up with a larger, a much more ambitious scheme called PM-MITRA Park Scheme. It is Pradhan Mantri Mega Industrial Textile Park Scheme in which we are trying to take a large format – 1,000-acre textile parks – and taking these parks to different States in a challenge mode. So, I would urge Tamil Nadu also to come in that competition, offer large piece of land, either at no cost or at a very nominal cost and offer utilities for those who set up industry in that park. Power could be offered for 15 years or 20 years at a low price or at a very defined concessional price. You could make the ease of doing business possible. So, various steps are possible by which we can encourage the industry to come to Tamil Nadu. We will be happy to consider any request that we receive from Tamil Nadu. These seven parks will be chosen from amongst all the States and Union Territories of India based on a challenge mode.

(1700/SNT/SJN)

As regards Tamil Nadu, I am happy to share that at three places –Palladam, Karur, Komarapalayam, we have already completed textile parks under SITP Scheme. We have parks coming up in Perarinagar Anna Handloom Silk Park, Seema Textile Processing Centre, Pallavada Textile Park, and the Great Indian Linen & Textile Infrastructure Company. … (*Interruptions*) Four more SITP parks are under implementation in Tamil Nadu.

(ends)

QUESTION HOUR OVER

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं एक व्यवस्था दे रहा हूं। कई माननीय सदस्यगण खड़े होकर दो-दो, तीन-तीन या पांच-पांच मिनट तक लगातार बात करते रहते हैं। आज के बाद एक सेकेंड, दो सेकेंड, तीन सेकेंड, चार सेकेंड और पांच सेकेंड तक तो खड़े होने की इजाजत है, लेकिन पांच सेकेंड से ज्यादा कोई भी सदस्य खड़ा होगा, तो मैं उनका नाम लेकर पुकारूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाइए। कोई माननीय सदस्य इधर खड़ा है, तो कोई उधर खड़ा है, खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये सदन है, इस सदन की गरिमा बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसको सदन रहने दें। ये तरीका बिल्कुल उचित नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रेमचन्द्रन जी ने कहा है कि 10 सेकेंड तक अलाऊ किया जाए। ठीक है, 10 सेकेंड के लिए अलाऊ किया जाता है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1702 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री वी. मुरलीधरन जी, आइटम नंबर 2 से 19.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Raj Nath Singh, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Defence for the year 2022-2023.

(2) Defence Services Estimates for the year 2022-2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Sarbananda Sonowal, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways for the year 2022-2023.

(2) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of AYUSH for the year 2022-2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Dr. Virendra Kumar, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2022-2023.

(2) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2022-2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Kiren Rijiju, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Law and Justice for the year 2022-2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Dr. Mansukh Mandaviya, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Health and Family Welfare for the year 2022-2023.

(2) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Health and Family Welfare for the year 2022-2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Rao Inderjit Singh, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Planning for the year 2022-2023.

(2) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Statistics and Programme Implementation for the year 2022-2023.

(3) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Planning for the year 2022-2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Dr. Jitendra Singh, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Department of Space for the year 2022-2023.

(ii) Detailed Demands for Grants of the Department of Atomic Energy for the year 2022-2023.

(iii) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Earth Sciences for the year 2022-2023.

(iv) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Science and Technology for the year 2022-2023.

(v) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Science and Technology for the year 2022-2023.

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under article 323(1) of the Constitution:-

(i) 71st Annual Report of the Union Public Service Commission, New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) Memorandum explaining reasons for non-acceptance of Commission's advice in respect of cases reported in Chapter 9 of the Report.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Physics, Bhubaneswar, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Physics, Bhubaneswar, for the year 2020-2021.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Trivandrum, for the year 2020-2021.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bengaluru, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research, Bengaluru, for the year 2020-2021.

(7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

(8) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the NewSpace India Limited, Bengaluru, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the NewSpace India Limited, Bengaluru, for the year 2020-2021 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the IREL (India) Limited (erstwhile Indian Rare Earths Limited), Mumbai, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the IREL (India) Limited (erstwhile Indian Rare Earths Limited), Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Uranium Corporation of India Limited, Jaduguda, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Uranium Corporation of India Limited, Jaduguda, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(d) (i) Review by the Government of the working of the Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Science Education and Research, Bhubaneswar, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Science Education and Research, Bhubaneswar, for the year 2020-2021.

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Homi Bhabha National Institute, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Homi Bhabha National Institute, Mumbai, for the year 2020-2021.

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Atomic Energy Education Society, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Atomic Energy Education Society, Mumbai, for the year 2020-2021.

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute of Mathematical Sciences, Chennai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute of Mathematical Sciences, Chennai, for the year 2020-2021.

(13) A copy of the Lokpal (Court Master) Recruitment Rules, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.913(E) in Gazette of India dated 30th December, 2021 under Section 61 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Faggansingh Kulaste, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Steel Authority of India Limited, New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Steel Authority of India Limited, New Delhi, for the year 2020-2021 alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the Rashtriya Ispat Nigam Limited and the Ministry of Steel for the year 2021-2022.

(ii) Memorandum of Understanding between the MOIL Limited and the Ministry of Steel for the year 2021-2022.

(iii) Memorandum of Understanding between the Steel Authority of India Limited and the Ministry of Steel for the year 2021-2022.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Ashwini Kumar Choubey, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 105 of the Consumer Protection Act, 2019:-

(i) The Consumer Protection (Direct Selling) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.889(E) in Gazette of India dated 28th December, 2021.

(ii) The Consumer Protection (Jurisdiction of the District Commission, the State Commission and the National Commission) Rules, 2021 published in Notification No. G.S.R.912(E) in Gazette of India dated 30th December, 2021.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Bureau of Indian Standards, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Bureau of Indian Standards, New Delhi, for the year 2020-2021.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (5) of Section 45 of the Food Corporations Act, 1964:-

(i) The Food Corporation of India (Staff) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 published in Notification No. EP-9(1)2019 in Gazette of India dated 15th December, 2021.

(ii) The Food Corporation of India (Staff) (Sixth Amendment) Regulations, 2021 published in Notification No. EP-7(1)2020 in Gazette of India dated 15th December, 2021.

(iii) The Food Corporation of India (Staff) (Seventh Amendment) Regulations, 2021 published in Notification No. EP-39(1)2020 in Gazette of India dated 30th December, 2021.

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for the year 2022-2023.

(ii) Output Outcome Monitoring Framework of the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for the year 2022-2023.

(iii) Output Outcome Monitoring Framework of the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution for the year 2022-2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Arjun Ram Meghwal, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following statements (Hindi and English versions) showing Action Taken by the Government on the assurances, promises and undertakings given by the Ministers during various sessions of Fifteenth, Sixteenth and Seventeenth Lok Sabhas:-

FIFTEENTH LOK SABHA

1.	Statement No. 36	Fifth Session, 2010
2.	Statement No. 39	Eighth Session, 2011
3.	Statement No. 34	Tenth Session, 2012
4.	Statement No. 27	Fifteenth Session, 2014

SIXTEENTH LOK SABHA

5.	Statement No. 27	Second Session, 2014
6.	Statement No. 27	Third Session, 2014
7.	Statement No. 26	Fourth Session, 2015
8.	Statement No. 24	Fifth Session, 2015
9.	Statement No. 23	Sixth Session, 2015

10.	Statement No. 20	Seventh Session, 2016
11.	Statement No. 22	Eighth Session, 2016
12.	Statement No. 21	Ninth Session, 2016
13.	Statement No. 17	Tenth Session, 2016
14.	Statement No.19	Eleventh Session, 2017
15.	Statement No. 18	Twelfth Session, 2017
16.	Statement No. 14	Fourteenth Session, 2018
17.	Statement No. 15	Fifteenth Session, 2018
18.	Statement No. 12	Sixteenth Session, 2018
19.	Statement No. 12	Seventeenth Session, 2019

SEVENTEENTH LOK SABHA

20.	Statement No. 11	First Session, 2019
21.	Statement No. 8	Second Session, 2019
22.	Statement No. 7	Third Session, 2020
23.	Statement No. 7	Fourth Session, 2020
24.	Statement No. 6	Fifth Session, 2021
25.	Statement No. 5	Sixth Session, 2021

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Krishan Pal, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Power for the year 2022-2023.

(2) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Power for the year 2022-2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Danve Raosaheb Dadarao, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Mines for the year 2022-2023.

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the Rail Vikas Nigam Limited, New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Rail Vikas Nigam Limited, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the Madhepura Electric Locomotive Private Limited, New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of Madhepura Electric Locomotive Private Limited, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(c) (i) Review by the Government of the working of the Singareni Collieries Company Limited, Khamman, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Singareni Collieries Company Limited, Khamman, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (a) & (b) of (2) above.

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Railway Welfare Organisation, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Railway Welfare Organisation, New Delhi, for the year 2020-2021.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Geological Congress, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Geological Congress, New Delhi, for the year 2019-2020.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shrimati Anupriya Patel, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Centre for Trade Information, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Centre for Trade Information, New Delhi, for the year 2020-2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Institute of Foreign Trade, New Delhi, for the year 2020-2021.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Agricultural and Processed Food Products Export Development

Authority, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority, New Delhi, for the year 2020-2021.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Chemicals and Allied Products Export Promotion Council (CAPEXIL), Kolkata, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Chemicals and Allied Products Export Promotion Council (CAPEXIL), Kolkata, for the year 2020-2021.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

(9) A copy each of the following Annual Reports and Accounts (Hindi and English versions) of the following SEZs for the year ended the 31st March, 2020 together with Auditor's Report thereon:-

(i) Falta Special Economic Zone Authority
(ii) Visakhapatnam Special Economic Zone Authority
(iii) Cochin Special Economic Zone Authority
(iv) Kandla Special Economic Zone Authority
(v) SEEPZ Special Economic Zone Authority

(10) A copy of the Consolidated Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the above SEZs for the year 2020-2021.

(11) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 19 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992:-

(i) S.O.5319(E) published in Gazette of India dated 20th December, 2021, regarding amendment in import policy of items under HS

Code 1511 90 of Chapter 15 of ITC (HS), 2017, Schedule–I (Import Policy).

(ii) S.O.67(E) published in Gazette of India dated 5th January, 2022, regarding Amendment in import policy conditions of gold under Chapter 71 of Schedule – I (Import Policy) of ITC (HS), 2017.

(iii) S.O.4898(E) published in Gazette of India dated 29th November, 2021, regarding Amendment in Export Policy of Agar Oil and Agarwood Chips and Powder obtained from artificially propagated source and insertion of policy conditions.

(iv) S.O.4899(E) published in Gazette of India dated 29th November, 2021, regarding Export Policy of Fertilizers-Updation in List of Manufactures/Units of NP/NPK Fertilizers.

(v) S.O.93(E) published in Gazette of India dated 10th January, 2022, 2021, regarding Amendment in Export Policy of Enoxaparin (Formulation and API) and Intra-Venous Immunoglobulin (IVIG) (formulation and API).

(12) A copy of the Tea (Marketing) Control (Second Amendment) Order, 2020 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.5294(E) in Gazette of India dated 17th December, 2021 issued under sub-sections (3) and (5) of Section 30 of the Tea Act, 1953.

(13) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 30 of the Tobacco Board Act, 1975:-

(i) S.O.86(E) published in Gazette of India dated 7th January, 2022, authorising the Tobacco Board to allow the traders/dealers of the Tobacco to purchase the excess unauthorized tobacco at the auction platforms by charging penalties as fixed by the Government in the State of Karnataka and Andhra Pradesh and relaxing the operation of the provisions of Section 10(1) of the Tobacco Board Act, 1975 in the State of Karnataka and Andhra Pradesh.

(ii) S.O.87(E) published in Gazette of India dated 7th January, 2022, authorising the Tobacco Board to allow the traders/dealers of the Tobacco to purchase the excess unauthorized tobacco at the auction platforms by charging penalties as fixed by the Government in the State of Karnataka and Andhra Pradesh and relaxing the

operation of the provisions of Section 10(1) of the Tobacco Board Act, 1975 in the State of Karnataka and Andhra Pradesh.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shrimati Darshana Vikram Jardosh, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Synthetic and Rayon Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Synthetic and Rayon Textiles Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2020-2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Powerloom Development and Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Powerloom Development and Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2020-2021.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the National Handloom Development Corporation Limited, Noida, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the National Handloom Development Corporation Limited, Noida, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(b) (i) Review by the Government of the working of the National Textile Corporation Limited, New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the National Textile Corporation Limited, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(6) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Som Prakash, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Industrial Corridor Development and Implementation Trust, New Delhi, for the year 2020-2021.

(2) A copy of the Boiler Operation (Amendment) Rules, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.890(E) in Gazette of India dated 28th December, 2021 under sub-section (2) of Section 28A of the Boilers Act, 1923.

(3) A copy of the Gas Cylinders (Amendment) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.44(E) in Gazette of India dated 25th January, 2022 under sub-section (8) of Section 18 of the Explosives Act, 1884.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Ajay Misra Teni, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs (Volume I) for the year 2022-2023.

(2) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Home Affairs (Union Territories)(Volume II) for the year 2022-2023.

(3) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Home Affairs for the year 2022-2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Shri Devusinh Chauhan, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Department of Posts for the year 2022-2023.

(2) Output Outcome Monitoring Framework of the Department of Posts for the year 2022-2023.

(3) Detailed Demands for Grants of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, for the year 2022-2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, on behalf of Dr. Bhagwat Karad, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Finance for the year 2022-2023.

(2) Output Outcome Monitoring Framework of the Ministry of Finance for the year 2022-2023.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह हर दिन की आदत बन चुकी है कि एक मंत्री खड़ा होता है और वे 19-20 मंत्रियों को रिप्रेजेन्ट करते हैं, तो यहां पर बाकी मंत्रियों के रहने की क्या जरूरत है?...(व्यवधान) मैं जानता हूं कि वे आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन यह आदत बनती जा रही है। मंत्रिगण के नदारत रहने का यह एक ज़रिया बनता जा रहा है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने कोविड के कारण यह व्यवस्था दी थी, लेकिन जैसे ही कोविड समाप्त हो जाएगा, पूर्व व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवृत्त

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की दिनांक 23.03.2021, 04.08.2021 और 20.12.2021 को हुई क्रमशः चौथी, पांचवी और छठी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति
335वां प्रतिवेदन

श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ (पंचमहल) : अध्यक्ष महोदय, मैं 'प्रदर्शन और ललित कला शिक्षा में सुधार' विषय के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का 335वां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के संबंध में विनिर्णय

1704 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं - श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, प्रो. सौगत राय, श्री हनुमान बेनिवाल, श्री हिबी इडन, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, श्री वी. के. श्रीकंदन, श्री एम. के. राघवन, श्री अधीर रंजन चौधरी और श्री बैन्नी बेहनन। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज शून्य काल में जिन माननीय सदस्यों के नाम लिस्टेड हैं, मैं उनको मौका दूंगा।

(1705/YSH/SRG)

*लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे

1705 बजे

माननीय अध्यक्ष : श्री श्रीरंग आप्पा बारणे।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यहां स्मार्ट सिटी के विषय पर अपनी बात रख रहा हूँ। माननीय प्रधान मंत्री जी की महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना देश के 100 शहरों में चल रही है। मेरे क्षेत्र पिम्परी-चिंचवड शहर में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा 50 प्रतिशत, राज्य सरकारों द्वारा 25 प्रतिशत तथा स्थानीय नगर निगमों के द्वारा 25 प्रतिशत का अंशदान इस कार्य हेतु दिया जाता है। पिम्परी-चिंचवड शहर में स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, उसमें टेक महिन्द्रा, एलएण्डटी, बीजी शिर्के, बेनेट कॉलमेन कंपनियां कार्य कर रही हैं, लेकिन असल में ये कंपनियां कार्य नहीं करती हैं। ये कंपनियां सब-ठेकेदारों को काम देती हैं। चूँकि ये ठेकेदार ठीक से काम नहीं करते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में जो विकसित भाग है, वहां पर इसका काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी की कमेटी और ठेकेदार पूरी तरह से मिलीभगत करके काम करते हैं। मेरी यह मांग है कि पिम्परी-चिंचवड शहर में चल रही स्मार्ट सिटी योजना के कार्य की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच की जाए और जो दोषी लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप नोट कर लीजिए।

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपका ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। आदिवासी जनजाति में धर्मांतरण एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। आदिवासी जनजाति के प्राचीन गौरव, एकता और परम्परा को गिने-चुने लोगों के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, मेरा संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर-बांसवाड़ा और पूरे राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं झारखण्ड आदि में आदिवासी लोगों की बड़ी आबादी का धर्म एक विशेष टीम ईसाई धर्म में परिवर्तित करने में सक्रिय है। इसे रोकना अनिवार्य है, अन्यथा जो लोग अपना धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाते हैं, उनके लिए आरक्षण आदि की सुविधा समाप्त कर देनी चाहिए और अल्पसंख्यक के नाम पर जो दोहरे लाभ ले रहे हैं, उसे तुरंत समाप्त करने की आवश्यकता है। जो लोग आदिवासी जनजाति में धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं, उस पर तत्काल अंकुश लगाया जाए एवं संसद द्वारा हिंदू धर्म के अतिरिक्ति किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होने वाले आदिवासियों के संविधान में प्रदत्त लाभों को समाप्त करने के लिए कानून बनाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से इसकी मांग करता हूँ।

---

* Please see pp. 310 – 311 for the list of Members who have associated.

*SHRI BHAGWANT MANN (SANGRUR): I thank you, hon. Speaker Sir. Today, I want to raise a very serious issue. As per Sugar Act, 1966, the sugarcane growing farmers must get money from sugar mills within 14 days, otherwise they must pay interest to the farmers.

Sir, in 2020 and 2021-2022, the government rates were Rs.360/- per quintal. Mills were providing Rs.325/- and Rs.35/- was being given by the Punjab government. The mills are providing Rs.325/- but the bonus of Rs.35/- is not being provided to them.

Sir, in my constituency Sangrur, Dhuri, Bhagwanpura, there are mills. But it is painful to know that 1.25 crores Rs. of last year and Rs.20 crores of this year are yet to be provided to the farmers.

Sir, sugarcane crop is sown and reaped only once every year. So, for the sugarcane farmers, after he cuts the sugarcane crop, the land becomes useless.

Sir, pink worms are wreaking havoc in several foodgrains but no compensation has been provided to the farmers. Sir, during the protests by farmers against black laws, 743 farmers sacrificed their lives. No compensation has been provided to the families of these farmers. FIRs have been lodged against the farmers.

So, sir, I want to draw the attention of the Central government towards the miserable condition of farmers. The Centre accepted its mistake and withdrew the black laws. The need of the hour is to withdraw the cases lodged against the farmers. Ample compensation must be provided to the farmers for their deaths, so that their families do not suffer.

In the end, I would like to quote the lines of Punjabi poet Sant Ram Udasi:

“The Jat farmer is crying miserably,
Rivers of tears are flowing,
It is the misfortune of the farmer
that he is being ignored,
In the end, only the husk remains
with the farmer.”

The sugarcane and cotton of farmers must be given adequate compensation so that those who fill the granary of the country do not go hungry themselves.

Thank you.

---

* Original in Punjabi

(1710/AK/RPS)

HON. SPEAKER: Shri Ramesh Bidhuri -- not present.

Shri T. N. Prathapan

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Hon. Speaker, Sir, there are 23 textile mills in India under the National Textiles Corporation. In the first lockdown of COVID-19 pandemic, that is in March, 2020, all these 23 mills were closed. When I asked about this during the Question Hour, I was given the answer that eight mills will be opened and the other 15 mills will remain closed. These eight mills were open for a short period and later they also had closed all operations.

1712 hours (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

In Kerala, there are four mills and two of them are in my Constituency, namely Alagappa Textile Mills, Alagappa Nagar Gram Panchayat and Kerala Lakshmi Textile Mills, Pullazhi, Thrissur Corporation. The workers in these 23 mills are not given their salaries in full. Further, there is no financial bonus or allowances for them, and there were many temporary workers who are suffering due to unemployment. My request is that all these 23 mills under the National Textile Corporation should be opened immediately and the pending payments should be distributed to them.

Actually, we talk about 'Make in India' but we had closed all our mills for two years. Indian textile products are very famous all around the world, but we cannot produce anything from closed mills.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Please put the demand and conclude.

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Will the Textile Minister take interest in opening all these mills without any delay? Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Shri Asaduddin Owaisi -- not present.

Shri Ram Kripal Yadav

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे शून्य काल में बिहार से संबंधित किसानों की समस्या को सदन में उठाने का अवसर दिया है।

पिछले दिनों बिहार में भारी ओला वृष्टि हुई है, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र के अलावा कई ऐसे जिले हैं, जहां किसानों ने जो फसलें लगाई थीं, वे ओला वृष्टि की वजह से बर्बाद हो गई हैं, खास तौर पर आलू, सरसों, हरी सब्जियां और दलहन को भारी नुकसान हुआ है।

महोदय, गरीब किसानों ने कर्ज लेकर फसल लगाने का काम किया था। मैं समझता हूं कि ओला वृष्टि की वजह से किसानों की पूरी फसल की बर्बादी हो गई है, जिसकी वजह से गरीब किसानों के सामने आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। कर्ज लेकर वे किसान फसल से आस लगाए हुए थे, अगर फसल अच्छी होती तो लोगों की आमदनी होती। सरकार का पूरा ध्यान है कि हम किसानों की आमदनी को दोगुना करें, उसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं, मगर स्थिति यह है कि आपदा से वे इतना अधिक प्रभावित हुए हैं और मैं समझता हूं किसानों की कमर ही टूट गई है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि तत्काल मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र के साथ ही बिहार के अन्य जिलों में, जहां भारी पैमाने पर ओला वृष्टि हुई है और किसानों को नुकसान हुआ है, वहां एक टीम भेजी जाए, एक जांच दल भेजें, ताकि इसका आकलन करके, जो उचित मुआवजा हो सके, वह किसानों को उपलब्ध कराया जाए। … (व्यवधान)

सर, यह अत्यंत गंभीर मामला है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय पर संरक्षण दीजिए और सरकार को यह आदेश दीजिए कि इसमें तुरंत हस्तक्षेप करके बिहार के किसानों को बचाएं। धन्यवाद।

(1715/SPS/SPR)

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं आपका ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र पाली ही नहीं, बल्कि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, नागौर व अन्य जिलों के रहने वाले प्रवासियों की रेल यात्रा की समस्या की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि इन जिलों के लगभग 20 लाख से अधिक लोग शिक्षा, व्यापार, नौकरी आदि के लिए सूरत, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, चेन्नई व हैदराबाद जैसे शहरों में रहते हैं। इन लोगों का समय-समय पर अपने घर आना-जाना होता है, जिसके लिए रेल यात्रा ही एकमात्र उपयुक्त साधन है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर शहर से इन स्थानों के लिए पर्याप्त रेल सुविधा नहीं है। वहां केवल साप्ताहिक या सप्ताह में दो बार ही रेल इन शहरों से आने-जाने के लिए ही उपलब्ध है। जैसे पुणे के लिए सप्ताह में एक बार, चेन्नई के लिए एक बार, हैदराबाद के लिए दो बार और बेंगलुरु के लिए भी दो बार है। उक्त ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट काफी लंबी है। इनमें दो से तीन महीने के बाद का भी टिकट लेने पर वेटिंग ही मिलती है। उनमें मजदूर लोग भी हैं, उनको भी आने-जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस कारण से लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अत: आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इन गंतव्य स्थानों पर आने-जाने की रेल सुविधा के बारे में अध्ययन करवाते हुए, संबंधित ट्रेनों के फेरे प्रतिदिन के लिए निर्धारित करने का फैसला इस बजट सत्र में करने की कृपा करें। मैं इस मामले के लिए निरंतर प्रवासियों के संपर्क में हूं और माननीय मंत्री जी के संपर्क में भी हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें शीघ्र कार्रवाई करके, राहत प्रदान कराएं।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : आदरणीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने मुझे एक बहुत ही ऐसे सेंसेटिव मुद्दे पर बोलने के लिए समय दिया है, जो देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है।

महोदय, मैं आपके और सदन के माध्यम से विशेषतः उत्तर प्रदेश, पंजाब व उत्तराखंड के निवासियों को एक गंभीर समस्या से आगाह कराना चाहता हूँ। जिस प्रकार संविधान में मूलभूत अधिकार हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद 514 में मूलभूत दायित्वों का भी वर्णन किया गया है। मूलभूत दायित्व में जीवों के सरंक्षण के विषय में भी बताया गया है। मैं वन्य जीवों की एक प्रजाति के प्रति बहुत चिंतित हूँ। वह प्रजाति गिरगिट है, जिसको देहात में करकैंटा भी बोलते हैं। गिरगिट सामान्यतः अपनी सुरक्षा हेतु समय-समय पर रंग बदलते हैं, परन्तु उनके एक फूफा आज उनको भी धोखा देकर रंग बदल कर अपने राजनीतिक स्वार्थ हेतु लोगों को ठग रहे हैं। मैं दिल्ली के मुख्य मंत्री जी की बात कर रहा हूँ, जो आजकल पड़ोसी राज्यों में रंग बदलते नज़र आए। इस प्रकार का डीएनए हमारी संस्कृति में कैसे आ गया? इस बात को लेकर गिरगिट बहुत चिंता में हैं।

सभापति महोदय, मैं इस व्यक्ति की कथनी व करनी का अंतर बताता हूँ। इन महाशय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैण्डल पर स्टेटस में लिखा है कि सब इंसान बराबर हैं, चाहे वह किसी धर्म या जाति का हो। हमें ऐसा भारत बनाना है, जहां सभी धर्म और जाति के लोगों में भाईचारा और मोहब्बत हो, न कि नफरत और बैर हो। जबकि सीएए के विरोध में शाहीन बाग में उपद्रवियों के समर्थन में खड़े होकर महीनों रास्ता बंद रखा गया। इंसान, मोहब्बत और नफरत शब्द का प्रयोग योजनाबद्ध रूप में हुआ है। अब करनी देखिए।

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन) : बिधूड़ी जी, आपकी डिमाण्ड क्या है?

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली में 300 मस्जिदों के मौलवियों व अजान लगाने वाले मुअज्जिन को प्रतिमाह 18,000 रुपये और 16,000 रुपये की सैलरी दी जा रही है। 1500 मस्जिदों में 14,000 और 12,000 का वेतन सरकारी खजाने से दिया जा रहा है। यानि प्रत्येक वर्ष जनता के पैसे से 59 करोड़ 4 लाख रुपये मस्जिदों में दिये जाते हैं।

माननीय सभापति : आपको अपनी डिमाण्ड रखनी है।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सर, मैं मांग कर रहा हूं। … (व्यवधान) इसी प्रकार से दिल्ली में लगभग 5 हजार मंदिर हैं। उन मंदिर के पुजारियों को वेतन क्यों नहीं दिया जाता है? यह भेदभाव क्यों? जबकि मंदिर में पूजा करने में अगरबत्ती, घी, दीपक, इत्यादि का भी खर्च होता है, परन्तु फिर भी उनके बारे में चिंता नहीं की जाती है। क्योंकि उन्हे एक धर्म विशेष का वोट चाहिए। … (व्यवधान) वहीं दूसरी ओर जिन राज्यों में चुनाव हैं, वहां कांग्रेस के राजकुमार मैं हिन्दू हूं, कहते हैं… (व्यवधान)

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Hon. Chairperson, Sir, first of all, I would like to express my regret for not being in the House when you took my name because I was attending the meeting of the Standing Committee on Finance.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : बिधूड़ी जी, एक मिनट।

… (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सर, कांग्रेस के राजकुमार जगह-जगह … (व्यवधान)

माननीय सभापति : बिधूड़ी जी, एक मिनट। आपका जीरो आवर का सबमिशन यह है कि हिन्दू टेम्पल के प्रीस्ट को अलाउंस देना चाहिए।

… (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सर, मेरी बात बस तीस सेकण्ड में खत्म हो रही है। सर, मेरी बात बस पन्द्रह सेकण्ड में खत्म हो रही है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी डिमाण्ड कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : सर, कांग्रेस की दो या तीन राज्यों में बची हुई सरकार है, वहां यह राजकुमार जाकर हिन्दू-हिन्दू की दुहाई दे रहे हैं।

(1720/RAJ/UB)

सभापति महोदय जी, दोनों ... (*Expunged as ordered by the Chair*) पंजाब में बिजली का वादा कर रहे हैं।…(व्यवधान) मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में, कांग्रेस शासित राज्यों में बिजली मुफ्त की गई है? …(व्यवधान) वह क्यों नहीं की गई है?…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Definitely, his speech will be verified.

… (*Interruptions*)

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Sir, such kind of statements cannot be made during 'Zero Hour'. Please review the speech and unparliamentary words should be expunged.

HON. CHAIRPERSON: That will be verified and corrected.

SHRI GAURAV GOGOI (KALIABOR): Please review the speech.

I rise to speak for the subject that was listed in 'Zero Hour' - the status of the four-lane highway, NH-37. Every day, the hon. Minister says that so many kilometres of highways are being constructed every day but if you see the state of the four-lane highway between Dibrugarh and Naugaon, this project was supposed to have been completed by December, 2019, but even in 2022, the completion is nowhere in sight. The hon. Union Minister visited the site so many times from 2014 till now, the Chief Minister has visited the site so many times, and the people have also complained to the officials of NHIDCL so many times but the state of this four-lane highway is absolutely poor. The people are facing inconvenience. The Jorhat Airport and the Dibrugarh Airport are located in Upper Assam where there is so much of pristine natural beauty. It is hurting the image of our State and it is affecting the tourists. I would request the Government to urgently complete the four-lane work of the highway on NH-37 between Dibrugarh and Naugaon.

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): सभापति महोदय, मैं असम के एक महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। महोदय, असम के साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम का सीमा विवाद चल रहा है। कुछ महीने पहले मिजोरम बॉर्डर पर असम के पुलिसकर्मियों को भी मार दिया गया। यह सुनने में आया है कि असम सरकार अपना कुछ एरियाज पड़ोसी राज्यों के लिए भी छोड़ देने वाली है। असम सरकार का पहले से ही इस विषय पर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। आपको पता है कि हमें अभी भी असम के विभाजित होने का गम है। हमारा बीटीसी भी अलग राज्य बनते-बनते रह गया।

इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि विवादित सीमा एरिया को केन्द्र सरकार की पहल से स्पेशियली इकोनॉमी जोन जैसा एक मॉडल बनाना चाहिए, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और बॉर्डर बिजनेस सेंटर बने, जिससे लोगों को रोजगार मिले एवं वहां शांति कायम हो। अगर यह नहीं किया जाएगा, वे अगर अपने बहुमत के दम पर वह एरिया छोड़ देंगे, तो असम के लोग उसका जरूर बुरा मानेंगे।

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Sir, as a part of the rationalisation exercise, Prasar Bharati is merging some radio stations with bigger ones. As a part of that exercise, one local classical music airing channel from Bengaluru called Amruthavarshini which predominantly was airing Carnatic classical music has been merged with another channel called Ragam, and many artists who were dependent on this channel have now lost out on opportunities. My request to the Government is to kindly make arrangements to restart operations of Amruthavarshini as an independent channel and provide for a platform and an opportunity for all the local talents who were performing on the platform of the erstwhile channel. The channel enjoyed great listenership both inside of this country and among the NRI population. Therefore, I once again request the authorities concerned to restart the operations of Amruthavarshini channel.

(1725/KMR/VB)

DR. T. R. PAARIVENDHAR (PERAMBALUR): Mr. Chairman, my Perambalur Parliamentary Constituency is one of the backward Constituencies in Tamil Nadu. Most of the people there belong to agricultural background. In the Union Budget 2020-21, the Government announced that 100 Sainik Schools would be established in the country. As an educationalist I welcome the announcement by the Government of India.

I would like to request the Union Government through you, Sir, to consider the proposal to set up a Sainik School in Pachamalai, Thuraiyur in Perambalur Parliamentary Constituency which is a hilly area and most suitable for defence education. Sainik Schools provide quality education at reasonable fees and help prepare boys academically, physically, and mentally to be strong to enter into the National Defence Academy to serve the nation.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, a landmark Bill has been brought which proposes to raise the marriageable age of women in the country, but it is being left to a Committee of 30 male MPs and only one woman MP. Nothing can be more unfair than this. The domination of male Members on the Committee reflects the patriarchal principle on which the Indian society is based. The future of crores of girls will be decided by a Parliamentary Committee which has only one woman! Since the Bill has been referred to the Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports, which is a Rajya Sabha administered Committee, hon. Chairman is empowered to invite additional members.

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Madam, this is a matter which falls under the jurisdiction of hon. Speaker.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, this is my request.

HON. CHAIRPERSON: Please listen. This is the decision of the Chairman. So, please avoid this observation.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I would like to request the hon. Speaker through you, since he is not in the chair.

HON. CHAIRPERSON: You can very well meet the hon. Speaker and make the submission. You are indirectly questioning the authority of the hon. Speaker in constituting a committee. You can very well meet the hon. Speaker. And it is under the consideration of the Speaker.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Mr. Chairman, she is not questioning, she is simply suggesting, she is urging for it.

HON. CHAIRPERSON: That is why I said that the matter which she has raised is under the consideration of the hon. Speaker. So, please keep it in abeyance. Let us close that issue with that.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Very well! You can speak on the subject of age.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Sir, I will write a letter to the hon. Speaker. Just permit me to speak so that I can conclude my submission.

Sir, I would like to request the hon. Speaker through you to look into the matter directly because only a gender-balanced panel will make sure that the women have equal say in issues which affect them. Thank you.

*SHRI S. VENKATESAN (MADURAI): Hon Speaker Sir, Vanakkam. On 15 January, a private TV Channel in Tamil Nadu aired a kids programme. Hon. Union Minister of State, taking cognizance of this programme which was said to have belittled hon. Prime Minister, sends a notice to the TV Channel.

What is taking place in Karnataka today? Politics of hatred is dividing the student community keeping hijab on the forefront. Instead of making them socialize with the students of their age, these agitations are against the priorities of the student community. Boys will not be permitted to wear crowns and girls will not be permitted to wear hijab. Should the school students stage a drama and college students wear dresses as per your orders.?

The National Commission on Children which went to inquire and investigate into the death of Lavanya to see the religious conversion angle did not take interest to go to Karnataka. Why is it so? A notice seeking clarification was issued by the Union Government for staging a kids drama in a channel. Why is it silent now? A courageous girl Muskan said, do not snatch our educational rights in the name of a small piece of cloth which we wear. “She further added that the co-students need not be punished and let them only be asked to seek apologies. These powerful words can make the religious fanatics to bow down. These are the words of Lord Rama, Prophet Mohammed and Jesus Christ. These words are created by humanity to defeat their rivals. These words should reverberate in the whole House.

* Original in Tamil

(1730/PC/RCP)

माननीय सभापति (श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन) : प्लीज़, बैठ जाइए। The issue is over.

… (*Interruptions*)

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने की अनुमति दी।

सर, हमारी सरकार ने वर्ष 2014 से रेलवे के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। … (व्यवधान) बजट में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने अगले तीन वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेन्स का निर्माण और संचालन की भी घोषणा की है। हमारा लक्ष्य वर्ष 2022 तक 100 प्रतिशत indigenous manufacturing of rail coaches का है। वर्तमान में भारत में सिर्फ तीन रेल कोच फैक्ट्रीज़ हैं। महाराष्ट्र के लातूर में एक कोच फैक्ट्री हमारी सरकार ने शुरू की है, लेकिन वहां सिर्फ लोकल ट्रेन्स और ईएमयू ट्रेन्स की मैनुफैक्चरिंग होती है।

हमारे देश में रेलवे के इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ मॉर्डन ट्रेन्स में विस्टाडोम, वंदे भारत, तेजस और भविष्य में बुलेट ट्रेन्स शामिल हैं। इनकी डिमांड्स को देखते हुए नया मॉडल इन्फ्रास्ट्रक्चर और टैक्नोलॉजिकली एड्वांस्ड रेल कोच फैक्ट्रीज़ की आवश्यकता है। मेरा सरकार से यह निवेदन है कि प्रधान मंत्री जी के मेक इन इंडिया के लक्ष्य को सार्थक करने के लिए मेरे लोक सभा क्षेत्र अहमदनगर में एक स्टेट ऑफ आर्ट रेल कोच का निर्माण हो, जिससे अहमदनगर और पूरे महाराष्ट्र में रोजगार के अवसर बढ़ें और अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो और भारतीय रेल की इंडनाईजेशन प्रक्रिया को और बूस्ट किया जा सके। धन्यवाद।

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़) : माननीय सभापति महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र नांदेड़ मराठवाड़ा क्षेत्र का एक मुख्य शहर है। यह गुरू गोबिंद सिंह जी की विश्व प्रसिद्ध 'गुरू की गद्दी गुरुद्वारा' की धरती है। यहां विश्व भर से धार्मिक और व्यवसायिक दृष्टि से लोगों का आवागमन होता है।

महोदय, सरकार से मेरी प्रमुख मांग यह है कि सरकार नांदेड़ में एक बड़ा उद्योग स्थापित करने का कदम उठाए। नांदेड़ ही नहीं, दूर-दूर तक ऐसा कोई उद्योग स्थापित नहीं है, जहां इस क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। मुझे यह कहने में दु:ख होता है कि नांदेड़ में देश के बड़े-बड़े नेता आए, वर्षों राज किया और चले गए, लेकिन कभी इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास के बारे में कोई विचार तक नहीं किया।

महोदय, हमारे पास उद्योग खोलने के लिए सभी संसाधान मौजूद हैं। इससे जो भी आवश्यकताएं उद्योग स्थापित करने के लिए होंगी, उनकी पूर्ति हो सकती है। जनता और हम जनप्रतिनिधि भी पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करने के लिए सरकार के साथ खड़े हैं। किसी भी अवस्था में सरकार इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करे और नांदेड़ में एक बड़ा उद्योग स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए, ताकि जिले के ग्रामीण किसानों एवं हर वर्ग के शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खुले। धन्यवाद।

SHRI SRIDHAR KOTAGIRI (ELURU): Thank you, Sir. Sri Krishna Jute Mills in my constituency is a hundred-year-old factory employing over five thousand people. It is a captive jute gunny bags manufacturer for the Food Corporation of India. It is closed down about a week ago on 27th January. Andhra Pradesh used to be next to West Bengal in jute production once upon a time. Today, it is almost zero. All this happened because of the price restriction policy of the Jute Corporation and the Food Ministry.

(1735/RK/IND)

While they are price sensitive, it is unfortunate that indirectly they are helping a plastic product from Reliance Industries in place of jute being produced by millions of farmers engaged in the jute industry.

I would like the Government to note that our hon. Prime Minister made an announcement to ban single-use plastic very soon. We are encouraging HDPE, petroleum-based polymer, plastic products. So, I would like the Government to realise that we will have to bring back the jute industry because jute bags are going to be a major source of carrying bulk goods, be it rice, sugar, or other essential commodities. Kindly realise that jute is a product coming out of the efforts of millions of farmers. We are talking of doubling farmers' income, rejuvenating rural economy, and saving environment. Hence, I would like the Government to take a serious note of it and come out in support of the jute industry in Andhra Pradesh, West Bengal, and rest of the country.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति जी, मैं विषय परिवर्तन की अनुमति चाहता हूं।

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Yes.

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान अभी हाल ही में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण राज्यों ने दिया था, उसे समाप्त कर दिया गया है, की ओर दिलाना चाहता हूं। राज्यों ने अपने-अपने राज्य की सामाजिक स्थितियों को देखकर अलग-अलग तरीके से पंचायतों अथवा अन्य स्थानीय निकायों में आरक्षण की व्यवस्थाएं की थीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है, उसके विरुद्ध हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। उसी के कारण राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव रोक दिए गए हैं। मैं भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री जी से मांग करता हूं कि राज्यों को अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व पुन: दिलाने हेतु संसद में कानून बनाए जाने की मांग करता हूं ताकि राज्य सरकारें अपने राज्य की स्थिति के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दे सकें।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): महोदय, आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यह वित्तीय सोसाइटी है और बीस सालों से काम कर रही थी। 18 अक्तूबर से निवेशकों को भुगतान बंद कर दिया गया है। सोसाइटी ने कारण बताया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खाते सीज कर दिए हैं। मेरा आग्रह है कि पूरे देश के लगभग 20 लाख लोगों का इसमें पैसा अटका हुआ है। सोसाइटी निवेशकों के बचत खातों में पैसा डाल रही है, लेकिन निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने एकाउंट सीज किए हुए हैं।

मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है क्योंकि यह मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और यह केंद्र के सोसाइटी मंत्रालय विभाग के तहत आती है, इसलिए सरकार इसे अपने नियंत्रण में लेकर निवेशकों का भुगतान करे और आम जनता को रिलीफ दे।

*SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): Hon Speaker Sir, Vanakkam. In my Kallakurichi parliamentary constituency, the new broad gauge railway line project between Chinnasalem and Kallakurichi for a 16 km stretch was started during the year 2016.

Chinnasalem railway station is situated on the Virudhachalam-Salem rail route. There are several rice mills, sugar mills, sago mill,s and cotton mills in and around this area. Various educational institutions are also situated, as a result of which. Chinnasalem area is the hub of commercial activities. Kallakurichi remains an important town for marketing agricultural produce. Agricultural products are transported from Kallakurichi to different parts of the country. More than 10000 people have gone to several States of the country seeking employment.

The foundation stone for this railway project was laid by the then Union Minister of Railways Shri Suresh Prabhakar Prabhu. As many as 22 small bridges and 2 major bridges are part of this project besides two level crossings, two road over-bridges and one underpass. The estimated cost of the project is Rs. 116.61 Crore. But the work has not been started as permission was not granted by the railway administration.

I urge upon the hon Railway Minister through this august House thatthe work relating to the long pending Chinnasalem-Kallakurichi Railway line project should be expedited. Thank you Sir.

* Original in Tamil

LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri T. N. Prathapan	Shri Dhanush M. Kumar Shri B. Manickam Tagore Dr. DNV Senthilkumar S.
Dr. T. R. Paarivendhar	Shri Dhanush M. Kumar Dr. DNV Senthilkumar S.
Shri S. Venkatesan	Shri Dhanush M. Kumar Dr. DNV Senthilkumar S. Shri B. Manickam Tagore
Shri Gautham Sigamani Pon	Shri Dhanush M. Kumar Dr. DNV Senthilkumar S.
Shri Sridhar Kotagiri	Dr. DNV Senthilkumar S. Shri Dhanush M. Kumar Shri Malook Nagar
Shri Subhash Chandra Baheria	Dr. DNV Senthilkumar S. Shri Gopal Shetty Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Kanakmal Katara	Shri Devaji Patel

Shri Ram Kripal Yadav Shri P. P. Chaudhary	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Ramesh Bidhuri	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Ganesh Singh Shri Uday Pratap Singh
Shri Tejasvi Surya	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Dr. DNV Senthilkumar S. Shri Malook Nagar
Shri Gaurav Gogoi	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Dr. DNV Senthilkumar S. Shri Malook Nagar
Shri Ganesh Singh	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Uday Pratap Singh Shri Malook Nagar
Dr. Sujay Vikhe Patil	Dr. DNV Senthilkumar S.
Shri Naba Kumar Sarania	Shri Malook Nagar

(1740/PS/KDS)

MATTERS UNDER RULE 377 – LAID

1740 hours

HON. CHAIRPERSON (SHRI N. K. PREMACHANDRAN): Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Hon. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table of the House within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

Re: Need to introduce the flight service between Bhopal and Prayagraj via Rewa

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): वर्तमान में Indigo की फ्लाइट भोपाल से प्रयागराज और वापसी प्रयागराज से भोपाल चल रही है जो ATR-72 एयरक्राफ्ट के हिसाब से इतने यात्री इस रुट पर नहीं हो पाते है यदि इसी फ्लाइट को भोपाल से रीवा और रीवा से प्रयागराज कर दिया जाये तो ये ATR-72 एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी के हिसाब से यात्री भी प्राप्त हो जायेंगे जिससे ये यात्री और एयरलाईन दोनों के लिए लाभदायक होगा |

अतः आपके माध्यम से आग्रह है कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी करवाके भोपाल से रीवा और रीवा से प्रयागराज के लिए हवाई यात्रा शुरू करवाने की कृपा करे |

(इति)

Re: Intercity train between Ahmednagar and Pune

डॉ. सुजय विखे पाटील (अहमदनगर): अहमदनगर इतिहास और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और प्रतिदिन हज़ारों की संख्या में यात्री पुणे तक की यात्रा शैक्षणिक,पर्यटन और उद्योग के उद्देश्य से करते है जिसके लिए उन्हें 4 घंटे का समय लगता है। पुणे तक यात्रा करने के लिए अभी बस सेवा और राजमार्ग उपलब्ध है लेकिन traffic के कारण उसमे बहुत समय का नुक्सान होता है।वर्तमान में अहमदनगर से पुणे तक कोई भी Intercity ट्रैन नहीं है। पिछले कई वर्षों से जनता की मांग है कि अहमदनगर से पुणे तक एक Intercity या Shuttle रेलवे सेवा प्रतिदिन शुरू की जाए जिससे मेरे क्षेत्र के लोगो को सुगम तरह से यात्रा करने की सुविधा मिले।मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि रेल मंत्रालय तत्काल इस पर विचार करे और अहमदनगर से पुणे जैसी दो महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने के लिए एक intercity या shuttle रेल सेवा शुरू करे जिससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम होगा और यात्रियों की संख्या ज़्यादा होने से रेलवे को राजस्व भी मिलेगा।मेरी मांग है कि इस intercity ट्रेन का अहमदनगर से प्रस्थान का समय सुबह 6 बजे किया जाए और पुणे से प्रस्थान शाम को 6.30 PM रखा जाए जिससे अधिक मात्रा में यात्री इस रेलवे की सुविधा का लाभ ले सके।

(इति)

Re: Need to provide funds for the Krishna-Bhima stabilisation project in Maharashtra

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर (माधा): महोदय, पश्चिम महाराष्ट्र के लगभग 22 जिले अधिकांशत: सूखाग्रस्त रहते हैं। कृष्णा घाटी में होनी वाली मूसलाधार वर्षा, जिसके कारण आधा कर्णाटक डूब जाता है, का अतिरिक्त पानी यदि पश्चिम महाराष्ट्र के इन सूखा ग्रस्त इलाकों को उपलब्ध करवा दिया जाए तो जहां एक ओर पश्चिम महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्र के लोगों और खेतों की प्यास बुझ पाएगी, वहीं दूसरी ओर कर्णाटक के अधिकांश इलाके हर साल आने वाली भीषण बाढ़ की तबाही से बच जाएंगे। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर जहां पश्चिम महाराष्ट्र को 110 टीएमसी पानी उपलब्ध होगा वहीं दूसरी ओर कर्णाटक में हर साल बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा। इस बांध से महाराष्ट्र के सोलापुर, पंढरपुर, अक्कलकोट, सांगोला, मंगलवेद जैसे छोटे और बड़े शहरों को पीने के पानी की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लगभग 12 साल पहले पहले कृष्णा भीमा स्थिरीकरण परियोजना की परिकल्पना की गई

अत: अनुरोध है महाराष्ट्र सरकार से इस परियोजना की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट पर आगे कार्यवाही करवाने तथा इस परियोजना को नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में शामिल करवाकर इस परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाने का की कृपा करें ताकि इस परियोजना पर शीघ्रातिशीघ्र काम शुरू हो सके।

(इति)

Re: Development of Elephant Reserve in Jangalmahal area

SHRI KUNAR HEMBRAM (JHARGRAM): The herd of elephants are on a rampage in West Bengal's Jhargram, Bankura, Purulia, Paschim Medinipur districts over the past few years. The herd of 44-50 elephants from Dalma forest in nearby Jharkhand are damaging houses, crops and killing residents. All the districts in Jangalmahal area are near the forests of Jharkhand and Odisha; from where herds of elephants come in search of food. In the past few years, there had been many incidents of elephants straying into human habitations in Jangalmahal area. Few years back, herds from Dalma forest in Jharkhand used to invade only farmlands in Jhargram, Purulia and Bankura, but in recent time they are entering the rural villages and even urban locality searching for food. Sometimes wildlife causality and death happens due to electric shock and collision with trains. The herd is at present in the forest area in Jangalmahal. At present, the Jangalmahal belt in West Bengal is the home to over hundred elephants.

Therefore, I request the concerned Ministry to develop elephant reserve in Jangalmahal area or set up elephant corridors in the forest areas of Jangalmahal belt so that any causality of human as well as wildlife may be averted.

(ends)

Re: Need to establish a Tribal University in Gumla district, Jharkhand

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान जनजातीय समाज की समृद्ध संस्कृति और जीवनशैली की ओर आकर्षित करते हुए, निवेदन करना चाहता हूँ कि जनजाति बहुल क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सुदूर ग्रामीण अंचल और वनों में निवास करने वाले जनजातीय क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का प्रचलन और उच्च शिक्षा प्रदान करने सम्बन्धी अवसर प्रदान करने होंगे। विलुप्त होती जा रहीं आदिम जनजातियों सहित सभी जनजातियों की संस्कृति,उनकी जीवन शैली, उनके हस्तशिल्प और समस्त कलाओं, उनकी भाषा और लिपियों पर अनेकों शोध हुए और हो रहे हैं। इसलिए गत अनेकों वर्षों से जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये, ऐसी आवश्यकता महसूस की जा रही है।

आदरणीय महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र लोहरदगा जनजातीय बहुल झारखण्ड राज्य का उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र और आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र हैं और यहाँ की शैक्षिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, मेरे संसदीय क्षेत्र का गुमला जिला दोनों ओर से छत्तीसगढ़ व् उड़ीसा प्रान्तों को झारखण्ड से जोड़ता है। उधर लोहरदगा जिले के निकट उत्तरप्रदेश राज्य के जनजातीय बहुल जिले मिलते हैं। महाराष्ट्र व् दक्षिण के प्रान्तों से रेल मार्गों से यह क्षेत्र जुड़ा हुआ है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के गुमला जिले में "जनजातीय विश्वविद्यालय" की स्थापना की जाये जिससे कि जनजाति समाज के युवाओं को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान हो सकें और जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करने सहायता मिल सके, भारत की अमूल्य धरोहर भारत की जनजातियों पर शोध कर भी सुलभता पूर्वक हो सके। लोकहित में व नजातीय संस्कृति के हित में मेरे आग्रह और प्रार्थना पर सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए, गुमला में "जनजातीय विश्वविद्यालय" की स्थापना करने का महान कार्य अवश्य किया जायेगा। धन्यवाद सहित !

(इति)

Re: Need to conduct test for recruitment in Army in Jhunjhunu district, Rajasthan

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): जिला झुन्झुनू(राजस्थान) सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। जिले ने देश को सबसे ज्यादा सैनिक दिए है। जिले में सेना भर्ती हुआ करती थी जिसमें जिले से बहुत से सैनिक देश को मिलतें थे। दो साल से अधिक का समय हो गया युवा निरतंर सेना भर्ती की तैयारी करते है। युवाओं को सेना भर्ती की प्रतीक्षा करते हुए तथा दो साल से कोरोना महामारी के कारण बहुत से युवा सेना में भर्ती हेतु निर्धारित उम्र से अधिक हो गये है जिससे बहुत से युवा सेना भर्ती से वंचित रह गये है। जिला झुन्झुनू(राजस्थान) में सेना भर्ती करवाई जाए तथा युवाओं को सेना में दो साल की उम्र में छूट हो।

(इति)

Re: Need to make penal provisions in the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 more stringent

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): अध्यक्ष जी, एक महत्वपूर्ण विषय को सदन में रखना चाहता हूँ जोकि पशु के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में दण्डात्मक प्रावधानों को बढ़ाने के संबंध में है। पशुओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का निर्माण संसद द्वारा किया गया था। पशुओं के हितों की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम ने विगत 6 दशकों तक अपने निर्माण के उद्देश्य के अनुरूप कार्य किया परंतु इस अधिनियम में तब से लेकर अब तक कोई भी संशोधन नहीं किया गया है जिसके कारण इसके दंडात्मक प्रावधान पशु हितों की रक्षा करने में अक्षम हो चले हैं तथा पशु क्रूरता रोकने में अपर्याप्त साबित हो रहे हैं।

अतः, महोदय से अधिनियम में इसके सृजन के समय पशु क्रूरता को किसी प्रकार से चोट पहुंचना उनके साथ हिंसा करने, उनको लड़ाई के लिए उकसाना इत्यादि में 50रु. से 100रु. के दण्ड तक वर्तमान समय में लागू है। अतः, महोदय से अनुरोध है कि पशु क्रूरता अधिनियम के दण्डात्मक प्रावधानों को और कठोर बनाने के लिए तथा जुर्माने की धनराशि 50/100 रु. से बढ़ाकर 5000रु. या 8000 रु. करने की कृपा करे।

(इति)

Re: Dissemination of information pertaining to rules/schemes

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): देश के सभी राष्ट्रवासियों का सौभाग्य है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में वर्ष 2014 से लेकर आज तक दर्जनों महत्वपूर्ण अधिनियमों में राष्ट्रहित में बड़े बदलाव किए गए हैं और व्यापक जनहित में नये कानून भी बनाए गए हैं तथा इस संबंध में वे जन-सभाओं एवं "मन की बात" इत्यादि के माध्यम से देश की जनता को समय-समय पर जागरूक भी करते हैं। लेकिन, यह दुःखद है कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के अधिकारी बनाए गए नए अधिनियम और पुराने अधिनियमों में किए गए बदलाव की जानकारी सही तरह से आम जनता तक नहीं पहुंचा पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश के गरीब और ग्रामीण लोग सरकार की नई योजनाओं के लाभ से वंचित रहते हैं।

अतः इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम-कानूनों एवं योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंच सके, इसके लिए शासकीय अधिकारियों के प्रति जिम्मेवारी सुनिश्चित की जाए और ये अधिकारीगण केन्द्र एवं राज्य सरकारों के नियम-कायदों का इस प्रकार से अनुपालन करें कि नागरिकों का अहित न हो। इस संबंध में मेरा यह भी अनुरोध है कि कोई भी सरकारी अधिकारी / कर्मचारी यदि सरकारी नियम-कानूनों की अवहेलना करता है अथवा उनका सुचारू रूप से कार्यान्वयन न करके सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास करता है तो उसके विरूद्ध अविलम्ब दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए उसे सरकारी नौकरी से तुरन्त बर्खास्त किया जाए एवं उन्हें पेंशन इत्यादि से संबंधित सभी सुविधाएं वंचित किए जाने हेतु केन्द्रीय सिविल सेवा नियम (आचरण), 1964 में प्रावधान किए जाएं तथा राज्य सरकारों को भी इससे संबंधित प्रावधान किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

(इति)

Re: Need to sanction establishment of an Outdoor and an Indoor Stadium in Palamu parliamentary constituency, Jharkhand

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पलामू संसदीय क्षेत्र के दोनों जिले यथा पलामू एवं गढ़वा देश के 112 आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आते हैं जहां खेल सुविधाओं का घोर अभाव है। विदित है कि मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू में न तो आउटडोर स्टेडियम है और न ही इंडोर। खेल सामग्रियों का भी घोर अभाव है, जबकि हॉकी एवं तीरंदाजी की खिलाड़ियों का भरमार है। मैं समझता हूं कि यदि इन खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान की गयी तो निश्चित रूप से वे एक दिन राज्य एवं देश का नाम रौशन करेंगे।

अतः आपके माध्यम से माननीय मंत्री युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थिति में मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू (झारखंड) के लिए एक आउटडोर स्टेडियम और एक इंडोर स्टेडियम स्वीकृत करने की कृपा की जाय।

(इति)

Re: Need to declare Bundelkhand as a Natural Farm region

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): बुंदेलखंड की सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा कृषि के तरीकों और गौधन की उपलब्धता को देखते हुए मेरे द्वारा पूर्व में भी बुंदेलखंड को प्राकृतिक कृषि क्षेत्र घोषित करने की मांग की जाती रही है | अभी हाल में सरकार द्वारा जीरो बजट आधारित प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किया गया और कृषि क्षेत्र में सहकारिता के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं |

महोदय बुंदेलखंड में वर्षों से पारंपरिक तरीके से ही कृषि की जा रही है और यहाँ पर देसी गौवंश भी बहुतायत में है। उर्वरकों का कम प्रयोग और देसी गौवंश के उत्पादों का प्रयोग जो कुछ समय पहले पिछडेपन का संकेत था आज वही बुंदेलखंड की अपूर्व विकास संभावनों का संकेतक है | जरुरत है केवल पुनरावलोकन की | केंद्र सरकार द्वारा कृषि और किसानों के विकास के लिए किए जा प्रयासों की साक्षात प्रयोगस्थली बुन्देलखण्ड है और यहाँ पर किए प्रयास पूरे भारत के लिए माडल सिद्ध हो सकते है |

अत: आपके माद्यम से मै सरकार से मांग करता हूँ कि बुंदेलखंड में खेती और गौवंश के समुचित संरक्षण के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र को प्राकृतिक कृषि क्षेत्र घोषित किया जाए |

(इति)

Re: Need to lay a broad-gauge railway line between Rajpipla and Kevadiya in Gujarat

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): गुजरात में बड़ोदरा से केवड़िया तक ब्राडगेज लाइन बन जाने से देश के अन्य भागों से ट्रेनों का आवागमन होता रहता है परंतु मुंबई और साउथ गुजरात के पर्यटकों के लिए यह रेल रूट सुविधाजनक नहीं है। इस रेल परिचालन में ज्यादा समय लगता है। अतः मुंबई और दक्षिण गुजरात के लोगों की स्टेच्यू आफ यूनिटी, केवड़िया तक की यात्रा को सुगम और सरल बनाया जाना आज की अतीव आवश्यकता है। वेस्टर्न रेलव द्वारा कुछ वर्ष पहले अंकलेश्वर-राजपीपला रेल लाइन को 800 करोड़ रूपये के खर्च से ब्राडगेज में परिवर्तित किया गया था। वर्तमान में अगर उपरोक्त अंकलेश्वर-राजपीपला ब्राडगेज रेल लाइन को मुंबई से वापी, सूरत, नवसारी तथा वलसाड आदि स्टेशनों से जोड़ते हुए राजपीपला से सिर्फ 15 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाकर स्टेच्यू आफ यूनिटी, केवड़िया से जोड़ दिया जाए तत्पश्चात् मुंबई से केवड़िया तक एक फास्ट ट्रेन का परिचालन शुरू करके मुंबई और दक्षिण गुजरात के लोगों को यात्रा हेतु एक बड़ी राहत दी जा सकती है। इसके साथ ही देश विदेश से स्टेच्यू आफ यूनिटी तक पहुंचने में बहुत सुविधा हो जाएगी तथा इस आवागमन से रेलवे के राजस्व में भी भारी वृद्धि। होगी। इस संबंध में सरकार से मेरा आग्रह है कि राजपीपला से केवड़िया तक तत्काल ब्राडगेज रेल लाइन बिछाए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश पारित किए जाएं।

(इति)

Re: Need to provide better internet services by telecom operators in rural areas particularly in Seoni and Balaghat districts in Madhya Pradesh

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): वर्तमान में भारत देश डिजिटल इंडिया के अवधारणा पर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल, आईडिया, जीयो आदि कंपनियों के मोबाईल टावर लगे है जिनमें कवरेज की काफी समस्या है। विशेषकर बी.एस.एन.एल की स्थिति बहुत खराब है। आये दिन मोबाईल टावर काम करना बंद कर देते है। संसदीय क्षेत्र बालाघाट के सिवनी-बालाघाट जिलें में ग्रामों एवं सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क की बहुत समस्या है। सिवनी जिले के पिपरिया, पनवास, सरेखा आदि ग्राम, कुरई तहसील एवं बालाघाट के बैहर, बिरसा तहसील के अनेक गांवों जिनके 3 कि.मी. के दायरे मे भी मोबाईल टावर लगने के बावजूद कवरेज और डाटा गति की अत्यधिक समस्या है। डाटा गति कम रहने से बैंक के काम, छात्रों की पढ़ाई, नौकरीपेशा व्यक्तियों, पंचायतों कार्य, सोसाईटियों में राशन वितरण इत्यादि कार्य जो डिजिटल हो चुके है, प्रभावित होते है जो कि भारत सरकार की डिजिटल इंडिया की अवधारणा को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाईल नेटवर्क एवं पर्याप्त डाटा गति उपलब्ध कराने के मोबाईल कंपनियों को निर्देशित कराने का कष्ट करें।

(इति)

Re: Construction of a new bypass in Attingal on NH-66 in Kerala

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): I would like to draw the attention of the house towards an important matter related to the construction of a new bypass in Attingal on NH-66 in Kerala. The Thiruvarattukavu temple is located on the alignment area of the proposed Attingal bypass in Thiruvananthapuram district. The alignment was done without making any damage to the main temple building but Thiruvarattukavu Temple portion of building at south west corner is getting affected and the seeveli patha (walkway inside temple compound) is also affected. In order to keep the structures of temple safe by keeping the alignment unchanged it's suggested to construct a flyover at this location. The flyover may be constructed for a length of about 500 mts so that the service road on both sides could be accommodated under the flyover. Hence, the structure of Thiruvarattukavu temple will not be disturbed and will also provide more comfortable traffic movement. I request the Government to convene a meeting of all the concerned to discuss the matter and look into the execution of this long pending project at the earliest.

(ends)

Re: Measures to protect small & marginal farmers

SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): Due to vagaries of weather, poor harvest can bring havoc and financial disaster to the small and marginal farmers. The prevailing economic condition has resulted in farmers selling their products at lower prices due to collapse in demand in the wholesale markets.

An amicable solution is needed for the distressed farmers who are affected by bad weather, pest attacks and other crop damages, to come out of their vicious cycle of debts.

Hence, I request the Government to take the following measures:

(a) Introduce a "Samadhan" scheme where the total interest amount, penalty charges etc., and 50% of the principal amount of agriculture debts be waived, so that the bad debts of distressed farmers could be settled.

(b) The said "Samadhan" scheme be made available for agricultural loans, agricultural development loans (for purchasing tractors, boring wells etc.) and crop loans to be availed from all banks either nationalized or private sector banks.

(ends)

Re Establishment of a Bamboo cluster at Payakaraopeta, Andhra Pradesh

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Sir, the usage of bamboo has been a tradition in India since time immemorial. Bamboo can be used as a sustainable resource for generating new jobs. Adopting new technology, skill development, and marketing strategy can evolve the bamboo industry and create new jobs. Moreover, India is moving towards increasing the export of Bamboo products. To promote our honourable Prime Minister's mission of "Vocal for Local", the artisans should be trained to create modern articles with bamboo. The government by establishing new bamboo clusters in the country could help the bamboo artisans in evolving with the changing trends in the market.

However, in Andhra Pradesh, the bamboo utility products made in Payakaraopeta town are very famous. The union government should set up a bamboo cluster at Payakaraopeta. The bamboo cluster could impart training and broaden the manufacturing ambit of bamboo products such as Bamboo curtains, Bamboo jewelry, Bamboo bags, Bamboo mural products, and other products.Hence, I request the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare to establish a Bamboo cluster in Payakaraopeta of Andhra Pradesh under the National Bamboo Mission for the benefit of Bamboo artisans in Andhra Pradesh.

(ends)

Re: Damage caused by river Bhagirathi in West Bengal

SHRI SUNIL KUMAR MONDAL (BARDHAMAN PURBA): Respected Hon'ble Speaker I want to draw the kind attention of the Minister of Jal Shakti through you towards dredging of the river Ganga, blocking of the bank with the help of concrete, stones, boulders and nets by the side of the river Bhagirathi to protect the villages getting eroded due to river water under my parliamentary constituency in West Bengal, specially Agradweep Gram and Charbishnupur Gram area people residing by the side of the river are very badly affected and are facing very dangerous natural disaster and above 2000 habitants need to be relocated to Kalikapur Mouja falling under the same constituency and also residents of Katwa, Uddharanpur to Hooghly Triveni and Farakka to Dakhineswar under Katwa to Kalna spreading over about 100 km. several villages are at risk and almost 2 square kilometer area has been eroded by river water of Bhagirathi and several people have moved and are still moving to another place to save themselves. The people of the area are very poor and 80% to 90% of the people belong to SC, ST & OBC community and others are not able to rebuild their houses particularly those people who works on daily basis like farmers and labourers are in very miserable condition.

Further, I say that the river water is gradually capturing and wiping out villages situated beside the river Bhagirathi. The habitants have no option of leaving their houses and fertile agricultural land which is their only source of income to survive. Beautiful houses, primary school buildings, temples, play grounds, Anganwadi centres etc. have been eroded by the water of river Bhagirathi. More than two thousand people are in dire need of rehabilitation. I suggest you to take immediate step in this regard to block the river side with the help of concrete, stones boulders, net etc. so that thousands of lives could be saved.

I, therefore, request the Hon'ble Minister to control the damage and take necessary steps to lessen the natural destruction.

(ends)

Re: Need to set up Textile Park in Ichalkaranji in Hatkanangle parliamentary constituency, Maharashtra under PM Mega Integrated Textile Region and Apparel (PM MITRA) parks scheme

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले): Textile सेक्टर रोज़गार देने वाला क्षेत्र है और हमारी अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है. सम्मानीय वित्त मंत्री जी ने अपने 2021 के बजट भाषण में Mega Investment Textiles Parks (MITRA) की घोषणा की है. मैं हातकणंगले लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ और मेरे क्षेत्र के अंतर्गत इचलकरंजी शहर स्थित है जिसे महाराष्ट्र का Manchester कहा जाता है और यहाँ पर सबसे प्रमुख कपड़े का उद्योग है जिसमे 1 लाख से अधिक संख्या में कामगार है. इचलकरंजी में 1 लाख plain powerloom , 25000 shuttleless powerloom, 100 processing unit और 225 sizing unit है जहा पर प्रतिदिन 1.5 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता है और इसके बाद इसको देश के विभिन्न राज्य मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका और पंजाब और देश के बाकी राज्यों को निर्यात किया जाता है। अभी GST और कोरोना महामारी के कारण इचलकरंजी के कपड़ा उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और कई कारखानों को बंद भी करना पड़ा जिससे बहुत सारे कामगार बेरोज़गार भी हुए है.

मेरा सरकार से निवेदन है कि 2021 के बजट में जो MITRA योजना की घोषणा हुई है जिसमें अगले 3 वर्षों में 7 textile parks की स्थापना की बात कही गयी है इसमें इचलकरंजी को शामिल किया जाए और वहाँ textile park की स्थापना के लिए तत्काल सरकार कदम उठाये जिससे इचलकरंजी के टेक्स्टाईल उद्योग को गति मिलेगी एवं विकास होगा और रोज़गार के अवसरो का निर्माण होगा जिससे मेरे लोकसभा क्षेत्र का विकास हो और यहाँ काम करने वाले कामगारों को आर्थिक सहायता प्राप्त हो।

धन्यवाद

(इति)

Re: Ban on wearing Hijab in educational institutions

DR. M.P. ABDUSSAMAD SAMADANI: Ban on the personal freedom for wearing Hijab. The objection raised against Hijab-wearing girls' dress by denying education to them in this pretext is highly condemnable. This move is against the principles of personal liberty and secularism enshrined in the constitution. It poses challenge to the norms of pluralism respected by all nations. It helps only to tarnish the image of our country.

It is very unfortunate that ban on wearing Hijab was started imposing by a government college. Then some other institutions followed. Now the disruptive forces are utilising the occasion for communal purposes and they are preventing Hijab wearing students from entering to their institutions disturbing the law and order situation.

It is well-known that wearing of Hijab belongs to the essential religious practices of girls who wear it. It is being practiced all over the world. Our constitution not only permits but ensures such rights of various sections of society including the minorities. Wearing dress in accordance with the faith is a constitutional right. And variations in the habits of food and dress actually represent our unity in diversity.

I, therefore, request the government to intervene in this matter for ensuring the constitutional rights of students and to check the tendencies of violating them.

(ends)

Re: Setting up of a committee to study the conditions of Christian minority in the country

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Scheduled Castes and Scheduled Tribes who convert to Christianity cannot avail any benefits of reservation. While those SCs/STs who convert to Sikhism and Buddhism continue to enjoy benefits of reservations even after their conversion to the new religion. This policy is discriminatory in nature as it treats converts of different religions differently. The Sachar Committee created by the government in 2005 which submitted its report in 2006, was formed to study the social, economic and educational condition of Muslims in India. The government should establish a new committee to study the conditions of Christian minority in the country. It should seek in its findings, the socio-economic and educational status of the community.

If the committee is established and its recommendations implemented, it would lead to upliftment of the threatened Christian minority community in the country. With the increase in threats to the minorities and desecration of churches across the nation, it is high time that the government wakes up to take an action in favour of its own citizens.

I urge the upon the government that the proposal should be considered.

(ends)

Re: Infrastructural issues pertaining to some Post Offices in Mavelikkara parliamentary constituency

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I am inviting the attention of the ministry of communications towards the most urgent matters pertaining to four post offices, 1) Vazhappalli, 2) Edathua,3) Mannar, 4) Kunnikode, located in my Lok Sabha constituency, Mavelikkara, Kerala under Kerala Postal Circle. These four post offices immediately require renovation and reconstruction and modernization as they have become dilapidated due to ageing and are affected by incessant rains and lack of repair works necessitating new buildings.

The buildings in which these post offices are located are dilapidated, old and lack basic infrastructure and are in urgent need of modernization to meet the demands. Despite repeated communication, the process for modernization and construction of new buildings for these posts offices has not commenced along with non-sanction of funds in the current financial year. Therefore, I request the government for urgently sanctioning funds for constructing new post office buildings and remove any hindrance or delay in approving proposals sent to appropriate authorities in Kerala postal circle so that construction work could commence immediately.

(ends)

Re: Need to develop Dardha River front in Jehanabad city, Bihar

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): जहानाबाद शहर में हॉस्पीटल मोड़ के पास दरधा नदी पुल के पास उत्तरी किनारे से श्यामनगर के पुल तक रिवर फ्रंट के निर्माण की अविलंब आवश्यकता है।

रिवर फ्रंट की परियोजना पूरी होने से शहर के विकास को बल मिलेगा तथा वहां के लोगों को इससे आवागमन में भी भारी सहुलियत मिलेगी। नए प्रोजेक्ट के जमीन पर उतरने से शहर के विकास को जहां बल मिलेगा वहीं इससे नदी किनारे लगातार हो रहे अतिक्रमण पर भी लगाम लगाने में प्रशासन को मदद मिलेगी।

यह शहर के विकास में मील का एक बड़ा पत्थर साबित होगा। इससे शहर की खूबसूरती में भी चार चांद लग जाएंगे एवं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मैं आवासीय एवं शहरी विकास मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि अपने मंत्रालय के अंतर्गत चल रही किसी भी स्कीम (जैसे- अमरुत या अन्य) के माध्यम से जहानाबाद शहर को यह अद्भुत सौगात दें और इस प्रोजेक्ट को पूरा करवाएं।

इसमें अगर बिहार सरकार से कोई सहयोग लिया जाना जरूरी है तो वह भी करवाना सुनिश्चित करें।

(इति)

Re: Construction of an under pass or level bridge at Shyampur in the Sealdah Diamond Harbour line

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I would like to take this opportunity to express the pain of the people of Shyampur which falls under my parliamentary constituency area. The said region is in urgent need of either a level crossing or an underpass road. This is so because the only mode of crossing the railway line is literally by foot. This is a major cause of concern for people of all age groups more specifically children, pregnant women and senior citizens. Due to the absence of a proper means of crossing the railway line, numerous accidents have taken place. They have resulted in severe outcomes and unfortunately death in some cases. Thus, I would sincerely request the Minister through you to build an underpass or level bridge at Shyampur which is located between Dhamna and Uttar Radhanagar Railway Station at Sealdah Diamond Harbour line. The post number of the same being 331/9 and pillar number being 351/7.

(ends)

Re: Establishment of a DD Nepali/Gorkha Bhasa channel

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): There are over 1.5 crore Indian citizens of Gorkha ethnicity whose mother tongue is Nepali. Our constitution under the 8th Schedule recognizes Gorkha Bhasa as one of the national languages of India. However, efforts towards the conservation and propagation of this glorious language is seriously lacking. While every major language recognized under the 8th Schedule has a dedicated Doordarshan Channel broadcasting programmes in their respective languages, the Nepali/Gorkha language has continued to be relegated to the side-lines. Till date we don't have a dedicated TV Channel broadcasting contents in Nepali/Gorka Bhasa.

In the absence of a National Platform, the Gorkha culture, diversity, society and language has suffered immense cultural loss. In Darjeeling, Kurseong, and Kalimpong, the infrastructure, artists and audience are already in place. All we need is the Prasar Bharati to initiate the efforts.

I, therefore, request the Government to kindly expedite the establishment of a DD Nepali/Gorkha Bhasa Channel.

(ends)

Re: Redressal of grievances of people pertaining to electricity in NCT of Delhi

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान विशेषतः माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान दिल्ली की गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आदरणीय महोदय, दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी है। वहां मेरे संसदीय क्षेत्र साउथ दिल्ली में प्रतिदिन 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती होती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी व तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल जी के प्रयासों से शूटिंग रेंज रोड पर 3100 करोड़ की लागत से 400/220 केवी के बिजलीघर के निर्माण से समस्या का समाधान हुआ है। परंतु बिजली के संबंध में दो समस्याएं और हैं।

दिल्ली में वर्ष 2010 में 40.47 लाख उपभोक्ता थे जो बढ़कर अब 61.68 लाख हो गए हैं। बीएसईएस यमुनापावर लि0 में काफी अनियमितताएं हैं। मेरे क्षेत्र में महरौली विधानसभा में स्थित किशनगढ़, मसूदपुर डेरी, जेजे बंधु कैंप, जय हिंद, रजोकरी, बीईएसई कैंप तथा छतरपुर विधानसभा में स्थित मांडी गांव, छतरपुर एक्सटेंशन छतरपुर एनक्लेव, राजपुर खुर्द, राजपुर कॉलोनी में नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं और कारण बताया जाता है कि लोड ज्यादा है और ट्रांसफार्मर फुक जाएगा। इसके साथ-साथ ओखला में बिजली चोरी होती है और जब रेड पड़ती है तो बिजली खपत के बिलों की 70 से 90 प्रतिशत पेनल्टी माफ की जाती हैं जबकि इन्हीं परिस्थितियों में संगम विहार, देवली, अंबेडकर नगर में मात्र 30 से 40 प्रतिशत की छूट मिलती है। यह भेदभाव क्यों ? पुराने ट्रांसफार्मर भी नहीं बदले गए हैं क्योंकि दिल्ली सरकार का ऊर्जा क्षेत्र में कुल प्लान एक्सपेंडिचर बहुत घटा है। वर्ष 2011 में यह कुल प्लान एक्सपेंडिचर का 13.44 प्रतिशत थी जो अब वर्ष 2020-21 में मात्र 0.31 प्रतिशत रह गई। मेरा आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से यह अनुरोध है कि इस विषय में संज्ञान लें एवं दिल्ली के एल0जी0 के माध्यम से कुछ समाधान निकालने का प्रयास करें।

(इति)

Re: Grant of Environmental clearance to the Rayalaseema Lift irrigation Project

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Sir, I would like to draw your kind attention towards the fact that the Government of Andhra Pradesh requires urgent Environmental Clearance for the Rayalaseema Lift Irrigation Project. During June 2020, the Andhra Pradesh Government announced the Rayalaseema Lift Scheme to facilitate the Rayalaseema region to stabilize irrigation and drinking water. The announced scheme is within the purview of KWDT Award (Krishna Water Dispute Tribunal), i.e. out of total 811 TMC water, 512 TMC for Andhra Pradesh and 299 TMC for Telangana.

• In July 2020, after study, the expert committee has given its opinion that the scheme does not require environmental clearance.

• During September 2020 also, NGT pronounced that the EC is required for the scheme. After that, the Hon'ble CM of Andhra Pradesh requested Hon'ble Minister, MOEF to consider expert committee opinion. During June 2021, the AP Government approached MOEF for amendment in the existing environmental clearance. Based on this application, EAC (Environmental Assessment Committee) in its June 2021 meeting discussed the topic and issued minutes asking some clarifications. AP Government submitted clarifications on this. In this regard, Sir, kindly grant environmental clearance to the Rayalseema Lift Irrigation project.

(ends)

Re: Need to transfer 'Asthi Kalash' of Lord Buddha from National Museum of India, Delhi to National Museum, Kapilvastu in Siddharthnagar district, Uttar Pradesh and also set up a Meditation centre at Kapilvastu for Buddhist pilgrims

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर जहाँ बौद्ध धर्म के मानने वाले लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष कपिलवस्तु आने में अपना सौभाग्य मानते हैं | कपिलवस्तु में पर्यटक आने के बाद वहाँ के इतिहास को जानने की जिज्ञासा रखते हैं| इसी क्रम में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना पिपरहवा कपिलवस्तु में की हैं | उसके अंतर्गत कपिलवस्तु में Department of Archaeology एवं कोलकाता विश्वविध्यालय के समस्त खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को उक्त संग्रहालय में रखा गया है| लेकिन यहाँ से खुदाई में प्राप्त दो अस्थिकलश वर्तमान समय में राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखे हुए हैं, जबकि गौतम बुद्ध ने जीवन के प्रारम्भिक 29 वर्ष कपिलवस्तु में ही व्यतीत किये थे | इसलिए बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए कपिलवस्तु अत्यंत महत्वपूर्ण है | यदि एक अस्थिकलश वहाँ से राष्ट्रीय संग्रहालय पिपरहवा, कपिलवस्तु में स्थिति कर दी जाय तो बौध धर्म को मानने वाले लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष सारनाथ, कपिलवस्तु, कुशीनगर एवं श्रावस्ती के साथ साथ अस्थिकलश के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे जिससे देश एवं प्रदेश को काफी विदेशी मुद्रा से राजस्व में वृधि होगी | तथा ध्यान लगाना बुद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसलिए बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए संग्रहालय के पास एक ध्यान केंद्र होना भी आवश्यक है|

अतः मैं सरकार से मांग करता हूँ की भगवान बुद्ध का एक अस्थिकलश राष्ट्रीय संग्रहालय कपिलवस्तु में उपलब्ध करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग को निर्देशित करें और बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए एक ध्यान केंद्र की स्थापना करवाने की कृप्या करें |

(इति)

HON. CHAIRPERSON: Now, let us resume the discussion on the General Budget. Today, the first speaker is Dr. Farooq Abdullah Ji.

GENERAL BUDGET – GENERAL DISCUSSION – Contd.

1741 hours

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): Mr. Chairperson, thank you for giving me this privilege to speak on the General Budget. I would like to put some points before the House.

The present situation in the country is that there is huge unemployment. सबसे बड़ा और बहुत जबरदस्त जो मुद्दा है, वह हम सभी के लिए और मेरी रियासत के लिए बहुत मुश्किल मुद्दा है कि हमारे पढ़े-लिखे बच्चे-बच्चियों के पास कोई नौकरी नहीं है। बड़ी-बड़ी तालीमें भी उन्होंने पाई हुई हैं, लेकिन वे बिल्कुल बेकार बैठे हैं and they are under great depression.

दूसरी ओर आप देखें कि कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे कुकिंग गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो। मुझे इस बात का डर है कि जल्दी ही एक बैरल की कीमत 100 डॉलर हो जाएगी और जब ये इलेक्शन्स खत्म हो जाएंगे, तब फिर से इनकी कीमतें बढ़ती जाएंगी। इसका असर हर कमोडिटी पर पड़ता है। हमारी जो पहाड़ी रियासतें हैं, जहां पर सारा माल गाड़ी से जाता है, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और लोग बहुत मुश्किल से वे चीजें ले पाते हैं। यह हालत बन गई है। मैं हुकूमत से यह गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके इन पर जो टैक्सेस हैं, उनको कम किया जाए और गरीबी को बढ़ने से रोका जाए। जो गरीब है, वह मिट रहा है और अमीर, बहुत अमीर हो रहा है।

सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं है कि कोविड ने न केवल हिन्दुस्तान को, बल्कि सारी दुनिया को प्रभावित किया है और उसका काफी असर हम सभी पर पड़ा है। बहुत बड़े मुश्किलात आ गए हैं। अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, it has increased by only Rs. 1.7 lakh crore from Rs. 37.7 lakh crore in 2021-22 to Rs. 39.45 lakh crore in 2022-23. This rise is even lower than the inflation rate.

Likewise, under the MGNREGA, Rs. 73,000 crore has been allocated. MGNREGA is the lifeline of our people and due to MGNREGA, poor people are able to feed themselves. The allocation of Rs. 73,000 crore is lower than the revised estimates of Rs. 98,000 crore for 2021-22 and the actual expenditure of Rs. 1,11,170 crore in 2020-21.

Now, I would like to talk about the progress on the works undertaken by the Government of India -- be it roads, tunnels or power projects. उसमें हालत यह है कि उनके जो सारे इम्प्लॉइज हैं, उनमें लोवर से लोवर इम्प्लॉइ भी ये बाहर की रियासतों से ला रहे हैं। आज हालत यह है कि किश्तवाड़ में, जहां पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, वहां चार हफ्तों से लेडी चेयरमैन, डीडीसी और लोग बाहर बर्फ और बारिश में इस सोच में बैठे हुए हैं कि लोकल लोग कहां जाएंगे?

(1745/CS/SMN)

इनका क्या होगा? मेरे वक्त में भी जब पावर प्रोजेक्ट्स थे, उनमें लोकल एम्प्लॉयमेंट थी। अगर आज उन इलाकों की हालत देखें तो उन प्राजेक्ट्स की वजह से वे गरीबी से ऊपर हो गए हैं। इसकी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तवज्जो देनी पड़ेगी कि उसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट जरूर होनी चाहिए।

Farmers are the backbone of our nation. I am very grateful to the Government कि इन्होंने वे तीन लॉ रिपील किए। हालाँकि 700 से ज्यादा लोग मारे गए, मगर रिपील किया, बहुत अच्छी बात है। मैं आगे भी इनसे गुजारिश करूँगा कि जब भी ये कोई लॉ बनाएं और अगर ओपोजिशन इनसे कहती है कि साहब इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, इसे देखिए तो उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। हम लोग कोई आपके दुश्मन नहीं हैं। हम आपको बेहतरीन एडवाइज देंगे, जिससे कि आपकी हुकूमत भी चल सकेगी और मुल्क भी तरक्की कर सकेगा।

सर, जम्मू-कश्मीर की जो इकोनॉमी है, very much dependent on two sectors. One is tourism and the other is horticulture.

सर, हमारे एप्पल ग्रोअर्स की यह हालत है, न सिर्फ हमारे, बल्कि हिमाचल प्रदेश का भी जो एप्पल ग्रोअर है, वह आज रो रहा है, क्योंकि ये लोग बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। ईरान से इम्पोर्ट कर रहे हैं और उनका एप्पल यहाँ बेच रहे हैं, जिसे यहाँ लाने पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। हमारे लोगों के एप्पल कोल्ड स्टोरेज और बाकी जगहों पर सर्दी में सड़ रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा धक्का हमारे इन लोगों को है।

सर, टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी बैकबोन है। उसमें होटेलियर्स भी हैं, उसमें घोड़े वाले भी हैं, उसमें टैक्सी वाले भी हैं, उसमें शिकारे वाले भी हैं, उसमें हाउस बोट वाले भी हैं, हर तरफ से, हर कोई इंसान इस टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व्ड है और लाखों की संख्या में इन्वॉल्व्ड है। मैं गवर्नमेंट से यह गुजारिश करूँगा कि कई सालों से हम यह गुजारिश कर रह हैं कि साहब, टूरिज्म को इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए ताकि हमारे लोग इसका बेनीफिट उठा सकें। मैं गुजारिश करूँगा कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए। मैं गवर्नमेंट से यह गुजारिश करूँगा कि वर्ष 2019 में, they conducted recruitment tests for the border battalions. People went through all the tests. आज देखिए हाल क्या है, वे आज इंतजार कर रहे थे कि अब नौकरी लग जाएगी। वे सब लिस्ट इन्होंने खत्म कर दी और एक नई लिस्ट लाएंगे, जिसमें ये चाहेंगे कि बाहर की रियासतों के लोगों को लिया जाए। यह हमारे साथ नाइंसाफी है और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इन लोगों को ऐसा धक्का न दिया जाए कि हमारे लिए और मुश्किलें खड़ी हो जाएं।

साहब, एक और चीज है, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पर बहुत सोचना पड़ेगा, गोल्ड कार्ड आया, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली। गोल्ड कार्ड आया कि गरीब लोगों को इससे फायदा मिलेगा, मगर आज हालत यह है कि गोल्ड कार्ड होकर भी जब वह अस्पताल जाता है, the gold card is not honoured.

Only, yesterday, a patient rang me. He had to undergo an operation for piles. He was a poor man. He had the gold card but the hospital refused to take him in Srinagar. So, I would be grateful if the Government could look into this thing.

Two sectors are vital for the growth of India. One is education and the other is health. I would request that much funding should be done for this also. Otherwise, we will remain backward and we will not be able to compete with the world of tomorrow. This is vital.

Finally, I would request you to please increase the funding. आज भी आप देखें, we have a national highway, the only highway connecting us to the rest of the country. उसका हाल यह है कि आप उसके पुराने में आइए, रामबन से बनिहाल, थोड़ी सी बारिश हो जाती है, बर्फ पड़ जाती है, वह सारी सड़क बैठ जाती है। यह लाइफ लाइन है, इसकी तरफ ध्यान देने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि please increase the funding for roads and tunnel. We need these very badly. This will make people's connection easier and the State will improve.

I am very grateful Sir for your time and to the people who have listened to me. Thank you.

(ends)

(1750/KN/SNB)

1750 बजे

श्री दिलीप घोष (मेदिनीपुर): सभापति महोदय, हम लोग पिछले तीन दिन से बजट पर चर्चा कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे सुझाव आए हैं, समर्थन और विरोध भी हुआ है। लेकिन इस अमृतकाल में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो अमृत हम लोगों को दिया है, उसके लिए मैं उनको और माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं।

पहले बजट आता था तो हम लोग बचपन में देखते थे और दूसरे दिन हम लोग पेपर में पढ़ते थे कि बजट क्या है? सिगरेट में कितना कर कम हो गया है, कॉस्मेटिक में कितना कर बढ़ा है, गैस के दाम कितने कम हुए हैं, गाड़ियों की कीमत कितनी कम हुई है और ऊपर-नीचे एक ऐरो देकर दिखाया जाता था कि कितना कम या ज्यादा हुआ है? फिर दूसरे दिन रेल बजट आता था। उसमें एक मुख्य बात होती थी कि लोग तुरंत पेपर देखते थे कि किस प्रदेश को कितनी नई ट्रेन मिली है? नई ट्रेन की ही राजनीति होती थी और यहीं तक बजट सीमित होता था। लेकिन इस बार का जो बजट आया है, उससे लोगों को लगा कि इसमें कोई चमक तो नहीं है, उनको देखने में लगा कि बहुत बड़ा कोई धमाका हो गया है। लोग देख रहे थे कि बहुत बड़ी घोषणा होगी। लेकिन पिछले दो साल में जिस बीमारी ने विश्व को ग्रसित किया है, उससे देश और समाज को निकालने के लिए, जिस प्रकार तैयारी होनी चाहिए, माननीय वित्त मंत्री जी ने उसका प्रयास किया है। अर्थ नीति को पटरी पर लाना, दुनिया के सामने चुनौती को स्वीकार करते हुए कम्पीटिशन में आगे बढ़ना, लोगों को एक बार फिर काम में लगाना और गति लाना, इसे देखते हुए बजट की प्रस्तुति हुई है।

हम लोग पहले बजट के लिए एक साल, दो साल, तीन साल और पाँच साल के लिए सोचते थे। यह बजट अगले 25 साल में हम देश को कहां ले जाएंगे, यह उसका एक रोडमैप है। इसलिए बहुत दूर की सोच कर बजट बनाया गया है। इसलिए लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि बजट क्या है?

यह बजट समावेशी है और महामारी से निकाल कर अर्थ नीति को पटरी पर लाना तथा साथ ही साथ गति देना है। ये दोनों काम इसमें हुए हैं और मुझे लगता है कि आगे भी होंगे। एक पूरी हताशा मिट जाएगी और फिर धीरे-धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी। हमारे विपक्ष के मित्र काफी चर्चा कर रहे थे और अलग-अलग आंकड़े दे रहे थे। यह स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि जैसे कि लोग बीमार होने के बाद लोगों का मुंह का स्वाद चला जाता है, पिछले दो साल की जो बीमारी है, उसके कारण समाज का और लोगों का वही हाल हुआ है। चाहे अच्छी चीज दीजिए या बुरी चीज दीजिए, लोगों को मुंह में टेस्ट लगता ही नहीं है। सब खराब ही लगता है। यह सब सही होने में थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए इंतजार भी करना पड़ेगा। महोदय, 25 हजार किलोमीटर हाइवे बनेगा। जल, सड़क, विमान, रेल, परिवहन के साथ ही सात क्षेत्रों में गति आएगी। 2000 किलोमीटर रेल लाइन को आधुनिक टेक्नोलॉजी से एक्सीडेंट रहित बनाने के लिए नई प्रयुक्ति और देशी तकनीक से उसका उन्नयन होगा। अभी-अभी जलपाईगुड़ी में बहुत बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। उसमें बहुत लोगों की जानें गईं, लाखों का नुकसान भी हुआ।

इससे बचने के लिए जो नई देशी टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका भी प्रयोग शुरू हो जाएगा। इस प्रकार जिन बड़ी-बड़ी चीजों की घोषणाएं हुई हैं, उसका आगे लाभ मिलेगा। माननीय अटल जी ने देश को सड़कों द्वारा जोड़ा था। 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' पूरे देश को जोड़ने के लिए पूरा प्रयास किया। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी उसी में 'प्रधान मंत्री गति शक्ति' के द्वारा देश की अर्थ नीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

हमने भारतमाला और सागरमाला का नाम सुना था। उसी का लाभ देश को मिल रहा है। इस बार पर्वतमाला एक नई योजना आई है, अभी माननीय फारुख अब्दुल्ला जी बोल रहे थे, जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर बंगाल के दार्जिलिंग तक ऐसे सैकड़ों गाँव हैं, जो दूर-दूर पहाड़ों में बसे हुए हैं और लोगों को शहर या बाजार से आने के लिए घंटों चलकर जाना पड़ता है। उससे लोगों को निजात मिलेगी। जो पर्वतमाला योजना है, उसके अंतर्गत आधुनिक तकनीक से लोगों को जोड़ने और आने-जाने में लाभ मिलेगा। 75 साल के बाद लोगों को विकास की सुविधा मिलेगी। जो नई योजना आई है, इसमें थोड़ा समय लगेगा।

मैं पश्चिम बंगाल से आता हूं, वहां सरकार है। वहां सरकार का एक ही काम है, बंगाल में एक ही समस्या है कि गवर्नर हटाओ। लगता है कि गवर्नर हट जाएगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

(1755/GG/RU)

पिछले चार-पांच दिन पहले माननीय गडकरी जी ने एक घोषणा की थी। बंगाल के साथ जुड़े हुए और बंगाल के हाईवे के लिए उन्होंने लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये की घोषणा की। अगले दो-तीन सालों में यह योजना फलदायी होगी। लेकिन हाईवे के लिए जो जमीन चाहिए, वह राज्य सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। खाली हाईवे के लिए ही नहीं है, यही स्थिति बागडोगरा एयरपोर्ट सिलीगुड़ी में है, उसके लिए 600 करोड़ रुपये सरकार के पास पड़े हुए हैं। केंद्र ने वह पैसा दिया है, अभी तक उसके लिए जमीन नहीं मिल रही है, इसलिए उसका एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। उसको अपनी कैपेसिटी से चार गुना बोझ उठाना पड़ रहा है और वहां से नयी-नयी विमान सेवा जो शुरू होने वाली है, वह भी संभव नहीं हो रही है, क्योंकि जगह की कमी है। वह एयरपोर्ट डिफेंस का है, इसलिए उसका समाधान नहीं हो रहा है। फैक्ट्रियों के लिए जमीन नहीं है, हाईवे के लिए जमीन नहीं है, रेलवे के लिए नहीं है, एयरपोर्ट के लिए नहीं है, तो फिर विकास कहां से होगा? नौकरियां कहां से आएंगी? लोगों के पास कहां से काम आएगा? राज्य सरकार इसमें लाचार है, इसलिए वहां के लोग इससे वंचित हो रहे हैं। यह बड़ी चिंता की बात है।

हमारे बंगाल में एक परंपरा बनी हुई थी कि केंद्र सरकार के बजट के पहले दिन वहां बजट आता था। लेकिन इस साल बजट कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, यह किसी को मालूम नहीं है। अधिवेशन कब होगा, यह किसी को मालूम नहीं है। वहां बजट सत्र नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के प्रवास पर गए हैं, वहां घूमने गए हैं और बंगाल के लोग, दो रुपये किलो चावल, तीन रुपये किलो गेहूं मिलता है, जो मोदी जी भेजते हैं, उससे गुजारा कर रहे हैं। लोगों की इनकम कहां से होती है?

मनरेगा से होती है। गरीब लोगों को सौ दिन का काम मिलता है और उसके लिए सबसे ज्यादा पैसा बंगाल सरकार को मिलता है। उससे गरीब लोगों का गुजारा होता है। पिछले दो साल से वहां लगभग 80 पर्सेंट लोगों को इस प्रकार फ्री में राशन मिला है, जिसमें केंद्र का भेजा हुआ चावल, दाल, गेहूं होता है, जिससे लोग जिंदा हैं। गरीब लोगों का काम तो मनरेगा हुआ और गरीब लोगों के गुज़ारे के लिए केंद्र सरकार की अन्न योजना में दाल-चावल मिलता है, जिससे गुज़ारा हो रहा है। पढ़ाई के लिए हमारे नौजवानों को बैंगलूरु या फिर हैदराबाद जाना पड़ता है और दवाई के लिए चेन्नई-मुंबई जाना पड़ता है, कमाई के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है।

बंगाल में क्या फैशन हो गया है कि वहां की सरकार जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग करती है, वह खुलेआम रास्ते में करती है, पंडाल लगा कर रास्ते में मीटिंग होती है, किसी हॉल में नहीं होती है और वहां से पीएम, एचएम और गवर्नर को गाली देने का एक फैशन सा बन गया है। वहां की जो पार्टी सरकार में है, उनके नेता और गुंडे विपक्ष पर, विशेष कर हमारे कार्यकत्ताओं पर अत्याचार करते हैं, मारते हैं और पेड़ पर टांग देते हैं। यह उनके मनोरंजन का माध्यम है। आप देश भर में दीपावली मनाते हैं, उसमें बम-पटाखे फोड़ते हैं, उनसे आवाज़ होती है। यह साल में एक बार होता है, लेकिन हमारे वहां तो हर महीने होता है। अभी चार दिन पहले हालिशहर, उत्तर 24 परगना में गंगा किनारे पर एक बम ब्लास्ट हुआ है।

वहां बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। उनकी फुटबॉल झाड़ी में गई तो वहां बम फटा और एक बच्चा वहीं मर गया, दो के शरीर के छितरे-छितरे हो गए, गंगा में चले गए और अभी तक मिले भी नहीं हैं। यह स्थित है। बंगाल में ऐसा कोई जिला नहीं है, जहां बम-बंदूक के कारखाने नहीं मिलते हैं और बम ब्लास्ट नहीं होते हैं। पूरे देश के गैंगस्टर और एंटीसोशल वहीं पनाह लेते हैं। बांग्लादेश के टेररिस्ट्स भी बंगाल में शेल्टर लेते हैं। पूरे देश में कोई बम बंदूक की आवाज नहीं है, कोई आरडीएक्स और माइन्स की आवाज़ नहीं है, लेकिन बंगाल के हर जिले में इस प्रकार से आवाज़ आ रही है और लोग डरे-डरे जीवन बिता रहे हैं। यह बड़ी चिंता की बात है।

1758 बजे (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी पीठासीन हुए)

किसान सम्मान निधि से पूरे देश में लगभग 11 करोड़ से ज्यादा गरीब किसान दो साल से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे बंगाल के लगभग 72 लाख किसान इस योजना के हक़दार हैं। पिछली मई में जब चुनाव हुआ, उसके बाद मुख्य मंत्री को लगा कि किसानों को इसका लाभ देना चाहिए, तब बंगाल के किसानों को यह सब देने की अनुमति उन्होंने दी। लेकिन फिर भी इन 72 लाख किसानों में से केवल 27 लाख गरीब किसानों को ही इसका लाभ मिल रहा है, बाकी लोगों को अभी-भी वंचित रखा गया है। राज्य सरकार को उनका नाम, एड्रेस, अकाउंट नंबर और फोन नंबर भेजना चाहिए, वह काम भी राज्य सरकार नहीं कर रही है, इसलिए मोदी जी द्वारा दिए जाने वाले 6000 रुपये की किसान सम्मान निधि से बंगाल के किसान वंचित रह गए हैं।

आज-कल दवाइयों और ट्रीटमेंट का कितना खर्चा होता है, यह सब जानते हैं। बंगाल के हॉस्पिटल्स की खस्ता हालत है। वहां के डॉक्टर्स, नर्स, कर्मचारी और जूनियर डॉक्टर्स आदि सभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं। लोगों को ट्रीटमेंट के लिए चेन्नई जाना पड़ता है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत की जो योजना लागू की है, उससे बंगाल के लोगों को वंचित रखा गया है। करोड़ों लोगों को उससे लाभ मिलने वाला था, लेकिन वहां की सरकार की इस प्रकार की नीति है कि बंगाल के लोगों को हर चीज़ से वंचित रखा जाए और केंद्र सरकार की केवल आलोचना की जाए।

(1800/RV/SM)

अभी हमारे यहां बहुत बड़ा तूफान आया। यह दो-दो बार आया। पिछले साल आया था। अब बंगाल में ओडिशा के जैसे लगभग हर साल तूफान आता है। उसमें धान की फसल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सब्जी खराब हो गई। अभी वहां सब्जी बहुत कीमती है। हमारे बंगाल के सात-आठ जिलों में आलू की उपज काफी बड़ी मात्रा में होती है। वह भी खराब हो गई। लोगों ने एक बार बीज बोया, वह खराब हो गया। दूसरी बार बोया, वह भी खराब हो गया। उसमें से कुछ-कुछ थोड़ा-बहुत कहीं उसकी उपज हो रही है, लेकिन वहां के किसानों की मदद करने के लिए वहां की सरकार तैयार नहीं है। किसान रो रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास जो भी पैसे थे, उसे उन्होंने उसमें खर्च कर दिए। अब उनके पास खाने के लिए नहीं है। अब वे खेती क्या करेंगे, इसके लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। इस प्रकार भयंकर परिस्थिति में वहां के लोग गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उसका विरोध करने से आपको जेल में ठूंसा जाएगा, आपको मारा-पीटा जाएगा। चुनाव के बाद लगभग 60 लोगों की हत्या हुई है। सी.बी.आई. इंक्वायरी हो रही है। अभी लगभग 42,000 फॉल्स केसेज हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हो रहे हैं। हम केसेज लड़ रहे हैं। हजारों लोग घर से बाहर पुलिस के डर से भागे हुए हैं, हजारों लोग जेल में हैं। अभी वहां लोकल बॉडीज़ का, म्युनिसिपैलिटीज़ का चुनाव हो रहा है। चार कॉरपोरेशन्स के और 108 म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव की घोषणा हुई है। इसी का फायदा उठाकर पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं पर केस डालकर उन्हें घर से बाहर कर रही है, ताकि वे चुनाव न लड़ पाएं। आज की खबर है कि वहां पुलिस के द्वारा नॉमिनेशन रोका जा रहा है। वहां पुलिस खड़ी है, डंडे चला रही है। उनको गुंडे घेरे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता नॉमिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। वहां लोकतंत्र मात्र चर्चा का विषय है, सेमिनार का विषय है। वास्तव में, वहां लोकतंत्र नहीं है। यहां आकर अधिकार मांगते हैं कि हमें लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है और वहां विरोधी के लिए कोई लोकतंत्र नहीं है। गवर्नर को गाली देना एक फैशन है।... (व्यवधान) वहां गवर्नर, जहां संविधान के प्रतिनिधि हैं, वहां उन्हें व्यक्तिगत नाम से काले झंडे दिखाना, उनकी गाड़ी को रोकना, उनके लिए गलत शब्द का प्रयोग करना, मुख्य मंत्री से लेकर सारे नेता बोलते हैं, यह गणतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा धोखा है, गणतंत्र का अपमान है। मैं इसका विरोध करता हूं।

माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। इस बजट का समर्थन करता हूं और सारे प्रतिनिधियों से मैं निवेदन करता हूं कि इस बजट को सहमति से पारित करें, ताकि आगे चलकर हमारे देश में खुशहाली आए।

धन्यवाद।

(इति)

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI): Shri Kathir Anandji.

... (*Interruptions*)

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Sir, one minute. I want to thank Nirmala Sitharamanji because she has not noted down even a single word from the speech of Shri Dilip Ghosh. He did not go through the Budget. He has only made complaints against the West Bengal Government.

HON. CHAIRPERSON: Shri Kathir Anandji

1802 hours

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Hon. Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the Union Budget. After this Budget was presented in this august House, many Chief Ministers had made their comments. The Chief Minister of Tamil Nadu, who is really revolutionising the State in administration as well as socio-economic policies, has criticised the Budget saying that it is not a Budget for the common men.

Sir, my father Shri Durai Murugan is a leader of the Tamil Nadu Legislative Assembly. He has been in politics for more than 50 years. Recently, the Tamil Nadu Assembly congratulated him for continuing in the Assembly for 50 years and still undefeated from the same Assembly constituency.

When I asked him about the reason behind the success of a politician or a political party, he clearly said that when a party or a Government fails to address the poorest of the poor man in governance, automatically the Government becomes a failure. I asked him about the reason for being elected again and again. He told me very clearly, "I respect my constituency as a temple and I worship my voters as my real God".

But, I do not see that this Government has done anything for the common men. No welfare schemes have been provided in this Budget. When you see the overall Budget proposals, the North has been given a lot of funds.

(1805/KKD/MY)

But the South has been deprived of funds. Even during the pandemic, every Member of Parliament went running to the Prime Minister's Office as well as Home Minister's Office asking for relief fund, but we did not get any fund. They gave us only good hope and sent us back. We did not have any relief fund.

The GST compensation to States is still due after 30th June, 2021. The MGNREGA scheme was a beautiful scheme, by which a common lady, the poorest lady in any Constituency, was able to make her day. They were not dependent on their husbands, but when the funds under this scheme are being reduced under MGNREGA, it is really depriving them of their daily livelihood.

Sir, there are repeated announcements – Housing for All, Doubling the Farmers' Income, Inter-linking of peninsular rivers, and sanctioning of loans up to Rs. 1 crore in 59 minutes for MSME segments, but everything is in documents. Nothing is happening in reality.

Sir, agriculture is a very big issue, which is being talked about. I was looking at the Government hoping that they would announce a lot of things about agriculture in this Budget, but nothing has been said about it.

Recently, a Member asked a question in this august House. He asked about the data of the farmers' suicide while protesting against the three farm laws. I am quoting what the hon. Minister replied. He said: "No information regarding the suicide by any farmer while protesting against the three farm laws is available with the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare." The Government is not even aware how many suicides have happened!

Further, he replied: "Further the subject of compensation to the families of the deceased farmers in the farmers' movement, is with the State Government." So, the Union Government has washed off its hands from whatever has happened to the farmers. They do not even care about farmers.

A second question was asked: "The Farm Acts have been repealed, but what happens to the contracts and other things which had been signed during the tenure of the farm laws?" The Minister says: "The agreements entered under the Act after the three principal Acts and before passing the Repeal Act, will be governed by the legal provisions." What does it mean? It means that whatever agreements had been made by the farmers and the organisations after and before repealing of the farm laws, will be in existence. So, whatever damage has been done, the Union Government does not care about. Not even a single rupee has been announced by the Union Government for the benefit of the deceased farmers. This is an anti-agriculturist Budget. That is what I can tell about it.

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI): Please conclude, now.

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, give me some time. I have got a few more points to make.

Sir, when we talk about projects that have been announced by this Government, especially railway projects, there is a contradiction. The Southern Railway has been allocated Rs. 7,114 crore whereas the Northern Railway has been allocated Rs. 66,000 crore.

This is an example of how the Centre treats the South. I would conclude by making only one point. Please do not disturb me. Just give me a moment … (*Interruptions*)

NEET is a subject which is a matter of this hour. Madam Minister understands Tamil language, so I would like to speak a few words in Tamil, if need be.

Before 2020, all the hospitals in the State were built with the State Government's own funds. But after 2020, the Central Government announced a scheme in the ratio of 60:40. Money was given by the Central Government and the hospitals were built. Now, about the NEET, they say that all the seats will be filled through NEET, and the States will not enjoy any benefit out of it. Everything is an open competition. But after the hospitals are built and completed by any Government, the maintenance of the hospitals, the salaries of employees and also all other expenses of the hospitals have to be borne by the State Government.

(1810/RP/CP)

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI): Member, kindly conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Now, tell me, Sir, what is the law behind it? The State has to spend all the money. Then, someone from North India will come to South India and take this seat and enjoy this MBBS seat.

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, kindly conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): I am concluding, Sir.… (*Interruptions*) After they complete their PG, the State Government used to send the doctors to the primary health centres and they used to serve in the villages..… (*Interruptions*) I am completing, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Shri M.K. Raghavan ji.

… (*Interruptions*)

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Now, the persons will come and take their degrees and walk back to their Northern States.... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I request all the hon. Members. We have a very long list of speakers. So all the remaining Members will have to conclude within five minutes.

... (*Interruptions*)

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Sir, I am concluding.

माननीय सभापति : आप एक सेन्टेन्स में कनक्लूड करिए।

श्री डी. एम. कथीर आनंद (वेल्लौर): सर, ठीक है। So, when I conclude my speech, I wanted to tell this Union Government through the hon. Finance Minister with her august presence here that this Government deprives the State of Tamil Nadu from all its rights. ... (*Interruptions*)

(ends)

1812 hours

माननीय सभापति: राघवन जी, आप पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: आप बहुत वरिष्ठ मेंबर हैं। यहां बहुत लंबी लिस्ट है और हमें कनक्लूड करना है।

… (व्यवधान)

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Thank you respected Chairman, Sir. आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने इस ऑगस्ट हाउस में कहा था कि हम टुकड़े-टुकड़े गैंग से हैं। हम ऐसे गैंग से नहीं हैं। हम एक महासंगठन से हैं। उसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस है। आप हमारे देश के ऐतिहासिक फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री पढ़ लीजिए। आप उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को देखेंगे। आपकी सरकार कॉरपोरेट सरकार है। हम इस देश के आम आदमी के साथ हमेशा रहेंगे।

Hon. Chairman, Sir, Madam Finance Minister has said that we have entered into an *amrit kaal*. Sadly, to enter into *amrit kaal*, we have to consume the *kaalakoota* to save the world. According to Bhagavata Purana:

"तत: करतलीकृत्य व्यापि हलाहलं विषम्।
अभक्षयन्महादेव: कृपया भूतभावन:। "

It means, Mahadeva, out of compassion for the welfare of all living beings, consequently took the widespread *halahala* poison in his hand and drank it. The *kaalakoota* that India faces today is the blow, the pandemic has attacked our economy. This *kaalakoota* could only be eliminated if we have allocated sufficient funds for Health to fight this pandemic. Unfortunately, that was not seen. The health costs are rising but the Budget outlay for Health has dropped. It is sad and a matter of shame that only after the intervention of the hon. Supreme Court, the Government fixed the compensation for the victims of COVID-19 Pandemic.

One of India's greatest poet and environmentalist Sugathakumari teacher has said:

"Aro parangu murichu mattam kedu badichoru avayavam,
pakshey kodum kedu badicha manasso."

It means, a diseased part can be cut and removed but what can be done to the poor heart deeply diseased. The Government is heartless when it comes to poor people, farmers, labourers, and *dalits*. The Government is heartless when it comes to country's youth. The Government is heartless when it comes to the women of this country. The Government is heartless towards our healthcare sector.

(1815/NKL/NK)

Sir, what you have done is this. In MGNREGA, you have cut the funds by 25 per cent, that is, up to Rs. 75,000 crore. Let us not forget about the massive arrears to be paid to the States under this scheme. This single scheme alone was the reason that the poor people from rural areas did not go hungry since the pandemic. You call us *"Tukde Tukde Gang",* and often ask what the legacy of the UPA Government is. We are proud to say that we do not belong to the *Tukde Tukde Gang;* rather we are the proud Members of the Indian National Congress. … (*Interruptions*)

Sir, we brought in MGNREGA; we brought in the Food Security Act; we brought in the RTI Act but you diluted it; we brought in the Right to Education Act; and we brought in the Street Vendors Act. The list is endless. What does your Government do? You pass Bills without discussion and then repeal it. In this context, I would say that we are proud of our great Leaders, Shrimati Sonia Gandhi and the former Prime Minister, Manmohan*ji,* who are the architects of the above-mentioned pro-poor schemes.

Sir, one thing is very clear. If the UPA Government had not brought in this MGNREGA, we would have to witness starvation, deaths, and mass suicides in our villages under the Modi regime. So, the entire nation is thankful to the UPA. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI): Kindly conclude.

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, please allow me some more time.

You did not double the farmers' income. We all know whose income was doubled in 2022. You leave people's minds divided. You have cut subsidies on food and fuels. I would ask what legacy this is.

According to the World Inequality Report 2022, India stands out as one of the most unequal countries in the world with widespread poverty along with an affluent elite. … (*Interruptions*)

Madam Finance Minister, I am sorry to say that the Budget has totally neglected India's middle-class people. I think, perhaps, you forgot about the State of Kerala as a whole. We are a part and parcel of the nation. … (*Interruptions*) Kerala is totally neglected deliberately in this year's Budget. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude in one sentence.

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I will cite examples for the same. There was no announcement for setting up of AIIMS at Kozhikode, for which we were waiting for many years. The defence allocation has totally neglected the NIRDESH at Kozhikode. The fate of this great institution now hangs in balance.

HON. CHAIRPERSON: Raghavan*ji,* please conclude.

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I will take only one more minute.

Sir, I would request the hon. Finance Minister to allocate funds for AIIMS at Kozhikode. Also, I would request that one NIMHANS teleconsultation centre be allocated to Kozhikode in association with the IMHANS, Kozhikode. I would also request that Kozhikode-Wayanad connectivity be brought under the National Ropeway Project.

Sir, the Government has continued with the habit of selling the Public Sector Undertakings. The Government has thanked the former Prime Minister of India, Pt. Jawaharlal Nehru*ji.*… (*Interruptions*)

Sir, there is a saying in Malyalam. It means, if you plant ten plants during your best times, you can reap its ten fruits during your hard times. This is exactly what your Government is doing. We have planted trees in the form of Public Sector Undertakings over the years, and now you are selling them.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Thank you. Now, Dr. Heena Vijaykumar Gavit.

… (*Interruptions*)

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, I am just concluding.

माननीय सभापति: आप एक सेन्टेन्स में कनक्लूड कीजिए।

SHRI M. K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I would say, you are not only using its fruits but also selling them and reaping benefits out of it. This is exactly what you are doing with the India's Public Sector Undertakings. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Thank you very much. Now, Dr. Heena Vijaykumar Gavit.

(ends)

1819 hours

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity.

I rise to support the Union Budget 2022-23. I would like to thank the hon. Prime Minister, Modi*ji* and also the Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman*ji* for presenting an all-inclusive Budget. The Union Budget seeks to complement macro-economic level growth with the focus on micro-economic level all-inclusive welfare.

(1820/MMN/SK)

Our Government has tried to address the needs of each and everyone in the country, let it be those living in the rural areas, let it be those living in the cities or those living in the borderline areas of the country.

To start with, the Union Budget 2022 is based on four pillars. First is the PM Gati Shakti National Master Plan. Second is inclusive development. Third is productivity enhancement and investment, sunrise opportunities, energy transition and climate action, and fourth is financing of investments.

The PM Gati Shakti National Master Plan has seven engines. Under road transport, the Government plans to expand the national highway network to 25,000 kilometres in 2022-23, for which Rs.20,000 crore will be mobilized. The Government plans to establish multimodal logistic parks at four locations through the public-private partnership model. Sir, 2000 kilometres of railway network under the indigenous technology will be expanded. The scheme ‘One Station, One Product’, which is a new concept, will help the local business and the supply chains.

It is worthwhile to mention that India has Asia’s largest rail network and the world’s second largest rail network, which means that this concept of ‘One Station, One Product’ is going to benefit each and every part of the country. Wherever there is a railway station, this ‘One Station, One Product’ Scheme will be implemented and by bringing this concept, the Government is trying to help the local businesses to come under the mainstream line.

The Government is also planning to develop 400 new generation Vande Bharat trains, 100 cargo terminals, and eight ropeway projects of 60 kilometres length.

The next pillar is inclusive development. Inclusive development of farmers is one of the main priority areas of the Government. As India has 70 per cent of its population dependent on agriculture and allied activities for their livelihood, it is obvious that the focus of the Government is going to be more on the agriculture sector. The Government has announced the usage of 'Kisan Drones' as an all-purpose tool for the farmers for crop assessment, digitisation of land records and spraying of fertilizers and insecticides.

As I am a doctor myself and I represent a rural constituency, we come across a lot of people who develop poisoning and cancer because they are continuously in contact with those chemical fertilizers. It is because of these Kisan Drones, now our farmers will be protected from this kind of poisoning and cancer, and, on behalf of all the farmers, I thank the Government because these Kisan Drones are going to be of much, much help to the farmers. Along with this, agriculture being the largest sector in the country, it can prove to be a major source of employment to those living in the rural areas, and also it can help in developing entrepreneurship. Keeping this in mind, the Government has focussed on the agri-business, and tried to support the rural and the agri-business start-ups by bringing in a fund with blended capital under co-investment model through the NABARD in order to finance these agri-start-ups. This will definitely create many jobs for the people, particularly for the people living in the rural areas of the country.

Rs.2.37 lakh crore MSP will be directly transferred to the accounts of 1.63 crore farmers. The Government has allocated funds for agro-forestry for the SC/ST farmers. This will definitely help in the earnings of the SC/ST farmers.

When I travel in my Nandurbar Parliamentary Constituency – my constituency lies mostly in the hilly areas of Satpura and Sahyadri ranges -- I see most of the tribal women carrying water in a bucket or something on their head that we call as '*handa'* and also by their sides, from miles away. I feel really painful to see our sisters taking water from a long distance. Therefore, I try to help these women as much as I can so that they get the water available very close to their houses. But when the Government brought the Jal Jeevan Mission Scheme – Har Ghar Nal Se Jal, I realise that the Government also feels the pain of the mothers and sisters of the country, and has launched this scheme. For this scheme, the Government is giving Rs.60,000 crore to cover 3.8 crore households in the year 2022-23.

Sir, Pradhan Mantri Awas Yojana ensures housing for all the poor, particularly those who do not have *pucca* houses. Under the Pradhan Mantri Awas Yojana, in my Nandurbar Parliamentary Constituency, more than one lakh people have got the houses so far, and there are still more numbers left behind.

(1825/VR/MK)

Now, under this Budget the Government has allocated Rs.48,000 crore for completion of 80 lakh houses, which is going to fulfil the dreams of 80 lakh people who have been waiting for their *pucca* house so far. On behalf of all those poor people, I would like to thank the Government for this budgetary allocation.

Sir, we all are aware that during the pandemic schools were closed and online education was started. We are aware that in most of the rural areas it was almost difficult to give online education to our children due to many hurdles. Therefore, lots of children had to face educational loss. To cope up with this educational loss, the Government has come up with 'One Class One TV Channel' programme under PM e-Vidya mission to cover 200 television channels so that the educational loss will be covered, and our children who are the future of our country will get education and whatever loss they had in the last two years will be covered. So, on behalf of all the parents, I would like to thank the Government for this initiative.

Sir, also Virtual Labs and Skill e-Labs will be set up to promote critical thinking skills and simulated learning environment. Digital university for world class education with personalized learning experience will be established. Skill training is also a very important sector and we must appreciate the efforts that the Government has put for empowering citizens to skill, reskill, and upskill through online training by planning to launch DESH Stack e-Portal. It is very important to give quality education to the people to ensure that they get good placements and job opportunities. Through this portal it will be assured that quality training is given by the master trainers to the people in the remotest parts of the country where it is difficult for the master trainers to reach.

Sir, along with this, for women empowerment also, the Government plans integrated benefits to women and children through Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. About two lakh anganwadis will be upgraded to Saksham Anganwadis. The National Family Health Survey-IV and the National Family Health Survey-V clearly show an improvement in child sex ratio and this has been possible because of the initiative 'Beti Bachao, Beti Padhao' of this Government.

Sir, in terms of strengthening initiatives towards achieving the climate targets voiced by the hon. Prime Minister, Modi ji, the latest Budget lays down significant provisions. Echoing the same day, hon. Finance Minister stated: "Risks of climate crisis are the strongest negative externalities that affect India and other countries." We are all witnessing the climate change effects. India being an agrarian country, the effects of climate change are affecting the agriculture sector. We are witnessing droughts, hailstorms, unseasonal rains, and extremes of temperatures. Therefore, this is the need of the hour to come up and start working on green initiatives.

This Budget provides impetus to clean and green economy by increasing allocation of Rs.19,500 crore for PLI schemes for manufacturing of high efficiency solar modules. Additionally, to promote the transition to electric vehicles, the Government has announced a Battery Swapping Policy as well as formulation of interoperability standards. The Government has also announced the intention to complement public transport and clean technology as well as implement Special Mobility Zones. Five to seven per cent biomass pellets will also be co-fired in thermal power plants which will result in reduction of CO2 emission. This will also reduce stubble burning, dependence on coal and consequently air pollution. Furthermore, sovereign green bonds will also be issued by mobilizing resources in green infrastructure.

Last but not the least, Rs.2,217 crores have been allocated to combat air pollution in 42 urban cities with a population of over one million. The Aspirational District Programme, which was made for backward districts to improve the quality of life of citizens, has shown remarkable improvement in a very short span. My constituency, Nandurbar is also one of the Aspirational Districts, and we have witnessed significant progress in health, nutrition, infrastructure, education, and financial inclusion.

In this year's Budget, the Government has announced its focus from Aspirational District to Aspirational Block which means going till the last mile and reaching till the last person. I am very much confident that the way Aspirational Districts have shown progress over the past few years, definitely improvement in the Aspirational Blocks will change the picture and will totally change the scenario of that area.

Sir, I thank the Government, the hon. Prime Minister, Modi ji and the hon. Finance Minister, Nirmala Sitharaman ji for brining in this very good Budget. I wholeheartedly support the Budget. Thank you very much.

(ends)

(1830/SAN/SJN)

1830 hours

*SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Honourable Chairman Sir, I thank you and my party YSRCP for giving me this opportunity to speak on General Budget 2022-23. I would like to mention about budgetary allocation for SCs and STs. In the present budget Rs.1,43,343 crores have been granted for their welfare. In comparison to previous year's Budget there is an increase of Rs.16,000 crores. I thank honourable Prime Minister and Finance Minister for this gesture. For STs Rs.89,625 crores have been allocated, which is only 5.5% of allocated funds. Similarly, population percentage of SC's is 15%, but only 8.8% of funds was allocated for them. We will thank Finance Minister if these funds are further enhanced. For sanitation workers, as per Manual Scavengers' Act 2013, Union Government decided to provide more facilities. In this regard, Rs.110 crores were provided, but only 16.6% of funds were utilised. I am bringing this to the notice of the Finance Minister regarding unutilised funds.

During Corona pandemic, Doctors, Nurses and Sanitation workers were in front line to fight the virus. We are deeply indebted for their services. Sanitation workers across many Municipalities risked their lives to cremate victims of Corona.

If special provisions for sanitation workers can be provided in our budget, that will be a sweet gesture for their service. I request Finance Minister to consider this request. In Andhra Pradesh, 'Rythu Bharosa Scheme' introduced by our Chief Minister is benefitting poor farmers including tenant farmers by providing Rs.13,500 per annum in the form of subsidy. There are around 42.4 lakh tenant farmers in Andhra Pradesh. Most of these tenant farmers belong to SCs, STs and background communities. Therefore, more funds should be ear marked under Tenants' Act. Similarly, MNREGA funds should be linked to farmers and agricultural labourers. I also demand for exclusive budget for farmers.

* Original in Telugu

In our country, to ensure speedy delivery of Justice through courts we should fill up vacant posts of Judges in High Courts and Supreme Court against SC, ST quota at the earliest. I request Finance Minister to provide funds for appointment of Judges and Officers across all the courts of the country.

In rural areas, due to Corona, students are facing difficulty in accessing education through smart phones. Therefore, more BSNL towers should be installed in rural areas. There are coaching centres in various States for providing free coaching to students belonging to SC, ST communities to appear in various competitive exams like Railways & Civil Services Exam etc.

I thank Finance Minister for providing more funds to post matric students. I further request Finance Minister to provide funds to operate free Coaching centres for SCs and STs to appear in Civil Services Exam.

We thank our Prime Minister for expressing concerns over financial situation of Andhra Pradesh in his latest speeches in Lok Sabha as well as Rajya Sabha. The reason for our financial crisis is our former Chief Minister N. Chandrababu Naidu, who requested Union Government to bifurcate Andhra Pradesh. Had our late former Chief Minister YS Raja Shekhar Reddy was alive, our State would have been intact and we would not be facing these difficulties.

Our Chief Minister met Prime Minister and Finance Minister in the last 2 and ½ years with requests for financial assistance. If we do not get assistance for our State, we will be in deep crisis. Due to recent natural disasters there were heavy crop losses and farmers are under severe distress. Sir, our Chief Minister is the role model in our country. He is providing special financial assistance of Rs.75000 per annum to women belonging to not only SCs, STs, Minorities, OBCs but also to Economically Background Classes (EBCs).

Through, Rythu Bharosa, farmers are being provided with Rs.13,500 of financial assistance. Pension of Rs.2,500/- is being disbursed to all eligible beneficiaries. In schools also quality of education is being improved. Our Chief Minister is working tirelessly for the welfare of the people of our State. It is the responsibility of the Union Government to encourage such committed Chief Minister. Therefore, we support this Budget and we request Prime Minister and Finance Minister to help our State emerge out of financial crisis.

As far as women empowerment is concerned, our Chief Minister provided portfolios of Dy. Chief Minister and Home Minister to women. Women are provided with robust representation in not only MPTC, ZPTC and Village Panchayats but also in recently held Corporation elections. Around 50% of posts in corporations were given to women. Founding father of our Constitution Dr BR Ambedkar provided for women's reservation but we are yet to pass this Bill in our Parliament. Credit goes to our CM Shri YS Jagan Mohan Reddy for implementing reservation for women. He is not only providing 50% reservation for women, but also providing financial assistance to households ranging from 1.5 to 2.5 lakhs every year. Union Government should recognise our Chief Minister's efforts and help our State Andhra Pradesh.

Especially, for backward classes like washerman, weavers, tailors and others, they are being provided with assistance ranging from Rs 10,000 to 18,000. One minute Sir. To complete Polavaram Project, funds should be released on time. For construction of new Railway lines also funds should be provided.

Thank you very much Sir.

(Ends)

(1835/YSH/SNT)

1839 बजे

श्री महाबली सिंह (काराकाट): सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन में वर्ष 2022-23 का जो केन्द्रीय बजट सदन में चर्चा के लिए रखा गया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, यह बजट देश के आम लोगों के हित में है। यह बजट सर्व समाज के हित में है। यह देश की तकदीर और तस्वीर बदलने की दिशा में एक सराहनीय कदम है, लेकिन इस बजट की विपक्ष आलोचना क्यों कर रहा है, यह हमें समझ में नहीं आता है।

महोदय, लोकतंत्र की यह परिपाटी बहुत दिनों से चली आ रही है कि सत्ता पक्ष कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर ले, लेकिन विपक्ष का काम उसकी आलोचना करना ही है।

(1840/RPS/SRG)

केन्द्र की सरकार ने इतना अच्छा बजट बनाया है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की तरफ, विकसित भारत की दिशा में और आम लोगों के हित में है, फिर भी विपक्ष इसकी आलोचना कर रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि आजादी के 75वें वर्ष में हम आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इन 75 वर्षों में से लगभग 62-63 साल तक कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया है। देश की जनता ने आपको 63 साल तक देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का मौका दिया था, लेकिन आप 63 साल के अन्दर न देश के गरीबों की तकदीर बदल सके, न इस भारत की तस्वीर बदल सके। इस सरकार को सिर्फ सात साल का मौका मिला है और आप जो काम 63 वर्षों के अन्दर नहीं कर सके, उसको मोदी सरकार ने इन सात वर्षों के अन्दर करके दिखाया है, फिर भी आप आलोचना कर रहे हैं। 63 साल में आपने देश के गरीबों के हित में, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के नाम पर बहुत सी नीतियां बनाईं, अच्छे बजट बनाए। नीतियां आप बनाते रहे, नीतियां बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, आप बजट बनाते रहे, बजट बनते रहे, बिगड़ते रहे, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों की तकदीर आप नहीं बदल सके। 63 सालों में इस देश के जो गरीब गन्दे नाले, नदी-नाले, पेड़ों के नीचे जन्म लेते थे और वहीं मर जाते थे, आप उनको मकान नहीं दे सके, शुद्ध जल नहीं दे सके, उनको स्वास्थ्य के लिए कोई सुविधा नहीं दे सके। आज मोदी सरकार इस दिशा में पहल कर रही है, फिर भी आप आलोचना कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा। निश्चित तौर पर आज देश विकसित देशों की श्रेणी में आने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में तभी आ सकता है, जब बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाया जाएगा। जब तक बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में नहीं लाया जाता है, तब तक देश को हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। इसलिए आज बिहार क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो निश्चित तौर पर बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आता। अगर बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आता है तो देश भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ सकता है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): महोदय, मैंने अभी तो शुरू किया।

माननीय सभापति : आपकी पार्टी का समय ही नहीं है और आपका पांच मिनट समय पूरा होने वाला है।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): महोदय, मुझे दो मिनट समय दीजिए।

माननीय सभापति : दो मिनट नहीं, अब आप कनक्लूड कीजिए।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): महोदय, इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है। देश के विकास के साथ-साथ, बिहार में दस वर्षों से जो परियोजनाएं बन्द पड़ी हुई हैं, मेरे क्षेत्र में भी दस साल से तीन परियोजनाएं बन्द पड़ी हैं।

माननीय सभापति : अब आप की बात आ गई है, अब समाप्त कीजिए। धन्यवाद।

श्री महाबली सिंह (काराकाट): महोदय, बिहटा से औरंगाबाद रेलवे लाइन का काम दस साल से बन्द पड़ा हुआ है। डिहरी से बंजारी रेलवे लाइन, जो उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, वह भी बन्द पड़ी है। डिहरी-डालमिया नगर फैक्ट्री, जो रेलवे वैगन फैक्ट्री है, वह भी दस साल से पेंडिंग पड़ी हुई है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि अगर देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाना है तो बिहार को विकसित बनाना होगा। धन्यवाद।

(इति)

(1845/AK/SPS)

1845 hours

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Sir, thank you for giving me an opportunity to speak. Under the leadership of the hon. Prime Minister, the country has witnessed an economic miracle in the last seven years.

From agriculture to education, aviation to Railways, IT to BT, soil to space, in every segment of the country's national life the Prime Minister has ushered in a complete transformation. The kind of economic progress the country has witnessed in the last seven years and the pace of reforms is also unprecedented.

The numbers are there to give more clarity on it. However, the political commentariat speaks very highly of the 1991 Budget and describes it as the Budget, which opened the doors for India's economic growth. One must keep in mind that the 1991 Budget and the reforms that were introduced therein were made at a time of economic compulsion. The reforms that were brought in then were not as a result of the Government's conviction for economic reforms. The difference between then and all the four Budgets that the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman ji has presented is that the economic reforms introduced in the last four Budgets that she has presented are very dedicatedly and concertedly a result of the conviction of the Government to introduce economic reforms. It would not be an exaggeration if I say that when the history of modern India is written, India's history can be viewed as a before-Modi era and an after-Modi era. The numbers are so clear as to the kind of comprehensive transformation that the country has witnessed.

When hon. Member of Parliament from Wayanad was speaking about the idea of two Indias, perhaps this should have been the two Indias that he should have elaborated upon that before Modi there was a different kind of India and after Narendra Modi there is a different kind of India. Let me elaborate on what is the difference. Before Modi, the country was witnessing double digit inflation. We were considered to be among the fragile five economies of the world. After Modi, the country has consistently seen single digit inflation and we are today the fastest growing major economy in the world. This is the two Indias that we must be seeing. Before Modi, the size of India's GDP was Rs. 110 lakh crore and after Narendra Modi, the size of India's GDP is Rs. 230 lakh crore.

This is the two Indias that we must be proud of and this is the two Indias that have changed. Before Narendra Modi, India's exports were at Rs. 2.85 lakh crore and after Narendra Modi, India's exports are now at Rs.4.70 lakh crore. Nobody can deny these facts.

India's foreign reserves, before Modi ji, was US $ 275 billion and after Modi ji, India's foreign reserves is at US $ 630 billion. In every aspect of macro-economic measurement whether it is foreign exchange reserves, FDI, inflation, India after Narendra Modi has consistently performed better than what it was under the rule of the dynasts of the Congress. This is something that is very clearly established. … (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Are you an economist?

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): I am elected by the people of the country with as much right as a dynast sitting in this hall to speak on behalf of the people, and the numbers that I am quoting are sacrosanct as they come from the sources of Government. … (*Interruptions*)

Before Narendra Modi, the poor of this country were left to fend for themselves. This was the reality that the poor of the country were facing, but after Narendra Modi, we today have 44.8 crore people who, for the first time, came inside the formal banking system through the Jan Dhan accounts. Can we imagine that we were speaking of inclusive development, and for the last 70 years close to 45 crore people were not even part of the country's formal banking system? These people lecture today on *Sabka Saath Sabka Vikas* to us. … (*Interruptions*)

(1850/SPR/RAJ) 9.2.22

For the first time in country's history, nine crore households have got tap water. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। .

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण): आपके पास 70 साल थे।…(व्यवधान) In 70 years, if the Prime Minister has to come in 2014 and deliver nine crore households tap water for the first time, it reeks of the kind of rampant corruption that was there during your regime.

This is the old India; Out of the two Indias, this was the old India that was there and that you ruled. Whether it is DBT, whether it is UPI, whether it is *Jan Aushadhi Kendras,* every single matrix of governance, very clearly states that the Prime Minister has established in this country transparent systems, accountable governance and clear and committed government structures. This is the difference between pre-Modi days and after-Modi days.

I come from Bengaluru, the start-up capital of the country. Before Shri Narendra Modi, the country had only 500 registered start-ups. After Narendra Modi's Government, the country today has more than 65,000 start-ups, of which, 41,000 plus became unicorns during the pandemic. This shows the kind of resilience, the talent, the capability, the Prime Minister, Narendra Modi's governance has unleashed in this country. This is the two Indias – the India before Narendra Modi has stifled entrepreneurship; the India before Narendra Modi *ji* had cropped the entrepreneurial spirit of India; it had shackled economic freedoms of the people; the India after Narendra Modi *ji* has unleashed the talent of our people, the talent of our young people. Today, the economy is on the rise. This is something that needs to be established time and again.

In the last two days, during the course of the debate, the Members from the Opposition have been relentlessly making baseless and dare I say, logicless arguments, criticising the Government that there is an increase in unemployment. I want to ask them - सर, फारुख अब्दुल्ला जी बात कर रहे थे कि बहुत सारे युवा बेकार हो गए हैं। This was the word that he used. I want to ask, if the size of the GDP can be increased multiple times; if Foreign Direct Investment has increased multiple times; if the size of the investment that the country has got has increased multiple times… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सिर्फ तेजस्वी सूर्या जी की बात रिकॉर्ड में जाएगी।

… (*Interruptions*) *… (Not recorded)*

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): If the number of unicorns has increased multiple times … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

… (*Interruptions*)

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): How can there be no employment generation? … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

… (*Interruptions*)

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): The Congress Party and its dynasty leaders are confusing their political unemployment as the unemployment of the country. Those who are hardworking, talented, meritorious young people coming from a modest background, they have enough number of opportunities. If there is one young person who is unemployed in the country, it is the prince of the Congress Party, the dynast of the Congress Party. Let them not confuse their political unemployment as the unemployment of the masses today. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए। You address the Chair.

… (व्यवधान)

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Sir, it is very clear why this stings them. … (*Interruptions*) It is very clear why this stings the Congress Party. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : कौन-सा रूल है?

… (व्यवधान)

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Sir, I request you to not consider this as part of my time. … (*Interruptions*)

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): Rule 353 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha says that no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given sufficient notice. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): What can you do? How can you address a Member who is perpetually absent from the House, a Member who spends more amount of time in foreign vacations than spending in the House? What can I do other than speak when I get a chance? … (*Interruptions*)

(1855/UB/VB)

It is very important to ask as to why the Congress Party in the last seventy years had specifically kept the country's economy under shackles. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI): Hon. Members, kindly take your seat.

… (*Interruptions*)

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Although we got Independence in 1947, the country got economic independence only in 2014. Until 2014 and until the hon. Prime Minister Narendra Modi came to Office, the country's economy was shackled. The licence quota permit *raj* that the British had introduced continued for a period of almost seventy years until the hon. Prime Minister came. … (*Interruptions*) I will come there. Please have patience. I still have ten more minutes. You should have the gumption to listen to everything that I am saying.

It was deliberately done as a matter of design to keep this country poor. I will tell you why. If you look at this country's political map, I know why Farooq ji was so upset, from Kashmir to Kanyakumari, before the advent of the hon. Prime Minister Narendra Modi, the country's States were majorly controlled by a few political families and dynasty-based political parties. आप भारत के मैप को देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो परिवारवादी पार्टियाँ थीं, वही पार्टियाँ समाजवादी पार्टियाँ भी थीं। इसलिए समाजवादी ही परिवारवादी थे और परिवारवादी ही समाजवादी थे, क्योंकि if you create an open economy, more and more self-made capable leaders, more and more self-made millionaire entrepreneurs will come and wealth generation will take place. The reason why the dynasty polities preferred socialism and kept a closed economy was because they did not want the challengers to come and challenge their thrones and fiefdoms. What the hon. Prime Minister Narendra Modi has done today is that he has democratised not only India's polity but also India's economy and, therefore, we are finding today first-generation self-made millionaires who are being raised in this country.

Before the hon. Prime Minister came, we had not heard of self-made millionaires or start-up millionaires. I come from the city of Bengaluru. Today, the kind of YouTube content that our young people are watching is the interviews of Kunal Shah, Vijay Shekhar Sharma of Paytm, Goyal from Zomato, and Bhavish Aggarwal from OYO. Sir, please give me five minutes.

HON. CHAIRPERSON: Please address the Chair. आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण): सर, मैं पाँच मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। अभी मेरे बहुत-से विषय बाकी हैं। All these names that I mentioned are self-made first-generation leaders. Why did our country not create these kind of business leaders and entrepreneurs before 2014? It is because the dynasty-based political parties did not want to create such kind of economic leaders in the country. This is something that must be established.

There are only two other points I would want to make. Why do I consider this budget as a budget for jobs and India's youth? I speak as a young Member of Parliament and I want to thank the hon. Finance Minister for giving the most futuristic and the most tech-savvy budget ever in the country's history in the budget 2022. Sir, this budget speaks of a roll-out of 5G technology, this budget speaks of a taskforce for EVGC, this budget speaks of artificial intelligence, machine learning, big data, this budget speaks about EV policy, this budget speaks of battery swapping policy, virtual apps, 75 digital banks, digital university, and introduction of blockchain-based Central Bank digital currency. This is going to be a game changer in the India's economic journey. This budget speaks of any time anywhere post offices, digital ecosystem for skilling and livelihood, drone as a service, kisan drones, drone shakti, boost to quantum computing, Rs. 50,000 crore to National Research Foundation. It speaks of clean tech, green jobs, and solar power manufacturing. It is also speaks of creating jurisdictions where foreign universities can come and invest and such jurisdictions where no domestic regulation will apply.

(1900/KMR/VB)

Every year, Indian students and parents spend billions of dollars to go outside of the country to seek this education. This one change is going to save huge amounts of revenue for the country and also is going to create competition in India's education space. That is why I said that from education to technology, aviation to space, soil to infrastructure, this Government has transformed the country in every way.

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI): Thank you very much.

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Sir, I just want to highlight one important point.

Sir, I come from a city. My father hails from a small village in Chikkamagaluru and he migrated to Bengaluru about 50 years ago. When he came in his late teens, he did not even have hawai chappals to go inside attend classes. But because he came, our entire family is today financially secure and in just one generation, the people of Bengaluru blessed me to be their Member of Parliament. Why I am saying this is because consistently in the last 70 years our policy makers had neglected urbanisation and this was done deliberately. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण): सर, मैं आखिरी पॉइंट पर आ रहा हूँ।

This is going to establish the design of these people. They had deliberately neglected urbanisation and this was also done by a form of design.

Today the Prime Minister in the Budget has promised new urban planning. He has promised urban infrastructure, creation of metros, etc. On behalf of all the millions of millions of people who live in urban areas, I thank the Prime Minister and the Finance Minister for this very concerted effort at urbanisation.

HON. CHAIRPERSON: Thank you Tejasvi Surya ji.

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण): सर, मैं 30 सेकेंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

Sir, I want to just trace back the history as to where this whole obsession with socialism started. In 1955, in Chennai, the Congress Party had organised their 70th national conference. It was held at a place called Avadi. Jawahar Lal Nehru ji, who was then the Prime Minister, invited the President of Yugoslavia to come and attend the Avadi national conference as a special guest.

There, the Congress Party passed a resolution to establish in India a system of socialist-based society. And the obsession with socialism was so high that Comrade Nehru, in 1956, the year next, invited the Prime Minister and President from Russia to again come to India. At that time, Nikita Krushchev and Nikolai Bulganin came to India and planned India's economy. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Conclude now.

SHRI TEJASVI SURYA (BANGALORE SOUTH): Sir, this is a very important point. The young people of India must know what they have done. … (*Interruptions*)

For fifty continuous years, this mindless obsession with socialism kept India deliberately poor. This whole command, control ecosystem, planned economies, … (*Interruptions*) We have other Asian economies like Singapore, Taiwan which raced ahead. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप अपनी बात एक सेंटेंस में खत्म कीजिए।

श्री तेजस्वी सूर्या (बंगलौर दक्षिण): सर, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त करता हूँ।

Sir, the young people of India, the present generation of India must know what was the price this country paid for this mindless obsession with socialism that the Congress Party imposed on this country for more than 70 years. … (*Interruptions*)

Sir, Swaminathan Anklesariya Aiyar, a very senior economist, in a paper titled 'Socialism Kills – The Human Cost of Delayed Economic Reform in India' has to say this. The study finds that had the economic reform taken place a decade earlier, 14.5 million more children would have survived, 261 million more Indians would have become literate, 109 million more Indians would have risen above the poverty line. The delay in economic reform represents an enormous social tragedy for India. It drives home the point that India's socialist era which claimed it would deliver growth with social justice, delivered neither growth nor social justice.

(1905/RCP/PC)

I will only say this. … (*Interruptions*) It is for the first time under the Prime Minister Narendra Modi that this country has got unshackled; this country is on the rise and this country has finally got out from this pernicious trap of perverted socialism. That is a new India. … (*Interruptions*) This is a new India that is emerging. … (*Interruptions*) Thank you so much, Sir. (ends)

1906 hours

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri M. Selvaraj in Tamil,
please see the Supplement. (PP 344A to 344C)}

1914 hours

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I would just request for two minutes of your indulgence on a topic which is not related to the Budget. With your permission, Sir, I would like to read a few lines in Marathi.

*{What will we wear and eat? Only they will decide;
When and where to go? They will decide;
What and when to speak? They will decide;
What to share and forward? They will decide;
If we call it autocracy, they will express their anger for 'Emergency';
If we criticize them, they will book us for treason;
If we protest for the sake of democracy, they will insult by calling us 'Aandolanjeevi';
Dear citizens, what will you do now as you cannot breath freely?
An open threat is there right in front of us;
Now you have to decide, you are with it or against it.}

(1915/PS/KDS)

Hon. Chairperson, Sir, I stand here and I ask for your indulgence just for one minute to talk about something which is not related to the Budget. The hon. Finance Minister is a very dignified lady. I am a woman. We both have daughters and we both are very proud. I am sure that she is very proud of her daughter and I am also very proud of my daughter. What happened in Karnataka is unfortunate. My young friend from Karnataka -- I think he is not in the House right now -- spoke exceptionally well. We have disagreement of views but he did speak very well.

I want to bring to the notice of the House that one gentleman -- I cannot call him a gentleman -- who is a BJP MLA from Karnataka, has said today that rapes are increasing because of women's clothing. Sir, I repeat, he said, 'rapes are increasing because of women's clothing'. हिजाब पहनें तो बीजेपी को दिक्कत है, दूसरे कपड़े पहनें तो भी दिक्कत है। वे मॉरल पुलिसिंग भी करेंगे और थॉट पुलिसिंग भी करेंगे। I actually urge the hon. Minister because the hon. Minister is elected from Karnataka. I would ask her for justice.

* Original in Marathi

I hope she will intervene. Whoever that MLA is, this must be condemned and I would like to request the entire House to condemn it. सबके घर में बीवी-बच्चे हैं। We should not tolerate any such thing and this House must condemn it unanimously. If any man is saying that women get raped because of their clothes, I think, it is shameful and condemnable. We have daughters and we are very proud of that.

Look at the example of our hon. Finance Minister. She wore a beautiful Sambalpuri saree on the day she gave the Budget. How dignified she looked on that day? It was a beautiful handloom saree from Odisha. We all take pride in our Indian clothing. How does it matter? We do not judge each other on clothing. As a matter of fact, I want to compliment her because they were increasing the GST on handloom to 12 per cent, but she brought it down to 5 per cent. I thank you on behalf of all the weavers of this country, whom I am very proud of. We are very proud of our Indian traditions. But if any man in this country is going to demean a woman like this, all the hon. Members, in one voice, must raise it and say 'no' to this.

Another small point is this. I think, the young hon. Member is not here. I just want to put the record straight. He spoke very aggressively against dynasty. It is okay. He has every right to say that in a democracy. I just want to ask you one small question. Who is Ravi Subramanian? He is a BJP MLA from Karnataka. Does he know him? If he knows him, by any chance, are they remotely related to each other? I am very proud of whose daughter I am. I am not ashamed about it at all. I am proud of the house that I was born in. But I want to ask him what is his story. I just want to make a small one-line note. Dr. Pritam Gopinathrao Munde, Shrimati Poonam Mahajan, Dr. Heena Vijaykumar Gavit, Shrimati Raksha Nikhil Khadse, Dr. Sujay Vikhe Patil, Shri Jyotiraditya M. Scindia -- who is also now an hon. Minister, Shri Piyush Goyal, Shri Dharmendra Pradhan, all are my very good friends. I am very proud of them. One common thing that I have with them is that we were all born in political families and I am not ashamed to be born in a political family. I am very proud to be born to my parents.

Now, I come back to the Budget. One more small point that the young man made. He said that no businesses were created. He talked about pre-Modi Ji's era and post-Modi Ji's era.

I just want to remind him that he talked about Bangalore. If I stand corrected, Wipro is probably also in Bangalore. Infosys is a very large company in India; it also happens to have some presence in Bangalore. I am very proud of it because we have them in our State. They have talked about a big vaccine. The vaccine company of Poonawalla has just received an award from this Government. I think, he has got Padma Bhushan. That company also comes from my district. That man started from zero. He went to school with my father. So, I know the entire background. So, all these companies, *viz.,* Wipro, Cipla, Infosys, Kirloskar, Ambani, Bajaj, Walchand Group, Kalyani, Firodia Group, Poonawalla, Dhoot Group, have contributed in the last fifty years. So, please do not run down these families. They have contributed to wealth generation. They have created wealth, not centric but to everybody, and they have created jobs also. They have influenced our lives. So, lets us not demean all these families who started from nothing.

Now, I come to the main points of the Budget. I would like to talk about fiscal deficit. I still remember Arun Ji. We used to listen to him very keenly. We were much young and very inexperienced Members. We used to take points from all of them when they read the Budget – be it Pranab da, Chidambaram Ji or Arun Ji.

There was this FRBM Act, which was brought by Atal Ji's Government. … (*Interruptions*) Yes, Shri Yashwant Sinha. It was under Atal Ji's Government. Thank you, Rudy Ji.

Many a time, we have all discussed that governance is about continuity. There are good things from this Government which we are proud to take and we are happy that we could continue them and perform and deliver superior results for this nation.

(1920/SMN/CS)

So, when your Government brought this FRBM Act, we continued it for ten years where it was decided that three per cent would be the fiscal deficit. Now, 6.9 per cent is what the Finance Minister has agreed to come to. If it was raised from three per cent to 6.9 per cent, have we agreed to it? It is a law which we all continued. I am not such a finance expert. So, this 6.9 per cent is what we have achieved as our fiscal deficit. Have we made those changes in Parliament where Arun Ji had committed to keep it at three per cent? So, just for my inexperience in finance and very limited knowledge of finance, I need to know this because this is connected to the rupees one lakh crore which has been given to the States. So, I am grateful to you for giving this rupees one lakh crore to the States. But I have a small question since my knowledge on finance is not so good. If it is three per cent of fiscal deficit, will the same thing be applicable to the States when they borrow money? It is because you have given rupees one lakh crore to the States.

Now, most of these programmes, which will go through, will be Centre driven - all kendriya yojanas. In PMGSY, you have again changed it to 60:40. Sarva Shiksha Abhiyan, PM Awas Yojana, ICDS and everything, whatever the Centre wants to implement in our State, they will decide how much we have to spend.

Nishikant Ji is sitting here. He was singing the praises of the railway that has come to Godda. We are very happy. If he says it is an aspirational district and it is doing better, we are happy for him. Congratulations. But my friend here Lavu Krishna Ji who is sitting here, was saying that his State needs to give for Railways rupees 6,000 crore. They do not have that kind of money. So, by giving rupees one lakh crore with this fiscal deficit with application of the FRBM Act, and with pushing all these Central programmes, will this rupees one lakh crore really help all our States is my question. You could kindly explain in your reply how it will help our States.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, to the extent that I am responding now, you do not cut the time given to hon. Member.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, that is very kind of you Madam.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I will elaborate during my reply but it is important for a Member. This was mentioned in the Budget but because it is important, I thought I will intervene so that everybody else can also benefit from it. The rupees one lakh crore is being given to the States. It is because we want to speed up infrastructure and capital expenditure over and above what the States have been given under their borrowing limits. So, it is not going to affect their borrowing limits.

Second, there is no interest on this amount. There is no interest being charged because the Centre is giving it and the Centre is giving it for fifty years. They do not have to return it before fifty years and if everything is fine in terms of inflation and even otherwise, after fifty years, what would that rupees one lakh crore be? So, keep that in mind Sir. That is one thing which I wanted to convey, through you, to the hon. Member.

When the State is being given the money, it is nowhere the intention that several of the projects which they would want to complete, they can use this amount in total. We are not saying we give matching grant and you give this much. This is exclusively for you to use fully. So, I thought it was a way in which we are supportive of the States and, therefore, we have given it. So, one, it does not affect you FRBM Act; and two, it does not give you any interest burden; three, you can use it; four, any project which you want to do.

Finally, coming to this question of FRBM and three per cent fiscal deficit during the period of Arun Ji, we honour all that. But that very same FRBM Act has a provision that you can, in case you breach it, you can always come to the House with a deviation statement – any Government which breaches it. I think I can probably say it off the cuff subject to correction, during the UPA Government, several times, it was breached and since you were alert, you would come to the Parliament and say, “sorry, there is a deviation”, and seek the Parliament’s indulgence on it.

Now, deviation and breaching 6.9 this time, I would wonder there is any Member in this House who will have an objection and, least of all, would Supriya Ji have an objection for it. Years of pandemic, one and half years and now, nearly two years, and the only call that I have had from everybody was spend, spend, and that is what is going to give the stimulus. Well taken. We spent. It showed difference. We are spending now. It will show difference and naturally, you will breach the three per cent fiscal deficit and therefore, we go to 6.9 per cent and I do not want anyone to think that oh, this is unusual. The pandemic was unusual. Therefore, 6.9 per cent is a responsible fiscal deficit.

(1925/SNB/KN)

In fact, that is a kind of deficit where we have tried to do enough balancing between keeping up spending and being fiscally prudent … (*Interruptions*)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : सुप्रिया सुले जी की ही बात रिकॉर्ड में जाएगी। *… (Not recorded)*

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Does it apply to the States? I would be thankful if she could let us know about it in her reply later. I will be happy to wait very patiently for that and I appreciate and thank her for being so indulgent.

The other question is about GST compensation. My State has a sum of Rs. 28,365 crore of GST compensation pending. I would like to request the hon. Finance Minister that if they are indulging and giving us so much flexibility, I have two questions. When will all our GST money come? With this, will this 6.9 per cent help us, if you could indulge the States, in more borrowing? I will give you an example of the Pune – Nasik semi high-speed railway. The project has come. We have tried to put some money together. But there is no mention about it in the Budget. So, we do not know where we really stand in such a big project.

The same thing is applicable to all the cesses. I want to make a humble request. Shri Bhartruhari Mahtab ji also talked about cess. Cess is something which actually takes away the revenue from the States. We have no problem if you take it for health and education. I understand that.

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI): Please conclude now.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I will take just two minutes. I will make two small points. I understand that I do not have that kind of time.

You are taking cess for health; you are taking cess for roads. Take CRS as an example. CRS was under Road Transport Ministry which has now been moved to the Ministry of Finance. I did not understand why this change was made. If this cess is collected, is it really for improvement of roads? The C&AG Report, I am not claiming this, said a lot of this cess collected is actually not used for the purpose for which it is being collected. Suppose, if it is collected for education, it is not used for education; if it is raised for health or roads, it is not used exactly for that head.

I do not want to make an allegation against anybody. But this is mismanagement of money, especially, I appreciate what she is saying. It is misappropriation of funds. I am not making an allegation. Madam Nirmala ji, please do not get me wrong. But I just need to know this because we are in a pandemic and States are under a lot of pressure.

The last point I would like to make, I will keep the rest of the points for my next speech, is that the hon. Prime Minister yesterday talked about coal. He was very kind enough. I still remember his speech and for me it is a very painful topic because I still remember that when we sat on that side and they were on this side they really talked about coal mismanagement. I was really pained to learn if that was really true. Eventually what happened is another story. But when we talk about coal, I still remember this Government saying that a sum of Rs. 3 lakh crore is the money that they will raise. Yesterday, the hon. Prime Minister, in his speech in Rajya Sabha, said that they have -- I would have spoken in detail, but I will make it as small and crisp as I can – managed to raise only Rs. 14,000 crore. Where is Rs. 3 lakh crore and where is Rs. 14,000 crore? My numbers could even be wrong. But they have not been able to manage and have not been able to generate the kind of money in coal auctioning. So, when we did it, it was considered as corruption and when they do it and do not get the money, it is okay. This is slightly unfair.

I think, we are all for a transparent and fair system. I wanted to speak much more, beyond coal, about smart cities. So much money is involved in it. But, maybe, I can speak about in my next speech. But I appreciate the efforts of the hon. Finance Minister during the pandemic. All I am requesting her is that the States are under a lot of financial stress. We need the big brother to support us. We are willing to walk an extra mile. I hope, you walk an extra mile so that we grow India together.

Thank you.

(ends)

1929 hours

SHRI PRADYUT BORDOLOI (NAWGONG): Sir, thank you very much for giving me this opportunity.

In November, 2021, the hon. Prime Minister visited Ayodhya and on that occasion 12 lakh *diyas* were lit in Ayodha. But then, in the aftermath of the event, when the dignitaries and VIPs left, moments after that, hundreds of women and children came out and they collected the mustard oil from the *diyas.* That was a very poignant scene. This is what I want to point out because mustard oil was selling at Rs. 265 per litre in Ayodha. When Yogi Adityanath assumed office as the Chief Minister in 2017, the cost of mustard oil was Rs. 70 per litre.

(1930/RU/GG)

But what I am basically trying to tell you is, underneath the façade of pomp and gaiety of monumental structures, statues and central vistas is actually the human cost of economic devastation in India.

Sir, the famous Nobel Laureate, Ronald Coase said: “If you torture the data long enough, it will confess to anything.”

And this has precisely happened in this august House. Even the hon. Prime Minister rattled statistics here saying that inflation was low in comparison to the Congress regime. Even the hon. Prime Minister and the members of the Treasury Bench very conveniently sidelined the Cyclopean unemployment, sky touching price rise and overall downslide of people who live in India.

Sir, starting from the Prime Minister, they have blamed only the COVID-19. But I want to point out that, just the day prior to the presentation of the Budget by the hon. Finance Minister, two very important documents were submitted in this august House. Apart from *The Economic Survey*, the Revised Estimates of National Accounts for 2020-21, the RENA, was also submitted. In that document, I just want to point out that, during the pre-COVID-19 time, in 2016-17, the economic growth of India was 8.3 per cent which came down to 3.7 per cent in 2019-20. This was prior to COVID-19.

The point is that this Government brought down growth to its knees to less than half of the level of 2016-17. In just three years, though there was no drought, no external crisis, no financial crisis, no financial crisis, no Pulwama and not even any act of God, economy went down even in the pre-COVID-19 days.

And after the COVID-19, we all know why it happened. It is because of very reckless action and head down type of action like demonetization and thoughtless implementation of GST in a hurry.

Sir, there is a saying in Assamese: "Hai Ra, Nije Nashibo Najana, Akho Khowa Shuthalkon Bale Beya." That means you are not adept at dancing. You do not have a sense of rhythm. You fumble in every step but you blame the dance floor. And that is precisely happening. It is because you were clumsy, you were sloppy and extremely incompetent due to which the economy of India was going down, and you are blaming the Congress Party for bringing all the havoc in the country. I just want to read out the data recently published by the International Monetary Fund. All the economies of countries went down and slowed down in the aftermath of COVID-19. They have given a list of countries.

As the aftermath of COVID-19, in 2020, the Indian position slowed down in such a level that it got 150th position. It is behind Dominican Republic, Malta, Morocco, Namibia, Bolivia, Republic of Congo, Trinidad and Tobago. Our country was going down and down; and for all these, you blame the Congress Party.

I just want to tell you what Kautilya said 2300 years ago. It is a very famous saying. I just want to quote that.

> "देश की समृद्धि के हित में, राजा को आपदाओं की संभावना का अनुमान लगाने में अध्यावसायी होना होगा, उनके घटित होने से पहले उन्हें टालने का प्रयास करना होगा, जो घटित हो गई हैं, उनसे निपटना होगा, आर्थिक क्रियाकलाप के सभी अवरोधों को दूर करना होगा और राज्य में होने वाली राजस्व हानि को रोकना होगा।"

If you are competent and if you are really efficient, you have to do this and we all know how COVID-19 crisis was handled in this country, and you blame Congress Party for that.

Sir, indeed, there are two Indias now. I want to tell my young friend of the Treasury Bench that there are two Indias. One India is there where you have a very fortunate select few, wealth generators and industrialists who are gobbling up all the generated wealth for themselves and there is another India where the impoverished people who form the vast majority live at the bottom layer of the pyramid.

Sir, for this vast majority of Indian people, the challenge is how to survive the Rahu Kaal, and Amrit Kaal is a distant dream for them. (ends)

(1935/RV/SM)

1935 बजे

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति जी, आपने मुझे बजट, 2022 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो बजट 'आत्मनिर्भर भारत' की नींव है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसे 'आधुनिक भारत' कहा है। मैं बाहर कई मेम्बर्स के भाषणों में यह सुनता रहा कि 35 साल बाद क्या होगा? जब वर्ष 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसकी नींव वर्ष 1857 में रखी गई थी। वर्ष 1857 में धन सिंह कोतवाल, मंगल पाण्डे मेरठ की जेल में, वे दस क्रांतिकारी और अँग्रेजी सेना में जो 50 सैनिक थे, अगर उन्होंने करवट न ली होती तो क्या होता और 90 सालों तक यह युद्ध चला, तब देश 200 सालों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। ये कहते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इन्होंने उसके बारे में कभी नहीं सोचा।

सभापति जी, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि 90 सालों के बाद देश आज़ाद हुआ और आज़ाद करने वाले शहीद लोग जाते समय यह कह कर गए थे कि 'इस देश को रखना मेरे बच्चों सँभाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के'। उन्हें यह नहीं मालूम था कि एक खानदान के हाथों में देश चला जाएगा, देश के लोग मजबूर हो जाएंगे और इतिहास के पन्नों में लोगों को केवल यह सुनने को मिलेगा कि उसी खानदान ने देश को आज़ाद कराया, उसी खानदान ने देश को सब कुछ दिया। वर्ष 1975 की इमरजेंसी में तो इस देश के लोगों ने यहां तक कह दिया था कि 'अरे, इस आज़ादी को जो लोग देकर गए थे, इस शासन पर बैठने वाले लोगों से तो अंग्रेज ही भले थे।' मैं उस समय मात्र 12-13 वर्ष का था। मुझे आज भी याद है। मेरे पिता जी कोई पॉलिटीशियन नहीं थे। वह सीट भी शिड्यूल्ड कास्ट के लिए रिज़र्व थी। वे केवल खनन का कार्य करते थे। गांव के अन्दर आर्य समाज मन्दिर, स्कूल और आज से 70 साल पहले वहां पर जो अस्पताल बने हैं, उन्होंने उसे दान किया था। वे केवल काँग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे, इसलिए मेरे पिता जी को खनन कार्य को छोड़ कर राजस्थान की पहाड़ी में 19 महीनों तक खनन मजदूरों के घरों में रहने को मजबूर होना पड़ा। एस.डी.एम. ने कहा था कि आप चले जाओ वरना जेल चले जाओगे। मेरे बड़े भाई को सीतापुर में ट्रक ले जाकर 19 महीने के लिए वहां व्यवसाय करना पड़ा। मैंने 12 साल की उम्र में यह हाल देखा है, जिसे इस काँग्रेस ने किया था और आज ये तानाशाही की बात करते हैं। आज ये काँग्रेस के लोग सबक सिखाने की बात करते हैं। क्या यह तानाशाही का जीवन है? वर्ष 1975 के समय में लोग सरे आम कहा करते थे कि 'इससे तो अंग्रेज का शासन बहुत बढ़िया था, जो आकर चले गए।' केवज 'संजय विचार मंच' के सदस्य बनोगे तो बचोगे, वरना बच नहीं पाओगे, यह स्थिति इस देश की इन लोगों ने की थी।

सभापति जी, सच्चे मायने में, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जैसा बताया, अभी प्रद्युत जी भी कह रहे थे कि हाँ, दो भारत हैं। इनको नजर ही नहीं आया कि 9 करोड़ गरीबों को 'उज्ज्वला योजना' में गैस कनेक्शंस देकर उनको सम्मानित किया। ये केवल 7-8 लाख मकान दस सालों में दे पाए। अब, तीन करोड़ परिवारों को मकान दे दिए गए।… (व्यवधान)

महोदय, दो भारत हैं। एक भारत वह है जो राजा चलाया करता था, जिसका दामाद बगैर कुछ किए अरबपति हो गया और उस शासन के अन्दर प्रजा एक तरह से उनकी दासी थी। आज के भारत में राजा सेवक है और जनता कर्णधार है। यह आज का भारत है, यह मोदी जी का भारत है कि राजा सेवक है, इसलिए इन्हें दो भारत नजर आते हैं।

सभापति जी, काँग्रेस के शासनकाल में जो पहला भारत था, उसमें 2-जी स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श, सत्यम जैसे दुनिया भर के घोटाले होते थे और 'छाज तो बोले बोले, छलनी बोले।' अभी डी.एम.के. के मेम्बर नहीं हैं। वे कल बोल रहे थे। वे कह रहे थे, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहे, जिन्होंने देश को लूट लिया, तभी तो प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि 'ये लूट रहे थे सपनों को, वे चैन से कैसे सो जाएं।' ये सपनों को, देशवासियों को लूट रहे थे। वे चैन से कैसे सो जाते? आज इनको यह नज़र नहीं आ रहा है। यह भारत है, जिसमें सात-आठ सालों के शासन में आप लोगों के पास एक भी उदाहरण नहीं है कि इस शासन के अन्दर कहीं कोई स्कैम हो, मोदी जी के नेतृत्व में आज वह सरकार चल रही है। पहले केवल स्कैम्स की सरकार चला करती थी।

सभापति जी, यह वही भारत है, दस सालों तक शासन किया मौनी बाबा ने। दस सालों तक कौन चलाता था? माँ-बेटे शासन चलाते थे। पिता ने कहा था कि 'एक रुपया जाता है गरीबों के लिए तो पन्द्रह पैसे पहुँचते हैं, 85 रास्ते में खा लिए जाते हैं।'

(1940/MY/KKD)

अगर पिता की बात मानते तो आप 10 साल में सपने को पूरा कर लेते और उनकी आत्मा को शांति मिल जाती। आप उस भ्रष्टाचार को रोक देते। मनमोहन जी की सरकार में, आप दस साल में उसे नहीं रोक पाए। आप कह रहे हैं कि 7.3 लाख करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से लाभ दिया गया, क्या उसमें किसान सम्मान निधि नहीं है, जिससे डेढ़ लाख करोड़ रुपए बिचौलिए व दलालों से बचाकर, देश के प्रधानमंत्री जी ने उन नौजवान-युवा वर्ग को रोजगार देने का काम किया? इस पैसे से 10 परसेंट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी लाभ पहुँचा, जो सामान्य वर्ग से आते थे। उन लोगों को आरक्षण देकर सुविधा देने का काम किया है। आप केवल इतिश्री करते थे, उसमें वूमेन, एस.सी., एस.टी. और अन्य समाज के लोग थे। इस बजट के अंदर 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी ने इसे चरितार्थ करके दिखाया है।

अभी फारूख साहब भी बोल रहे थे कि बड़ी बेरोजगारी बढ़ गई है। बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, बेरोजगार तो गोगोई जी की पार्टी हो गई। आप बेरोजगार हो गए हैं। वर्ष 2009 में आप 206 थे और वर्ष 2019 में 52 रह गए। आप बेरोजगार हो गए। वर्ष 2009 में बी.जे.पी. 116 थी और अब 303 पर आ गई है। इसलिए, आप बेरोजगार हो गए हैं। देश में बेरोजगारी है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप उसका प्रतिशत निकालेंगे तो 70 साल में वह आपकी देन थी। 70 साल का कूड़ा सात साल में नहीं निकलेगा। इसके लिए जब मोदी साहब को देश और दस साल देगा तब आपको नजर आएगा।

आत्मनिर्भर भारत के साथ ही कौशल विकास योजना है। मैं एक एग्जाम्प्ल देता हूँ, रूडी साहब कौशल विकास मंत्री थे। मेरे यहाँ ओखला में इन्होंने एक कौशल विकास केन्द्र खोला था। वर्ष 2015 में उस कौशल विकास केन्द्र में जो छात्र आते थे, उनकी संख्या दो हजार थी।

आज वहाँ पर 7300 नए नौजवानों कौशल योजना के हिसाब से स्किल्ड हुए है और 76 परसेंट लोगों को प्लेसमेंट दी गई है। मैं यह एग्जाम्प्ल केवल साउथ दिल्ली के ओखला का दे रहा हूँ।

सर, अभी वे कह रहे हैं कि गरीबों के लिए कुछ नहीं किया गया। जब मैं छोटा था तो अपनी माँ के साथ खेतों में जाता था। मैं गाँव का रहने वाला हूँ। पाँच बजे माँ कहती थी कि बेटा, अब मैं घर के लिए निकलूँगी, क्योंकि मुझे कुएं से पानी भरकर लाना है और तुम कटाई करते रहो। आज इस बजट के अंदर 60 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जब नौ करोड़ गरीब परिवारों के घर में नल से जल दिया जाएगा तो किसान व मजदूर खेत में काम करेगा। वह खेत से पाँच बजे नहीं भागेगा और वह सात बजे तक काम करेगा, क्योंकि उसके घर में नल से जल आ जाएगा। इस बजट के माध्यम से उसके काम की हरजाई को रोका जाएगा।

मुद्रा बैंक के लोन के कारण 20 करोड़ लोन दिए गए और 30 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है। आप आरटीआई लगा लीजिए। पप्पू भाई से भी लगवा लीजिए, थोड़ा-सा ज्ञानवर्धन हो जाएगा और पता लगेगा कि रोजगार मिला है या नहीं है। आप आरटीआई के माध्यम से पता कीजिए। आप लोगों में कब तक भ्रम फैलाते रहेंगे? वर्ष 2013-14 में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 1,87,000 करोड़ रुपये थे। आज 7,50,000 करोड़ रुपये है। आप लोग सपने में भी नहीं देख सकते थे। यह पैसा कहाँ से आ रहा है? आप लोग जानते हैं कि रोजगार बढ़ा है या कम हुआ है, इस बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। यह बजट गरीब, मध्यम वर्ग और युवा को मूलभूत सुविधा प्रदान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग की आकांक्षा को पूरा करने के लिए यह बजट दिया है।

आप महँगाई-महँगाई करते रहते हो, वर्ष 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गई थी तो पेट्रोल 37 रुपये लीटर था, डीजल 25 रुपये लीटर था। जब वर्ष 2014 में मोदी जी आए थे तो पेट्रोल 78 रुपये लीटर था और डीजल 62 रुपये लीटर था। दस साल में 37 से 78 किसने किया? अब 78 से केवल 30 परसेंट बढ़ा है और 100 पर आया है। आप महँगाई की बात करते हैं। हमने महँगाई गाना भी सुना है- 'हाय महँगाई तुम कहाँ से आई, तुझे मौत न आई।' यह काँग्रेस के जमाने में घर-घर में गाया जाता था कि हाय महँगाई तुम कहाँ से आई। उन दिनों को आप भूल गए। आप याद कीजिए कि महँगाई कहाँ थी। जी.डी.पी. की वृद्धि दर 6.9 परसेंट से बढ़कर 9.2 परसेंट हो गई। शिक्षा पर 65 हजार करोड़ रुपये से 93 हजार करोड़ रुपये हो गया। विश्वविद्यालय 723 से बढ़कर 1000 बन गए। देश की राजधानी दिल्ली में 45 साल में कोई नया कॉलेज नहीं खुला। अगर पहला कॉलेज खुला है तो मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर खुला है। मैं माननीय फाइनैंस मिनिस्टर से निवेदन करूँगा कि आप उसके लिए 225 करोड़ रुपये जरूर दें। दिल्ली विश्वविद्यालय के तहत वह कॉलेज दिल्ली के नौजवानों के लिए तैयार हो जाएगा। इसे आपने 45 सालों में मंजूर नहीं किया था। इस सरकार ने इसे मंजूर किया है। यह है हमारी मोदी सरकार। आप हमसे क्या बराबरी करेंगे? दस साल में 13.82 लाख घर बनाए थे, माल कहाँ गया? अब इन सात सालों के अंदर तीन करोड़ परिवारों को मकान बनाकर कर दे दिया गया है। यह है, मोदी है तो मुमकिन है। यह है गरीबों की सरकार और गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली सरकार।

(1945/CP/RP)

मैं उज्ज्वला योजना का जिक्र कर चुका हूं। गरीब, वंचित, उपेक्षित, जो रेहड़ी लगाता है, पटरी लगाता है, उस आदमी को साहूकारों के सामने 10 पर्सेंट पर धन लेना पड़ता था। बैंक के अधिकारी अब घर पर जाकर कह रहे हैं कि आइए, स्वनिधि योजना से 10 हजार रुपये का लोन लीजिए। 10 हजार रुपये के लोन पर एक पैसा ब्याज नहीं देना पड़ेगा। वह लोन देश के कम से कम 50 लाख नौजवानों और गरीबों को दिया जा रहा है। जो रेहड़ी, पटरी, फल-सब्जी बेचने वाले गरीब लोग हैं, उनकी व्यवस्था इस सरकार ने की है। आप उसकी क्या बराबरी करेंगे? इस स्वनिधि योजना से 38 करोड़ लोगों के ई-सिम कार्ड बनाने का टार्गेट है। इन लोगों के लिए दो लाख रुपये के इंश्योरेंस की व्यवस्था है। जो लोग प्राइवेट सैक्टर में काम करते हैं, जिनका पीएफ वगैरह नहीं कटता है, अगर उनकी मौत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? ई-श्रम कार्ड बनाने का काम मोदी साहब ने किया है। उनका 2 लाख रुपये का इंश्योरेंस है, उनका 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा है। जो भी सुविधायें हैं, ये उनके खाते में जाएंगी। गरीब लोगों को स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। 60 साल आयु होने के बाद, उन सभी श्रमिकों के लिए 3 हजार रुपये वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था ई-सिम कार्ड के द्वारा की गई है। यह बजट है। आप इसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए।

दिल्ली में 27 पर्सेंट पॉल्यूशन मोदी जी की वजह से कम हुआ है। 15 सालों तक लटकना-भटकना हुआ। ईस्टर्न-वेस्टर्न पेरिफेरल, दोनों का मोदी जी ने शिलान्यास किया। मोदी जी ने मेरठ हाईवे का उद्घाटन कर दिया है। अब एक घंटे में मेरठ जा सकते हैं। सुप्रिया जी सदन से चली गईं, ये अब दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंच सकती हैं। दिल्ली चाहे मीठापुर, ईस्ट से आ जाइए, चाहे महिपालपुर, वेस्ट से जाइए। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में पहुंचाने वाले हाईवे बनाने का काम इस सरकार ने किया है। आप लोगों ने आजादी के बाद 70 सालों में केवल 90 हजार किलोमीटरहाईवेज़ बनाए थे। मोदी साहब ने तो 7 साल में 56 हजार किलोमीटर हाईवेज़ बना दिए। इस बजट के अंदर 36 पर्सेंट प्रोविजन बढ़ाकर रखा गया है कि और 25 हजार किलोमीटर हाईवेज़ बन जाएं। हाईवेज़ के ऊपर किसानों की जमीनें महंगी होंगी, किसानों को उसका लाभ मिलेगा और व्यापारी वहां जाकर बस सकता है। यह है मोदी की सरकार।

किसानों की आय दुगुनी कैसे होगी? वर्ष 2009 से 2014 तक आपका बजट एलोकेशन 88 हजार करोड़ रुपये था। वर्ष 2014 से 2020 में बजट, 4 लाख 87 हजार करोड़ रुपये, यानी फाइव टाइम्स हो गया। यह है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो गरीबों की सरकार है। यह बजट किसानों के लिए 5 गुना बढ़ाया गया। आप कभी जिंदगी में नहीं सोच सकते थे।

एमएसपी पर खरीद के लिए इस बजट के अंदर 1 लाख 56 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। एमएसपी की इतनी खरीद आप लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं की। आपके शासन में गेहूं का प्रोक्योरमेंट 33 हजार था। इस सरकार ने गेहूं का प्रोक्योरमेंट बढ़ाकर 62 हजार किया। धान का पहले प्रोक्योरमेंट 63 हजार होता था, जिसे इस सरकार ने 1 लाख 40 हजार किया है और एमएसपी पर किसानों की फसल खरीदी है।

डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में डायरेक्ट पैसा गया है। अब 85 वाले, आपके नेताजी के, पप्पू जी के पिता जी बेचारे कहते रह गए, वह सपना मोदी जी ने पूरा किया है कि 100 रुपये जाएंगे तो 100 रुपये ही गरीब के खाते में पहुंचेंगे।

महोदय, मेरा 15 मिनट का टाइम था, माननीय राकेश जी ने मुझे इतना टाइम दिया है, इसलिए मुझे 15 मिनट बोलने दिया जाए। आज 42 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो जाता है, 34 साल के लड़के को हार्ट अटैक हो जाता है। किसलिए, पेस्टीसाइड का जो उसमें प्रयोग होता है। इसके लिए प्राकृतिक खेती का प्रावधान किया गया है। नदियों के किनारे 25 हजार किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर चौड़ा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि गंदे पानी को नदी में जाने से रोका जाएगा और नदी के पानी से खेतों की सिंचाई की जाएगी। जो नौजवान आज पेस्टीसाइड युक्त सब्जियां आदि खाकर बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनकी जिंदगी को बचाया जाएगा।

आज दिल्ली के अंदर 27 परसेंट पॉल्यूशन कम कर दिया है। डेढ़ से दो लाख हैवी वाहन बाहर से बाहर निकल जाते हैं, वरना दिल्ली के हजारों लोग दम घुटने से हर साल मरा करते थे। उनका जीवन बचाने का काम किया है, जो अब दम घुटने से नहीं मरते हैं।

महोदय, मैंने मुम्बई कनेक्टिविटी के संबंध में आप सबके सामने बताया। मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं पुन: वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय का जो एक कॉलेज सैंक्शन हो गया, उसकी चारदीवारी हो रही है, यूजीसी के चेयरमैन ने 66 करोड़ रुपये दे दिए हैं, लेकिन उसके भवन में सवा दौ सौ करोड़ रुपए लगेंगे। वह आप मंजूर कर देंगे तो एक ऐतिहासिक काम दिल्ली के लिए हो जाएगा। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय भारत-जय हिन्द।

(इति)

(1950/NK/NKL)

1950 बजे

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, मैं बिधुड़ी जी से पूछना चाहता हूं, इन्होंने सस्पेंस रखा है, ये पप्पू जी कौन थे। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : हनुमान जी, आप अपनी बात रखिए, आपका समय समाप्त हो जाएगा।

… (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, मैं तो पूछ रहा था, हम सब जो सोच रहे हैं, वही पप्पू जी हैं या दूसरा है?

माननीय सभापति (डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी) : आप अपना विषय रखिए।

… (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनिवाल (नागौर): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मेरे से पूर्व पक्ष-विपक्ष के विद्वान सांसदों ने अपनी बात रखी। इस बजट से देश के नौजवानों, किसानों और आम आदमी को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि इस बार का बजट अलग तरह का आएगाा, रोजगार की गारंटी होगी, किसानों का इस बजट के अंदर बहुत बड़ा भला होगा। लेकिन जब बजट पढ़ा गया तो इसके अंदर कुछ विशेष नहीं लगा, आपके दो साल पहले के जो बजट थे, उससे हटकर यह बजट है, प्रधानमंत्री जी का बजट है। हमें नहीं लगता कि 25-50 साल आगे की बात कही गई है, हम वहां तक पहुंच पाएंगे।

सवाल यह उठता है, आपने कहा कि विश्वास का क्या होगा? पिछले 7 सालों में लोगों ने आपके ऊपर भरोसा करके सत्ता में लाए। कांग्रेस के कुशासन से दुखी होकर लंबे समय बाद एनडीए के साथ भारतीय जनता पार्टी को अकेले 303 का बहुमत दिया। इस बार का जो बजट था, उससे नौजवान, किसान और मध्यम वर्ग को एक झटका लगा है। उनको लगा कि बजट हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं है और यह हमें आगे लेकर नहीं जाएगा।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, बजट में वित्त मंत्री जी ने 25 सालों के ढांचागत विकास की रूपरेखा रखी, लेकिन अगले 25 दिन या 25 महीने आम आदमी किस उम्मीद में बिताएगा, इस बारे में बजट किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं देता। पिछले दो सालों में कोरोना काल के अंदर लगाए गए प्रतिबंध, उद्योग और नौकरियों पर बहुत बुरा असर पड़ा, रोजगार खत्म हुए, आधे वेतन पर लोग काम करने को मजबूर हुए, महंगाई बढ़ गई, स्कूल-कॉलेज बंद रहे, जिससे ऑनलाइन पढ़ाई करना विद्यार्थियों की मजबूरी हो गई थी। महामारी के कारण स्वास्थ्य के खर्चों में बढ़ोत्तरी हुई, कृषि कानूनों के विरोध में साल भर तक किसानों को आंदोलित रहना पड़ा, इसका व्यापक असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा। बजट में गति और शक्ति का जिक्र हुआ। बजट में बताया गया कि वित्त वर्ष 2022-23 में 25 हजार किलोमीटर का हाईवे तैयार किए, तीन सालों में 100 नए कार्गो टर्मिनल विकसित किए।

पीएम गति और शक्ति योजना के तहत रोड, रेलवे और वाटरवेज के इन्फ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक विकास पर फोकस किया जाएगा। इतनी बड़ी-बड़ी बातों और योजनाओं में गांव का भारत गुम होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें सरकार कैसे सुनिश्चितता लाएगी?

मध्यम वर्ग ने सबसे ज्यादा आप लोगों को वोट डाले, बजट से उनको निराशा हाथ लगी, इस बजट में उसको अपने लिए करों में राहत की उम्मीद थी। कोरोना काल में आम आदमी रोजगार के लिए जूझ रहा था, लाखों लोग भी चले गए, लेकिन आपने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। वित्त मंत्री जी का आम मध्यम वर्ग के लोगों के लिए संदेश है कि हमने दो साल इनकम टैक्स नहीं बढ़ाया और लोगों पर कोरोना काल के बावजूद टैक्स नहीं बढ़ाया, यह सबसे बड़ी राहत है। लेकिन कोरोना सहित अन्य कारणों से निर्धन और मध्यम वर्ग की जो हालत बनी, उस पर सरकार ने गंभीरता से इस बजट में कुछ नहीं किया।

कृषि क्षेत्र के लिए आम बजट में वर्ष 2022-23 में कुल आबंटन में केवल 4.8 प्रतिशत वृद्धि हुई। जबकि फसल बीमा और किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी को सक्षम करने वाले आबंटन के अंदर भारी कमी की गई है। इतना ही नहीं, बजट में किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें आप बार-बार कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, इस पर पूरी तरह से चुप्पी साध दी गई है जबकि इस योजना की समय सीमा इसी वर्ष 2022 थी।

बजट में कृषि क्षेत्र के लिए वित्त वर्ष 2022-23 में चालू वित्त वर्ष 2021-22 में केवल 5700 करोड़ रुपये की मामूली वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आबंटन 15989 करोड़ रुपये से घटाकर 15500 करोड़ रुपये कर दिया, यह भी चिंताजनक है।

सभापति महोदय, एमएसपी पर जब किसान आंदोलन चला, जब सहमति बनी, किसानों के आंदोलन के चलते भारी दबाव में तीनों कृषि बिल वापस ले लिए। किसानों को एक वायदा किया था, एमएसपी खरीद गारंटी का कानून बनेगा। अभी जो एमएसपी पर खरीद हो रही है, वह 25 क्विंटल से ज्यादा किसान की खरीदी नहीं होती, राइडर लगा हुआ है, आपने इसके अंदर एमएसपी की पूरी बात नहीं की है। जो कमेटी गठित करनी थी, वह भी गठित नहीं हुई।

(1955/SK/MMN)

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, एमआईएस - पीएसएस और मूल्य समर्थन योजना के आबंटन में भारी कमी की गई। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना को केवल एक करोड़ रुपये का आबंटन किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में इसी मद पर 400 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। यह कटौती ऐसे समय में की गई जब किसान संगठनों की प्रमुख मांग है कि फसलों की खरीद के लिए एमएसपी की गारंटी दी जाए। सरकार ने संगठनों को भरोसा भी दिलाया था, लेकिन इस पर अभी कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है।

सभापति महोदय, दस्तावेजों में खाद्य और पोषण सुरक्षा को लेकर विरोधाभासी बात दिखती है। दस्तावेज कहता है कि मिशन का उद्देश्य पोषण सुरक्षा के साथ इन फसलों में आत्मनिर्भता प्राप्त करने के लिए दलहन और पोषक अनाज पर विशेष जोर देना चाहिए, जबकि वर्ष 2021-22 में खाद्य और पोषण सुरक्षा के तहत आबंटन 1540 करोड़ रुपये से घटकर 1395 करोड़ रुपये हो गया।

इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दालों का वितरण करने के लिए खरीदी गई दालों के स्टॉक का निपटान भी करना है।

इसके अलावा मिड-डे-मील, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आईसीडीएस आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए केवल नौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जबकि वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान 50 करोड़ रुपये था और वर्ष 2021-22 के बजट में अनुमानित आबंटन 300 करोड़ रुपये था।

सभापति महोदय, अभी महंगाई की बात चल रही थी। वर्ष 2014 में आप थे, उससे पहले यूपीए सरकार थी। वर्ष 2012-13 में यूपीए सरकार में तेल का अधिकतम प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 140 डॉलर था और यहां 50 डॉलर के आसपास डीजल का मूल्य था और 60 डॉलर के आसपास पेट्रोल का मूल्य था। वर्ष 2014 से कीमतें घटती गईं और ये 20 डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ाते रहे और 50 डॉलर तक बढ़ा दिए, जबकि 80 डॉलर से अभी भी ज्यादा नहीं हैं। आप बहुत बड़ा धोखा देश की जनता के साथ कर रहे हैं। चुनाव आता है तो उस समय आप इसे नहीं बढ़ाते हैं, इसके बाद बढ़ाकर एक रुपये घटा देते हैं।

मेरी माननीय प्रधान मंत्री जी से मांग है कि आप आम आदमी की चिंता कीजिए और महंगाई कम कीजिए। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही चुनाव नहीं हैं, इसके बाद और चार राज्यों में चुनाव हैं। आपको यहां कड़ी चुनौती मिलेगी। आप जिन वादों के साथ सत्ता में आए हैं, देश का नौजवान, किसान, मध्यम वर्ग, भूला नहीं है। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई समीकरण बन जाए और आप सत्ता हासिल कर लें, … (व्यवधान) इसका मतलब यह नहीं है कि वर्ष 2024 में 303 और 308 आ जाएंगे। एनडीए के साथियों ने धीरे-धीरे आपको छोड़ दिया। … (व्यवधान) एक गया, दो गए, तीन गए, चार गए। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON (DR. (PROF.) KIRIT PREMJIBHAI SOLANKI): Hon. Members, the hon. Minister of Parliamentary Affairs will make an announcement.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, I would like to inform the Members that the arrangement for dinner has been made for the Members in Room No.70 and for officers and staff in Room Nos.73 and 74.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): माननीय सभापति जी, अब मैं कुछ सुझाव देता हूं, लगता है ये लोग ज्यादा नाराज़ हो गए।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान के लंबित मुद्दों और सुझावों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार ने ईस्टर्न कैनाल, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया लेकिन बजट भाषण में निराशा ही हाथ लगी। आप इस योजना को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करें, इससे राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे। वहां भारतीय जनता पार्टी के 13 मैम्बर हैं।

आप रेल को सेवा बताते हैं, लेकिन गैर अर्थ क्षम बताकर जब किसी परियोजना को रोका जाता है, तो जाहिर होता है कि आपके रेलवे को सेवा का ज़रिया मानने और कहने में अंतर है। इस वर्ष राजस्थान को रेलवे से जुड़ी परियोजनाओं में निराशा हाथ लगी है, इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, सबसे बड़ी बात है कि रेल मंत्री राजस्थान से आते हैं, इसलिए राजस्थान सहित पूरे देश का ध्यान रखें। विशेषकर राजस्थान और मारवाड़, जो मेरा भी संसदीय क्षेत्र है, आप इसका ज्यादा ध्यान रखें।

कोरोना का नाम लेकर पिछले वित्तीय वर्ष में सांसदों का बजट ले लिया। वैसे तो सरकार में कोई कमी नहीं होती। राजस्थान में विधायकों का बजट बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दिया, लेकिन हमारा पूरा दो साल का बजट ले लिया और हमें केवल दो करोड़ रुपये दिए हैं। मेरी मांग है कि पांच करोड़ रुपये सांसदों को दें। इतने बड़े संसदीय क्षेत्र हैं। आजकल तो लोगों ने सांसदों को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना बंद कर दिया है। कार्ड पर नाम ही नहीं लिखते हैं। पैसा नहीं है तो लोग क्यों बुलाएंगे? (2000/MK/VR)

इसलिए, मैं चाहता हूं कि सांसदों का सलाना बजट कम-से-कम 50 करोड़ रुपये किया जाए, मैं आपसे यही मांग करता हूं। किसी भी क्षेत्र में स्थानीय सांसदों को कमियों या जरूरी कार्यों को जानना आवश्यक होता है। उसके लिए आपने सांसदों के लिए अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं आपकी तारीफ भी करूंगा। दिशा का चेयरमैन सांसद होता है। आपने ही उसमें सांसदों की उपस्थिति दर्ज कराई है। पहले सांसदों को कोई नहीं पूछता था। यह सही बात है, लेकिन कई राज्यों में वहां की राज्य सरकार दिशा की मीटिंग नहीं होने देती है। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है।

सभापति महोदय, मैं आधे मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। डिजिटल शिक्षा और प्रत्येक काम को डिजिटल तरीके से करने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि बीएसएनएल की 4-जी सेवाएं लोगों को नहीं मिल रही हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों में आज भी नेटवर्क का अभाव है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति देखते हुए, अगर देश में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है, तो राजस्थान को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए।

… (व्यवधान)

(इति)

2001 बजे

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपनी पार्टी जेएमएम की तरफ से बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बातों को आगे बढाऊंगा। प्रधान मंत्री जी ने जिक्र किया कि पैंडेमिक के दौरान पूरा देश बहुत मुश्किल दौर से गुजरा। लेकिन, उन्होंने जो प्रेसिडेंट स्पीच पर अपनी बात कही कि विपक्ष लोगों को जाने के लिए बस और पैसे दे रहे थे, यह शर्म की बात होनी चाहिए। उस समय की जो परिस्थिति थी, हमारी स्टेट से जो बिहार के लोग गुजर रहे थे, उनको हम रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना दे रहे थे। पैंडेमिक के समय उन लोगों से पहले ही बोल देना चाहिए था कि आप लोग वापस घर चले जाइए। जितने कामगार हमारे बिहार, झारखंड और बंगाल से हैं, उन लोगों को इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ीं कि उसके लिए हमें माफी मांगनी चाहिए। इस पूरे सदन को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन, यहां उस पर राजनीति होती है। यह बहुत गलत बात है।

2002 बजे (श्री भर्तृहरि महताब पीठासीन हुए)

यह देश डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन, हमारे यहां जो 70-75 प्रतिशत किसान लोग हैं, यदि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो यह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इस देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। आज आप बोल रहे हैं कि आपने रबी फसल का भंडारण किया है, जो यह दिखाता है कि हमारे देश के किसान सक्षम हैं और वे कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। लेकिन, उनकी जो लगातार डिमांड है, जिसको वे कई दिनों से रख रहे हैं और कितने लोग शहीद भी हो चुके हैं, उसके बावजूद भी यह सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है, यह बहुत गलत बात है। आप लोगों को अपने देश के लोगों के लिए इतना दर्द रखना चाहिए।

हमारे कई साथी झारखंड के बारे में जिक्र कर रहे थे कि वहां पर बिजली की कटौती की जा रही है। मैं यहां पर जिक्र करना करना चाहता हूं कि सेंट्रल एजेंसी द्वारा झारखंड की सरकार जो विपक्ष में है, उसको परेशान किया जा रहा है। आप एक बात बताइए कि आप हमारी बिजली काटेंगे, तो हमारे पास जो कोयला है, हम कोयला रोक देंगे, क्या इस तरह से देश चलेगा? देश सेंट्रल और स्टेट दोनों के को-ऑपरेशन से चलता है। लेकिन, जहां विपक्ष है, आप उनको परेशान करेंगे, तो इस तरह से देश और सरकार नहीं चल सकती है। हम भी चाहते हैं कि को-ऑपरेशन हो और सबका काम हो। लेकिन, आप हमारे यहां बिजली गुल कीजिएगा और उसके बाद राजनीति कीजिएगा तो यह बिल्कुल गलत बात है।

कुछ लोग कोयला चोरी की बात कर रहे थे। हमारे यहां स्थिति यह है कि आप जंगल से लकड़ी नहीं लेने देते हैं। आपने कानून बहुत कड़ा कर दिया है। अगर कोई चार बोरी कोयला घर में जलाने के लिए ले जा रहा है, उस पर डंडा बरसाए, तो ऐसा हमारी सरकार नहीं कर सकती है।

यहां पर आवारा पशु की बात हो रही थी। इससे पहले वहां बीजेपी की सरकार थी। वहां पर मवेशी खुली रोड पर घूमते रहते थे। अब हमारे यहां मवेशी हाट खुल गया है। जो भी गरीब, किसान और मजदूर लोग हैं, उनके पास जो भी मवेशी हैं, वे फ्री होकर बेच सकते हैं। उनके घर में जो पैसा जाना होता है, वह जाता है। राजनीति के चक्कर में देश के पशुधन को खत्म मत कीजिए। गाय को राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए, क्योंकि, गरीब लोगों का रोजी-रोजगार और घर पशुधन की वजह से भी चलता है।

मैं कहना चाहूंगा कि हमारे स्टेट द्वारा यूनिवर्सल पेंशन योजना आरंभ की गई है। आज आप बोल रहे हैं कि इतने सारे लोगों को पेंशन दी जाती है। यह बहुत अच्छी बात है। माननीय हेमंत जी की सरकार ने यह पेंशन योजना आरंभ की है। जितने भी 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, उन सबको पेंशन दी जाएगी। 18 वर्ष से ऊपर जितनी भी विधवाएं हैं, उनको भी पेंशन दी जाएगी।

(2005/SJN/SAN)

वहां पर एक साल में गरीब लोगों के लिए 10 रुपये में दो बार 'सोना सोबरन धोती साड़ी योजना' चलती है। हमें केन्द्र सरकार की तरफ से जो राशन दिया जाता है, वह पूरा नहीं पड़ता है, इसलिए गरीबों को अन्न देने के लिए वहां पर 'ग्रीन राशन कार्ड योजना' शुरू की गई है। जो गरीब लोग हैं, उनके लिए 10 लीटर पर 25 रुपये की छूट दी गई है। हमारी सरकार की तरफ से और भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सिर्फ हमारे राज्य में ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएं चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप केन्द्र की योजनाओं में भी उनको शामिल कीजिए।

इस कोरोना काल के बाद लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से आर्थिक बोझ पड़ा है, सभी को दिक्कतें हुई हैं, टैक्स में कुछ छूट मिलनी चाहिए थी, वह बिल्कुल नहीं मिली है। इसलिए देशवासियों को इस बात का दुख है। मुझे लगता है कि आपको जरूर इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कुछ रिबेट दी जानी चाहिए, सभी लोग तकलीफ में हैं। सभी राज्यों पर भी भार है, उनके टैक्सेशन का जो पोर्शन है, वह भी समय पर पहुंचना चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने राज्यों को अच्छी तरह से चला सकें।

मेरे राज्य की तरफ से रेलवे को बहुत सारा टैक्स दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड से कोई भी रेल मंत्री नहीं बन पाता है, इसलिए हमें रेलवे का ठीक तरह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपने बताया है कि आप कई सारी नई-नई ट्रेनें शुरू करेंगे, नई रेलगाड़ी तो छोड़ दीजिए, हम लोग सात सालों से कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज मांग रहे हैं, हमें वह भी नहीं मिल रहा है। आम बजट में रेलवे बजट के सम्मिलित हो जाने की वजह से और भी नुकसान हुआ है। हम लोग रेलवे पर सही तरीके से बोल भी नहीं पाते हैं।

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब) : विजय जी, जब डिमांड फॉर ग्रांट्स में रेलवे पर चर्चा होगी, तब आप उस समय अपना वक्तव्य रख सकते हैं। आपके पांच मिनट का समय पूरा हो गया है।

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल) : सभापति महोदय, मैं एक मिनट का समय और लूंगा।...(व्यवधान) जहां तक जॉब क्रिएशन की बात है, आज सात सालों के बाद 60 लाख जॉब्स की बात की जा रही हैं, इसकी जो संख्या है, मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। आप सात सालों के बाद 60 लाख जॉब्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप सरकार में आए थे, तब आप 2 करोड़ जॉब्स की बात कर रहे थे। आज मनरेगा में जिस तरह से पैसा कम किया गया है, जॉब क्रिएशन कहां से हो पाएगा? आप लोगों को उसको भी देखने की जरूरत है।

मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहूंगा और मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जब आपको लगा कि पेट्रोलियम सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपने पेट्रोलियम मिनिस्टर बदल दिया। हेल्थ सेक्टर अच्छा नहीं चल रहा है, तो हेल्थ मिनिस्टर बदल दिया। रेल मंत्रालय अच्छा नहीं चल रहा है, तो रेल मंत्री बदल दिया। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी चुनाव बहुत अच्छा जिता सकते हैं, लेकिन सात सालों में यह समझ में आ गया है कि वह देश अच्छा नहीं चला सकते हैं। आप कृपया उन्हें बदल दीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। चुनाव का समय है, इसलिए यह समझ में आता है, कांग्रेस और स्वर्गीय नेहरू जी का नाम लिया जा रहा है।

माननीय सभापति : प्लीज कनक्लूड कीजिए।

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल) : महोदय, मैं यह बात समझ रहा हूं, लेकिन स्वर्गीय नेहरू जी को कोसने से आपकी गलतियों की धूल नहीं मिट पाएगी। आप जो गलतियां कर रहे हैं, वह नहीं मिट पाएंगी। अंत में बजट के विरोध में और अंधभक्ति का जो आलम है, मैं उस पर दो लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा -

"आसमां निहारते रह गए, बारिश की उम्मीद में और कोई धोती खोल ले गया।"

(इति)

2008 hours

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I have very little time. So, Madam Finance Minister, can I have your attention? I will speak for only five minutes.

Madam, I invite your attention to paras 63 and 64 of your Budget Speech. You have spoken about ease of doing business. Are you aware that the ease of doing business has been discarded by the World Bank last year? Is it your ignorance? I am reading from the report of the World Bank. It says:

> "After reviewing all the information available to date on Doing Business, including the findings of past reviews, audits, and the report the Bank released today on behalf of the Board of Executive Directors, World Bank Group management has taken the decision to discontinue the Doing Business report."

It is of September 16, 2021. You, as our Finance Minister, were not aware that the World Bank has given up? You should cut out these lines, these words 'doing business'. … (*Interruptions*)

रेल मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्वनी वैष्णव) : दादा, आपके ये संस्कार हैं?…(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह (जबलपुर) : सौगत राय जी, आप ऐसे बात करेंगे? आप इतने सीनियर मेंबर हैं, यह बात करने का कोई तरीका है?...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : सभापति महोदय, ठीक है, मैं आपको एड्रेस करते हुए बोल रहा हूं। बजट में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए।…(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please address the Chair.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I have a short time. … (*Interruptions*)

(2010/SNT/YSH)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Please sit down.

… (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Chairman Sir, on 24th September, 2021, Kaushik Basu said that the Bank announced that it would discontinue the report after an independent investigation by the law firm WilmerHale revealed the Bank's sordid efforts, starting in 2017 to manipulate data in order to improve China and Saudi Arabia's DB rankings. The Bank had suspended publication of the Index last year. And our ... (*Expunged as ordered by the Chair*) does not know that it has been discontinued. It is a matter of some ... (*Expunged as ordered by the Chair*)

Secondly, I would like to draw your attention to the fact that the Finance Minister has talked about increasing CapEx, Capital Expenditure. She wants to pump prime the public investment in order that she can bring in private investment. That is their policy. The Government spends money to build Air India. The Government sells it to Tatas for Rs. 18,000 crore only. This will go on. Even the Government will pump in money to build airports. They will be sold to Adanis. So, pump priming investment means the Government will spend money, the private sector and the favoured ones will get it. The Government will build a port, Adanis will buy it up. This is your idea of private investment.

About this CapEx, she says that Rs. 7.5 lakh crore will be given as capital expenditure. But if you look at the figures, you will see that only the central sector schemes/projects of Rs. 5.58 lakh crore really qualify as capital expenditure for infrastructure and other development purposes. In this, only road transport and highways, and housing are the development and employment generating items totalling only Rs. 2.14 lakh crore. So, the total CapEx projected compared to corresponding figure last year is Rs. 4.76 lakh crore. That means it has gone down by 17 per cent.

HON. CHAIRPERSON: Be conscious of the time. You have only one more minute.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I will complete. I will be very, very brief.

Lastly, I say that of all the Budgets presented by Mrs. Sitharaman so far, this is the best. She has given a Budget in a very difficult pandemic time. I acknowledge that. The economy is just coming back to pre-pandemic levels. Agriculture is at same level; industry and service sectors have come back to that level; but tourism, travel, and trade have received the maximum heat. The Finance Minister has not promised anything for these employment generating areas. And what I asked her earlier, she refused to reply to me. Your fiscal deficit is 6.9 per cent. Your wholesale expenditure has reached double digits. Inflation is there. That is why the common man is feeling the pinch. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, I call the next speaker.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, in one minute I will finish. The number of poor people in the country have doubled. It has reached 134 million. So, this Budget is actually a cruel budget against the poor. The food subsidy has been reduced by 28 per cent. Money allocation of MGNREGA has been reduced. That is the only employment generation programme. It has been reduced.

(2015/SRG/RPS)

Sir, I am ending my speech. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): You are not ending the speech at all.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): We are concerned about these matters, that is why, I am seeking your indulgence.

HON. CHAIRPERSON: No, you already have taken more than five minutes.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): We wanted the Finance Minister repeatedly to give some cash support to the poor. This has been advocated by Shri Abhijit Vinayak Banerjee, the Nobel laureate. The Finance Minister refused to give the cash support to the poor.

HON. CHAIRPERSON: You never know.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): So, the poor are poorer and that is the condition. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, I call the next speaker.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Please allow me to speak the last sentence.

HON. CHAIRPERSON: Okay, last line please.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Let me not have to act like some other Members have.

HON. CHAIRPERSON: You never do that.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Lastly, I want to say this. The IT Minister is sitting next to the Finance Minister. They are talking of digital India. When they talk of these big things, I remember the pictures of migrant labourers walking on the highways after the lockdown, sleeping on the highways, being run over by trains, and not having food to eat. I think that is the progress. We have dealt with our human beings like cattle. The poor have become poorer.

Tagore wrote a long time back:

**Jare tumi niche felo she tomare bandhiche je niche*

Those whom you are putting down, they will pull you towards it.

**Hey more durbhaga desh, jahader korecho apoman*

Oh, my unfortunate country, those whom you have insulted

**apomane hote habe tahader sabar soman*

In the insult, you will have to be equal to all of them.

I end my speech on the Budget, and I hope that the Finance Minister will correct ease of doing business about which … (*Interruptions*) maximum fault..

(ends)

HON. CHAIRPERSON: Do you want to make any point of order?

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर, रूल 353।

सर, इन्होंने मिनिस्टर के ऊपर और कई ऐसे नाम लिए हैं, जो सदन में नहीं हैं। नियम 353 दोनों बातें कहता है, जैसे इन्होंने रेलवे मंत्रालय पर एलिगेशन लगाया या इन्होंने किसी बिजनेसमैन का नाम लिया, वे सभी एक्सपंज होने चाहिए।

HON. CHAIRPERSON: That I will examine.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): यदि कोई भी वक्ता बोलता है तो मंत्री को एडिक्वेट इनफॉर्मेशन दिए बिना, उनके ऊपर कोई डिफेमेटरी एलिगेशन नहीं लगा सकता है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको एक्सपंज कर देना चाहिए।

माननीय सभापति : आपके प्वाइंट ऑफ ऑर्डर में, according to Rule 353 – "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a Member against any person." So, accordingly, Chair will examine it and will take the necessary steps.

Dr. Sanjay Jaiswal.

2018 बजे

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा लाए गए इस बजट का पूर्ण समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी हमें अचानक बहुत बृहद ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो स्वयं मंत्री थे, जिनके जमाने में 400 स्टार्ट-अप्स थे, वे आज 65 हजार स्टार्ट-अप्स बनने के बाद कहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। जिनके जमाने में कुछ राज्यों में ही फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था लागू थी, आज के जमाने में जब दो साल से मुफ्त अनाज लगातार केन्द्र सरकार दे रही, तब इनको लगता है कि यह गरीबों का भला नहीं है। जब इनके समय में इंदिरा आवास योजना में 45 हजार रुपये मिलते थे और आज डेढ़ लाख रुपये मिलते हैं, तब इनको लगता है कि यह गरीबों का भला नहीं है। वे जिस जमाने में मंत्री थे, उस जमाने में इन्हीं के प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कहते थे कि 24 रुपये एक आदमी के पूरे दिन में खाने के लिए पर्याप्त है। उस जमाने में यह साहब मंत्री थे। 24 रुपये में प्रतिदिन खिलाकर इन्होंने सबको अमीर बना दिया था, अब अचानक हम लोगों से ऐसा हो रहा है कि हम लोग हर किसी को कह रहे हैं कि हम आपको डेढ़ लाख रुपये का मकान देंगे, मुफ्त अनाज देंगे, गैस का चूल्हा देंगे, बिजली देंगे तो जाहिर बात है कि यूपीए सरकार के मंत्रियों को लग रहा होगा कि यह सबको गरीब नहीं, अमीर बनाने की योजना है, इसलिए गरीबों को लेकर इनको संकट दिख रहा है।

सभापति जी, सच बात यह है कि यह बजट वाकई 'अमृत काल' का बजट है। जो बात स्वामी विवेकानन्द ने आज से 100 साल पहले कहा था कि आने वाली शताब्दी भारत की होगी, सही अर्थों में यह बजट उनके शब्दों को चरितार्थ करता है। अगर हम बात करते हैं वर्ष 2047 की, मैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस से लेकर अभी तक सुन रहा था, इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि आप आज ही 25 साल आगे की बात कर रहे हैं।

(2020/SPS/AK)

इन लोगों को यह भी समझ नहीं है कि देश दीर्घकालीन योजनाओं से ही चलता है। इन लोगों ने जिंदगी भर, जब 5 साल शासन किया तो 4 साल घोटाले में बिताते थे और 1 साल मुफ्त रेवड़ियां बांटते थे तथा उम्मीद करते थे कि हम फिर सरकार में आ जाएंगे। इनकी तो ऐसे ही पंचवर्षीय योजनाएं चलती थीं। आज अगर हम एक विश्वास की नींव रख रहे हैं और इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि वर्ष 2047 में भारत विकसित देश बनेगा, उसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं तो लोगों को कष्ट हो रहा है।

महोदय, इन लोगों के लिए हमेशा से बजट सत्ता का खेल होता था। इसमें टैक्स बढ़ा दो, उसमें टैक्स घटा दो और जिसको टैक्स बढ़ाना है, उसको पहले से खबर कर दो कि वह बेच दे, जिसमें घटाना है, उसको पहले से खबर कर दो कि वह खरीद ले, बैठे-बैठाए लोगों के पैसे बन जाएं। आज जब हम बजट बनाते हैं तो हम लोग एक स्टेबल बजट बनाते हैं, हर साल ऊंचा-नीचा करने का खेल नहीं चलता है। हम लोगों ने पिछले सात वर्षों में जो भी काम किया है और केवल दो साल की बात करें तो पिछले साल साढ़े पांच लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में और इस साल साढ़े सात लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में हैं। इनकी सरकार में, यूपीए की सरकार में जितना पूरे एक साल का बजट होता था, उतना आज हम केवल प्रधान मंत्री गति शक्ति और कैपिटल एक्सपेंडिचर में व्यय कर रहे हैं।

सभापति महोदय, जब एक बड़ा हाईवे बनता है तो वह केवल एक हाईवे का निर्माण नहीं होता है, उसके कारण न जाने कितने हजारों मजदूरों को रोजगार मिलता है। हजारों लोग, जो बालू का काम करते हैं, कचरा उठाने का काम करते हैं, गिट्टी का काम करते हैं, सीमेंट का काम करते हैं, छड़ का काम करते हैं, इन सबकी जो अलाइड जॉब्स हैं, जो इनके अलाइड उद्योग हैं, उन सबको इससे मदद मिलती है। राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह इन सभी में हम विश्व स्तरीय अवसंरचनाओं का निर्माण कर रहे हैं। इससे न केवल हम वैश्विक बाजार की डिमांड सप्लाई चैन से जुड़कर, प्रधान मंत्री जी ने जो एक सपना देखा है कि विश्व के हर घर में मेड इन इंडिया का एक सामान अवश्य होना चाहिए, उस सपने को चरितार्थ करने वाला यह बजट है। हम पीएलआई के माध्यम से केवल 14 क्षेत्रों में 60 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं और 5 वर्षों में उनका बिजनेस 30 लाख करोड़ रुपए का होगा, लेकिन न जाने हमारे विरोधी दल के नेता किस तरह से बजट सुनते हैं, मुझे यही समझ में नहीं आता है। यह 60 लाख रोजगार के लिए केवल 14 क्षेत्रों की बात हो रही है। इसके अलावा हमने लाखों रोजगार, चाहे वह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, चाहे अन्य क्षेत्र हों, सभी में हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया है।

माननीय प्रधान मंत्री जी स्वयं कह रहे थे कि 27 लाख रोजगार केवल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आए हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने जो एवीजीसी के लिए टास्क फोर्स बनाया है, देश के लिए यह भी आगे के समय में जॉब देने का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा, क्योंकि एनीमेशन, विजुअल इफैक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स यह बिल्कुल नए तरह की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है और इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई है तथा यह दीर्घकालीन योजना है। इसी प्रकार से रेलवे के क्षेत्र में भी 2000 किलोमीटर रेल मार्ग, रेल दुर्घटनाओं को बचाने के लिए कवच संरचना, 400 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, सभी रेल लाइनों का विद्युतीकरण, डबलिंग रेल लाइन जैसी योजनाओं से भारतीय रेल न केवल अत्याधुनिक बनेगी, बल्कि रेलवे में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

महोदय, इसी प्रकार इस बजट में सीजीटीएमएसई स्कीम, अर्थात् क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल एंटरप्राइजेज में जो तीन लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण दिया हुआ है, यह छोटे और लघु उद्योगों के लिए बहुत सारे रोजगार के अवसर देगा। इतना ही नहीं, हमने कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम दी। इसके कारण 1 करोड़ 30 लाख एमएसएमई उद्योगों को न केवल हम बचाने में सफल हुए, बल्कि आगे बढ़ाने में भी सफल हो सके हैं।

सभापति महोदय, एक सौ पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट, इन सब को जोड़ने के लिए 4 नए मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं। ये सभी ऐसी योजनाएं हैं, जो अगले 25 वर्षों में भारत को विकासशील देश से विकसित देश में खड़ा कर देंगी। बैंक की पीएमईजीपी की जो योजना है, अभी माननीय जी बात कर रहे थे की बहुत सारे बिहारी मजदूर आए थे, वह सही बात है, वह त्रासदी हम सभी ने देखी है, लेकिन प्रधान मंत्री जी का जो पैकेज था और जो पीएमईजीपी योजना है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो मैं विरोधी दलों के सांसदों को इनवाइट करता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में चलें। इस तरह के लोगों को पीएमईजीपी के माध्यम से हमने चनपटिया में 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स शुरू किए हैं।

(2025/RAJ/SPR)

जो मजदूर हमारे यहां पैदल चल कर आए थे, वैसे 200 लोगों ने स्टार्ट अप जोन बना कर अपेरल की फैक्ट्री लगाई है और वे लोग 3,000 लोगों को रोजगार दे रहे है। जो कभी खुद मजदूर थे, लेकिन आज वे उद्यमी बन चुके हैं। ये सब कुछ पीएमईजीपी योजना के कारण संभव हो सका है।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी ने 'मन की बात' में जिस प्रमोद कुमार की बात की थी, वह भी हमारे दूसरे प्रखंड का रहने वाला है। वह भी मजदूर आया था, लेकिन आज वह एलईडी फैक्ट्री बना कर उद्यमी बना हुआ है। इस देश में ऐसे हजारों उदाहरण मौजूद हैं, जिन्होंने पीएम योजना के पैकेज से लाभ उठा कर, वे न केवल खुद आर्थिक रूप से सशक्त हुए हैं, बल्कि उन लोगों ने हजारों नए लोगों को रोजगार दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जनवरी में हमारा जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड 1,40,000 करोड़ रुपए हुआ है। हमारा निर्यात 390 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा है। यह बताता है कि कोरोना की परिस्थितियों में सरकार की नीति, नियत और दिए गए पैकेज बिल्कुल सही थे। आईएमएफ का भी मानना है कि इस बार ग्रोथ 9.2 प्रतिशत रहेगा और वर्ष 2022-23 में भी यह आंकड़ा 8.5 प्रतिशत रहने वाला है।

इस बजट का दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में है। हम एक कक्षा-एक टीवी चैनल से आगे बढ़ कर अब दो सौ टीवी चैनल्स पर जा रहे हैं, ताकि अब हर बच्चा, हर रीजनल लैंग्वेज में सारे विषय पढ़ सकेगा। सरकार ने डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है, इससे अनेक युवाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। साइंस-मैथ्स के लिए 750 वर्चुअल ऐप्स, 75 नए स्किल ई-लैब्स, गिफ्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये सभी ऐसी योजनाएं हैं, जो युवाओं को एक नए मुकाम पर खड़ा करेंगी।

सभापति महोदय, पिछले साल भी हमारा स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन ऐतिहासिक रहा और इस साल भी यह बहुत अच्छा है। इसके साथ ही पीएम केयर्स फंड, सीएसआर, उद्योगों एवं पीएसयूज से हजारों करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र में मिले हैं। वे हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र पर अच्छा असर डालेंगे।

रोजगार और शिक्षा के अलावा, गरीबों के लिए 80 लाख नए मकान, दो लाख सक्षम आंगनवाड़ी, कृषि क्षेत्र में 2.37 लाख करोड़ रुपए से एमएसएपी के माध्यम से खाद्यान्न की खरीदारी, गंगा के किनारे पांच किलोमीटर तक ऑर्गेनिक फसलों को बढ़ावा देना, अगर हम सब गरीबों को लिए यह कर रहे हैं, तो अमीरों के लिए भी क्रिप्टो करेंसी पर 30 प्रतिशत टैक्स वसूलना, यह बताता है कि हमारी सरकार और यूपीए की सरकार में क्या अंतर है। हम लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम देश को मजबूत करने, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम आत्मनिर्भर भारत के लिए पूर्णत: संकल्पित हैं एवं श्रेष्ठ भारत ही हमारी सिद्धि है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं कि यह बजट न सिर्फ भविष्योन्मुखी है, बल्कि सर्वस्पर्शी और व्यापक तौर पर समाज के सभी वर्गों के लिए हित कर है।

सभापति महोदय, आपने मुझे इतनी देर तक बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(इति)

2028 बजे

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश किया है, मैं इसके संबंध में सदन में अपनी बात रख रहा हूं। सदन में पहले के भारत और दूसरे भारत की बात हो रही है। हम अखंड भारत की बात करेंगे, जो सावरकर को अभिप्रेत था। भारत का हर नागरिक कोरोना महामारी के बाद आर्थिक रूप से जूझ रहा है। इस बजट से खासकर नौकरीपेशा, व्यवसायी, किसान एवं आम आदमी को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे लोगों में निराशा बढ़ गई है। लोग कोरोना महामारी में लगातार दो सालों से बजट से आयकर रिटर्न में राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस बजट से मध्यम वर्ग को निराशा हुई है।

मोदी सरकार ने कहा था कि वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन सरकार हर कदम पर पूरी तरह से विफल है।

(2030/VB/UB)

आज किसान परेशानी में है। बिन मौसम बारिश और चक्रवात के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। डीजल की कीमत बढ़ने के कारण बीज और खाद के दामों में भारी वृद्धि हुई है, जिसके कारण भी किसान परेशानी में है। अगर गांव या गांव के कई इलाकों में देखा जाए, तो आज भी किसानों को बीज के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, यह स्थिति है। बजट में किसानों की बात होती है, लेकिन पिछले कई वर्षों से आज तक किसानों की परिस्थिति खराब है।

मैं यह बात भी रखना चाहता हूँ कि फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक लाख करोड़ रुपए से अधिक मुआवजा देने की बात कही जाती है। आज भी देश में बहुत-से ऐसे किसान हैं, जिनको उनकी फसलों के बीमा के पैसे नहीं मिलते हैं। यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो किसानों की फसल नष्ट हो जाती है और जब किसान फसल के मुआवजे के लिए आवेदन करता है, तो बीमा कम्पनी किसानों को परेशान करती है। मैंने यह भी देखा है कि जब किसानों की बीमा वापसी की बात होती है, तो बीमा कम्पनी किसानों से केवल चक्कर लगवाती है, लेकिन उनको मुआवजा देने में बिल्कुल सहायता नहीं करती है।

सरकार ने शुरुआत में यह योजना बनाई थी कि कोई भी सरकारी कम्पनी सरकार द्वारा नहीं बेची जाएगी। लेकिन आर्थिक परेशानी के कारण सरकार एलआईसी की हिस्सेदारी बेच रही है, बीपीसीएल की कम्पनी, जो मुनाफे में है, उसे भी बेच रही है।

सरकार किसानों और मजदूरों के लिए काम करने की बात कर रही है, जबकि सरकार कृषि क्षेत्रों को प्राथमिकता देने में विफल रही है। जब हम बजट का अध्ययन करते हैं, तो मनरेगा, रक्षा और जनता के समक्ष आने वाली चुनौतियों का कोई जिक्र इस बजट में नहीं किया गया है। व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों की स्थिति भी बहुत ही निराशाजनक है। वित्त मंत्री जी ने व्यापारियों की पूरी तरह से उपेक्षा की है।

इस सरकार ने वर्ष 2022 तक चार करोड़ घर बनाने का वायदा किया है। सरकार ने इस बजट में 80 लाख घरों के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया है। सरकार द्वारा चार करोड़ घर देने का वायदा भी पूरा होगा या नहीं, यह आगे देखना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत भी राज्यों को अपना हिस्सा समय पर नहीं मिलता है। महाराष्ट्र में इस योजना का हिस्सा न मिलने के कारण कई ग्रामीण इलाकों में पंत प्रधान आवास योजना – ग्रामीण आज भी बंद है।

सरकार ने देश भर में प्रति वर्ष दो करोड़ नई नौकरियाँ देने का वायदा किया था, जबकि वर्तमान में बेरोजगारी बढ़ी है। कोरोना के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। मैं जिस इलाके से आता हूँ, वह 70 प्रतिशत अर्बन इलाका है और 30 प्रतिशत ग्रामीण इलाका है। यदि कोई युवा आता है, तो वह नौकरी की अपेक्षा से आता है। लेकिन बेरोजगारी का डाटा जारी करने वाली संस्था- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक सितम्बर, 2021 के दौरान देश में बेरोजगारों की कुल संख्या 3.18 करोड़ रही। देश के युवा रोजगार की तलाश में इधर-उधर जा रहे हैं। इस समय 1.18 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। पिछले चार सालों में 1.26 करोड़ युवा बेरोजगार हुए हैं। जबकि इस बजट में सरकार ने 60 लाख नौकरियाँ देने का वायदा किया है। आज भी सरकार ने देश के युवाओं को नौकरी देने का वायदा किया है, लेकिन नौकरियाँ नहीं मिली हैं।

(2035/PC/KMR)

माननीय सभापति महोदय, कोरोना के कारण निश्चित रूप से देश में बुरी हालत है। लोगों की नौकरियां गईं, लोग रोजगार के लिए जूझ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में आज जो ऑनलाइन शिक्षा हो रही है, वह नेटवर्क ठीक न होने के कारण, टॉवर्स न होने के कारण बीएसएनएल काम नहीं कर रहा है। इस कारण ग्रामीण इलाकों के बच्चे, जो स्कूल और कॉलेज जाते हैं, वे जूझ रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं अंत में केन्द्र सरकार से और खासकर वित्त मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि गैर भाजपा सरकार का बकाया, जैसे जीएसटी का बकाया महाराष्ट्र सरकार को देना बाकी है। अत: ऐसी गैर बीजेपी सरकार के राज्यों को बकाया दिया जाए, जबकि सभी राज्य केन्द्र सरकार को आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, निश्चित रूप से उसमें ये जो सब खामियां हैं, उन्हें आगे चलकर दूर करने की आवश्यकता है। जो राज्य अधिक रूप से केन्द्र सरकार को आर्थिक सहायता करता है, उस राज्य को ज्यादा से ज्यादा सहायता मिले और खासकर महाराष्ट्र राज्य को यह सहायता मिले।

सभापति महोदय, मुझे अपनी बात को रखने की अनुमति देने के लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं।

(इति)

2036 बजे

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहां बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के विचारों को रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को भी आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े ही संक्षेप में अपना वित्त भाषण दिया। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब) : आपको मालूम है कि आपके पास बोलने के लिए मैक्सिमम पांच मिनट हैं?

... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : हां, सर।

उन्होंने बड़े ही संक्षेप में अपना भाषण दिया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि, भारतीय अर्थव्यवस्था भारी संकट से गुजर रही थी और उससे कुछ उबरकर सामने आने का काम कर रही है। जैसा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2019-20 के समकक्ष जो हमारा ग्रोथ लेवल था, आज उस पर पहुंचकर और लगभग एक प्रतिशत की बढ़ोत्तरी और देखने को मिल रही है। यह काबिल-ए-तारीफ है। इस महामारी का सामना पूरे देश की अर्थव्यवस्था ने बड़ी कठिनाइयों के साथ किया है और अब बेहतर दिनों को देखने के आसार हमें लग रहे हैं।

जहां कन्ज़्यूमर डिमांड अभी भी अप्रत्याशित रूप से गिरी हुई है, हमारा मानना है कि इसको सुधारने के लिए देश में रोजगार के जो अवसर एमएसएमईज़ से आने की जरूरत थी, उन एमएसएमईज़ को सहारा न देकर इस सरकार ने इन एमएसएमईज़ के साथ घोर अन्याय करने का काम किया है। मैं यहां पर एक शेर जरूर कहना चाहूंगा, जो उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत प्रचलित है -

हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब,
हम जब कब्रस्तान से भी गुजरते हैं, तो मुर्दे भी उठकर पूछते हैं कि भाई, लगी क्या नौकरी?

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सबसे पहले वित्त मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि देश में भारी रोजगार का संकट भयानक रूप से अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने 60 लाख नौकरियों को सृजित करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्स हैं, उनके जरिए ये नौकरियां सृजित होंगी। लेकिन अगर इंडियन इंक की हम बात करें, जो इन प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्स का फायदा लेती हैं, उनका यह कहना है कि ये प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्स कन्ज़्यूमर डिमांड पर आधारित हैं। वे जो सामान प्रड्यूस करेंगे, उसको भी सरकार प्रोडक्शन से लिंक करके यह कहती है कि यदि आप उसको एक निर्धारित रूप से प्रड्यूस नहीं करेंगे, तो उसके लिए आपके ऊपर पैनाल्टीज़ लगाने का काम होगा।

(2040/IND/RCP)

महोदय, ये पैनल्टीज इतनी भारी हैं कि बड़ी-बड़ी देसी कम्पनियां इन प्रोडक्ट्स को लेने से या इनमें निवेश करने में अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। इस हिसाब से 60 लाख नौकरियां सृजित होने का काम होगा, यह अभी भी एक ख्याली पुलाव है। यह हेडलाइन बटोरने का एक प्रयास करने का काम हुआ है। असल में भारत में उपभोक्ता डिमांड में गिरावट बेरोजगारी और वेतन की अस्थिरता से हुई है। पिछले दो सालों से वेतन बढ़ाने का काम नहीं हुआ है और बेरोजगारी व्यापक रूप से फैल चुकी है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह से विफल हो चुकी है। पीआईएल जैसी स्कीमें जो बड़ी-बड़ी कम्पनियों को सहायता देने के लिए सामने रखी गई हैं, वहीं लघु और मध्यम उद्योग जो देश के करोड़ों श्रमिकों को रोजगार देते थे, उन्हें पर्याप्त सहायता देने का सरकार ने काम नहीं किया है जिसकी वजह से ये उद्योग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इस महामारी के दौरान लघु और मध्यम उद्योगों के बंद होने के बाद उनका मार्केट शेयर बड़ी कम्पनियों ने ले लिया है, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जो छोटी कम्पनियां थीं, वे पूरी तरह बंद हो गई हैं और उनका जो मार्केट शेयर था, उसे बड़ी कंपनियों ने ले लिया है और आज सरकार ढिंढ़ोरा पीटकर कहती है कि हमारी कम्पनियां बहुत बेहतर कर रही हैं। उसका कारण यह नहीं है कि उनके गुड्स की क्वालिटी अच्छी हो गई है या उनकी मांग बढ़ गई है, बल्कि उसका कारण यह है कि छोटी कम्पनियां जो उन चीजों को बनाने का काम करती थीं, वे बंद हो गई हैं और उनका मार्केट शेयर इन बड़ी कम्पनियों के पास पहुंच गया है और यह सरकार की विफलता से पर्दा हटाने का काम करती है। यह अत्यंत दुखद है। महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे करोड़ों श्रमिकों को एमएसएमई का फायदा नहीं हो रहा है। यदि आप डिफेंस में देखें तो आपको पता चलेगा कि जल, वायु और आर्मी की जो डिमांड्स थीं, उनके हिसाब से यह बढ़ोतरी काफी नहीं है और उसी के साथ-साथ यदि आप इन्फ्लेशन को देखें तो यह बढ़ोतरी एक हिसाब से नगण्य है।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने जीडीपी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पर मात्र 0.7 प्रतिशत खर्च किया है। यदि आप अमरीका को देखेंगे, तो वहां 3.1 परसेंट खर्च करता है। ब्राजील 1.3 परसेंट और चीन, जिससे हमें सबसे ज्यादा खतरा है, वह 2.2 परसेंट खर्च करता है। मेरा मानना है कि वित्त मंत्री जी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का शेयर बढ़ाना चाहिए था और करीब दो परसेंट होना चाहिए था, तभी फायदा हो सकता है।

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब): आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि हमारी महिलाओं और बच्चों को पोषण देने की बात है, वहां इस सरकार ने इस विषय पर बजट को बढ़ाने का काम नहीं किया है। इसके लिए जो फंड्स दिए जाते थे, उन्हें क्लब करके एक हेड के अंदर करने के बाद भी ऐसा प्रतीत होता है कि जो खर्चा होना है, वह पूरी तरह से कम हो गया है। गरीब बच्चों के लिए, जो दलित अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, अल्पसंख्यकों के बच्चे हैं, शोषित पीड़ित वर्ग के बच्चे हैं, उनके लिए घोर अन्याय है क्योंकि उन्हें पौष्टिक आहार न मिलने की वजह से सामान्य अवसर भी नहीं मिल पाते हैं। मैं आखिर में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा

"अपनी गुरबत की कहानी हम सुनाए किस तरह
रात फिर बच्चा हमारा रोते-रोते सो गया।"

साहब, मुझे यही आपके माध्यम से कहना है कि जो कुपोषण हमारे देश में फैला है, दलितों, मजलूमों के ऊपर जो संकट है, आज पोषण का बजट घटाकर सरकार ने उनके साथ बेहद अन्याय किया है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

(इति)

2043 hours

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Thank you, Chairman, Sir. The previous day, we heard the hon. Finance Minister's speech and the hon. Prime Minister's speech.

Nirmala *ji*, you are a very good orator and always, your presentation is very good. But I am sorry to say that your Budget and Budget speech is disappointing us. We hope more from the hon. Prime Minister. But the Prime Minister's speech is more disappointing. He shared most of his time to criticise and blame the Congress Party and the Congress leaders. It is high time that the Prime Minister of our country learnt history to refrain from speaking historical blunders that bring shame to the people of India.

Ignorant of the history of the Indian Independence movement that saw the Hindutva movements of the period trying to divide the country communally, in his speech, the hon. Prime Minister blamed the Congress that Congress is dividing the country. That is his main argument. Modi blames Congress. But I can say, the truth is that Congress always stood for upholding the motto of One India, One Nation.

(2045/RK/KDS)

One Nation, One India is not a mere slogan to us; it is the pulse of INC. It is an emotion for the Congress workers. Modi ji is not saying this because he has forgotten history, but because he has hardly learnt the Indian history.

Through provocative hate speeches, that are often blunders too, unfortunately the ... (*Expunged as ordered by the Chair*) of the country is trying to bring conflict between the States and the religions. Congress and Gandhiji were always against division, whereas the Britishers followed the theory of divide and rule, about which Modi ji is ignorant. The ... (*Expunged as ordered by the Chair*) supported the British idea of making this country a *Hindu Rashtra.*

... (*Expunged as ordered by the Chair*) who belongs to a group that betrayed even the Quit India Movement… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Shri Benny Behanan, please speak on the Budget.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): I am coming to the Budget.

HON. CHAIRPERSON: Please come to the Budget.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY):They are trying to teach us patriotism. In contrast, the Indian National Congress has always stood for it. I would like to say that Modi ji need not waste time trying to teach us patriotism because it is nothing but asking whether sandal has an inherent fragrance.

I will now come to the Budget. The Budget was presented before the august House when the Indian economy was facing its biggest crisis. The demonetisation has already shattered the very foundation of our financial security. Moreover, the outbreak of COVID-19 aggravated the crisis like a devastating thunderbolt. All these resulted in the worst growth rate of the economy, which is clear from the Economic Survey released by the Government.

Sir, with this Budget, the hon. Finance Minister dreams of development that may go on for over 25 years. But what is the present position of our country? The common man is worried about his daily bread. If the Government is not ready to take up the real issue faced by the common man, the Government will have to face the consequences.

The Government describes that it is a digital Budget. During demonetisation, a Chinese company like Paytm had gained enormous profits. Similarly, this digital Budget, which has been celebrated here, opens the public treasury to the global multinationals. It is like the Government is… *(Not recorded)* digital currency into the country.

A few days before in a global meeting, the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji announced that the global leaders were going to join hands against digital currency. Here, our Finance Minister has come up with a digital Budget that will recognise cryptocurrency by imposing -- doing a blunder of imposing -- a tax on the income from smugglers. A multinational company like … *(Not recorded)* has already started advertising cryptocurrency two months before the Budget. This is a clear evidence of the Government's actual intention to help the monopolists and smugglers.

The joke is that our Finance Minister began her Budget speech by being proud of selling the country's public sector undertakings. The Government has sold out public sector companies like Air India, insurance companies, BPCL, and will sell off even the most significant public sector company like the Indian Railways. The Government is least bothered about the country's poor people, and instead kills the goose that lays the golden eggs.

Not only the economist, but also the common man knows that to overcome this financial crisis, the best thing is to make more money available in the hands of the common man. All nations are already following it when they are facing economic recession. This is called the Keynesian Theory. On the other hand, our Government is taking away money from common man's pocket, which is like *… (Not recorded)* them.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY):Agriculture is the backbone of the country. The Government has completely ignored it. The health sector has also been largely neglected in the Budget. Nothing has been set aside in the Budget to benefit those who have lost everything in COVID. Coming to the Railway Budget, I would say that Kerala has been wholly neglected.

(2050/PS/CS)

The Central Government is taking the position that Kerala is not on the map of the Indian Railways. Kerala's total allocation is Rs. 1085 crore, while the States of Andhra Pradesh and Telangana have got more.

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Please conclude.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Yes, Sir. I am concluding. Sir, just a token sum was allotted for the Sabari route and Palakkad Coach Factory.

What is the basic structure of our country? It is secularism and democracy. These are the pillars on which our nation is built on. But this Government has totally demolished these pillars.

Sir, please give me one minute. What is the backbone of our economy? It is agriculture and public sector undertakings. On the one hand, the Government is selling the Navratna companies … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Your point is already taken. Now, I am calling the next speaker.

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): On the other hand, the farmers are crushed to death under tractors. Please give me one minute. It is a shame that the Government had to witness the son of a Minister firing bullets on the innocent farmers.

The Government is destroying the fundamental structure and economic security of the country. Hence, I strongly oppose this Budget. Thank you.

(ends)

2051 बजे

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमारी माननीया वित्त मंत्री जी यहाँ पर विराजमान हैं, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद दूँगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने एक दूरदर्शी और विजनरी बजट पेश किया है। हमें पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि यह बजट दूरदर्शी, विजनरी है और इस बजट को अगर हम देखें तो साफ जाहिर है कि इसका पूरा फोकस ग्रोथ पर है। इसका पूरा फोकस गरीबों के वेलफेयर पर है। इस बजट के द्वारा जो डेवलपमेंट दिखाये गए हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलपमेंट को देखा जा रहा है। अगर हम पूरे बजट को ध्यान से देखें तो इसकी चार प्राथमिकताएं हैं। इसकी पहली प्राथमिकता पीएम गति शक्ति है; दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट है; third one is Productivity, Enhancement and Investment, Sunrise Opportunities, Energy Transition, and Climate Action; and fourth one is Financing of Investments. अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यह बजट कोई एक साल का नहीं है, यह बजट आधारशिला है। इस बजट के द्वारा जो नींव रखी गई है, वह अगले 25 सालों के लिए रखी गई है। इस बजट को इसीलिए विजनरी बजट कहा जा रहा है। जब बजट पेश किया गया तो उस समय पूरे देश में, नॉर्मली जब होता है तो इतना क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन धीरे-धीरे विपक्ष के साथियों को भी यह बात समझ में आने लगी कि वास्तव में यह बजट विजनरी है और यह बजट अगले 25 सालों के लिए एक फाउंडेशन है, एक आधारशिला है। नॉर्मली जो बजट होते हैं, वे पॉपुलिस्ट होते हैं। वे पॉपुलिस्ट होते हैं या इलेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, इलेक्शन को ध्यान में रखकर किया जाता है कि पार्टी को फायदा कैसे होगा। आज तक बजट रखे जा रहे थे तो उस हिसाब से रखे जा रहे थे, लेकिन पिछले 7 सालों में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार इसमें कदम उठाए हैं और जो एक रोड मैप देश का बनाया है कि बजट जो है, पार्टी का फायदा नहीं, वास्तव में उससे देश को फायदा कैसे हो, देश का डेवलपमेंट कैसे हो और हमारी जो इकोनॉमी है, जिस हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज की हम बात कर रहे हैं। इस बजट से पूरा हम देखते हैं कि एक फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यह अपने आपमें एक बहुत बड़ी बात है। ज्यों ही हम अलग-अलग सेक्टर देखेंगे कि अलग-अलग सेक्टर में फॉर्मूलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात कही है। जहाँ पर हम फॉर्मलाइजेशन की बात करें, वित्तीय वर्ष 2018 में सिर्फ 48 परसेंट था और अब फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो है, वह जीडीपी का लगभग 80 प्रतिशत है और 20 परसेंट इनफॉर्मल सेक्टर हैं। मैं मानता हूँ कि एग्रीकल्चर सेक्टर में केसीसी की वजह से सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर 72 से 75 परसेंट ही रहा है। जब हम फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो जिस हिसाब से भीम ऐप, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक यूपीआई प्लेटफॉर्म 30.12.2016 को लांच किया और हम जगह-जगह देखते हैं कि चाहे ठेले वाला हो, चाहे सब्जी की दुकान वाला हो, चाहे राशन की दुकान वाला हो या छोटे से छोटा व्यापारी हो और उसके यहाँ क्यू. आर. कोड लगा रहता है।

(2055/KN/SMN)

डिजिटल पेमेंट के बारे में विपक्ष के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया था। भारत में जहां इतने अशिक्षित लोग हैं, गाँव वगैरह में हम क्या डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं? वर्ष 2016 में मोदी जी का विजन और सोच थी कि देश में जब तक डिजिटल इकोनॉमी डेवलप नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। यही कारण है कि अमेरिका जैसा देश, जिसको पेंडेमिक के वक्त अपने लोगों को पेमेंट देनी थी, वह सिर्फ 50 लाख लोगों को पेमेंट एक सप्ताह में कर पाया। हमारा आधार का बेस भी बड़ा जबर्दस्त है, जन-धन के एकाउंट्स खुले हुए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हैं, प्रधान मंत्री मोदी जी का जो टेक्नोलॉजी का विजन है, उस वजह से यह सम्भव हो पाया है। आज हम कहीं भी देखें, डिजिटाइजेशन का उपयोग खास कर गाँव में बहुत जबर्दस्त हुआ है। इससे इस सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है। जब ये एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अन-ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी है। खास कर ये सारी एक्टिविटीज डिजिटाइजेशन से है, इससे अन-ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है।

हम जब फार्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी का अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष 2014 में माननीय मोदी जी ने जिस हिसाब से रूरल कनेक्टिविटी के लिए स्पीड से काम किया, मैं मानता हूं कि जो आइडिया कंसीव हुआ है, जो रूरल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वह वर्ष 2009 में कंसीव हुई। लेकिन उस समय यह प्लान किया गया कि तीन साल के अंदर-अंदर रूरल कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए। लेकिन वर्ष 2012 तक 2 लाख 60 हजार ग्राम पंचायतों में से, वर्ष 2013 तक, सिर्फ और सिर्फ 59 ग्राम पंचायतों को ब्रॉड बैंड से कनेक्ट किया गया। वे लोग 2जी स्कैम वगैरह में रहे हैं, उनका विजन यह नहीं था कि देश में डेवलपमेंट आगे बढ़े। प्रधान मंत्री मोदी जी के विजन और सरकार की स्पीड से ऑप्टिकल फाइबर करीब दो लाख 60 हजार ग्राम पंचायतों में और सात लाख 50 हजार विलेजेज में जो ले-डाउन करनी है, उसमें से वर्ष 2014 से 2021 के बीच में, वर्ष 2014 के पहले जहाँ सिर्फ 59 थी, लेकिन अब 1 लाख 60 हजार ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है और दो लाख 80 हजार गाँवों में पहुंच चुका है।

अब हम 5जी स्पैक्ट्रम के ऑक्शन की बात करें। यह देश के लिए आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बात है। जब तक डिजिटल इकोनॉमी और हमारी जो इकोनॉमी है, उसका फॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तब तक देश बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। यह सोच प्रधान मंत्री मोदी जी की है कि हर गाँव में वाई-फाई, हॉट स्पॉट हो, पीएम वाणी हो, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट हो और उसका सबसे बड़ा फायदा रूरल को मिलेगा। अभी कांग्रेस के मित्र यह बता रहे थे, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि दो भारत हैं। आज दो भारत नहीं हैं, दो भारत लम्बे समय तक आपने खड़े कर रखे थे। हमारी सरकार ने ब्रिज और सेतु बनाने का काम किया। मैं मानता हूं कि उसमें डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है।

आज हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करें, तो हमारे ग्रामीण इलाके में क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी। उस क्वालिटी एजुकेशन की वजह से... (व्यवधान) सर, मेरे दस मिनट हैं और पाँच मिनट हुए हैं। मेरे पाँच मिनट और बाकी हैं।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्री भर्तृहरि महताब): आपके नौ मिनट हो चुके हैं।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मुझे यह कहा गया कि आपको 15 मिनट मिलेंगे। मेरे दूसरे साथियों ने कह दिया, इसलिए मुझे पाँच मिनट और बोलने दीजिए।

माननीय सभापति : पीपी चौधरी जी, आप वकील हैं। आपको किसने क्या कहा, यह मुझे पता नहीं है। आपके नौ मिनट हो चुके हैं और एक मिनट बाकी है।

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सर, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जब तक मैं ठीक बोलता हूं, तब तक आप मुझे बोलना देना, अन्यथा मुझे रोक दीजिएगा।

जो दो से तीन करोड़ जॉब्स हैं, इससे जनरेट होंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि हम जीएसटी की बात करें, तो यह अटल विहारी वाजपेयी जी का ब्रेन चाइल्ड था। कांग्रेस ने वर्ष 2009 में कहा कि हम 1 अप्रैल, 2010 तक इसको इम्प्लिमेंट कर लेंगे। हमने उनको सपोर्ट किया।... (व्यवधान)

(2100/SNB/GG)

HON. CHAIRPERSON (SHRI BHARTRUHARI MAHTAB): Hon. Members, I have to make an announcement. It is 9 o'clock now. If the House agrees, we can extend the time of the House for discussion on the Budget till 10 p.m.

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, yes.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): हमने उनको जीएसटी बिल के लिए सपोर्ट किया, लेकिन कांगेस के नेता उसके इम्पिलिमेंट के लिए प्रॉब्लम थे। उस समय वह इम्पिलिमेंट नहीं हुआ, लेकिन जीएसटी की वजह से जनवरी, 2022 में 1,40,000 करोड़ रुपये, जो कि हम अभी तक का हाइएस्ट कह सकते हैं, इतने रेवेन्यू का जनरेशन हुआ। जहां तक हम बात करें हर घर नल से जल की, तो यह कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। मैं वेस्टर्न राजस्थान से आता हूँ, मेरे लोक सभा क्षेत्र में भी दूर-दूर ढाढियां हैं, जहां महिलाएं अपने सर पर मटका या घड़ा रख कर दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर तक पानी ले कर चलती थीं और उनका आधा दिन उसी में खराब हो जाता था। प्रधान मंत्री मोदी जी ने वर्ष 2024 तक हर घर को नल से जल देने का प्रावधान रखा और उसके लिए 60 हजार करोड़ रुपये का बजट रखा। ... (व्यवधान) सर, जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, वर्ष 2014-15 से पहले तो सिर्फ तीन किलोमीटर ही सड़क बनती थी। वर्ष 2014-15 में 12 किलोमीटर से बढ़ कर वर्ष 2021 में 37 किलोमीटर प्रति दिन और वर्ष 2022-23 में इससे भी ज्यादा बनने के चांसेज़ हैं। लेकिन 4,410 किलोमीटर वर्ष 2014-15 में और 13,327 किलोमीटर वर्ष 2021 में और 25 हज़ार किलोमीटर प्रति वर्ष अबकी बार बजट में टारगेट है। कहने का मतलब है कि काम के साथ-साथ स्पीड और क्वालिटी से काम हो रहा है। ... (व्यवधान) जब हम प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो गांवों में पहले कनेक्टिविटी के नाम पर कुछ नहीं था। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: आपकी बात पूरी हो गई है। यह सारा रिकॉर्ड में आ गया है।

... (<u>व्यवधान</u>)

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): आज 100 किलोमीटर प्रति दिन सड़क गांवों में बन रही है। मैं भारत माला के बारे में कहना चाहता हूँ। रेल मंत्री जी यहां पर हैं, मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि ये 400 वंदे भारत ट्रेन्स अगले तीन सालों में चलाएंगे। खास कर पाली लोक सभा क्षेत्र में भी इसका बड़ा फायदा होगा, क्योंकि वहां पर फ्रेट कॉरिडोर के लिए डेडिकेटिड लाइन अलग बनी है। वहां पर सभी समस्याओं का इससे हल होगा। … (व्यवधान) सर, मैं पीएम आवास के बारे में कहना चाहता हूँ। गरीब कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे मकान मिलेगा। सर, मैंने एक ऐसा वीडियो देखा, जिसमें घूमंतू जाति के लोग बाहर बैठे थे। उस समय उन्होंने कहा कि … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप कनक्लूडिंग लाइन बता दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सर, एक मिनट में फिनिश कर रहा हूँ। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि देखिए, प्रधान मंत्री मोदी जी का धन्यवाद हो कि हम खुले आसमान के नीचे बैठे थे, बरसात, गर्मी और सर्दी में ऐसे ही बैठे रहते थे, लेकिन मोदी जी का धन्यवाद हो कि हम तो हजारपति भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमें लखपति बना दिया और हमें घर दिया। प्रधान मंत्री मोदी जी के बारे में आम जनता में यह भावना है। इस बजट में देखें तो चाहे गरीबों के लिए आवास योजना हो, चाहे किसी तरह के सैक्टर में भी देखें तो वेलफेयर गरीबों की तरफ है। … (व्यवधान) मेरे साथी कहते थे, ये तो सिर्फ ग्रोथ की बात करते हैं, वैलफेयर की बात नहीं करते हैं। यह बजट ग्रोथ के साथ वेलफेयर की भी बात कर रहा है। … (व्यवधान)

सर, मैं लास्ट पॉइंट एग्रीकल्चर के बारे में बोल कर अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं किसान परिवार से हूँ। मैं स्वयं किसान रहा हूँ, इसलिए यह बात तो मुझे बतानी पड़ेगी। सर, जहां तक एमएसपी की खरीद की बात है, किसानों को अगर भड़काने का काम ये लोग कर रहे हैं, तो मेरे लोक सभा क्षेत्र का किसान जानता है, उनको पता है कि एमएसपी के 2,37,000 करोड़ रुपये डायरेक्ट किसानों के खातों में जाएंगे। यही नहीं, हजारों किसानों को कैश भी दिया जा रहा है। मैं नटशैल में यह बताना चाहूंगा, दो बात और कह कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि एम्पलॉयमेंट जनरेशन एग्रीकल्चर में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, या मैन्युफैक्चरिंग में हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में हुआ है। … (व्यवधान) सर, पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग में डिसइनवेस्ट की बात आई। सन् 1971 में चाइना और इंडिया की सेम ग्रोथ रेट थी। चाइना ने अपनी इकोनॉमी सन् 1974 में ओपन की। कांग्रेस वाले चाइना की बात करते हैं, उनके बड़े प्रशंसक हैं। … (व्यवधान) ये कुछ तो उनसे सीखें। उसने सभी सैक्टर्स को प्राइवेटाइज़ कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, उनका एम्पलॉयमेंट बढ़ा। हमारी सरकार जब एयर इंडिया का प्राइवेटाइज़ेशन कर रही है तो ये लोग उसकी खिलाफ़त कर रहे हैं।… (व्यवधान) नहीं तो उसमें हर साल 6,000 करोड़ रुपये पंप करना पड़ता। यह बड़ा लॉस था। वही पैसा गरीबों के लिए काम आएगा। … (व्यवधान) सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। … (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : आपने 15 मिनट बोला है।

(2105/RU/RV)

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Dr. Thol Thirumaavalavan in Tamil,
please see the Supplement. (PP 225A to 225C)}

2106 hours (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

(2110/MY/SM)

2110 बजे

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): सभापति महोदय, मैं इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमसे पहले बहुत से विद्वान वक्ताओं ने अपना विचार व्यक्त किये हैं। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए, सबसे पहले अपने राज्य बिहार के लिए कुछ जरूरी माँगें रखता हूँ।

नीतीश बाबू की अगुवाई में बिहार सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले- यह इच्छा बिहार के प्रत्येक निवासी की है। क्योंकि, बिहार के विभाजन के बाद और झारखंड के अलग होने के बाद, बिहार में रेवेन्यू का सोर्स बहुत ही कम हो गया है। मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की माँग करता हूँ। इसके लिए कई सांसदों ने भी माँग की है। बिहार विधान सभा और विधान परिषद से भी इसकी माँग की गई है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से वह विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा होगा। इसलिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस पर विशेष विचार किया जाए।

महोदय, पिछड़े वर्ग को उनका हक और समृद्धि देने के लिए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि जातीय जनगणना अविलंब कराई जाए। स्व. कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। इसकी रिकमेंडेशन बिहार विधान सभा और बिहार सरकार ने पहले ही की है। मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूँ और मेरी केन्द्र सरकार से विनती है कि जननायक स्व. कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न अविलंब दिया जाए।

सभापति महोदय, अब मैं अपनी बात इस बजट के संबंध में रखता हूँ। यह देश के लिए बहुत अच्छा बजट है। इस बजट में अगले 20 वर्षों, यानी वर्ष 2047 तक की आर्थिक रूपरेखा तय की गई है। यह देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक अच्छा प्रयास है। बजट में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को ऐतिहासिक रूप से बढ़ाने का ऐलान किया गया है। भारत को दुनिया के बाजार में एक खरीदार की बजाय, एक निर्माता के रूप में पेश करने के लिए ऐसा रोडमैप बनाया गया है, जिसका बहुत लंबा असर होगा। इससे देशवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। इस बजट में गाँव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग तथा कारोबारी सभी की भलाई के लिए कुछ न कुछ किया गया है। बजट में कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मदद देने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव दिया गया है। अब तक आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस होता था, लेकिन इस बार आदरणीय वित मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए प्राथमिकता दी है। इसके लिए मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विदेशी पूंजीनिवेश को केन्द्र में रखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2 प्रतिशत रखा गया है। यह हमारे देश के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इस बजट में ड्रोन के माध्यम से किसानों की खेती होगी और उससे सहयोग मिलेगा। इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। सरकार फसलों की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये का सीधे किसानों के खाते में भुगतान करेगी। यह एक अच्छा कदम है।

महोदय, गंगा नदी के आसपास जैविक खेती होगी। इसके भी बहुत फायदे मिलेंगे। मुझे विश्वास है कि विकास और गरीबों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध, मल्टीमॉडल इंफ्रास्ट्रक्टचर और निवेश के नए रास्तों पर हमारा महान देश चलेगा। इसके सकारात्मक प्रभाव होंगे।

महोदय, मुझे दो मिनट का समय दीजिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जहानाबाद एवं अरवल को आकांक्षी जिलों में शामिल किया जाए। यह पहले भी आकांक्षी जिले से जुड़ा हुआ था। हम आग्रह करते हैं कि आकांक्षी जिला में फिर से शामिल किया जाए।

(2115/CP/KKD)

जहानाबाद जिले में मोरहर नदी की उड़ाही कर तटबंध मरम्मत कराने एवं सम्मत बीघा में बने त्रुटिपूर्ण स्यूलिस गेट के अतिरिक्त गेट खोले जाने की व्यवस्था की जाए। जहानाबाद लोक सभा क्षेत्र की सभी नदियां, जैसे – मोरहर, दरधा, बदलइया को नमामी गंगे स्कीम से जोड़कर जीर्णोद्धार कराया जाए।

महोदया, मैंने रेल से संबंधित बहुत सारे प्रतिवेदन मंत्री जी को दे रखे हैं। उन प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं का विस्तार किया जाए। मेरा संसदीय क्षेत्र बहुत ही उग्रवाद प्रभावित रहा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

जहानाबाद में एनएच 110 के अंडरपास के ऊपर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने की मांग मैंने केंद्र सरकार से शून्य काल में की थी, परंतु मुझे एनएच के राज्य मंत्री जी की तरफ से जवाब मिला कि यह परियोजना संभव नहीं है। मैं आग्रह करता हूं कि फ्लाई ओवर ब्रिज बनाना बहुत ही आवश्यक है। यह जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट की लाइफलाइन है। यह ब्रिटिश टाइम का बना हुआ अंडर पास है। उस पर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाने के लिए मैं आदरणीय गडकरी जी से फिर से आग्रह करता हूं।

मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

(इति)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): श्री के. नवासखनी।

श्री के. नवासखनी (रामानाथपुरम): Sir, … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप इंग्लिश में बोलिए। आपने तमिल में बोलने का नोटिस नहीं दिया है। आप इंग्लिश या हिंदी में बोलिए। आप हिंदी में नहीं बोल सकते हैं, तो प्लीज इंग्लिश में बोलिए।

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Madam, I have already given a notice to speak in Tamil … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : आप कृपया बाद में बोलिएगा, जब आपकी भाषा में अनुवाद आ जाएगा।

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Madam, I have already given a notice and informed that I will speak in Tamil … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : अभी अनुवाद नहीं हो रहा है। हम बाद में देख लेंगे। आप अभी बैठ जाइए।

श्री कुरूवा गोरांतला माधव जी।

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Okay, Madam.

2118 hours

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Madam Chairperson, both Congress and BJP have turned a deaf ear to the hue and cry of the people of Andhra Pradesh. Since the division of Andhra Pradesh, our party has been representing to the Union Government to extend sufficient financial allocations in order to fulfil the promises made.

The lethargic attitude of the Union Government is nothing but a violation of the spirit of federalism. The Constitution has defined what federalism is. The most deprived States should be given preference while making allocations through the Budget.

However, Madam, this Budget has turned a blind eye to the needs of Andhra Pradesh. There is no capital expenditure allocated to boost the economy.

A very important point that I would like to make from this platform is that the present Government of Andhra Pradesh took all possible measures to curtail school and college dropouts against the odd conditions caused by the COVID-19, by implementing a scheme named 'Ammawadi, the first of its nature in the country where the money for attending schools is transferred directly into the account of mothers. But unfortunately, the Budget, 2022-23 seems to have utterly neglected the welfare schemes for our State.

Despite the deficit financing, the Andhra Pradesh Government has been maintaining primary health centres especially during the COVID situation.

Madam, we were expecting that the Central Government would support the infant economy of the newly emerged State but to our disappointment, the Budget neglected our case.

We really are stuck at a point where we are unable to decide if we have to appreciate the Budget or not.

(2120/RP/NK)

On this occasion, I am reminded of a beautiful poem written by a Telugu poet Vemana:

Medi pandu chooda melimai yundu
potta vippi chooda purugulundu
piriki vaani madini binkameelaaguraa
viswadabhiraama vinura vema

Let me read out the meaning. If you see a fruit, cluster fig, known as gular in Hindi, it looks very nice and neat from the outer side, but inside of it, you will find bugs. The Budget 2022-23 also looks showcased as good as a gular but if we keenly observe it, it made less sense and more noise as far as Andhra Pradesh is concerned.

I would also, once again, draw your kind attention to the special category status. Unfortunately, the first Chief Minister, after bifurcation,*… (Not recorded)* the demand of special status like a cattle trader sells away cattle in a cattle market.

I would like to restrict myself due to shortage of time to highlight the few important issues of my state of Andhra Pradesh only. I hope, the Government seriously looks into the matter and does the needful.

The Finance Minister in the budget for 2022-23 has disregarded the commitments made by the Centre under the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 and the promises of special category status. The people of Andhra Pradesh are highly dissatisfied and disappointed with no allocations made to the State under the Budget.

According to the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014, it is the responsibility and duty of the Central Government to develop and establish 11 Central educational institutions mentioned under Schedule 13 of the Act within a span of 10 years. Eight years have already passed and the Government is far from completing its obligations.

HON. CHAIRPERSON (SHRIMATI RAMA DEVI): Please conclude.

… (*Interruptions*)

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Madam, our Party is having 10 minutes time. … (*Interruptions*) The Union Budget, 2022-23, made a minimal allocation of funds to the Central University of Andhra Pradesh, the Central Tribal University of Andhra Pradesh, and the Indian Institute of Petroleum and Energy, Andhra Pradesh. All these three institutes are functioning from temporary campuses and the funds allocated under the budget are insufficient.

The Centre has allocated only Rs. 56.66 crores to the Central University of Andhra Pradesh in the current Budget against the requirement of approximately Rs. 1,500 crores for building its campus on a 491-acre land given by the State Government.

The Finance Minister in the Budget Speech mentioned about inter-linking rivers including Godavari-Krishna, Krishna-Pennar, and Pennar Cauvery. The Andhra Pradesh Government is welcoming this decision and we also urge the Central Government to ensure that in the case of Inter-State waters, there is due justice done to the lower riparian State. I also request environmental clearance for the Rayalaseema Lift Irrigation Project urgently.

Finally, I would like to conclude by reiterating the long pending demand of special category status to the State of Andhra Pradesh which was a promise made in this august House which has not been honoured till now.

I urge the Central Government to grant special category status to Andhra Pradesh at the earliest. Thank you very much, Madam.

(ends)

2124 hours

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM):

{For English translation of the speech
made by the hon. Member,
Shri K. Navaskani in Tamil,
please see the Supplement. (PP 390A to 390C)}

(2130/MK/MMN)

2130 बजे

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चौथी बार इस बजट को रखने वाली श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे समय यह बजट रखा है, जब कोरोना काल चल रहा है। सारे विश्व में अफरा-तफरी मची हुई है। सारे देश में आर्थिक मंदी आई है। ऐसे समय में भी एक रुपये का कोई नया कर न लगाकर और लोगों पर कोई नया बोझ न डालकर जिस कुशलता के साथ बजट पेश किया है, उसकी निश्चित रूप से तारीफ की जानी चाहिए।

हम सबके घरों के बजट बिगड़े हैं। कहीं न कहीं सभी के सामने दिक्कतें आई हैं। ऐसे ही हमारे सामने देश में भी आर्थिक रूप से मंदी का दौर आया, लेकिन आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व के कारण, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जीएसटी के बाद, जिन देशों ने कभी जीएसटी लगाई थी, उसके बाद वे दोबारा कभी सरकार नहीं बना पाए। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी लगाने एवं नोटबंदी के बाद भी दोबारा सरकार बनी । यह देश के लिए करिश्मा है। आज जीएसटी ने सिद्ध कर दिया कि 1.4 लाख करोड रुपये की जीएसटी आने के बाद इस देश के लोगों का कितना विश्वास यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने जीता है। वे जिस थीम जिस पर वे काम करते हैं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं- 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।', 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया' । मैं समझता हूं कि मोदी जी जो इन तीन मंत्रों को लेकर चल रहे हैं और जिस तरह का बजट आ रहा है, उसमें उन्होंने यह बताने का काम किया है कि यह देश कैसे शक्तिशाली हो । मुझे एक बहुत पुरानी पिक्चर 'आंखें' ध्यान में आती है। उस 'आंखें' पिक्चर का एक गीत था –

'उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता
जिस मुल्क की सरहद की निगेबान है आंखें ।'

आज मोदी जी के नेतृत्व ने देश और रक्षा तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। बजट में जीडीपी का लगभग 13 परसेंट केवल रक्षा में खर्च किया गया है। तभी देश आज सुरक्षित है। आज देश आतंकवाद से मुक्त है। … (व्यवधान) कश्मीर की सीमा को छोड़ दें तो आज सभी सीमाएं सुरक्षित हैं। सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने किया है। आज हमारे पास उसका उदाहरण भी है। एक समय था जब चीन और पाकिस्तान जैसे देश हमें आंखें दिखाते थे। आज की परिस्थिति में बालाकोट जैसी घटनाएं होती हैं। आज रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। 200 से ज्यादा स्वदेशी उपकरण बनाए गए हैं। 'आत्मनिर्भर भारत' की कल्पना करके काम किया गया है। इसलिए, मैं कहना चाहूंगा कि आज मोदी जी नहीं होते तो क्या होता? यदि आज मोदी जी इस कोरोना काल में नहीं होते तो क्या देश के 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग पाती? क्या छ: महीने के अंदर वैक्सीन बन पाती? क्या ये देश के लोगों को सुरक्षित रख पाते? जब कोरोना की दूसरी महामारी आई तो देश के सभी जिलों में पीएसए प्लांट लग गए।

इतना ही नहीं यदि हम मोदी जी के पिछले सात साल के कार्यकाल का हिसाब देखें तो यदि वे जन-धन खाते नहीं खुलवाते तो क्या हम कोरोनाकाल में लोगों की जेब में एक हजार रुपया, हमारी उन बहनों, जिनको उज्ज्वला गैस दिया गया है, उनको पैसे पहुंचा पाते? हमने उन लोगों के बारे में विचार किया, जिनके बारे में यहां लोग कहते हैं कि दो भारत हैं। इनके राज में सही में दो भारत रहे हैं। एक अमीरों का भारत, दूसरा गरीबों का भारत। जहां चलने को सड़कें नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, रहने के लिए छत नहीं थी, तब इस देश में हमारे पहले प्रधान मंत्री अटल जी ने गांव-गांव में सड़कें बनाकर देने का काम नहीं किया होता तो आज ग्रामीण क्षेत्र के सुदूर अंचल आदिवासी क्षेत्रों में बाइसाइकल से चलने वाला हमारा आदिवासी भाई नजर नहीं आता। यह कमाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ और मोदी जी ने इसको आगे बढ़ाया। हरेक आदमी की इच्छा होती है कि वह लखपति बने। कौन चाहता है कि वह गरीब रहे? हरेक के मन में होता है कि मैं अमीर बनूं। इसलिए, इनके राज में जो गरीबी रेखा की सूची बनती थी, वे कभी नहीं चाहते थे। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, मैं चार बार विधायक रहा हूं, मेरे साथ के कांग्रेस के विधायक साथी कहते थे कि तुम लोग इतना काम क्यों करते हो? तुम क्यों इनके लिए गांव में सड़क, पुल-पुलिया, स्कूल, तालाब और शिक्षा की चिंता करते हो? जब तक ये लोग गरीब, नंगे और भूखे रहेंगे, तब तक कांग्रेस जीतती रहेगी। तुम लोग आकर इनका काम करते हो। आज हमने अंत्योदय योजना के माध्यम यह करके दिखाने का काम किया है।

(2135/SJN/VR)

उसी अंत्योदय की थीम ने उनको आवास दिया, उनको उज्ज्वला गैस योजना दी, उनको शौचालय बनाकर देने का काम किया, उनके यहां बिजली देने का काम किया, सड़कें बनाने का काम किया है। यही कारण है और मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में माननीय मोदी जी और आदरणीय गडकरी जी ने सिवनी से नागपुर जाने के लिए हमें एशिया की पहली साउंड प्रूफ रोड बनाकर दी है। उसका एशिया में नाम लिया जाता है।...(व्यवधान) इसी सड़क को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में अड़गें लगाए गए, कोर्ट में केस पहुंचाए गए थे। ये कभी नहीं चाहते हैं कि लोगों को सारी सुविधाएं मिलें।

सभापति महोदया, इतना ही नहीं, आज 25,000 किलोमीटर तक नई सड़कें बनेंगी। मेरे क्षेत्र को नए एनएच मिले हैं। मैं कुछ डिमांड रखना चाहूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आज मोदी जी नहीं होते, तो क्या 80 लाख परिवारों को अनाज मिल पाता? लोगों को समाज में समरसता देने का काम किया गया है, क्या वह कर पाते? इसीलिए चाहे शौचालय हो, चाहे घर में नल हो, बैंक का खाता हो, आयुष्मान कार्ड हो, ये सब देने का काम किया है।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी) : आप अपनी मांग रखिए।

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट) : सभापति महोदया, मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूं। मोदी जी जो 'सर्वे भवन्तुः सुखिनाः' और 'आयुष्मान भारत योजना' लाए हैं, मैं डॉक्टर होने के नाते इसमें दो लाइन कहना चाहता हूं। अभी बिधूड़ी जी ने एक बात कही थी, हम इस देश को सुखी और स्वस्थ देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें जैविक अनाज की चिंता करनी पड़ेगी।

हम आज जो अनाज खा रहे हैं, हम जो फल-फूल और सब्जियां खा रहे हैं, उन सबमें जहर मिला हुआ है। हम जो हवा खा रहे हैं, उसमें भी कहीं न कहीं जहर है। हम जो पानी पी रहे हैं, उसमें भी कहीं न कहीं जहर मिला हुआ है। इसी कारण से हमें शुद्ध जल की चिंता करनी है, इसी कारण से जैविक खेती की चिंता करनी है, ताकि आगे आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं, वे 25 सालों तक स्वस्थ्य रह सकें। मोदी जी ने आज उसकी नींव रखने का काम किया है, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी सुखी और स्वस्थ रह सके, वह कैंसर मुक्त रह सके। बीमारी की वजह से आयुष्मान कार्ड की जरूरत न पड़े, वह बचपन से ही ठीक रहे। हमने सशक्त आंगनबाड़ियां बनाने का काम किया है।

सभापति महोदया, मैं कुछ मांग रखते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मेरा बालाघाट संसदीय क्षेत्र एक नक्सलाइट क्षेत्र है। वहां बहुत दिक्कतें हैं। 250-300 किलोमीटर तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। बालाघाट में एक मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। यहां पर आदरणीय रेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी बैठे हुए हैं, हम लोग एक ही क्षेत्र से आते हैं। हमारे यहां जबलपुर से गोंदिया तक का रेल मार्ग बनकर पूरा हो गया है। दोनों तरफ के मार्ग पर रेलगाड़ियां चल रही हैं, लेकिन समनापुर से लामता के बीच रेल नहीं चल रही है। उसको चलाने की चिंता की जाए। ऐसे ही तुमसर और तिरोड़ी के बीच और तिरोड़ी और कटंगे के बीच एक नया रेल मार्ग बन गया है। वहां भी रेलगाड़ी चलाई जाए। उसको बने हुए लगभग 6 से 8 महीने हो गए हैं।

सभापति महोदया, एक बड़ी पुरानी मांग है। हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंव राव जी थे, वह रामटेक से सांसद हुआ करते थे। हमें अपने काम के लिए नागपुर जाना पड़ता है, तो नागपुर से रामटेक और रामटेक से गोटेगांव तक के लिए एक नए रेल मार्ग का सर्वे हुआ था, उसको नॉट फीज़िबल कहकर छोड़ दिया गया।...(व्यवधान) उससे पेंच और कान्हा पार्क में आने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। अभी हमें 400 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसकी वजह से नागपुर से जबलपुर की दूरी 250 किलोमीटर हो जाएगी। 150 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी।

माननीय सभापति : अब आप कन्क्लूड कीजिए।

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट) : सभापति महोदया, मैं अपने क्षेत्र की एक और बात रखना चाहता हूं। हमारे यहां आष्टा का एक बहुत प्राचीन मंदिर है, वह एएसआई का मंदिर है, उसके पुनर्निर्माण के लिए राशि देने की चिंता की जाए। लाखों लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं।...(व्यवधान) मेरे यहां पर कान्हा और पेंच नेशनल पार्क हैं। इन दोनों पार्कों से 10 किलोमीटर की दूरी पर हवाई पट्टियां हैं, जो लोग दिल्ली से वहां पर्यटन के लिए जाते हैं।...(व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी) : आपको बोलते हुए 8 मिनट हो गए हैं।

2139 बजे

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : सभापति महोदया, आपने मुझे केन्द्रीय बजट 2022-23 पर बोलने का मौका प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदया, मैं मुंबई को रिप्रेजेन्ट करता हूं। हर बार बजट में मुंबई को जितना फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है। हर बार मुंबई के साथ अन्याय होता है। मुंबई को चाहे टैक्स रिलैक्सेशन हो या जितना भी बेनिफिट मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है। गिफ्ट सिटी जोकि अहमदाबाद में है, उसको बेनिफिट मिल रहा है। इससे पहले गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज़ सेंटर का जो निर्णय लिया है, वह भी गलत है, क्योंकि बीकेसी (मुंबई) में ऑलरेडी आईएफएससी के लिए प्लॉट रिजर्व है। उसका काम भी चालू होने वाला था। वहां पर बुलेट ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज आने की वजह से उसका काम रुका हुआ है। आगे आने वाले दिनों में वहां पर इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज़ सेंटर बनने वाला है। गिफ्ट सिटी को जितना बेनिफट मिल रहा है, चाहे वह फाइनेंशियल बेनिफट हो, चाहे टैक्स में छूट हो, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स (बीकेसी) को सभी बेनिफिट्स मिलने चाहिए, क्योंकि वहां पर आईएफएससी का निर्माण होने वाला है। मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है। मुंबई में ही इंटरनेशनल फाइनेंसियल सर्विसेज़ सेंटर होना चाहिए। यह मेरी मांग है।

(2140/YSH/SAN)

बहुत दिनों से मांग है कि मुम्बई में आई.आई.एम. होना चाहिए, क्योंकि मुम्बई देश की आर्थिक राजधानी है, लेकिन मुम्बई में आई.आई.एम. नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करता हूँ कि मुम्बई में आई.आई.एम. होना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट के 52 नम्बर के पॉइंट में नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में कहा है। टेली मेडिसिन का प्रोग्राम ऑलरेडी मुम्बई में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे जी की सूचना के अनुसार पिछले 10-12 साल पहले से इंप्लीमेंट हो रहा है। के.ई.एम. हॉस्पिटल के माध्यम से और जे.जे. हॉस्पिटल के माध्यम से टेली मेडिसिन का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसके तहत ही सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने यह प्रोग्राम इस बजट में अनाउंस किया है, वह बहुत ही अच्छा प्राग्राम है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि के.ई.एम. हॉस्पिटल को एम्स का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि के.ई.एम हॉस्पिटल पूरे महाराष्ट्र को टेली मेडिसिन के जरिए से पूरी तरह से हेल्प कर रहा है।

सभापति जी, आपको भी पता है कि के.ई.एम. हॉस्पिटल मुम्बई का बड़ा हॉस्पिटल है इसलिए के.ई.एम. को एम्स का दर्जा देना चाहिए। आपने डिजिटल यूनिवर्सिटी के बारे में भी अनाउंस किया है। यह बहुत अच्छी बात है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, उस क्षेत्र में धारावी एक जगह है। धारावी में हमने 6 महीने पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी को फॉर्म करने का निर्णय लिया था। वहां पर हम स्टेट गवर्नमेंट की सहायता से पूरा काम कर रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके माध्यम से हम लोग काम करने वाले थे, लेकिन अभी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल यूनिवर्सिटी अनाउंस कर दी है, जिससे हमें बहुत राहत मिली है।

माननीय वित्त मंत्री जी से मैं यह मांग करना चाहता हूँ कि धारावी में पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हमने धारावी में डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए पूरी तैयारी की है, उसका वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि धारावी के लोगों ने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में पूरी दुनिया को धारावी मॉडल पर काम करके दिखाया है। उसकी डब्ल्यूएचओ ने सराहना की, केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहना की। मैं आपसे मांग करता हूँ कि धारावी को डिजिटल यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए।

'हाउसिंग फॉर ऑल' का आपने अपने भाषण में जिक्र किया है। मैं उसके अंतर्गत मांग करता हूँ कि इन-सीटू स्लम रिडेवलपमेंट (आईएसएसआर) जो अरबन डेवलपमेंट की स्कीम है, उस स्कीम के अंतर्गत सेन्ट्रल गवर्नमेंट की लैंड पर जितनी भी स्लम्स हैं, अगर उन स्लम्स को सेन्ट्रल गवर्नमेंट की यूनिट एनओसी देती है तो स्लम रिडेवलपमेंट वहां पर हो सकता है। यूडी डिपार्टमेंट के अनुसार पूरे देश में 4.9 लाख लोगों को आईएसएसआर स्कीम के माध्यम से घर मिला है, प्रधान मंत्री आवास योजना के माध्यम से घर मिला है तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मुम्बई में रेलवे लाइन पर जो स्लम्स हैं, उनको नोटिस इश्यू किए गए हैं, उनको इन-सीटू स्लम रिडेवलपमेंट स्कीम के माध्यम से घर मिलना चाहिए। उनको प्रधान मंत्री आवास योजना के माध्यम से घर मिलना चाहिए।

मैं माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। मुम्बई के सभी लोगों को, जिनको डिमोलिशन के नोटिस मिल चुके हैं, उन नोटिसेज़ को कैंसिल करके 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के माध्यम से उन्हें घर मिलना चाहिए। अरबन डेवलपमेंट के बारे में भी आपने अपने बजट में कहा है, that a high-level committee of reputed urban planners, urban economists and institutions will be formed to make recommendations on urban sector policies. मैं इस सदन को एक बात बताना चाहता हूँ कि मुम्बई का जो डेवलपमेंट प्लान 2034 है, अगर उसको इंप्लीमेंट करना है तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से एक डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि मुम्बई का पहले वाला डेवलपमेंट प्लान सिर्फ 9 प्रतिशत इंप्लीमेंट हुआ है। अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डेवलपमेंट इंप्लीमेंटेशन कमेटी फॉर्म करेंगे तो वर्ष 2034 का डेवलपमेंट प्लान 100 प्रतिशत इंप्लीमेंट हो सकता है। ब्लॉकचेन, डिजिटल रुपये के बारे में एक अच्छा निर्णय लिया गया है, उसी की वजह से और आरबीआई की गाइडलाइन की वजह से क्रीप्टोकरेंसी और एनएफटी इललीगल है। डिजिटल रुपये को ही लीगल करेंसी माना जाएगा। डिजिटल रुपये के बारे में मेरा सजेशन है कि अगर ब्लॉकचेन का इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट करती है तो इसमे ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और करप्शन भी कम होगा। सरकार एक ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डेटा की रक्षा कर सकती है। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकती है और साथ ही विश्वास और जवाबदेही को बढ़ाते हुए धोखाधड़ी, बर्बादी और दुरुपयोग को कम कर सकती है। एक ब्लॉकचेन आधारित सरकारी मॉडल पर व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारें क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित वितरित लेजर पर संसाधनों को साझा करती है। यह संरचना विफलता के एकल बिंदु को समाप्त करती है और स्वाभाविक रूप से संवेदनशील नागरिक और सरकारी डेटा की सुरक्षा करती है।

एक ब्लॉकचेन आधारित सरकार में विरासत के खराब बिदुओं को हल करने और निम्नलिखित लाभों को सक्षम करने की क्षमता है। सरकार, नागरिक और व्यावसायिक डेटा का सुरक्षित भंडारण, श्रम प्रधान प्रक्रियाओं में कमी, जवाबदेही के प्रबंधन से जुड़ी अत्यधिक लागतों में कमी, भ्रष्टाचार और दुरुपयोग की कम संभावना, इसके साथ ही ऑनलाइन सिविल सिस्टम में विश्वास बढ़ेगा तो डिजिटल मुद्रा भुगतान, भूमि पंजीकरण, पहचान प्रबंधन, आपूर्ति श्रृंखला ट्रेसबिलिटी, स्वास्थ्य देखभाल, कॉर्पोरेट पंजीकरण, कराधान, मतदान और कानूनी संस्थाओं के प्रंबधन में ब्लॉकचेन यूज करेंगे तो करप्शन कम हो जाएगा।

(2145/RPS/SNT)

अंत में, मैं फाइनेंशियल एसिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूं कि जीएसटी के बारे में महाराष्ट्र के सभी माननीय सदस्यों ने कहा है।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): आपका समय हो गया।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): उसके बारे में सीएंडएजी की एक रिपोर्ट है कि शॉर्ट क्रेडिटिंग और शॉर्ट ट्रांसफर की वजह से महाराष्ट्र का बहुत नुकसान हुआ है।

माननीय सभापति : अब कनक्लूड कीजिए।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): महाराष्ट्र को वर्ष 2017-18 में 950 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 2622 करोड़ रुपये और वर्ष 2019-20 में 2900 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। माननीय वित्त मंत्री जी को शॉर्ट क्रेडिटिंग के बारे में विवरण देना चाहिए because short crediting was a violation of the GST (Compensation to States) Act, 2017. वह वायलेट हुआ, उसकी वजह से सभी स्टेट्स को लॉस हुआ है। उसके बारे में भी आपको जवाब देना चाहिए।

अंत में, मैं सीनियर सिटीजन्स के बारे में बताना चाहता हूं। यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2026 तक भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के 17.3 करोड़ बुजुर्ग होंगे। ग्लोबल एज वॉच इंडेक्स के अनुसार भारत 96 देशों में 71वें स्थान पर है।

माननीय सभापति : अब हो गया।

डॉ. मोहम्मद जावेद ।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): मैडम, यह लास्ट प्वाइंट है। भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 87वें स्थान पर सबसे नीचे है, जो महामारी के कारण उत्पन्न खतरों से अधिक बढ़ा है। इसके अलावा, ऐसे समय में जीने के तनाव से वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव पड़ रहा है। वर्तमान में अटल पेंशन योजना केवल 3.5 करोड़ लोगों को बीमा प्रदान करती है। सदस्यता लेने वाले लाभार्थियों के लिए सरकार को उसी के कवरेज का विस्तार करने पर विचार करना चाहिए। वर्ष 2021 में सरकार ने 75 वर्ष से अधिक आयु के लिए केवल पेंशन और आय के स्रोत के रूप में ब्याज के साथ कर-फाइलिंग छूट की घोषणा की। … (व्यवधान)

(इति)

2147 बजे

डॉ. मोहम्मद जावेद (किशनगंज): बहुत-बहुत शुक्रिया, मैडम। स्पीकर साहब को भी बहुत-बहुत शुक्रिया देता हूं कि उन्होंने टाइम बढ़ाया।

We the people of Seemanchal and neighbouring districts of Bengal have been requesting for funds for the AMU centre at Kishanganj. The UPA Government, under Dr. Manmohan Singh Ji, had allotted a sum of Rs. 136 crore in 2013-14. The foundation of the centre was laid by my leader and the then Chairperson of UPA in January 2014. Only Rs. 10 crore has been released so far. I have been raising this issue for the last two-and-a-half years inside and outside this august House. I had met the hon. Finance Minister and the Education Minister, written to them multiple times. There has been a formal request now from AMU, Aligarh for a sum of Rs. 352.75 crore. I request the Finance Minister to release the funds along with the sum of Rs. 126.82 crore due since January 2014. I also request you to provide UGC-sanctioned teaching and non-teaching staff for AMU, Kishanganj and a sum of Rs. 50 crore for boys and girls hostel as provided to the other two centres.

Madam, through you, I would to like draw the attention of the hon. Minister towards the NITI Aayog report on 'National Multidimensional Poverty Index' released in November 2021 which says 52 per cent people in Bihar are poor. 65 प्रतिशत मतलब किशनगंज और सीमांचल में हर तीन में से दो आदमी गरीब हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि why does the Modi Government ignore the plight of Bihar? What about the promise of Rs. 1.25 lakh crore announced by the Prime Minister for Bihar? Was it just a *jumla*? Therefore, special attention to Bihar is a must by incorporating Bihar under article 371 of the Constitution considering its special needs. Special aid and provision must be granted to Bihar, especially to Seemanchal for development projects so that they too can contribute for the growth of Mother India.

The three backbones of the economy – education, farming and employment have been ignored by this Modi Government. Education continues to suffer under this Government. It continues to be less than 3 per cent of the GDP whereas the Government in its NEP talks about 6 per cent.

The Government keeps repeating the slogan of 'Beti Bachao Beti Padhao' and yet in the Budget, they have allocated no funds for the National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education.

Funds for the Maulana Azad Foundation under the Minority Affairs Ministry has been slashed by 99 per cent. Allocation for scholarship and grant funds have been reduced to just Rs. 969.50 crore from Rs. 1,395 crore.

In farming sector, fertilizer subsidies have been cut from Rs. 1.4 lakh crore to Rs. 1.05 lakh crore, and procurement budget has been reduced to Rs. 2.37 lakh crore from Rs. 2.48 lakh crore. What about the doubling of farmers' income? (2150/SRG/SPS)

मैडम, आपको जानकार ताज्जुब होगा कि किसानों को ... (व्यवधान)। मैडम, अभी तीन ही मिनट हुए हैं। आप टाइम देखिए। आप सबको पांच-पांच मिनट एक्स्ट्रा दे रही हैं। मैंने अपनी स्पीच को पांच मिनट में कन्साइज किया है। एक हेक्टेयर में 25 हजार रुपये से ज्यादा किसानों का खेती करने में लगता है। उसमें 6 हजार रुपये देते हैं और 25 हजार रुपये वापस ले लेते हैं। The 6.3 crore MSMEs are giving employment to 11 crore Indians, लेकिन 70 लाख एमएसएमईज़ बंद हो गई हैं। 50 per cent of MSMEs have lost 25 per cent of revenues and running in net loss. This Government's main focus is always on election win by whatever means. They speak of development and *sabka sath sabka vikas,* but when an election comes, we hear slogans like बीस परसेंट-अस्सी परसेंट, कब्रिस्तान, शमशान घाट, कपड़ों से पहचानें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, लव जिहाद। The news of lynching, inciting violence, call for genocide, auctioning of Muslim women on social media, children being stopped from attending school for wearing a piece of cloth on their head, Muslims not being allowed to offer prayers on permitted public land, and now a Member of Parliament being fired at have become a concern for all Indians. Muslim, Christians, Sikhs, other minorities, tribals, OBCs, Dalits, job seekers, farmers, students, intellectuals have become the hallmark of this Government. No wonder 23,000 millionaires, in US Dollars not Rupees, and nine lakh highly educated and skilled Indians have renounced their Indian citizenship जब से यह देशभक्त सरकार बनी है।

When my leader Rahul Ji says, there are two Indias, does he say a wrong thing? Do we not know about हम दो, हमारे दो। हम दो में से एक की दौलत 15 गुना बढ़ गई और दूसरे की 5 गुना बढ़ गई। वहीं पर 90 परसेंट हिन्दुस्तानियों की दौलत 10 से 60 परसेंट घट गई और जो बीच के 50 परसेंट लोग हैं, उनकी इनकम 40 परसेंट घट गई।

मैडम, अगर सही मायने में जमीन से कोई जुड़ा हुआ है तो मेरे नेता राहुल जी हैं, जिन्होंने कोविड के लिए चेतावनी दी थी कि सावधान हो जाइए, तैयारी कीजिए, लेकिन सुनाई नहीं दिया। … (व्यवधान) उन्होंने बगैर सोचे ही लॉकडाउन कर दिया। करोड़ों लोग अलग-अलग जगहों में फंस गए, उसमें लाखों की जानें चली गईं। … (व्यवधान)

मैडम, मैं अपनी बात आधी मिनट में समाप्त कर रहा हूं। अगर हिन्दुस्तानी और कांग्रेस नहीं झुकते तो पता नहीं कितने लोग मर जाते? उसी तरह से जब किसानों के खिलाफ तीन कानून पेश किए गए थे तो राहुल जी ने मना किया था, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और साल भर के बाद वे … *(Not recorded)..* कानून वापस लेने पड़े। अगर उनकी बात वह सुन लेते तो हमारे 700 किसान शहीद नहीं होते। … (व्यवधान) मैडम, बस कन्क्लूड करने दीजिए। मैं एक लास्ट लाइन में कन्क्लूड कर रहा हूं।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी) : आपको सात मिनट दे दिए हैं।

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): Madam, for this Government, I say, a lie does not become a truth, a wrong does not become a right and evil does not become good just because it is accepted by the majority.

(ends)

2154 hours

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam, I rise to speak on the Union Budget 2022-23. It is nice to see that the hon. Finance Minister is here. Due to paucity of time, I will come directly to the main points. I would like to take this opportunity to ask a couple of questions to the hon. Finance Minister and I will be happy if she addresses my questions in her Budget reply.

Firstly, delving into the food security scenario, the total food subsidy budgeted is Rs. 2.1 lakh crore. This is significantly lower than Rs. 2.9 lakh crore which will go towards food subsidy as per the revised estimates for 2021-22. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana might possibly be coming to an end in March. The Government needs to compensate the Food Corporation of India for giving away food grains for free. If it has not budgeted for it, how will it compensate for it?

(2155/AK/RAJ)

Secondly, changes in the income tax and rates, hike in standard deduction, hike in basic exemption limit, work from home tax benefits were the many expectations that the common man had from Budget of 2022. But again, the common man has got nothing and has been disappointed. A large part of the Budget speech revolved only around the Gati Shakti Scheme making no beneficial direct relief that people were looking forward to.

Thirdly, just a four per cent increase is witnessed compared to six per cent increase in allocation for Police. This year, there is no real increase in defence expenditure. Does this mean that external security is less important than internal security? Also, the Government has decided that the demand for subsidized urban housing is either not needed or not a priority, obviously overlooking the slums in major cities.

Fourthly and the most crucial, why has not the health sector been given the push that it deserves? There has been no clear policy on vaccination. Compared to the Revised Estimates of last financial year, there has been a massive 45.2 per cent decline in the allocation for medical and public health. Even after the heart wrenching visuals of dead bodies floating in the rivers and series of unending pyres been lighted up, the Government is still ignorant.

Madam, I have two more demands to place before you. My Constituency of Jaynagar is absolutely coastal and rural based. A noticeable part of the Sundarbans falls in my Parliamentary Constituency. There is no Kendriya Vidyalaya. So, it is my demand. If you kindly take care of this issue, I will be grateful for it.

Now, we are getting only Rs. 2 crore as MPLAD Fund. It will be beneficial for all the MPs if you increase this Fund. I am concluding my speech. Thank you so much for allowing me to conclude my speech.

(ends)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The hon. Member has concluded her speech without any interruption from the Chair. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल-उपस्थित नहीं।

2157 बजे

डॉ. राजदीप राय (सिल्चर): नमस्कार सभापति महोदय। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

Budget 2022 is a landmark Budget in the history of Indian Union because this is actually a plan for the coming 25 years. I must compliment the Finance Minister for presenting a Budget despite five States going into elections. I must compliment her because Budget does not reflect any political gimmicks or assurances, which generally a Budget is linked to because of elections.

World War – II led to the establishment of power houses in the world, and following World War – II of 1939-1945, we saw the establishment of United Nations, International Monetary Fund, World Bank and the likes, and with the establishment of those we saw the new world order coming to power all across the world. It is my hunch that the post-COVID world will throw up new leaders and our India will be the new leader in the coming world. I am saying this because we have proved it in solar energy regulation, in climate change operations and also by manufacturing vaccines so promptly. We have given first dose vaccines to 93 per cent people and almost 80 per cent second dose vaccine to the people of our country. We have proved that in a post-COVID world India will be the leader and India will attain the position of *vishwa guru* in the coming days.

The Budget has given us few landmark areas of progress.

(2200/SPR/VB)

In the health sector, an open platform for the National Digital Health Ecosystem is to be rolled out. It is a visionary move. What this could mean is a single window connecting patients to beds, ailments to specialists and technology. This is a massive enabler and this system will help healthcare delivery in ways that will define the future of healthcare in our country. Madam, the set-up of unique health identity will also help the insurance providers in better risk assessment, premiums, and claims.

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): श्री राजदीप राय जी, एक मिनट रुक जाइए।

माननीय सदस्यगण, अभी कुछ और माननीय सदस्य अपना वक्तव्य सदन में रखना चाहते हैं, यदि सभा की सहमति हो, तो सभा की कार्यवाही 11 बजे तक बढ़ा दी जाए।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

DR. RAJDEEP ROY (SILCHAR): For a country like India, which has dismally low internet penetration, the open platform for the National Digital Health Ecosystem will not only encourage people to buy health insurance and change the narrative of health insurance penetration in the country, further, the platform will go a long way in digitising our data about healthcare providers and extending universal access to health facilities on a digital platform.

The creation of an open platform for the National Digital Health Ecosystem will also speed up any medical processes in the health care system and can avoid unnecessary and repeated investigations. It will be an easy transition to a paperless health care system.

In the field of education, we have seen in the Budget 2022-23, almost Rs. 40,000 crore have been allocated to the Ministry of Education. This is almost 6.6 per cent of the Budget 2022-23. It is a great step forward in terms of education. Funding for central universities, the Indian Institutes of Technology (IITs), National Institutes of Technology (NITs) and the University Grants Commission (UGC) and the All-India Council for Technical Education (AICTE) is a significant step in this year's Budget.

A higher budget for Higher education could likely lead to the inclusion of digital infrastructures, such as Digital Universities, as announced by the Finance Minister during the Budget 2022-23.

The three initiatives that could be game-changers in the Indian education needs to be mentioned here. The first is a Central Digital University with a hub-and-spoke arrangement. Secondly, the DESH portal could bring about a similar revolution in the upskilling and life-long skilling space. This would lead to skill requirement across job functions. This new method of education would take care of that. The third is the convergence of digital channels and vernacular push in school education will be a model for many countries with large, dispersed learners.

माननीय सभापति जी, एक जमाना था, जब लोग कहते थे:

पढ़िए गीता, बनिए सीता,
फिर इन सबमें लगा पलीता,
किसी मूर्ख की है परिणीता,
निज घर वर बसाइए।

आगे यह कहा जाता है:

होए कतली, आँखों गेली,
लकड़ी सीली, तबीयत ढ़ीली,
घर की सबसे बड़ी पतीली,
भरकर भात पसाए।

माननीय सभापति जी, आज की यह हालत है कि out of 77 Union Ministers, 11 are women. और हमारी जो नीति है, वह 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' से आगे यानी 1:7 है। मतलब यह है कि 11 यूनियन मिनिस्टर्स महिलाएं हैं। आज महिलाएं प्लेन भी उड़ाती हैं। इसलिए यहाँ पर जो महिला सशक्तिकरण है, वह इसको दोहराता है।

मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, मिशन आंगनबाड़ी, पोषण-2.0 आदि हमको दिखलाती हैं कि सरकार महिलाओं के लिए कितनी गंभीर है।

माननीय सभापति : अब कनक्लूड कीजिए।

डॉ. राजदीप राय (सिल्चर): मैडम, थोड़ा समय दे दीजिए।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का रेशियो दिखाता है कि पहले जो सेक्स रेशियो 991 था, वह पिछले पाँच साल में बढ़कर 1,020 हो गया है।

वर्ष 2015-16 में इंस्टिट्यूशनल वर्क का जो परसेंटेज था, वह 2 परसेंट था, वह बढ़कर 76.4 परसेंट हो गया है। A resilient economy amidst global uncertainly has been provided in this Budget. The current level of foreign exchange reserves enough to cover more than one year of imports has also been indicated in this Budget. The economic growth of the financial year 2022-23 is estimated to be 8 to 8.5 per cent.

(end)

(2205/UB/PC)

2205 hours

ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL): There was an expectation that the Government will give importance to social welfare measures in this Budget while the people in the country are in distress. However, it turned out to be a disappointment as it totally ignored the issues of the common people. The Government announced 'Atmanirbhar Bharat Abhiyan' as part of the relief measures in the aftermath of COVID-19. The primary goal of this Rs. 20 lakh crore stimulus package is to make India self-reliant in its major economic sectors. The Government is claiming that the package saved jobs of a lot of people during the pandemic.

The hon. Finance Minister in the budget speech stated that the Productivity Linked Incentive Scheme in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received an excellent response. It has the potential to create sixty lakh new jobs, and an additional production of thirty lakh crore jobs during next five years. But almost at the end of two years, there is no clarity on spending and achievements under this package.

As per the latest reports, India has 53 million unemployed people and a majority of them are women. However, the Government is not ready to admit the fact and making unrealistic claims on employment creation. More effective measures are needed to address the issue of unemployment and it should be the first priority of the Government.

As usual, the Government is not ready to admit the seriousness of price rise. At 14.23 per cent, country's wholesale inflation rate in November 2021 was the highest in three decades. The prices of edible oil, pulses, and LPG are continuously rising. No positive measures have been taken by the Government to address this issue burdening the common people. Government is not ready to restore the direct subsidy on LPG.

Millions of rural workers depend on MGNREGA for their survival. It is necessary to revise wages under the scheme and enhance allocation. The Government should consider the recommendation of the Parliamentary Standing Committee.

Considering the current situation, the allocation to the health sector is not sufficient. Especially, for the people of Kerala, this year’s budget is a

disappointment. The State under the threat of coronavirus spread is more prone to other viral outbreaks. Establishment of a top institute like AIIMS is the urgent need of the State. Delay in sanctioning AIIMS is an injustice to the people of Kerala. Madam, I am concluding.

While the Government is taking measures to promote MSME sector, the coir sector is not getting due importance. Kerala is the home to Indian coir industry. More than 3.5 lakh women workers are engaged in the coir industry in Kerala. Kerala accounts for 80 per cent of the country's coir export of Rs. 3,778 crore. The main issues being faced by coir workers are the absence of regular employment and very low wages. I request the Government to provide more financial assistance to the State of Kerala for implementing wage revision and regular employment to the coir workers. Madam, I am concluding.

The hon. Finance Minister announced the introduction of four hundred new-generation Vande Bharat Trains during the next three years. The Government of Kerala has proposed to implement a Semi-High Speed rail project in the State. The State Government is going ahead with the land acquisition process before getting the final approval from the Union Government. This huge project which requires large scale eviction and land acquisition has invited huge public protest in the State.

(2210/KMR/IND)

Still, the process of stone laying on the marked land is going on with the help of police force. … (*Interruptions*)

(ends)

1010 बजे

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट 2022-23 पर बोलने की इजाजत दी है। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं। 25 वर्ष की लम्बी यात्रा के बाद हम 'Bharat at the Show' पर पहुंचेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में 'Bharat at the Show' के दृश्य को निर्धारित किया है। सुरक्षा, आर्थिक स्तर, समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास की सहायता करना है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, इनटेक प्रौद्योगिक समिति विकास, ऊर्जा परिवर्तन एवं जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता प्रोत्साहन को उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इसमें साठ लाख नई नौकरियां सृजित करने और अगले पांच वर्ष के दौरान 30 लाख अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने की क्षमता है। इस बजट में अमृतकाल, जो भविष्य समावेशी है, जिसमें महिलाओं, किसानों, युवाओं, एससी, एसटी के लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख है कि राजस्थान में रीट की परीक्षा का पेपर आउट हुआ। इसमें 26 लाख युवाओं के साथ धोखाधड़ी हुई। भारी भ्रष्टाचार हुआ, पेपर बेचे गए। पेपर बेचने वाले पकड़े भी गए। राजस्थान की लेवल-2 की परीक्षा निरस्त कर दी है और एसओजी जांच कर रही है लेकिन यह जांच प्रभावित हो रही है। मैं मांग करता हूं कि ऐसे युवाओं और शिक्षित बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

महोदया, आदरणीय मोदी जी नौकरियां देने की बात कह रहे हैं और राजस्थान में जिस प्रकार की स्थिति है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग दुखी है। यह आशा थी कि उनका बच्चा पढ़ेगा, आगे पढ़कर डाक्टर और शिक्षक बनेगा, लेकिन आज क्या स्थिति बन गई है। जैसा रितेश जी बता रहे थे कि कब्रिस्तान में यदि मुर्दे को गाड़ कर दोबारा निकाला जाए, तो वह कहेगा कि मेरी नौकरी कहां है? वाकई कांग्रेस के समय में इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है। आज भी राजस्थान इसका जीता जागता उदाहरण है और चार-चार व्यक्ति पकड़े गए हैं और परीक्षा निरस्त कर दी है। इस कारण आज युवा और बेरोजगार लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए।

महोदया, वर्ष 2022 में एक्सप्रेस मार्ग के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान लाया जाएगा ताकि वस्तुओं का तेज गति से मूमेंट हो सके। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय राजमार्ग 25 हजार किलोमीटर जोड़ा जाएगा। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री और आदरणीय गडकरी जी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 311 किलोमीटर हाईवे की स्वीकृति प्रदान की है। मेरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया है और इस वजह से लोग खुश हैं कि इस तरह का काम बहुत अपेक्षित था। मोदी जी के नेतृत्व में यह काम पूरा हो रहा है। आने वाले समय में भारत में रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा जो ऊर्जा क्षमता और यात्रियों को सुविधा देने की दृष्टि से बेहतर होगा। मेरा संसदीय क्षेत्र डुंगरपुर बांसवाड़ा है। आज देश के किसी कोने से यह क्षेत्र जुड़ा हुआ

नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन किया है कि जो 400 नई रेलों का प्रावधान है, इसलिए वंदे भारत योजना के तहत रतलाम से अहमदाबाद वॉया डुंगुरपुर रेल प्रारम्भ की जाए।

(2215/KDS/RCP)

मैं इस अवसर पर यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में भी दो लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम किया जाएगा। इसके साथ ही हर घर नल और नल में पानी योजना के अंतर्गत 8.7 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है। राजस्थान में अभी 10,180 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मेरे क्षेत्र में भी बहुत अच्छी धनराशि उपलब्ध कराई गई है। मेरे क्षेत्र में जनजाति समुदाय पहाड़ियों पर रहते हैं, अत: बड़ी-बड़ी टंकियां बनाकर पाइपलाइन के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्र के लोगों को निश्चित रूप से पानी मिल सकेगा। बिजली के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की गई है। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ....

(इति)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): आपके बोलने का समय पूरा हो गया है। कृपया बैठ जाइए। श्री कृपाल बालाजी तुमाने जी।

2216 बजे

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): सभापति महोदया, आपने इस बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूं। प्रधान मंत्री आवास योजना के बारे में वित्त मंत्री महोदया ने बताया कि 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी यह है कि जो डेटा आज उपलब्ध है, वह वर्ष-2011 का है। इस वजह से सही मायने में जो इसके लाभार्थी हैं, उनको यह बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मेरी मांग है कि जो डेटा है, उसका री-सर्वे किया जाए और नए डेटा के हिसाब से सभी लोगों को मकान दिया जाए।

महोदया, बजट में 5जी के बारे में भी कहा गया है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बीएसएनएल की हालत क्या है। आज बीएसएनएल 3जी भी नहीं दे पा रहा है। हमें सरकार ने जो मोबाइल दिया है, वह 3जी के अलावा चलता ही नहीं है। इस बारे में भी आप गंभीरता से विचार करें। 5जी की स्कीम बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इसे बीएसएनएल के द्वारा आप चलाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। उर्वरक का विषय हमारे देश का एक बहुत ही गंभीर विषय है। आज यूरिया और फर्टिलाइजर पर जो सब्सिडी कम कर दी गई है, उससे किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मेरी सरकार से इस विषय में यह मांग है कि किसानों की हालत बहुत गंभीर है। हमारे देश का जो वैदर है, उसके कारण कभी भी बारिश के हालात पैदा हो जाते हैं। उस मामले में पहले जो सब्सिडी थी, उसे ऐज इट इज अगर किया जाए तो बहुत अच्छा होगा।

मैडम, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में भी इस साल कटौती की गई है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार से हर राज्य बार-बार बोलता है कि जब चक्रवात आता है, तूफान आता है तो उन्हें इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जो एजेंसियां होती हैं, वे किसानों के खेत तक आकर भी उनको कोई लाभ नहीं देती हैं। इस बारे में भी सरकार को गंभीरता से सोचने की जरूरत है।

मैडम, एक और महत्वपूर्ण विषय है। जब वर्ष 2020 में कोरोना आया था, तो उस समय हमारे जो बच्चे थे, जो अनइम्प्लॉएड लोग थे, उनकी आयु एलिजिबिलिट की आखिरी सीमा पर थी। उनके दो साल कोरोना में चले जाने के कारण सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देकर उनको दो या तीन साल की मदद बढ़ा देनी चाहिए। किसानों के लिए एक सबसे अच्छी योजना नाबार्ड के द्वारा हमारे देश में इम्प्लीमेंट की जाती है। यह बहुत अच्छी संस्था है। हमारे महाराष्ट्र में इसका रीजनल ऑफिस पूना में है। नागपुर के अगर एक कोने से जाएं तो यह 1 हजार किलोमीटर की दूरी पर है।

माननीय सभापति : कृपया आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : जी मैडम। मैं वित्त मंत्री जी से यह मांग करता हूं कि नाबार्ड का रीजनल ऑफिस हमारे नागपुर में खोला जाए।

(2220/CS/RK)

जिससे कि विदर्भ और मराठवाडा के सभी किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अभी जो नाबार्ड का ऑफिसर होता है, ऑफिस न होने की वजह से वह घर में बैठकर काम करता है। मैं थोड़े अपने निर्वाचन क्षेत्र के, पिछले बजट में जो घोषणा हुई थी, उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। वर्ष 2017 में मेरे नागपुर में नाइपर की घोषणा हुई थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): हो गया, अब कनक्लूड कीजिए।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।... (व्यवधान) पिछले बजट में मेट्रो की घोषणा नागपुर से रूरल एरिया तक के लिए हुई थी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिलने के कारण यह प्रपोजल रूका हुआ है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल।

... (व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): मैडम, बस आखिरी तीन सेकेंड दे दीजिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : नहीं, हो गया।

... (व्यवधान)

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक): उसी तरह से हमारे यहाँ पर नागपुर से सिवनी, जो माननीय सदस्य ने भी माँग की थी, अगर उसको रामटेक से सिवनी तक बढ़ा दिया जाए, तो एक रेलवे लाइन का लाभ होगा।... (व्यवधान)

(इति)

माननीय सभापति : हो गया, बढ़ा दिया जाएगा।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल।

... (व्यवधान)

2221 बजे

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, मैं इस बजट का स्वागत करते हुए बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। माननीया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं कहूँगा कि वह एक ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि हर साल बजट आता है, उसमें एक रूटीन बजट होता है और ज्यादातर बजट चुनावी क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पेश किए जाते हैं। इस बार के बजट में पहली बार बॉर्डर के एरिया तक, जहाँ दो घर हैं, सात घर हैं, उस जनसंख्या को भी ध्यान में रखते हुए इस बजट ने पहली बार बॉर्डर को स्ट्रेंग्थन करने की बात की है। किसान, गरीब, मजदूर, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी चीजों में, मैं इन चीजों पर नहीं जाना चाहूँगा, मैं बॉर्डर क्षेत्र से आता हूँ, लद्दाख, एलओसी, एलएसी, तिब्बत के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ जहाँ बॉर्डर लगते हैं, वहाँ हमेशा एक तनाव रहता है। विपक्ष की तरफ से हर वक्त मुद्दा रहता है कि बॉर्डर पर क्या है, बॉर्डर पर क्या है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बॉर्डर की कहानी बता दूँ। इसलिए मैं पूरा बॉर्डर पर फोकस करके बताना चाहूँगा।

महोदया, कांग्रेस के शासनकाल में पूरा बॉर्डर खाली करने का काम किया गया। नेहरू जी फॉरवर्ड पॉलिसी बताते रहे और बॉर्डर पर बैकवर्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई। हमारे बॉर्डर खाली होते गए, लोगों को सुविधा ही नहीं दी। फैसेलिटीज तो छोड़िए, फंडामेंटल राइट तक नहीं दिया। शिक्षा नहीं दी, स्वास्थ्य नहीं दिया, टेलीकम्युनिकेशन नहीं दिया, सड़क नहीं दी, लेकिन आज पहली बार इस बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत जितनी भी सीमाएं हैं, जो नॉर्दर्न सेक्टर में हैं, चीन के साथ, तिब्बत के साथ जो सीमाएं लगती हैं, उन गाँवों को, वहाँ के लोगो को सशक्त करने की जो बात की है, मैं ऐसे बजट का स्वागत करता हूँ। मैं एक चीज यहाँ पर कोट करके बताना चाहता हूँ। यूपीए सरकार के दौरान 6 सितम्बर, 2013 को तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के.एन्टोनी जी का इसी सदन में दिया हुआ स्टेटमेंट है।

I quote:

> "Independent India had a policy for many years that the best defence of the country's border is not to develop the border. Undeveloped border is safer than the developed border."

So, for many years there was no construction of either airfields or roads along the border areas. By that time, China continued to develop its infrastructure on the border. As a result, China has now gone ahead of us in comparison to its infrastructure and capability.

यह तत्कालीन रक्षा मंत्री जी का इस सदन में दिया हुआ स्टेटमेंट है। बॉर्डर को बैकवर्ड रखना, बॉर्डर को डेवलप नहीं करना, वे समझते थे कि यह बॉर्डर की सुरक्षा है। आज उसी पार्टी के लोग बेशर्मिंदा होकर यह सरकार से पूछ रहे हैं कि बॉर्डर पर क्या है, गलवान पर क्या हुआ, पैंगोंग पर क्या है, चुशूल पर क्या है? मैं बताना चाहता हूँ कि आज बॉर्डर पर खतरा बढ़ रहा है तो यह कांग्रेस की नीति के कारण से बढ़ रहा है। चाइना की ओर से (CPEC) चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया। यह मोदी जी के शासनकाल में नहीं बना। डेमचोक के आगे ताशीगंग में हाइडल पॉवर डैम बना दिया, रोड बना दिया, 6-8 एयरपोर्ट्स बना दिए, पूरे लद्दाख को घिरवा दिया।

(2225/KN/PS)

यह कांग्रेस के शासन काल में हुआ और कांग्रेस सरकार ने उफ तक नहीं बोला। मैं बताना चाहता हूं कि अभी गलवान सेक्टर की बात बार-बार आती है। गलवान, मोरगो, Daulat Beg Oldie सेक्टर, पूरे उस एरिया को नॉदर्न सब-सेक्टर कहते हैं। जहाँ कनेक्टिविटी के लिए Darbuk-Shyok-Daulat Beg Oldie (DSDBO) जो एक सड़क है, माननीय अटल जी की सरकार के दौरान वहां 220 किलोमीटर की सड़क बनाने का निर्णय लिया और फिर वह काम चालू हुआ। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई। मैडम, मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2012 तक वह सड़क कम्पलीट नहीं हुई। वहां पर बनाई ही नहीं और विजिलेंस प्रारंभ हो गई। विजिलेंस ने बताया कि वह इतनी दूर है, बर्फ है, पानी है, वहां नहीं जा पाएंगे। आपको हैली का रेकी कराते हैं, तो विजिलेंस कमेटी को हैली में ले गए। मैं आपको बहुत इंट्रेस्टिंग कहानी सुना रहा हूं। हैली में लेकर गया और ऊपर हैली से देखा कि हां, नीचे सड़क है। अच्छा, ब्लैकटॉप किया हुआ है, उसे देखा और रिपोर्ट सब्मिट की। उसे यह बताया गया कि बीच-बीच में पानी आ रहा है, यह रीएलाइनमेंट करके दोबारा बनाना पड़ेगा। जितने भी हजारों-करोड़ हैं... (व्यवधान) मैडम, अभी तो मैंने बोलना शुरू ही किया है। उस सड़क के बारे में रिपोर्ट में बता दिया कि अच्छा, ये ब्लैकटॉप हुआ है, इसको बीच-बीच में रीएलाइनमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि सड़क बनी ही नहीं। इन्होंने नीचे ब्लैकटॉप की जगह कम्बल बिछा दिया। क्या आप यकीन करेंगे? मैं Shyok, Darbuk, Tangtse जाता हूं और लोगों से मिलता हूं तो वही लोग ग्राउंड की हकीमत और कहानी मुझे बताते हैं कि सांसद जी ऐसा होता था। वर्ष 2014 में मोदी जी की सरकार आई, तब से उस काम ने रफ्तार पकड़ी और उसे नए सिरे से शुरू किया। Daulat Beg Oldi सेक्टर तक 220 किलोमीटर की सड़क चकाचक बना दी। वर्ष 2019 में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, 500 मीटर के गलवान घाटी के सामने, एक ब्रिज का उद्घाटन होता है। क्या यह बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? उस रोड समेत 37 ब्रिजेज, जो स्ट्रेटेजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉर्डर पर यह हो रहा है। ये बार-बार पूछ रहे हैं कि बॉर्डर में क्या होता है? पीपी-14 गलवान घाटी बार-बार चर्चा में आती है। मैं बताना चाहता हूं कि गलवान घाटी बहुत बड़ा इलाका है। नेहरू जी के टाइम गलवान घाटी ऑलरेडी अक्साई चीन में जा चुकी है। हमारे पास जो बचा है, वह पीपी-14 गलवान का मुंह है। आज भी हम वहीं पर है, जहां पर हम थे, एक इंच भूमि नहीं गई। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर क्षेत्र में Lukung

से लेकर Spangmik, Man, Merak, Chushul, जिन गाँवों का मैं नाम ले रहा हूं, ये पैंगोंग त्सो झील के किनारे वाले हैं। वहां सड़क ही नहीं थी। आज माननीय मोदी जी ने सीआरएफ के फंड से, पीएमजीएसवाई के फंड से वह सारा ब्लैकटॉप हो चुका है। बॉर्डर पर यह हो रहा है। चुशूल, जहां वर्ष 1962 में रेजांग ला वॉर बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है, उस चुशूल में आज 4जी से ज्यादा स्पीड में टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क चलता है। बॉर्डर पर यह हो रहा है। आज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके अपनी सीमा सुरक्षा बढ़ा रहा है। चुशूल के बारे में मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि वहां पर मेजर शैतान सिंह समेत 114 कुमाऊं के जवानों ने शहादत दी, 18 नवंबर, 1962 को बलिदान दिया। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने माना ही नहीं। यह बताते हुए बहुत दु:ख होता है। वहां 18 नवंबर, 1962 को सुबह युद्ध हुआ और हमारे 114 जवान शहीद हुए। कांग्रेस ने 4 महीने तक उनकी पूछताछ नहीं की। सरकार ने माना कि कहीं भाग गए होंगे, सरैंडर किया होगा, युद्ध का मैदान छोड़ दिया होगा। विंटर में बर्फ पड़ी और हमारे सारे वीर जवानों की लाशें ढंक गईं। धीरे-धीरे बर्फ पिघलती गई तो जो भेड़-बकरी चराने जाते थे, उन लोगों ने देखा कि अरे, ये तो लाश हैं। ये तो हमारे फौजियों की लाशें हैं। तब जाकर पता चला कि हमारे भारतीय सेना ने एक इंच भूमि तक नहीं गंवाई। इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा स्लोगन आता है, जो अंतिम व्यक्ति, अंतिम एम्युनिशन तक वहां पर लड़ाई की। 'The Last man, Last Round' आज यह बहुत फेमस हो रहा है। हमारी सेनाओं की वहां जो लाशें पड़ी थीं, किसी के हाथ में बम, किसी के हाथ में बंदूक और किसी के हाथ में मेडिकल असिस्टेंस थे।

(2230/GG/SMN)

कांग्रेस ने पूछा ही नहीं, इतनी *… (Not recorded)* दिखाई। आज 60 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मेजर शैतान सिंह समेत 114 जवानों को अपनी शौर्य कथा लिखने का जो समय दिया, वहां पर वॉर मैमोरियल बना कर, इस बार उसका उद्घाटन किया। यह कांग्रेस पार्टी हमेशा भारतीय सेना पर संदेह करती रहती है, उंगली उठाती रहती है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि वहां पूरा बॉर्डर समेत तूरतुक इलाका, एक बहुत बड़ा इलाका सन् 1971 में पीओके से लिबरेट हो कर हिंदुस्तान के साथ जुड़ा। लेकिन इन्होंने पूछा ही नहीं। इस बार, माननीय मोदी जी की सरकार में हम यहां आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तूरतुक वालों ने इस बार 50वीं सालगिरह मनाई है। वहां तूरतुक, तेक्सी, थांग, भोक्कांग आदि सभी चुलुंग इलाके में आता है। उसको पहचान मिल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केवल चुशूल ही नहीं वहां से जा कर थागा, फिर दुंगटी, दुंगटी की कहानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वहां पर एक ब्रिज होता था, काकचुंग वैली, सैकड़ों किलोमीटर वहां पर हमारा पाश्चर लैण्ड होता है, वहां पर हमारे नोमैड लोग जाते हैं। चाइना ने उस पर ऑब्जेक्शन किया तो कांग्रेस सरकार ने अपनी ही जमीन से ब्रिज को वर्ष 2007 में हटा दिया। यह कौन सी सुरक्षा है? आज मोदी जी की सरकार साहसिक कदम दिखा कर वहां पर 25 करोड़ रुपये की राशि से ब्रिज बना रही है। बॉर्डर पर यह हो रहा है। मैडम, मैं जल्दी-जल्दी खत्म कर रहा हूँ। … (व्यवधान)

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी): जल्दी कीजिए। अभी पांच-छह सदस्य और बोलने वाले हैं।

… (व्यवधान)

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): मैडम, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। आज यह सरकार वायब्रेंट विकास प्रोग्राम में बॉर्डर एरिया में विकास कर रही है। मैं आपको उत्तराखण्ड की कहानी बता रहा हूँ। मैं नाम भूल गया, आपने बीच में इंट्रप्ट किया। वहां पर पिथौरागढ़ जिले में एक छोटा सा गांव है। वहां से सभी माइग्रेंट हो चुके थे। आज वहां पर लोगों को दोबारा बसाने के लिए टेलिकम्युनिकेशन आदि सारी सुविधा दी जा रही है। इन्होंने पूरा अक्साईचिन तो दे ही दिया है। जब यहां पर धारा-370 हटाई जा रही थी, तब कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया था। मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। धारा-370 के रहते हुए आपने कैलाश पर्वत के समय मानसरोवर झील चाइना को दे दिया। धारा-370 के रहते हुए कैसे दे दिया? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। सन् 1962 से ले कर वर्ष 2019 के इलैक्शन तक कांग्रेस पार्टी ने अक्साई चीन को वापस भारत के साथ जोड़ने के लिए एक बार भी अपने मेनिफेस्टो में यह बात नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? क्या चीन से डरते हैं? नेहरू जी की छवि खराब होने से डरते हैं? या आपको चीन से इतना प्यार है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप बॉर्डर के बारे में सुनने में बहुत तरसते हैं न? सभापति जी, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री को ले कर आज मैं यहां पर कुछ मांगे रखना चाहता हूँ। पूरा बॉर्डर आज मोदी सरकार ने टूरिज्म के लिए खोल दिया है। सियाचिन बेस कैंप तक मैं खुद ग्रुप ले कर गया हूँ। तेक्सी, थंग, द्रास की मुश्को वेली तक, हुंदलमान तक, डेमचोख, उमलिंग ला पास तक, हाइएस्ट मोटरएबल रोड तक। लेकिन साथ ही साथ पिछले तीन साल कोविड के चलते लद्दाख की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत लॉस हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको इस्टैब्लिश करने के लिए कुछ इंसेंटिव दें। सभापति जी, हमारे लद्दाख में आईटीबीपी की जितनी भी बॉर्डर पोस्ट्स हैं, वहां पर नेटवर्क की जरूरत है, वहां पर इलैक्ट्रिसिटी की जरूरत है।

माननीय सभापति : आप लिख कर दे दीजिए। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): सभापति जी, सरकार ने पूरे लद्दाख को एक बार फिर से सर उठाने का मौका दिया और इस बजट में 5,958 करोड़ रुपये फिर से लद्दाख को दे रहे हैं। इससे सौभाग्यशाली हम क्या हो सकते हैं? लद्दाख का हर एक व्यक्ति आज गौरवान्वित महसूस करता है। हम बॉर्डर की चौकीदारी करेंगे। देश के लिए मर-मिटेंगे। कांग्रेस की तरह अपने देश को नीलाम नहीं होने देंगे। यहां पर कांग्रेस के लीडर यह सवाल खड़ा करते हैं कि मोदी जी ने भारत को दो राष्ट्रो में बांट दिया है। मैं बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना जी ने टू नेशन की थ्योरी दी। कांग्रेस मोहम्मद अली जिन्ना से इंसप्रेशन लेते हुए और दो कदम आगे बढ़ी है। इसी भारत के उन्होंने तीन टुकड़े किए हैं। … (व्यवधान) एक भारत, जहां पर आज हम खड़े हैं। दूसरा भारत, अक्साईचिन, जिसको चाइना के हवाले कर दिया है। तीसरा भारत पीओके है, जिसको पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। कांग्रेस पार्टी *… (Not recorded)* से आज सरकार की नीयत और इंडियन आर्मी की शौर्यगाथा पर सवाल खड़े कर रही है। मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इस बजट का स्वागत करता हूँ।

(इति)

(2235/RV/SNB)

2235 बजे

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): महोदया, आपने मुझे बजट पर हो रही चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। हमारा देश आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गया है और सरकार 'अमृत महोत्सव' मना रही है, तो यूं कहिए कि भारत 'अमृत काल' में प्रवेश कर चुका है।

महोदया, हर बजट भाषण में धार्मिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक रूपकों का इस्तेमाल होता है, लेकिन 'अमृत काल' की अवधारणा इन सब प्रतीकों के इस्तेमाल से काफी अलग है। इसलिए बजट हर साल पेश होता है, ताकि पिछले साल और इस साल के हिसाब का लेखा-जोखा जनता के बीच प्रस्तुत किया जा सके। अगर 25 सालों का विज़न होगा, तब आप उस बजट का मूल्यांकन कैसे करेंगे?

महोदया, जब वित्त मंत्री जी ने सूटकेस छोड़ा तो कहा गया कि यह अंग्रेजों की परम्परा थी, अब बजट को भारतीय परम्परा के अनुसार लाल कपड़े में लपेट कर इसे बही खाते का रूप दिया गया है। देश में हर साल दिवाली के मौके पर नया बही खाता शुरू होता है और पिछले साल का बही खाता बंद कर दिया जाता है। संविधान के अनुच्छेद -112 में बजट का वैधानिक नाम है - 'एनुअल फाईनैंशियल स्टेटमेंट।' इसे कहीं भी 'विज़न डॉक्यूमेंट' नहीं कहा गया है। अनुच्छेद - 112 में लिखा है कि 'राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री उस साल का वित्तीय लेखा-जोखा पेश करेंगे।' इस साल के बजट की पहली लाइन में भी यही है कि वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन अगले कुछ पैराग्राफ में वर्ष 2047 के विज़न की बात होने लगती है। इतना लम्बा काल खण्ड किसी बजट में कैसे हो सकता है? फिर अगले साल कितना काम हुआ, कितने पैसे खर्च हुए हैं, इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? इसके बारे में पूछने पर यह कह दिया जाएगा कि अभी 25 साल बाकी हैं, काम हो रहा है।

'आत्मनिर्भर भारत' के तहत प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक (पी.आई.एल.) योजना के तहत पाँच सालों में 14 सेक्टर्स से 60 लाख रोजगार पैदा होने की बात कही गई है, लेकिन 100 लाख करोड़ रुपये के 'पी.एम. गतिशक्ति' में रोजगार की कोई अनुमानित संख्या नहीं बताई गई है।

महोदया, वर्ष 2019, 2020, 2021 के 15 अगस्त के दिन 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात प्रधान मंत्री जी ने की, तो इस दौरान कुछ खर्च हुआ होगा, कुछ काम हुआ होगा, कुछ रोजगार पैदा हुआ होगा, उसका हिसाब कुछ तो इस बजट में या बाहर देना चाहिए था। क्या यह गलत सवाल है? इस 100 लाख करोड़ रुपये को लेकर कितनी बार और कितने सालों तक हेडलाइन्स छपती रहेंगी?

इस बजट में 'पी.एम. गतिशक्ति' के सात केन्द्र बताए गए हैं – सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बन्दरगाह, लोक परिवहन, जल परिवहन, लॉजिस्टिक, लेकिन इस बजट में पैसे का जिक्र केवल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर है। यह कहा गया है कि 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने के लिए 20,000 करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे।

महोदया, बजट में महाराष्ट्र को पूरी तरह से नजरंदाज किया गया है। यहां तक कि जी.एस.टी. बकाया, जो राज्य का अधिकार है, उसे भी नहीं दिया जा रहा है। केन्द्र के कुल जी.एस.टी. संग्रह में राज्य ने 48,000 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया है, फिर भी पुनर्भुगतान के रूप में 5,500 करोड़ रुपये की एक छोटी-सी राशि दी गई है। केन्द्र इस तरह से राज्यों को बकाया जी.एस.टी. का हिस्सा न देकर परेशान कर रहा है।

महोदया, मेरी कंस्टीट्युन्सी से संबंधित एक सवाल है। मैंने रेल मंत्री जी से 'मेरी-गो-राउण्ड' ट्रेन के बारे में अनुरोध किया था। बलहारशाह से नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चांदा फोर्ट होते हुए बलहारशाह तक का यह सफर करीब 600 किलोमीटर का होता है, जो कि मध्य तथा दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे के तहत आता है। 'मेरी-गो-राउण्ड' वाली यह प्रस्तावित ट्रेन पूर्व विदर्भ के चन्द्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया तथा गढ़चिरौली जिलों को अपने साथ जोड़ सकती है, जिससे क्षेत्रवासियों को बहुत सुविधा होगी।

महोदया, लाखों श्रमिकों के बचाव में आई योजना मनरेगा में एक बार फिर कटौती की गई है। वर्ष 2021-22 में मनरेगा के बजट में 34 फीसदी की कमी की गई। हमने चेतावनी दी थी कि यह पर्याप्त नहीं होगा। हम सही साबित हुए जब सरकार को 25,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि का आवंटन करना पड़ा। फिर भी सरकार ने इससे कुछ नहीं सीखा और इस बार भी मनरेगा के बजट में आर.ई. 2021-22 की तुलना में 25 प्रतिशत की कमी की गई है।

धन्यवाद।

(इति)

(2240/RU/MY)

2240 hours

SHRI RAHUL KASWAN (CHURU): Madam Chairperson, I support the Union Budget presented by the hon. Finance Minister. The Union Budget is the right choice at the right time. The priority of this Budget is growth, and growth-oriented Budget will create job opportunities for the youth of this nation and make India as the fastest growing country among the major economies of the world.

With this Budget, the vision of hon. Prime Minister's Atma Nirbhar Bharat as a digital super power will surely be achieved. One of the biggest takeaways of this Budget is the increase of 35 per cent of capital expenditure to Rs. 7.5 lakh crore, that is, 2.9 per cent of GDP which is the highest in the last two decades.

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से कहना चाहता हूँ और एक ही चीज महसूस करता हूँ कि भारत सरकार का जो गति शक्ति प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत सात इंजन्स होंगे। इस प्रोग्राम को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह बजट पेश किया है। इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इसमें हमारे रेल, पोर्ट्स, सी- पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और वाटरवेज़ होंगे। इसमें लॉजिस्टिकल हब्स होंगे। मास अर्बन ट्रोसपोर्टेशन की जो बात कही गई है, इसमें साढ़े सात लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हिन्दुस्तान की एक नई नींव रखने का काम किया जाएगा। इससे जॉब क्रिएशन के साथ-साथ अलग इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में देश आगे बढ़ेगा। रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर पिछले सात सालों में इस देश के अंदर बड़ा जबरदस्त परिवर्तन आया है। मैं माननीय मंत्री गडकरी साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदय, वर्ष 2014 में जहाँ देश में सिर्फ 91 हजार किलोमीटर नेशनल हाइवेज़ का नेटवर्क है। वह आज बढ़कर एक लाख 41 हजार किलोमीटर से ऊपर हो चुका है। इस बार इसका टारगेट 25,000 किलोमीटर रखा गया है। मैं समझता हूँ कि अगर इसे इस साल पूरा किया जाएगा तो प्रतिदिन करीब 68 किलोमीटर का नेशनल हाइवेज़ हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो वर्ष 2013 के अंदर सिर्फ 12 किलोमीटर था। मेरे ही लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत दो नेशनल हाइवेज़ पहले भी सैंक्शन हुए हैं। बीते कई सालों से एक राष्ट्रीय राजमार्ग सिरसा से लेकर चुरू तक डीपीआर सैंक्शन हुई। यह 1 करोड़ 40 लाख रुपये की थी। अब यह बनकर तैयार हो चुकी है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे जो क्षेत्र हैं, इसमें मेरा लोक सभा क्षेत्र चुरू आता है। यह राजस्थान के अंदर है। यह भारत के नॉर्थ टू साउथ की लाइन पर हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस हाइवे के बनने से क्षेत्र में बड़ा विकास होगा। इससे

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी डायरेक्ट साउथ इंडिया से होने का काम करेगी।

जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से भारत सरकार ने इस बार 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह 'हर घर नल से जल' पहुँचाने का प्रोग्राम है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। मेरी लोक सभा क्षेत्र के अंदर चार लाख घरों को जोड़ने का प्रावधान है। इसके अंदर भारत सरकार ने एक एश्योर्ड फंड राजस्थान को एलॉट किया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। वे बड़े-बड़े बातें करते हैं। एक सोई हुई सरकार के पास भारत सरकार के द्वारा 11,000 करोड़ रुपये का एश्योर्ड फंड उपलब्ध है। परंतु, बीते हुए साल के अंदर मात्र 495 करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए हैं। चुरू जिले के अंदर गर्मी में टेम्परेचर 50 डिग्री टच करता है और सर्दी में माइनस वन तक टच कर जाते हैं। ऐसे में पीने की पानी का महता क्या हैं, इसे हम समझते हैं। परंतु, राजस्थान सरकार आज भी सोई हुई है। उसमें पैसा देने की काबिलियत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इनको प्रेशराइज्ड़ क्रिएट करेगी। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को प्राथमिकता पर लिया जाएगा, जहाँ पर पानी का हमेशा अभाव रहता है।

महोदय, एग्रीकल्चर के अंदर सरकार ने किसान ड्रोन की स्कीम निकाली है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपये का एलॉटमेंट है। राजस्थान के अंदर चुरू जिला को मौसम आधारित फसल बीमा योजना का बेहतरीन फायदा मिला है। आज की तारीख में, वर्ष 2017 से लेकर अभी तक, इन पाँच वर्षों के अंदर करीब 5500 करोड़ रुपये का क्लेम मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसान भाइयों को मिला है। इसमें एग्रीकल्चर एंश्यारेंस कंपनी है, जिसके द्वारा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। नौहर और भादड़ा मेरी बेहतरीन कंस्टीचुएन्सी में हैं। वहाँ मैक्सिमम किसान बड़ा जागरूक है और वे इस योजना का बड़ा फायदा लेते हैं। बीते हुए साल, यानी वर्ष 2021-22 में 550 करोड़ रुपये का क्लेम इस ए.आई.सी. कंपनी ने आज तक रिलीज नहीं किया है। किसान दर-दर की ठोकरे खाने के लिए मजबूर हैं। बीमा कंपनी को एक साल से ऊपर हो चुका है, जबकि टाइम से पेमेंट नहीं देने पर 12 परसेंट का ब्याज देने का प्रावधान भी लिखा हुआ है।

महोदय, हमारे फाइनैंस मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि जिन बैंकों ने पोर्टल पर गलत तरीके से एंट्री चढ़ाई, ऐसे 52,000 किसान मेरे कंस्टीचुएन्सी के हैं, जिनको अपना बीमा क्लेम नहीं मिल पाया। बीमा पॉलिसी कहती है कि यदि किसान का क्लेम बनता है तो उसको क्लेम मिलना चाहिए। अगर बैंक कसूरवार है तो बैंक अपनी पॉकेट से देगी, अन्यथा बीमा कंपनी देगी। मैं निवेदन करता हूँ कि उन 52,000 किसानों को भी फायदा मिलना चाहिए।

महोदय, मैं रेलवे की बात करूँगा। वह बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' लेकर चली है। इसके तहत 100 पीएम गतिशक्ति कार्बो टर्मिनल बनाने की बात की गई है।

(2245/CP/SM)

हम आज की तारीख में नई-नई ट्रेन्स चलाने की बात कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि देश की 75 साल की आजादी के बावजूद भी हमारे ऐसे कुछ तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, जो रेल कनेक्टिविटी से जुड़ नहीं पाए हैं। हमारे यहां सीकर, अनोखा वाया बिदासर का एक बेहतरीन रूट है, जिसकी डिमांड हमेशा की गई है। राजघर से तारानगर और तारानगर से सरदारशहर के रूट के बारे में भी पब्लिक की डिमांड रही है।

मैडम, यह 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है और हमारे तहसील हेडक्वार्टर्स रेल से नहीं जुड़े हैं। मैं सरकार से उम्मीद करता हूं कि यह प्रावधान रखा जाए कि कुछ वीजीएफ, वायबिलिटी गैप फंडिंग्स करके इन स्टेशंस को आप जोड़ने का काम करें।

मैडम, मेरा अंत में यही कहना है कि बहुत बड़ा डिफेंस बजट दिया गया है। पिछले दो सालों से आर्मी की भर्तियां नहीं हो रही हैं। हमारे यहां युवा बहुत मेहनत कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर दो साल से भर्तियां नहीं हुई हैं। कृपा करके भर्तियों की ओर फोकस किया जाए। मैं अंत में आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(इति)

2246 hours

KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): Madam, I am thankful to you for giving me an opportunity to participate in this discussion. We expected a popular Budget during this pandemic. But the Budget is really disappointing. I think the Budget has become just a proclamation of projects rather than focussing on real issues.

Madam, it is unfortunate that though the Government claims the development of Scheduled communities, the allocation of fund for these communities is very little especially in this pandemic situation. For the upliftment of these communities, the Government has to allot more funds with special schemes.

MGNREGS is the hope and solace of the poor rural people in the country. But the Government has cut down the allocation for this Scheme. In 2020-21, the allocation was Rs.73,000 crore and the Government was compelled to revise it as Rs.98,000 crore. But this Budget has allotted only Rs.73,000 crore for this Scheme. I cannot understand the intention of the Government in decreasing this allotment.

Madam, the cut down in the allocation of Price Stabilisation Fund is really a setback to farmers of the country. It has been decreased from Rs.11,135 crore in 2020-21 to Rs.1,500 crore in 2022-23. I cannot understand what message will be conveyed to the farmers and agriculture sector by cutting down of 7.5 folds to this allocation.

Unemployment is a major problem of youth in this pandemic era, especially among educated youth. On the one hand, the Government has announced 20 lakh job opportunities, but on the other hand, the allocation has been reduced for job and skill development as compared to the previous year.

During this pandemic, MSME sector is facing a lot of financial crises. But the Government is not putting forward any sustainable financial package or scheme for this sector. Even the Government has not declared adequate interest subsidy to MSMEs during the moratorium period. Then, how can we say that this Budget has kept in the mind the interests of small-scale entrepreneurs?

Madam, regarding railways, suggestions from the Kerala Government and Members of Kerala have been totally denied and neglected. I may mention here that even I had proposed a pilgrim train connecting Guruvayur, Rameshwaram and Palani. But, there is no mention about such a proposal.

Madam, we are surviving from the COVID-19 pandemic. But the amount allotted for NHM is very less compared to the needs of health sector. We faced the shortage of health facilities in rural and remote areas in several phases of COVID-19. People expected that the Government would allot more funds for the health sector. But the Budget has really disappointed them.

The condition of women and children should be brightened. I expected that the Government would announce a special package for starting MSMEs or small-scale industries for women. But there was no such proposal. I appreciate the Government for establishing centres to strengthen the mental health of women. I request the Government to increase the number of such centres as it should cover all the constituencies.

Madam, the Government has declared that this Budget aims at sustainable development. But we could not find the real pulse of the economy of India and any long-sighted vision projects in the Budget.

Regretfully, I would like to say here that the Central Government did not consider Kerala in any area in this Budget. Thank you.

(ends)

(2250/NK/KKD)

2250 बजे

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): सभापति महोदय, आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने देर रात तक इस चर्चा में हम सब लोगों को शामिल किया, आपका धन्यवाद।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने कोरोना के समय इतना बेहतरीन बजट पेश किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इस बजट में देखा जाए तो गांव, गरीब और किसानों का ध्यान रखा गया है। दूसरी ओर उद्योग, स्वास्थ, शिक्षा, रोजगार और शहरी क्षेत्रों का भी ध्यान रखा गया है।

कोरोना के समय किसानों की बात करें, तो 30 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन किसानों ने किया है और 33 करोड़ टन उत्पादन फल और सब्जी के रूप में किया है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इस बार किसानों ने 3 लाख करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट किया है जो कि गत वर्ष से 25 परसेंट ज्यादा है। अगर खाद सब्सिडी की बात करें तो पिछले वर्ष बजट में 79 करोड़ खाद सब्सिडी के लिए रखी गई थी जो इस बार बढ़ाकर 1 करोड़ 5 लाख रुपये रखी गई है, जो अब तक की सबसे ज्यादा खाद सब्सिडी है।

ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारा प्रावधान किया गया है। अब किसानों को भी ड्रोन सुविधा मिल पाएगी, यह मोदी सरकार की डिजीटल इंडिया के बारे में सोच है। अगर हम किसान सम्मान निधि की बात करें तो 11 करोड़ किसानों को 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का अभी तक भुगतान हो गया है। इस वर्ष 58 हजार करोड़ रुपये का प्रवधान किसान सम्मान निधि में किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 2 करोड़ पक्के घर बन गए हैं। हर घर में बिजली पहुंच गई है और हर घर में नल पहुंचाने की योजना में 9 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल अभी तक पहुंच चुका है। इस बार बजट में 4 करोड़ लोगों को स्वच्छ जल पहुंचाने के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

मोदी जी के राज में ग्रामीणों की बात करें तो मकान पक्का, बिजली, जल, सड़क सब मिल गया है, अब गांव को डिजिटल बनाने के लिए फाइबर केबल की योजना लागू की जा रही है जिसके माध्यम से पूरा गांव डिजिटल हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारा आलू, प्याज और लहसुन का पैदावार होता है। बहुत सारे किसान संघों ने यह मांग की है कि इसका एक्सपोर्ट खोला जाए। आलू, प्याज और लहसुन के एक्सपोर्ट खोलने के लिए सरकार को शीघ्र कोई नीति बनानी चाहिए। शहरों के विकास में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विशेष ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि उसको ध्यान में रखते हुए शहरी विकास मंत्रालय के बजट में इंदौर- सावेर-उज्जैन और इन्दौर-मऊ-प्रितमपुर रैपिड या मैट्रो ट्रेन चलानी चाहिए। गति शक्ति मास्टर प्लॉन के अंतर्गत रेल, सड़क, एयरपोर्ट विकास की योजना रखी गई है।

मैं चाहता हूं कि इंदौर में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट स्टेशन बनना चाहिए। रेलवे की बात करें तो बहुत सारी जगह रेलवे का काम हो रहा है। मीटरगेज को ब्रॉड गेज में, डीजल को इलेक्ट्रिक में और जहां आजादी के बाद ट्रेन नहीं पहुंची है, वहां भी अब ट्रेन पहुंच रही है।

मैं इंदौर की तरफ से रेल मंत्री जी से मांग रखना चाहता हूं कि इंदौर-मनमाड रेल ट्रैक का काम होना चाहिए। इंदौर रेलवे स्टेशन को भोपाल-कमलापति की तरह बनाना चाहिए। इंदौर को वन्दे भारत ट्रेन से अन्य शहरों से भी जोड़ना चाहिए।

मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ और उनकी कर्मस्थली मुंबई में रही। हम चाहते हैं कि इंदौर से मुंबई के लिए दुरांतो एक्सप्रेस चलती है, उसका नाम लता मगेशकर के नाम से रखा जाए।

कोरोना की विषम परिस्थितियों में रोजगार के बहुत सारे अवसर मिले, 60 हजार नए स्टार्ट-अप बने हैं और 40 यूनिकार्न स्टार्ट-अप भी बने हैं। मैं चाहता हूं कि इंदौर स्टार्ट-अप का एक कैपिटल हब बने, उसके लिए सरकार मदद करे। इसके साथ-साथ मोबाइल मैन्युफेक्चरिंग की सरकार की जो योजना है, उसमें भी इंदौर को जोड़ा जाए, इंदौर में मोबाइल मैन्युफक्चरिंग बनना चाहिए।

अंत में, बजट में डिजिटल सिटी की घोषणा की गई है। इंदौर स्वच्छता में लगातार पांच बार क्लिनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया बना है तो डिजिटल यूनिवर्सिटी भी इंदौर में बनना चाहिए। यह आत्मनिर्भर भारत का बजट है, नए भारत के निर्माण के लिए यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

(इति)

2254 बजे

श्री मलूक नागर (बिजनौर): माननीय सभापति, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

इस बजट में पिछड़ों जिसमें जाट, गुर्जर, यादव, पाल, सैनी, लोहार, सोनार, कुम्हार, दलित और अकलियत के लोगों का कुछ ज्यादा हो सकता था। बजट में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ सामान्य बातें भी हैं। कांग्रेसियों ने उसका पूरा बखान कर दिया है, इनकी प्रदेशों की सरकार में अगर यह देखें तो सीधा-सीधा इनका दोगलापन साफ दिखता है। पिछले 70 सालों में इनके जो बजट आए हैं, उसको अगर देखें तो आज कोरोना महामारी के बाद का बजट है तो उसको हम अच्छा मान सकते हैं।

(2255/MK/RP)

मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। बजट में जो ड्रोन द्वारा खेती और डिजिटल पेमेंट की बात की गई है, वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन, ग्रामीण एरिया में वाई-फाई की जो स्थिति है और पेमेंट करने के जो तरीके हैं, उसके लिए जिलेवार एक ट्रेनिंग सेंटर अथवा प्रशिक्षण शिविर लगाकर किसानों को ट्रेंड किया जाए, ताकि माननीय प्रधान मंत्री जी की जो सोच है, वह असलियत में आखिरी प्वाइंट तक क्रियान्वित हो सके।

इस बजट में इन्कम टैक्स का स्लैब नहीं बढ़ाया गया है, जो पिछले बजट में पांच लाख और कुछ बेनिफिट देकर साढ़े सात लाख था। कोरोना महामारी में जो लोग घरों में रहे हैं, उनको दो साल बाद मौका मिला है कि वे अपनी जिन्दगी बढ़िया तरीके से शुरू करें। उसके लिए स्लैब को बढ़ाकर 10 लाख तक कर दिया जाता तो कुछ कंपनसेट हो सकता था। अगर माननीय वित्त मंत्री जी इस बारे में सोचेंगी तो अच्छा रहेगा। कोरोना महामारी काल में जो सरकारी नौकरियां थीं, वे दो साल तक अंदर बंद रहीं और उनका समय निकल गया, तो जो नौकरी करने वाली अभ्यर्थी थे, या तो उनकी उम्र दो साल बढ़ाई जाए या उसमें दो साल का एक्सटेंशन दिया जाए, जिससे उन्हें भी न्याय मिल सकें।

अब मैं कुछ अपनी मांग रखना चाहूंगा, नहीं तो आपकी घंटी बज जाएगी। रात के ग्यारह बजे हैं। बिजनौर लोक सभा क्षेत्र, जहां से मैं सांसद हूं। मैं कई बार केंद्रीय विद्यालय का विषय उठा चुका हूं। वहां केंद्रीय विद्यालय खोलने की व्यवस्था की जाए। चांदपुर विधान सभा, जो मेरी लोक सभा क्षेत्र में है, वहां एक रेलवे क्रासिंग है, जनहित में उस पर एक फ्लाई ओवर बनाई जाए। उसमें आधा-आधा किलोमीटर तक लाइन लग जाती है। मीरापुर में शुक्रताल एक ऐतिहासिक जगह है। वहां के एरिया का सौंदर्यीकरण किया जाए। हस्तिनापुर, जिसके बारे में कई बार चर्चा हुई है। मैंने सदन में कई बार हस्तिनापुर के बारे में कहा है। वहां पर एक स्टेडियम बनाया जाए। दिल्ली से सीधी हस्तिनापुर और बिजनौर के लिए रेल चलाई जाए। मेरठ में डिजाइन इंस्टिट्यूट, जिसके बारे में मैंने पिछले बजट में और डिजाइन से संबंधित जब बिल आया था, उस समय भी कहा था। उससे संबंधित एक इंस्टिट्यूट मेरठ में स्थापित किया जाए। (इति)

2257 hours

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Vanakam, Madam Chairperson. This Budget was presented after a hard-hit pandemic which resulted in loss of jobs and income associated with it. The unemployment has touched a four-digit high record. The fiscal consolidation measure of this Government comes at the cost of social welfare spending which can be seen in reduced expenditure to MNREGA, healthcare and rural development. The food and fertilizer subsidy has also seen a reduction. The taxation policy is seen favouring the rich companies. The income tax slab for middle class or salaried class remains unchanged but the Corporate Tax surcharge has been reduced from 12 per cent to 7 per cent.

I would like to thank the Finance Minister for taking care of the poor by reducing import duty on cut diamonds and increasing tax on umbrellas used by the common people. The Maulana Azad Education Foundation which had been allocated around Rs. 70 crore to Rs. 90 crore in the previous years has now seen just an allocation of Rs. 1 lakh which was a disparity. Is it just because this Institute has an Islamic name to it?

At present, the Central Government pensioners are getting fixed medical allowance at Rs. 1000 per month only. Considering the present rise in cost of medicines and treatment, this amount is very less. Hence, the amount may be increased upto Rs. 6000 per month.

One Nation, One Registration is a step to further infringe on State's rights which was raised even by our Tamil Nadu Chief Minister Shri M.K. Stalin. Around eight railway projects in Tamil Nadu have been allocated an amount of Rs. 1000 crore. This Budget favours only the corporates, making rich, the richer; and poor, the poorer. This is not a paperless Budget but it is seen as a people-less Budget.

Thank you, Madam.

(ends)

2259 बजे

श्री दीपक बैज (बस्तर): धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं सामान्य बजट वर्ष 2022-23 की चर्चा में भाग ले रहा हूं। देश का कुल बजट 39.45 लाख करोड़ रुपये का है। यह बजट भारत को 75 से 100 सालों तक और 25 वर्ष तक अर्थव्यवस्था को दिशा देने वाला बजट है।

(2300/SJN/NKL)

माननीय सभापति महोदया, ये मोदी सरकार का देश की आम जनता को सपना दिखाने वाला बजट है, क्योंकि इस बजट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सार्वजनिक उपक्रम, एयर इंडिया, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड और एलआईसी को बेचने का काम किया जा रहा है।

माननीय सभापति (श्रीमती रमा देवी) : माननीय सदस्यगण, अगर आपकी अनुमति हो तो, सभा का समय दो वक्ताओं के बोलने तक बढा दिया जाए?

अनेक माननीय सदस्य : हां-हां।

श्री दीपक बैज (बस्तर) : माननीय सभापति महोदया, देश की विरासत, देश की संपत्ति, जहां इस सरकार और प्रधानमंत्री बनने से पहले कहा था कि हम देश की सुरक्षा करेंगे, हम देश की संपत्ति को नहीं बेचने देंगे, लेकिन अपने चहेते उद्योगपतियों के लिए देश की हर संपत्ति को बेचने का काम किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदया, इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और पूरी सरकार ने महंगाई कम करने का उल्लेख नहीं किया है। गैस सिलेंडर लगातार आसमान के रेट छू रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट्स में लगातार वृद्धि हो रही है। यह सरकार गरीबों की जेबों में डाका डालने का काम कर रही है। रोजगार देने में यह सरकार असफल रही है। मैं प्रतिवर्ष दो करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वाली सरकार से आज पूछना चाहता हूं कि क्या आपने 7 सालों में 14 करोड़ लोगों को नौकरी दी है? आप देश के नौजवानों को 'आत्मनिर्भर भारत' में 60 लाख नौकरियां देने का सपना दिखा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ाई है। इसका उदाहरण बिहार जैसे क्षेत्रों में है। जहां बेरोजगार नौजवान सड़कों पर उतरकर ट्रेनों को जलाने का काम कर रहे हैं, वे नौकरियों की मांग रहे हैं, लेकिन इस सरकार के पास नौकरियां देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये सरकार का नारा है, 'सबका साथ, सबका विकास'। ये जुमला निकला। मैं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सरकार को आइना दिखाने का काम किया है। उन्होंने देश के चंद उद्योगपतियों के पास 40 प्रतिशत धन जमा होने का हवाला दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति महोदया, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। आपकी सरकार में अमीर, अमीर होते गए और गरीब, गरीब होते गए। देश के अमीरों और गरीबों को बांटने का काम किया गया है। आपकी सरकार में किसानों का उल्लेख नहीं हुआ। आपने पिछले एक साल के

आंदोलन में देखा है कि किसानों की क्या हालत हुई है? आपने किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। किसानों को आंतकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आपने किसानों को सिर्फ बदनाम करने का काम किया है।

मैं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने इसी लोक सभा में कहा था कि आपको ये तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे और आपको वापस लेने पड़े। आपने सड़कों के लिए 25,000 किलोमीटर का लक्ष्य रखा है तथा 20,000 करोड़ रुपयों का प्रावधान हुआ है। मैं इस सरकार से पूछता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ के लिए कितनी सड़कों को बनाने का प्रस्ताव रखा है? हम जगदलपुर से रायपुर तक के फोर लेन के लिए लगातार मांग कर रहे हैं, क्या आपने उस सड़क को बनाने का प्रस्ताव रखा है?

माननीय सभापति महोदया, पीएम आवास बनना चाहिए, मैं यह नहीं कहता हूं कि नहीं बनना चाहिए। हर सरकार का सपना होता है कि गरीबों के लिए आवास बने, लेकिन मेरा कहना है कि क्या इससे पहले 'इंदिरा आवास योजना' नहीं बनी थी? क्या ये सरकार पहली बार प्रधानमंत्री आवास बनाकर गरीबों को आवास दे रही है? इससे पहले भी 'इंदिरा गांधी आवास योजना' बनी है और उसमें गरीबों को घर देने का काम किया गया है।

माननीय सभापति महोदया, आपकी सरकार में टैक्स कम नहीं हुआ। गरीबों और छोटे-छोटे फुटकर व्यापारियों पर टैक्स लगा है, जीएसटी का कलेक्शन हुआ, लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार और जहां-जहां गैर बीजेपी सरकार है, आपने उनको जीएसटी का पैसा देने का काम नहीं किया है। आप निश्चित रूप से बदले की भावना से काम कर रहे हैं।

बस्तर में सड़क चाहिए, बस्तर में रेल का विस्तार चाहिए, बस्तर में हवाई कनेक्टिविटी चाहिए। इसके लिए बस्तर की जनता और मैं इस हाउस में लगातार मांग कर रहा हूं। क्या यह सरकार वह मांग पूरा करेगी?

2303 बजे (माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट निश्चित रूप से दिशाहीन बजट है। यह बजट देश को बर्बाद करने वाला बजट है। यह बजट कहीं न कहीं मोदी सरकार के फेल्योर का बजट है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बजट जनता व देश हित में नहीं है। मैं इस बजट को निश्चित रूप से मोदी सरकार का फेल्योर बजट मानता हूं और मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय बजट 2022-23 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

(इति)

*SHRI S. MUNISWAMY (KOLAR): Respected Speaker Sir, The Budget of 2022, envisioned by our beloved Prime Minister Sir and presented by our learned Finance Minister Madam, is one of the best keeping in view that not only India, but the whole world is in the grip of COVID pandemic since last two years. India, under the visionary leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji, has maintained a steady economic growth even in the toughest times in comparison to even the most developed countries of the world.

This Budget is based on main four components i.e. PM GatiShakti, inclusive development, productivity enhancement and investment sunrise opportunities, energy transition and climate action and financing of investments. The PM GatiShakti driven by seven engines, roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, and logistics infrastructure. Also, National Master Plan aimed at world class modern infrastructure and logistics synergy. 25,000 kilometer national highways will be completed during 2022-23, which has never been witnessed before. Open Source Mobility Stack has been brought for seamless and hassle free travel of the citizens of our nation and also Four Multimodal Logistics parks through PPP will be awarded in 2022-23. This scheme also provides 400 new WB generation Vande Bharat Trains.

Under the inclusive development, this Budget provides promotion of chemical free natural farming starting with farmers' lands close to river Ganga; Promotion of post-harvest value addition, consumption and branding of millet products; delivery of digital and Hi-tech services to farmers in PPP mode; use of Kisan Drones to aid farmers; launching fund with blended capital to finance agriculture startups, all of which will strengthen our farmers not only productivity wise but also financially and technologically.

This Budget also made the historic provision of Ken-Betwa Interlinking Project which will benefit 9.1 lakh hectare farm land and will provide drinking water to 62 lakh people and generating 130MW power. Not only that, five more such projects is under process of implementation. Universalization of quality education is the one of its kind which has been provided in this Budget which

* Laid on the Table

makes provisions for One class One TV channel programme which will be expanded to 200 TV channels. Digital University will be established with world class quality universal education. High quality e-content will be delivered through Digital Teachers; startups will be promoted to facilitate Drone Shakti for Drone-As-A-Service which shows the commitment of the Government to modernize the nation via technology. In the Health Sector, National Tele-Mental Health Programme will be launched for quality counseling which will ease the difficulty travelling for the patients, Integrated architecture, Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi under which two lakh Anganwadis to be upgraded to Saksham Anganwadis and Poshan 2.0 to be launched nutritionally enriching the kids and facilitating the Anganwadi workers of our nation.

Apart from this, the Budget has also made the provisions for PM-Awas Yojana under which 80 lakh houses to be completed in 2022-23. PM-DevINE which will fund infrastructure and social development based on felt needs of the North East. There are other programmes like Aspirational Blocks Programme for development of lagging blocks of aspirational districts, Vibrant Villages Programme, targeting development of villages on the Northern Border left out from the development gains, Digital Banking by Post Offices under which 100% of post offices to come on the core banking system. Digital Payments enabling Scheduled Commercial Banks to set up 75 Digital Banking Units in 75 districts.

Overall, this Budget is not only a boon for the people of our country but also shows the commitment of our Government in handling the economy as well as every other aspects of the country in a progressive manner under severe and hardest condition like the COVID pandemic and its dedication towards the service of the nation.

Respected Speaker Sir, with these words, I whole heartedly support the Budget.

(ends)

*SUSHRI DIYA KUMARI (RAJSAMAND): Sir, I stand before this House to congratulate our Prime Minister and the Finance Minister for presenting a holistic Budget that envisions the progress of our nation through the Amrit Kaal and sets out a vision for India at 100.

Along with the rest of the world, India was also affected by the coronavirus pandemic. I would like to express my gratitude to our hon. Prime Minister and everyone in the Government for working tirelessly to develop made in India vaccines and vaccinating lakhs and crores of people. This has helped mitigate the effects of the coronavirus, and even though we lost many precious lives, we were able to contain the spread of the coronavirus. This resulted in our economy growing by 9 per cent, which is the highest among the major economies in the world. Thank you.

This economic performance highlights what heights we can achieve if everyone works hand in hand -- the Government, the industry, and every single citizen of this country. The Make in India campaign has the potential to show the world that world-class manufacturing can indeed happen in India. We can see the initial effects already -- the Make in India campaign has created more jobs and with the hard work put in by the hon. Prime Minister and the Government we have already seen several thousands of startups in the last seven years! In this regard, I would like to commend our hon. Prime Minister and hon. Finance Minister for presenting a forward-looking, development oriented, strong Budget for 2022-2023 that has the potential to be a game changer. A game changer for everyone -- man or woman, rich or poor, people from all classes and including the underprivileged tribal people.

I know that development does not just happen overnight. But this Budget will sow the seeds for development that can be sustained for decades into the future and ensure our progress towards Amrit Kaal (India at 100). Indeed, there are several areas where such seeds are clearly visible. The allocation to capital expenditure has increased by more than 35 per cent, and the Government has clearly signaled its intention of working with the States by allocating an unprecedented Rs. 1 lakh crore interest-free loans. The States

* Laid on the Table

now cannot complain about a lack of funds -- it is time for them to work with our hon. Prime Minister and the Central Government, and ensure that development touches every nook and corner of our great country.

The investment in infrastructure is critical in this regard. I would like to express my gratitude to the hon. Prime Minister and hon. Finance Minister for extending their support for PM Gati Shakti. Along with significant upgrades to high-speed passenger rail and commercial rail, the Budget envisions adding a further 25,000 kms. to the National Highway network, thus providing much needed connectivity even to rural areas and remote villages. India cannot develop without development in the villages, and this is a significant step in that direction.

I note that the Budget also has provisions that will improve the daily lives of the common people, both in urban and rural areas. The emphasis on clean energy will reduce air pollution and improve the health of citizens. The expansion of the Jal Jeevan Mission with a significant allocation of Rs. 60,000 crore and the interlinking of the six rivers will ensure "Har Ghar Jal" by ensuring the availability of water for every household. It will reduce the burden on women who often have to trek several kilometers to secure water for cooking and drinking.

I will be remiss if I do not mention the Budget's provisions for technology, especially its focus on using technology for improving the lives of the poor and the underprivileged. Initiatives such as using digital currencies, Kisan Drones to facilitate crop assessment, and the auctioning of the 5G spectrum have the potential to profoundly change every household's life for the better whether they are in cities or in the villages.

There are many initiatives that aim to support women, children, and others who often feel left behind. I would like to specifically mention the extension of Poshan 2.0, increasing the number of Saksham Anganwadis to 2 lakh anganwadis, extending the Emergency Credit Line Guarantee Scheme for MSMEs (many of which are run by women and people in rural areas), expanding the one class-one TV channel program of the PM eVIDYA program to 200 TV channels so that students can access quality education even in regional languages, extending support for divyangjans, the Tele-Mental Health Programme (which is especially important given the impact of the coronavirus

pandemic).

This is indeed a forward-looking Budget that aims to improve the lives across the board -- no nation can afford to exclude a large part of the population from contributing to national development. The provisions in the Budget will help ensure that women can lead the nation's developmental efforts towards Amrit Kaal from the front by taking the lead in areas ranging from health, education, technology and business. Women will increasingly be able to compete in the emerging STEM fields and become entrepreneurs who will then employ other people, thus accelerating the nation's development. During the able leadership of the hon. Prime Minister, we are already seeing women leading some of the most successful companies that have gone public in India. I have no doubt that under his inspiring leadership, this trend will not only continue but will accelerate.

If we want a strong and vibrant India, an India that is a vital cornerstone of democracy and one that will play an important role in ensuring peace and prosperity in an increasingly divided world, then we will have to ensure that every single Indian contributes to making India strong. Thank you, hon. Prime Minister and hon. Finance Minister, for a Budget 2022-2023 that is a strong step in that direction. Jai Hind.

(ends)

*SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Sir, with the permission of HON. Chairperson, I want to raise few demands for the people of my constituency Tiruvannamalai in Tamil Nadu. I would like to request the Government to please include these demands for funding through this grants of Budget.

There is a need for quick completion of Tindivanam-Krishnagiri NH 77 road project work. There is an urgent need for budgetary allocation of fund and expediting the Tindivanam to Tiruvannamalai new railway line construction work and the urgent need for desilting for Satnur Dam. A new airport for Tiruvannamalai under the PM Gathi Sakti Scheme is required which would facilitate large number of international and domestic tourists and pilgrimage. Most of the people of my constituency are dependent on agriculture. There is an urgent need to set up agro-based industries at Tiruvannamalai and Tripattur areas.

Tiruvannamalai has huge tourism potential. To promote the same there is an urgent need for a Special Package for overall development of Tiruvannamalai parliamentary constituency. Allocation of funds for development of Melchangam, underused forest land. Apart from this, the area needs more railway infrastructure for better railway connectivity. Hence, I would request the hon. Minister and this Government to allocate funds for overall development of my constituency area.

(ends)

* Laid on the Table

*SHRI A. GANESHAMURTHI (ERODE): Sir, I would like to participate in the general discussion on General Budget for the year 2022-23.

I oppose the Budget proposals made by the hon. Finance Minister since there are no measures in the Budget which would bring employment opportunities, more growth rate or relief to poor and marginalized people. There are no schemes in the Budget for providing package to the farmers and other people engaged in horticulture, fishing, honey bee breeding etc., to provide some relief during the Covid pandemic period.

Make-in-India Scheme is limited to sloganeering only and the efforts being made by this Government point to the direction of Sale India. They are privatizing all the public sector undertakings even those which are making profit like LIC, BPCL etc. In the last seven years of NDA rule, people are losing employment opportunities and you will see, recently there was violence and students and candidates have resorted to agitation during the railway recruitment examinations held in Bihar, citing malpractices and irregularities in recruitment of various posts.

Previously, Staff Selection Commission used to conduct examinations for filling up of various posts in the Government Departments region-wise. But for last eight years, examinations are held at centralized level and with the result, our candidates belonging to Tamil Nadu are losing the chance to get entry into the Government Departments. In the year 2013, out of 8243 posts all over India in Departments like Income-tax, Central Excise, Customs and Accountant General's Office, 949 posts were allocated to the State of Tamil Nadu. Out of them, only 52 candidates belonged to Tamil Nadu and 897 candidates, that is, 94 per cent of the posts in Tamil Nadu were taken by the candidates belonging to other States.

Similarly, in 2014, 97 per cent of the posts, that is, 508 posts out of 522 were taken away by outside candidates. In 2015, 95 per cent of the posts were filled by outside candidates. The trend is continuing year to year and because of this, the local youth who deserve employment in the Government

* Laid on the Table

Departments are getting agitated as their dues are denied by the candidates who usurp all these posts.

There is a persistent demand among the people that the recruitment examinations should be held region-wise as being done earlier and the candidates should be allowed to write their examination in their own regional languages also so that equal opportunity is being given to all the candidates.

The manufacturing sector is affected the most along with MSME sector, because of the pandemic. But I do not find any scheme provided in the Budget for the uplifting of these sectors. In the income-tax ceiling limit, there is a demand for raising the exemption from income tax up to Rs. 10 lakh. The Government should also raise the limit of tax rebate under 80C up to Rs. 3 lakhs, instead of Rs. 1.5 lakh, since the ESI, PF contributions were hiked, so that the workers could get the benefit.

I am coming from the region where hosiery industry, textile industry is concentrated, namely Erode, Tiruppur etc. I have already requested the hon. Finance Minister to reduce the GST on yarn since it is affecting the power loom industry. The yarn prices are skyrocketing and the Government should do something to control the price. Cotton should be procured directly by the Government agency and distributed through their channel so that the price can be regulated.

We strongly oppose the policy of NDA Government to bring one nation-one language, one nation-one religion, one nation-one culture, one nation-one tax, one nation-one education, and one nation-one registration. This is nothing but imposing its authoritarianism on the people of the country and the States. India is a multi-lingual, multi-cultural State with diverse ethos and traditions and that is the ‘Unity in Diversity’. We strongly condemn the attitude of the Union Government to encroach upon the powers of the States and undermining the autonomy of the States.

The hon. Finance Minister announced in the Budget speech that the GST collection for the month of January has exceeded Rs.1,41,000 crore. But this is being paid by the people from various States and, therefore, the Government should not delay in payment of GST arrears to the States. The allocation of financial resources from the divisible pool should be done to various States without any discrimination.

I find there is no specific scheme for railway workers and projects in the State of Tamil Nadu. I would request the hon. Finance Minister and the Railway Minister to pay attention to the State of Tamil Nadu, since our State is continued to be denied the benefit for the last 7 years. I have some demand specific to my constituency Erode for reconstruction of the Road under Bridge (RUB) as follows: Dharapuram Road (SH 83A) in lieu of existing Railway Bridge No. 352 at Railway KM 391/900 - 392/000 at Erode Railway Yard, Solar Bridge (Nilgiris) Bridge No. 375 KM 2/400 (Vendipalayam Barrage) to Karur Bypass State Highways Road No. MD 110, Bridge No. 361 KM 295/100 KK Nagar, Erode to Chennimalai Road, Road No. MD 108, Bridge No. 371, KM 402/600, Pungambadi Road (ODR), Mettukadai to Vellode Road, and Bridge No. 378, KM 406/300, Perundurai RS, Perundurai to Chennimalai Road, No. MDR 1137.

The Railways have announced resumption of normal train services all over the

country. However, in my constituency Erode and the region around it, they have not restored express trains and passenger trains which is causing hardship to daily commuters and travelling public.

From Erode to Tiruppur and back, MEMU trains were running and thousands of daily commuters were using it for going to their place of work and back home. Similarly, the following passenger trains are also to be resumed: Train No. 66601 - 66600 - Erode-Coimbatore-Erode Passenger, Train No. 66608 - 66609 - Erode -Palakkad Town-Erode Passenger, and Train No. 66602 - 66603 - Coimbatore - Salem - Coimbatore Passenger.

I also demand that Izzat Season Ticket Scheme which was useful for the daily wagers and labourers for travel should be reintroduced for the benefit of workers in the industrial areas like Tiruppur, Coimbatore, Karur, Salem, etc. I have raised this matter in the Zero Hour also.

(ends)

*SHRIMATI SUMALATHA AMBAREESH (MANDYA): Hon'ble Speaker, Sir, thank you for allowing me to participate in the discussion on General budget presented by the hon. Finance Minister for the year 2022-23.

As per the budget announcement, the Government is estimated to spend Rs 39,44,909 crore during 2022-23. This is an increase of 4.6 per cent over the revised estimate of 2021-22. The central government also proposes to transfer Rs 16,11,781 crore to states and union territories in 2022-23. This is a marginal increase of 0.5 per cent over the revised estimates of 2021-22.

India is achieving its target towards becoming a global leader in digital payments. The government-backed payment system has shown the positive trend. Prime Minister's Jan Dhan scheme has enabled millions of unbanked poor families to enter the formal economy. This is a huge step in the right direction, especially since it allows the direct transfer of cash benefits, cutting out middlemen.

Union government has been laying 36km (22 miles) of highways a day on average, compared to his predecessor's daily count of 8 11km.

Installed renewables capacity - solar wind has doubled in five years. Currently at about 100 gigawatts, India is on track to achieve its 2023 target of 175 gigawatts. The government has done well with other populist signature schemes millions of new toilets to reduce open defecation, housing loans, subsidised cooking gas and piped water for the poor. But as per the available reports many of the toilets aren't used due to lack water availability.

The sugar sector is an important agro-based sector that impacts the livelihood of about five crore sugarcane farmers and their dependents and around five lakh workers directly employed in sugar mills, apart from those employed in various ancillary activities including farm labour and transportation. In my Lok Sabha constituency Mandya, major crop is sugarcane. So FRP (fair
and remunerative price) paid to sugarcane growers.

The union government approved Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane for sugar season 2021-22 (October September) at Rs 290 per

* Laid on the Table

quintal last year. So, the new rate is Rs.290/quintal or Rs. 2,900/tonne. However, farmers in Karnataka were unhappy with the hike as the cost of production is very high.

The Department of Agriculture has accepted that the cost of production for one tonne of sugarcane is Rs. 3,200, but the Central government has fixed a rate of Rs. 2,900 per tonne. This is a loss for the farmer.

Hence, I urge upon the union government to take necessary measures to safeguard the interest of the sugarcane farmers of my Mandya district and also of the country.

India has among the lowest levels of public spending on healthcare in the world. Like previous governments, this one has continued to neglect healthcare. scheme, launched in 2018, appears to have been under-used even during Covid.

I would like to suggest that Government of India needs to use Covid as a wake-up call to invest heavily in strengthening primary healthcare.

While MSP is announced for 23 crops every year, public procurement is limited to a few crops such as paddy, wheat, and, to a limited extent, pulses.

I am of the opinion that the government should take necessary steps to procure more crops to help the farmers. The BJP on the demand of minimum support price plus 50 per cent, gave a version that satisfied no one There are reports on shortcoming in the implementation of MSP. Mainly, procurement is largely from a few states. And lack of awareness among farmers before the sowing season. Increasing cost of transportation for farmers, and also there is an inadequate storage capacity.

Therefore, I would like to suggest that the government should address these issues to ensure benefits for the farmers.

I would like to suggest that the agricultural pricing policy needs to be reviewed to ensure that farmers are receiving remunerative prices for their produce. Farmers are often forced to engage in distress sales, i.e., selling below MSPs.

At the outset I congratulate the hon'ble Finance Minister Nirmala Sitharaman ji for encouraging ethanol blending program. At present the average blending ratio for petrol sold by state companies is 8 per cent. Target is to rise to 20 per cent by 2025.

And, state-run oil companies, which control 90 per cent of the fuel retail pumps, sell ethanol spiked petrol in most parts of the country while private retailers do not sell it as they sell only unblended petrol. The Budget proposal will disincentivise the sale of unblended petrol. All oil companies will make an extra effort to source ethanol. So, it will accelerate our path to blending. Therefore, I congratulate the government for priorities the blending of fuel by announcing an additional excise duty of 22/ litre from the 1st day of 20 per cent blending. Therefore, I congratulate the Government for prioritising the blending of fuel by announcing an additional excise duty of Rs.2/litre from the 1st day of October 2022.

Incentives given to the Anganwadi workers is minimal. Incentive and honorarium. amount to anganwadi workers extending services at village level under women empowerment department.

At present there are around 65911 Anganwadi centres are functioning in Karnataka state. Out of them 2546 Anganwadi centres functioning in my Mandya parliamentary constituency. Anganwadi workers are paid Rs. 10000/- per month and Assistants are paid Rs. 5000/- per month and Mini Anganwadi workers are getting only Rs.6250/. getting only Rs. 10000.

Their long-pending demands. Incentives given to the Anganwadi workers is minimal, and in that too the state government's share is more. Anganwadi unions call for protest against the Union government to address their demands for minimum wages instead of honorarium and higher allocation for nutrition.

As we all know, their workload increased due to COVID-19-related responsibilities or for nutrition, especially when food insecurity worsened and India ranked 101 out of 116 countries in the Global Hunger Index.

They are the ground workers who have been taking care of the children the grassroots level.

The recent Niti Aayog report that suggested better sanitation facility for the Anganwadi workers and pleaded for better infrastructure development for health workers.

The Ministry of Women and Child Development will extend support to over 2,00,000 anganwadis, to upgrade them as Saksham Anganwadis under the umbrella scheme of Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0.

Hence, request upon the union government under that the new scheme their demand should considered increase honorarium of Anganwadi workers, Mini Anganwadi workers and assistants.

The budget announced the support river-interlinking projects including Krishna, Pennar Cauvery. Karnataka has extending support to river-linking scheme. However, my state has demanded its share in surplus water. That is why the projects related Krishna, Pennar, Cauvery are of concern to Karnataka. Though river water disputes between riparian states have more or less been settled by various commissions, sharing surplus water continues to be a contentious issue. Therefore, peninsular rivers should not be interlinked before the state's share of surplus water is finalized.

Hence would like to say that proposal interlinking of rivers transfer surplus water from Godavari Krishna Cauvery a decision. However, the benefit transfer surplus water must accrue equally to Karnataka.

In our country, farmers are trying to shift from primitive cultivation methods to technology driven cultivation methods in the recent times. Traditionally-used plough and relevant native accessories are replaced with tractors, triller and weed cutters etc. As there is increase in the use of machineries and equipment, the farmers are facing difficulties in the absence of skilled manpower to maintenance and repair of the farm machineries.

Maintenance and repair of the equipment are causing great financial burden and worrisome for the farmers. Though the companies take care within the warranty period, thereafter farmers are facing great difficulties for repairing equipment such as tractors and instead force farmers to hire outside contractors, which is not economically feasible. Therefore, I would like to request the government to provide skill training to youth in rural India for repair and maintenance.

PM-SVANidhi Scheme has facilitated collateral free working capital loan up to Rs.10,000/- for one-year tenure to street vendors, to help them resume their businesses. Under this scheme, amount of Rs 2641.46 crore has been disbursed to 26.46 lakh beneficiaries.

With the regard to Housing for All by 2022, I would like to say that it is a very good initiative by the Union government, But the scheme is not properly

implemented and real beneficiaries are not getting the benefits of the Housing scheme.

However, there is a need for review of the implementation of the scheme. Out of the total 4.3 crore persons earmarked for the scheme, only 2.32 crore have become eligible after verification by Gram Sabhas, The possibility of a politically motivated approach in identification of beneficiaries. To ensure proper identification of beneficiaries, So, there is a need for downsizing the role of Gram Sabhas and Panchayats in identification of beneficiaries and roping in private/ non-governmental bodies for verification and authentication.

I would like to suggest that the government should take necessary steps to streamline the identification of beneficiaries for incorporation of a block development officer for oversight and also to take steps to transferring ownership of the housing unit to the designated nominee after the death of a beneficiary. So that real beneficiaries would get the benefits of the scheme.

The overall economic, employment situation in the country has been a matter of grave concern for all of us due to Covid-19 led crisis. The widespread havoc that it inflicted on the economy.

While MSP is announced for 23 crops every year, public procurement is limited to a few crops such as paddy, wheat, and, to a limited extent, pulses. I am of the opinion that the government should take necessary steps to procure more crops to help the farmers. The BJP on the demand of minimum support price plus 50 per cent, gave a version that satisfied no one.

There are reports on shortcoming in the implementation of MSP. Mainly, procurement is largely from a few states. And lack of awareness among farmers before the sowing season. Increasing cost of transportation for farmers, and also there is an inadequate storage capacity.

Therefore, I would like to suggest that the government should address these issues to ensure benefits for the farmers.

I would like to suggest that the agricultural pricing policy needs to be reviewed to ensure that farmers are receiving remunerative prices for their produce. Farmers are often forced to engage in distress sales, i.e., selling below MSPs.

India has a real opportunity to become a global leader if it chooses to focus strongly on ethanol made from a by-product of the sugar industry, namely molasses and farm wastes. This would help our farming community and also bring a strong. climate and air quality benefits, since these wastes are currently often burned, contributing to smog. Therefore, I would like to suggest that the government should take firm steps in this regard to provide benefits to the farming community. particularly for sugarcane growers.

India is one of unique countries in the world that has the legacy of diversity of languages. Among these three languages, Sanskrit, Tamil and Kannada have been recognized as classical language with special status and recognition by Government of India.

The government is not funding adequately for the promotion of Kannada as a classical language.

Classical language Kannada Rs.1 crore in 2017-18, Rs. 0.99 crore (Ninety nine lakhs) in 2018-19 and Rs. 1.07 crore in 2019-20. Rs 643.84 crore on the promotion of Sanskrit in the last three years, which is 22 times the total amount of Rs 29 crore spent on the other five classical Indian languages - Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and Odia.

During the same period the funds given to Tamil was Rs.10.59, Rs. 4.65 and Rs. 9.80. Rs.11.73 crores allocated during 2020-21. Till date Tamil language. received nearly Rs. 50 crores. However, it is only Rs. 8 crores to Kannada language.

Hence, I urge the union government to do justice to Kannada language and people of Karnataka by releasing adequate funds.

(ends)

*SHRI NALIN KUMAR KATEEL (DAKSHINA KANNADA): Hon'ble Speaker sir, thank you for allowing me to participate in the discussion on General Budget presented the hon'ble Finance Minister for the year 2022-23.

Budget is the government's blueprint on expenditure, taxes it plans to levy, and other transactions which affect the economy and lives of citizens. The government is estimated to spend Rs 39,44,909 crore during 2022-23. This is an increase of 4.6% over the revised estimate of 2021-22.

This Budget lays blueprint for the Amrit Kaal, which is futuristic and inclusive. This will directly benefit our youth, women, farmers, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. II. Big public investment for modern infrastructure, readying for India at 100. This shall be guided by PM GatiShakti and be benefited by the synergy of multi-modal approach.

The country is progressing. Factories are being set up. Nearly 1,80,000 crore rupees have been given to more than I l crore farmer families through 'Kisan Samman Nidhi Yojana'.

The government has started 'Swamitva Yojana' to provide documents to the people in rural areas for their properties. So far more than 40 lakh property cards have been given in 27,000 villages.

The government has started 'Kisan Rail Seva' for farmers to get higher price for their crops, to promote their produce and so that their goods can reach the market.

For the first time in the world, the World Health Organization is going to set up a Global Centre for Traditional Medicine in India.

India has also taken Green Grid Initiative - 'One Sun', 'One World', 'One Grid’ by taking the world community along.

Women empowerment is the biggest example of the success of 'Ujjwala Yojana’. Through ‘Mudra Yojana’, the enterprise and skills of the mothers and sisters of our country are being promoted.

- As far as employment generation is concerned, the most growth of 152 percent has been recorded in the IT/BPO sector, while growth rates in Health is 77 percent, in Education it is 39 percent, in Manufacturing it is

* Laid on the Table

22 percent, in Transport it is 68 percent and in Construction it is 42 percent.

- Under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY), Government of India has contributed both 12% employer's share and 12% employee's share under Employees Provident Fund (EPF), totalling 24% of the wage for the wage month from March to August, 2020 for the establishments having 100 employees with 90% of such employees earning less than Rs. 15000/-. This has helped in providing employment in EPFO registered establishments during post Covid period.
- Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY) has been launched with effect from 1st October, 2020 as part of Atmanirbhar Bharat package 3.0 to incentivize employers for creation of new employment along with social security benefits and restoration of loss of employment during Covid-19 pandemic. This scheme being implemented through the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), seeks to reduce the financial burden of the employers and encourages them to hire more workers. The terminal date for registration of beneficiaries has been extended from 30 06.2021 to 31.03.2022. Benefits have been provided to 39.59 lakh beneficiaries through 1.17 lakh establishments.
- The Government launched the Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan (GKRA) of 125 days on 20th June, 2020 to boost employment and livelihood opportunities. The Abhiyaan has achieved an employment generation of 50.78 crore person-days with a total expenditure of Rs 39 293 crore
- Prime Minister Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme has been launched on June 01 , 2020 to provide working capital loans to Street Vendors, vending in urban areas, to resume their businesses, which were impacted adversely due to COVID19. Under this scheme, amount of Rs 2641 46 crore has been disbursed to 26 46 lakh beneficiaries.
- Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) is being implemented by the Government for facilitating self-employment. Under PMMY collateral free loans up to Rs. 10 lakh, are extended to micro/small business enterprises and to individuals to enable them to setup or expand their

business activities Up to November 2021, 31 28 crore loans were sanctioned under the scheme

- PM-SVANidhi Scheme has facilitated collateral free working capital loan up to Rs. 10,000/- for one-year tenure to street vendors, to help them resume their businesses. Under this scheme, amount of Rs 2641.46 crore has been disbursed to 26.46 lakh beneficiaries.

River-interlinking projects:

The budget announced the support to river-interlinking projects including to Krishna, Pennar and Cauvery. Karnataka has been extending its support to the river-linking scheme. However, my state has demanded its share in surplus water. That is why the projects related to Krishna, Pennar and Cauvery are of concern to Karnataka. Though river water disputes between riparian states have more or less been settled by various commissions, the sharing of surplus water continues to be a contentious issue. Therefore, peninsular rivers should not be interlinked before the state's share of surplus water is finalized.

Hence, I would like to say that the proposal of interlinking of rivers to transfer surplus water from the Godavari to Krishna to Cauvery is a right decision. However, the benefit of transfer of surplus water must accrue equally to Karnataka. With these words I conclude my speech. Thank you.

(ends)

*SHRI GAUTHAM SIGAMANI PON (KALLAKURICHI): One of the characteristics of the present Government headed by Mr. Narendra Modi is that it never cares for the under privileged people of this country and it never attempts to hide that as well. Every budget presented by this Government is evidence of that. It is to empower the rich in the furtherance of profit building and expose the rest of the nation to this atrocious act. This budget, which proudly announces the proposal to reduce GST on Diamond Jewellery is a marker. This budget which must have had the priority in rebuilding the Nation ravaged by the pandemic and extending support to the worst affected lower middle classes and poor has absolutely failed them in every way.

The Finance Minister has increased the budget allocation for infrastructure expenditure by 35.4 per cent to Rs. 7.5 lakh crore, which could be called fine. But that being compensated by reduction in the allocation to MGNRGEA scheme is absolutely not acceptable. One does not understand the logic behind such high-handed acts. Excuses like infrastructure projects compensating MGNRGEA labour is not convincing at all. That too a Government that invests in public sector enterprises with a motive to monetize/sell them off to its Patron Industry Bosses at a throwaway price is a crime against the ordinary people. Developing infrastructures at the common man's money and handing them over to private sector to loot is nothing but swindling Government to benefit friends of the ruling people.

There are two key allocations to health and education which does not make any sense. A Nation still under pandemic threat and a vaccination programme that has not covered the entire population of the country chooses to reduce the allocation to health sector. The budget proposes to reduce the allocation to Rs. 41,101 crore for the next fiscal from the current year's allocation of Rs. 74,820 crore. Is the Government under the impression that the pandemic situation is over and has been tackled effectively? The process of vaccination is not over yet but the Government is comfortably relaxing. It is true that Modi's Government always was callous in handling the pandemic and was quick to blame the States for all kinds of failures.

---

* Laid on the Table

More alarming is the allocation to education. The budget allocation for education for the next fiscal is Rs. 93,224 crore of which Rs. 38,350 crore is towards higher education and Rs. 54,874 crore for school education. But this allocation is Rs. 6087 crore less than current fiscal's allocation. The nation has almost lost two years of education. The online classes managed were just an effort to keep the children connected and this too was not effective in the case of poor and under privileged people. Most of them need to be updated through novel and innovative programmes, but a Government that reduces the allocation cannot be understood. The Government which proudly showcases the Eklayva Schools for the tribal children cannot be expected to act better. Eklayva who had to lose his thump for 'learning' was a victim of sanatanic brahminism and the BJP party that runs this Government which wants to make India a Hindu Nation cannot be expected to do otherwise.

(ends)

*SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI): Hon. Speaker Sir, thanks for giving me opportunity to speak. Sir today, I am here to oppose the Union Budget 2022-23. Our Finance Minister presented a Budget with no aim and care for the general public. Let us discuss point by point.

First of all, India's GDP is totally dependent on agriculture sector. What has Madam given for agriculture unit? Our farmers are suffering today with a heavy debt. They were promised for MSP and various demands were supposed to be fulfilled. But in this Budget, they are given only and only disappointment.

Secondly, Sir, mainly the Budget of any country is decided on the income via taxes. Our middle-class man is suffering from heavy tax rates. Inflation is increasing rapidly but the tax slab for an employed person remains the same. Then how will it be possible to pay these taxes with a ta slab with old calculation of inflation?

Simply this Budget is making poor people poorer. Also, there is a new clause of tax on cryptocurrency and that is only on profit part. If you suffer loss, then also you have to pay the taxes. So, this is also against the normal humanity.

There is nothing for the youth in this Budget. As you are aware, Sir, the unemployment rate is very high in our country. They can simply shut down the organisation who tell the unemployment rate but cannot control the unemployment. This seems to be funny but this is true, Sir.

There is a lot of disappointment everywhere for this Budget in every sector. For students, they make promises in election only and not in Budget.

For industry, nothing better is given but same as all time. For this difficult time, it should be responsibility of the Government to give relief to a middle-class man as well as the industry sector persons. GST rates on many items should be slashed and inflation should be in control.

So, there is nothing in this Budget. With these words, I strongly oppose this Union Budget 2022-23. Thank you.

(ends)

---

* Laid on the Table

*SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): Hon'ble Speaker Sir, while we are standing at the cusp of becoming an economic superpower under the leadership of the Hon'ble Prime Minister, the Union Budget 2022 comes as a decisive and crucial step towards holistic and sustainable development. This budget is path-breaking in many ways. Against the backdrop of the pandemic, only our committed Hon'ble Finance Minister like Nirmal Sitaramji could have brought out a growth-supportive yet inclusive budget. Under the visionary guidance of Hon'ble PM Modiji, Hon'ble FM has created an atmosphere of optimism and enthusiasm with this budget.

This budget is a people-centric and progressive blueprint for our country. We have embarked upon this progressive journey in the year 2014 under Hon'ble PM Narendra Modiji and now, we are marching with unprecedented speed towards आत्मनिर्भर भारत.

We have been crossing milestones after milestones in terms of infrastructure development by our government. It is a proven fact that the nation which invests in infrastructure leads on the path of development. Looking at the prominence given to PM Gati Shakti, Inclusive Development, Productivity Enhancement, sunrise opportunities, energy transition, and climate action, I do not doubt that this path will lead us to a new pinnacle of development. A well-balanced approach that will boost manufacturing and agri-economy along with encouragement to start up industries is the hallmark of budget 2022. This is no surprise that the budget has brought cheers from all sectors of the economy.

Even while there are repercussions of Covid -19 pandemic on the entire global economy, including our country, the Hon'ble finance minister has chosen not to burden the common man with additional taxes. The outlay for capital expenditure stepped up by 35.4 pc i.e Rs 7.5 lakh crore. It's a sensitive approach for an economic rebound with higher spending on infrastructure, without tinkering the tax slabs. This approach is aligned with the government's commitment of 'HOT HY Hoont faol. The short-term and long-term structural emphasis in this year's budget will lay the foundation for a strong economy.

* Laid on the Table

Digitalization, Urban development, and sustainability at its core, this is one of the most futuristic budgets. Dignified life for every poor family is something that our government is committed to. Rs 60,000 cr is allocated to provide tap water connections to 3.8 crore households in 2022-23. With an outlay of Rs 48000 crores under Pradhan Mantri Awas Yojana and construction of 80 lakh homes will facilitate affordable houses.

There is a much-needed emphasis on ease of doing business. This is linked to employment generation. 75,000 compliances have been eliminated and 1,486 union laws repealed to make it easier for businesses. There is a new confidence in the air because of this budget. My constituency has a huge presence of MSMEs and in the past 8 years, the bottlenecks and issues have been resolved by the government. Even remote area like my constituency has seen continuous infrastructure up- gradation in terms of railways, highways, and airports. Institute of Teaching and Research in Ayurveda-(ITRA) Jamnagar is an institute of national importance dedicated to Ayurveda. I feel proud to be part of the government which respects our culture and strives to strengthen our knowledge systems.

Recently, Khijadiya of my constituency was declared as Ramsar site- a wetland of international importance. It is possible only because of the continuous conservation efforts of the government. Hon'ble PM Modiji's vision to revive the past while taking progressive actions for environmental protection and climate change is commendable. While our commitment to green energy is being watched by the entire world, the budget announced an additional 19,500 crore for PLI in solar PV module manufacturing. Electric vehicles are being specifically encouraged not only by boosting manufacturing but also with mobility zones declared. The budget announced a battery swapping policy with interoperability at its core as key measures to pave the way for fast charging infrastructure. 'Battery as a service will be developed as a new business model. All these are historic steps for which the young generation will thank us for adopting green vehicles and de-carbonize India's economy. This budget is also proof of the dynamism and farsightedness of our leadership. Spectrum auction will be conducted to roll out 5G mobile services within 2022-23. There is an optimistic and enthusiastic wave among start-ups, with the government's

slew of initiatives in the Budget aimed at facilitating growth for these new businesses.

Amidst the worst calamity of the century, the youth, farmers, and business community can the possibilities of growth and development. Our indigenous vaccine invention, the largest vaccination drive, and food-ration distribution mission proved our strength and sensitivity as a nation. In the worst pandemic of history, our government ensured nobody goes hungry. The focus on accessibility and digitalization of education is a ray of hope. Amid the prolonged impact of pandemics on learning due to the closure of schools, we have also learned a lot about online education. The new e-learning content delivery platforms, TV & Radio can bridge the gaps in learning across sections. A crucial component is also the provision of supplementary teaching aids in regional languages. This will certainly improve learning outcomes by overcoming language barriers. Aiming to attract world- class foreign institutions to Gandhinagar GIFT city, they will be allowed to offer courses in financial management, fintech, science technology, engineering, and mathematics without regulatory bottlenecks. This is not a 'gift' to only the youth of Gujarat but to the youth in the country. For youth, another great news is the increased allocation of Rs 3062 crores for sports. Our country's success in the recent Tokyo Olympics and Hon'ble PM's personal attention to athletes and sportspersons have influenced the mindsets of our entire nation in a very positive manner. I am an enthusiastic supporter of sports culture and I am sure, this budget will start a new era for sports in our country.

Since the present Government has taken over, there has been an economic transformation. The focus of the budget is to spend more in rural areas, infrastructure, and poverty alleviation, yet maintain the best standards of fiscal prudence. One of the many takeaways from the budget is the innovative reforms in the farm sector. There will be a big technology push to the farm sector, proposing delivery of hi-tech services to farmers and the use of Kisan Drones to aid them for multiple activities. This will be useful for farmers in crop assessment, digitalization of land records, spraying of insecticides and nutrients. In a bid to boost farmers' income in the allied sector, Animal husbandry, and dairying have been increased by 44% to 6407.31 crore and food processing industries by 2.25 times to 2941.99 crores.

As much as the Government is focusing on rural India, on agriculture, and farmers, the Government is equally committed to developing infrastructure. The 7 engines mentioned by Hon'ble Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitaramji will drive our country towards an unprecedented growth path. Railways, roads, airports, ports, mass transport, waterways and logistic infrastructure are key areas and I congratulate Hon'ble FM and PM for emphasizing on all of them in this budget. 400 new generation Vande Bharat trains to be manufactured in the next 3 years and 2,000 km of the rail network will be brought under indigenous technology. The national highway will be expanded by 25000 kilometres in the year 2022-23.

नारी शक्ति is the harbinger of India's bright future and accordingly, Mission Shakti, Mission Vatsalya, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be strengthened this year. The budget allocated to the women and child development ministry is Rs 25, 172 crore -3% more compared to the previous year. There are a number of initiatives marking it '3147 ICT for Women-led development. There is 16% hike for the health sector with an outlay of Rs 86,200.65 crores. With the announcement of a national tele mental health program and the roll-out of the national digital health ecosystem, we are entering into a more progressive health sector reform era.

The budget is aimed at taking forward economic reforms. The country's development is not only dependent on the services and sectors but on also on the people. It's the people who make our nation and this Budget is aimed at improving everyone's life in some form or the other. We are witnessing a change...

A change from despair to hope; a hope ignited by the vision of our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji. It is a vision that would bring dignity and honor to every Indian family! It is also a vision to build the nation of our dream!

Thank You!

(ends)

*DR. TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): Respected Speaker, thank you very much for this opportunity to respond on union budget 2022-23.

1. The finance minister's budget speech didn't mention any major announcements on Agriculture. Even though this Government promised our Kisans of country to double the income of theirs by 2022. We must not forget that we entered in the year 2022. Whose incomes doubled? in which state? In which District? Better known to the Government.
2. The budget mentioning the year 2023 has been announced the international year of millets. Thanks for the finance minister for the support given to millets and oilseeds.
3. It's irony that very important and crucial schemes for sustainable to agriculture and schemes related to food security have been reduced drastically. The price stabilisation fund has been reduced by 44%, allocation of National Security Mission 33% decline and National Horticulture Mission 20%.
4. It is happy to note that 86% increase in Prime Minister Matsya Sampada Yojana. But no substantive increases for Dairy development and Animal Husbandry development.
5. The revamp and renaming of all Agricultural schemes not been increasing of allocations for the revamped RKVY as compared previous year as compared previous year.
6. There is urgent need for a more inclusive policy paradigm that focuses on rain fed and dry land agricultural practices landless farmers, tenant farmers, women farmers as well as agriculture labourers with in farming community.
7. In this context, I request the Government to confer Special category status to my state of Andhra Pradesh without further delay and complete all the promises made under provisions of Andhra Pradesh reorganisation 2014.

(ends)

* Laid on the Table

***श्री देवजी पटेल (जालौर):** आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने एक ऐसा विलक्षण बजट 2022-23 प्रस्तुत किया है जो बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है, में इस बजट का तहेदिल से समर्थन करता हूँ, तथा माननीय वित्त मंत्री जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ऐसा दूरदर्शी बजट पेश किया है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती देने वाला साबित होगा।

ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा सच तो यह है कि यह बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है. इससे ग्रीन जॉन्स का भी क्षेत्र और खुलेगा, इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है- गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है।

यह बजट More Infrastructure More Investment More Growth, **और** More Jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। भारत के कोटि-कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 परसेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के डैम सेक्टर को मिलेगा।

किसानों के लिए भी ये बजट काफी महत्वपूर्ण एवं फायदेमंद है। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं की कृषि लाभप्रद हो, इसमें नये अवसर हो। नए एग्रीकल्चर स्टार्ट अप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज, इससे किसानों की आय बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी. डैच खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में सवा दो लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। उल्लेतखनीय है कि विगत किसी भी सरकार के काल में किसानों से एम एस पी पर की खरीद के पैसे उनके खातों में सीधे ट्रांसफर नहीं किए गए।

कोरोना काल में MSME यानि हमारे छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए थे। अनेक प्रकार की मदद पहुंचाई थी। इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 परसेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के डैडा सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। साढ़े 7 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक

* Laid on the Table

इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही, छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे।

सच कहा जाए तो यह एक ऐसा दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इससे पहले भी एक तरह से पांच मिनी बजट पेश हुए हैं। यह बहुत ही शानदार बजट है इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। रक्षा क्षेत्र के बजट में बढ़ोतरी हुई है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने का बजट है। इस बजट को सभी सेक्टरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है,स्वास्थ्य सेक्टर में लगभग 137 की वृद्धि की गई। यह बजट 70,000 गांवों को मजबूत करेगा। 602 गांवों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लीनिक बनेगे वो विशेष उपलब्धि है।

2022 में 1.5 लाख डाकघरों में से 100 प्रतिशत कोर बैंकिंग प्रणाली पर आएंगे, जो वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच को सक्षम करेगा और डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी प्रदान करेगा। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक होगा, जिससे अंतःक्रियाशीलता और वित्तीय समावेशन सक्षम होगा। वर्तमान में डाकघर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से बचत खाता सेवाएं और भुगतान बैंक सेवाएं प्रदान करते हैं।

इस बजट में टैक्स स्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म के आधार पर बरकरार रखने का प्रयास किया गया है। हर साल इसमें अब छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं होगी। बजट में इन्फ्रा एक्सपेंडिचर पर जोर दिया गया है। सरकार जिन सेक्टर्स पर ज्यादा खर्च करेगी, वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की गुंजाइश बढ़ेगी। बजट में आर्थिक और इन्फ्रा ग्रोथ पर ध्यान दिया गया है। वास्तविकता तो यह है कि हाउसिंग फॉर ऑल, रोड, पोर्ट और अन्य इन्फ्रा सेक्टर को प्रोत्साहन देने से भारतीय अर्थव्यवस्था को ही गति मिलेगी। डिजिटल रेवोल्यूशंस से न केवल टेलिकॉम सेक्टर को, बल्कि आईटी एवं बीएफएसआई सेक्टर के साथ ही बैंकिंग सेक्टर को भी फायदा होगा। सरकार ने इस साल विनिवेश का टारगेट काफी कम रखा है। हमारी सरकार फिस्कल डेफिसिट को बैलेंस करने में सफल रही है।

सभी जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को नियमन की जरूरत है। हालांकि, आरबीआई की डिजिटल करेंसी की वैल्यू को लेकर कई तरह की चर्चा है। डिजिटल करेंसी पर 30 फीसद टैक्स लगाने से सरकार को ही फायदा होगा। उसका रेवेन्यू बढ़ेगा। सरकार ने ग्रॉस वैल्यू पर टैक्स लगाकर क्रिप्टो पर नकेल कसने की कोशिश की है। इससे हवाला और अन्य मार्गों से क्रिप्टो व अन्य डिजिटल करेंसी में होने वाले अनुचित निवेश पर लगाम लगेगी। बजट में युवाओं की नौकरी के अवसर प्रदान के लिए काफी कुछ ध्यान दिया गया है । बढ़ती बेरोजगारी के बीच यह बजट युवाओं को राहत देने वाला है।

बजट में 80 लाख सस्ते घरों को देने की योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है और इसका बड़ा फायदा गांवों और सब-अर्बन इलाकों पर दिखेगा. इसके अलावा इस

बजट की अवधि के दौरान शहरी इलाकों में भी अफोर्डेबल हाउसिंग को सुलभ बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसका फायदा जरूरतमंद लोगों को मिलेगा. ये आम लोगों का बजट है और इसमें सभी वर्गों पर ध्यान दिया गया है. पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को इस बजट से फायदा होगा. उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो काफी प्रशंसनीय हैं।

बजट में 60 लाख नौकरियों का प्रावधान भी रखा गया है जिससे युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के मौके पैदा होंगे. बजट किसानों की आय दोगुनी करने से लेकर आत्मनिर्भर भारत की सोच को पूरा करने वाला साबित होगा, यह बजट एक विजन पेश करता है कि इस साल और आने वाले सालों में देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसी रहेगी. यह बजट विजन वाला बजट है और स्पष्ट तौर पर तरक्की को नई दिशा देने पर काम करने में मददगार साबित होगा. इस बार का बजट सरकार के विजन को दिखाता है, अगले 25 सालों के लिए जो ब्लूप्रिंट है वो देश के भविष्य को ध्यान रखकर बनाया गया है. निवेश के लिए बड़ा बजट एलोकेशन किया गया है और पहले जहां 5 लाख करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट था, इस बार उसे 7.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस बार सड़कों, हाईवे, रोपवे से लेकर डिजिटल पढ़ाई तक पर जोर इस बजट में दिया गया है. देश की तरक्की के लिए ऐसा बजट बेहद सहयोगी साबित होगा।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वावस है कि इस आम बजट से आत्मनिर्भर भारत की मुहिम रंग लाएगी और हमारा भारत देश आपके कुशल नेतृत्वब में विश्वर गुरू बनकर उभरेगा।

यहां मैं अपने जालोर सिरोही क्षेत्र की कतिपय समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र विगत कई दशकों से भूजल की कमी का सामना कर रहा है। इसके कारण इस क्षेत्र में न केवल पेयजल संकट व्याप्त है अपितु सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है।यहां कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है तथा यह क्षेत्र औद्योगिक रूप से पूरी तरह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यही नहीं विगत दो सालों के दौरान अति वृष्टि व बेमौसम बरसात तथा टिडडी के आक्रमण के कारण पहले से ही परेषान किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। उनके खेतों में खड़ी हजारों हेक्टेयर की फसलें बरबाद हो गई, मेरा सरकार से अनुरोध है कि जालोर को एसपायरेशनल जिलों की सूची में शामिल कर इसके समेकित विकास हेतु एक योजना बनाकर उसे शीघ्रातिषीघ्र कार्यान्वित किया जाए ताकि यहां की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सके तथा रोजगार के नए अवसर पैदा हों तथा बेरोजगारी की समस्या से निजात मिल सके। जालोर के अधिकतर लोग अपने व्यापार के लिए दक्षिण के राज्य मे रहते है परन्तु जालोर से दक्षिण प्रांत के लिए सिधी रेल नही होने के कारण यहाँ के नागरिको को काफी परेशानियो का सामना करना पडता है। जालोर से दिल्ली के लिए भी कोई ट्रेन नही है 75 वर्षों के बाद भी सिरोही जिला रेल लाइन नही जुड पाया है। मेरे संसदीय क्षेत्र के रेलवे से संबंधित प्रमुख समस्या इस प्रकार है-

1. मेहसाणा-आबूरोड मेमू ट्रेन (09437/09438) का आबूरोड से फालना तक विस्तार किया जाए

2. उतर पश्चिम रेलवे स्थित पिंडवाडा रेलवे स्टेशन पर अहमदाबाद जम्मुतवी एक्सप्रेस (19223-24) और अहमदाबाद वाराणसी एक्सप्रेस (19408-09) का ठहराव दिया जाए
3. ट्रेन संख्या 22483/84 जोधपुर -गांधीधाम ट्रैन का मोदरान स्टेशन पर ठहराव दिया जाए
4. बाडमेर यशवंतपुर एसी एक्सप्रेस 14805/14806 ट्रेन को सप्ताह में सातो दिन (प्रतिदिन) चलाने एवं स्लीपर कोच जोडा जाए।
5. आश्रम एक्सप्रेस (12915/12916**)** और हरिद्वार मेल(19105/19106**)** का ठहराव स्वरूपगज स्टेशन पर किया जाए
6. गाँधीधाम से दिल्ली वाया जालोर (समदडी-भीलडी) नई ट्रेन प्रारंभ किया जाए
7. जालोर जिला का दक्षिण भारत के प्रमुख शहरो से रेल संपर्क से जोडा जाए
    - बेंगलोरु से जोधपुर वाया समदडी भीलडी
    - हैदराबाद से जोधपुर वाया समदडी भीलडी
    - कोयम्बटुर से जोधपुर वाया समदडी भीलडी
    - चेन्नइ से जोधपुर वाया समदडी भीलडी
8. सिरोही जिला केन्द्र को रेलवे नेटवर्क से जोडा जाए।
9. अहमदाबाद गोरखपुर 19409/19410 ट्रेन को प्रतिदिन (दैनिक) चलाया जाए।

जालोर सिरोही में सडको की स्थिती बहुत ही खराब है। इस क्षेत्र में 2015-16 और 2017-18 मे बाढ आने के कारण के कई सडकें पुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए है। इस सडको पर लगातार दुर्घटनाऐ बढ रही है-

1. जालोर और सिरोही दोनो जिला केन्द्र के सम्पर्क मार्ग को “गति शक्ति योजना” के अंतर्गत स्वीकृत कर निमार्ण करवाने की जरूरत है
2. गुजरात स्थित झेरडा से सिरोही मार्ग (वाया रेवदर और मंडार में बाईपास) तथा
3. रोहिट- भीनमाल-करडा-सांचोर मार्ग को 'गति शक्ति योजना से स्वीकृत कर निमार्ण किया जाए
4. भीनमाल पुनासा से मीठीबेरी तक इस सड़क के निमार्ण की आवश्यकता हैं

सिरोही जिला में माउट आबु और शक्ति पीठ अम्बा जी माता मंदीर, दो विश्व स्तरीय प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ब्रह्माकुमारी समाज का अंतराष्ट्रीय मुख्यालय माउट आबु है । माउट आबु को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। 50 नये टूरिस्ट सर्किट व गतव्य स्थलो की सूची में माउंट आबू को सम्मिलित किया गया है। माउट आबू में केन्द्रिय रिजर्व पुलिस बल का (C.R.P.F**)** आफिसर ट्रेनिग सेंटर है। सेना की दृष्टि से भी यह स्थान महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखो की संख्या में विदेशी पर्यटक आते है। इन पर्यटक को हवाई सफर के लिए 228 कि0मी0 दूर जोधपुर या 231

कि0मी0 दूर अहमदाबाद जाना पडता है। उडान योजना के अंतर्गत सिरोही स्थित मानपुर हवाई पटटी से वायु सेवा शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसे जल्द से जल्द शुरू करने की आवश्यकता हैं।

जालोर सिरोही जिला के पेयजल से संबधीत माही का पानी उपलब्ध कराना बहुत ही आवश्यक है जैसा की पूर्व में खोसला कमेटी की रिपोर्ट 01.09.1965 के अनुसार गुजरात राजस्थान बोर्डर पर कडाणा बांध बनाना प्रस्तावित किया गया । ततपश्चात 01.10.1966 को राजस्थान एवं गुजरात राज्य के बीच माही जल बंटवारा समझौता के तहत कडाणा बांध का निमार्ण हुआ जिसमें पैरा सं0-1 में वर्णित है जब गुजरात मे (खेडा जिला) नर्मदा से सिंचित होगा तब कडाणा बांध के पानी का 2/3 भाग राजस्थान का तथा 1/3 भाग गुजरात का होगा। यह पानी हाई लेवन नहर के माध्यम से जालोर सिरोही को दिया जायेगा । समझौता अनुसार शर्ते की पूर्ति 2005 मे हो गई थी जबसे खेडा जिला नर्मदा से सिंचित होने लगा था। इसके बाद कडाणा बांध का पानी 337 कि0मी0 सुजलाम सुफलाम नहर बनाकर उतरी गुजरात में सिचाई एवं पेयजल हेतु उपयोग किया जा रहा है । जो समझौते के विरूद्व है । कडाणा बांध 37 साल मे 27 बार ओवरफलो होने के कारण लगभग 1.30 लाख एमसीएम पानी व्यर्थ में बह गया। 15 सितम्बर 2019 को कडाणा से करीब 5.47 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, इस कारण बडोदरा समेत कई जगह बाढ़ आई थी। इस क्षेत्र की पेयजल एवं सिचाई की समस्या को देखत हुए कडाणा बांध पर निर्मित सुजलाम सुफलाम से पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। इससे यहाँ की पेयजल और सिंचाई की समस्या हल हो सकती है। इसी प्रकार नाला बतिसा सालगाँव डैम को जल्द जल्द पुरा किया जाएं।

इस क्षेत्र मे पर्यटन की अपार संभावनाएं है सिरोही ,जालोर, बाडमेर और जैसलमेर में पर्यटन सर्किट रूप में विकसित किया जा सकता है

जालोर सिरोही मे लोगो की आय का प्रमुख साधन कृषि है। दोनो जिले में बड़ी मात्रा मे पशुधन है तथा कृषि के बाद लोगो का आजीविका प्रमुख साधन पशुपालन ही है। किसानो के पास तुलनात्मक रूप से जोत का आकार बडा है। जालोर जिला में नर्मदा नहर के आने से पर्याप्त सिचाई की सुविधा उपलब्ध हो गयी है। सिंचित क्षेत्र मे नगदी फसले जैसे- अरण्डी जीरा व ईसबगोल मीर्च पपीता खजुर की खेती के अच्छे अवसर है । लेकिन प्रशिक्षण के अभाव में यहां के किसान उन्नत कृषि तकनीकी का खेतो मे कम उपयोग करते है। नर्मदा नहर प्रोजेक्ट आने के पश्चात यहाँ के किसानो के लिए मिश्रित खेती व फसलो के विविधिकरण के अपार अवसर है। एक दशक से यह क्षेत्र विश्व का चालीस फीसदी ईसफगोल का उत्पादन करता है। इस प्रकार आज जालोर ईसफगोल उत्पादन के लिहाज से भारत ही नही विश्व में अहम योगदान रखता है। भीनमाल में ईसफल गोल की विशिष्ट मण्डी भी स्थापित है। आज यहाँ की आवश्यकता है कि हाईस्कूल और इंटरमीडियट पास युवको को रोजगार संबंधी शिक्षा मिल सके और वे सफल कृषि उद्यमी बने, यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना होने से कृषि और ग्रामीण व्यवस्था को रोजगार उन्मुखी बनाना जा सकता है तथा गाँवो से युवाओ का पलायन भी रोका जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं हमारी सरकार के बजट 2022-23 का पुनः समर्थन करता हूं तथा आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

(इति)

***श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली):** अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम मैं मा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद देता हूँ की उन्होंने वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया जो की हमारे देश में चल रही विकास की योजनाओं को प्रोत्साहन देता है। हम सब भली भांति जानते हैं की हमारे यशश्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार वर्ष 2014 से गरीबी और हाशिए पर रह रहे लोगों को सशक्त बनाने में जुटी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का तेजी से सुदृढ़ होना तथा इतनी बड़ी महामारी के बाद भी पटरी पर आना, हमारे देश की सुदृढ़ आघात सहन क्षमता को दर्शाता है। इस बजट में इस बात का पूर्ण ध्यान रखा गया है की नारी और अधिक सशक्त हो, गरीब का अपना आवास हो, किसान आर्थिक और तकनिकी रूप से सुदृढ़ एवं मजबूत बने।

हमारे देश में नारी और अधिक सशक्त हो और उनका भविष्य उज्जवल हो इसके लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया है, ताकि महिलाओं और बच्चों की योजनाओं को सक्षम तरीके से उन तक पहुंचाया जा सके। 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके माध्यम से उन्नत किया जाएगा।

देश में प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ जल मिले इसके लिए बजट में उचित 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावाधान किया गया है, जिसके माध्यम से वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जायेगा। हमें निश्चित रूप से सरकार की सराहना करनी होगी की पिछले 2 वर्षों में हर घर नल से जल को 5.5 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

हर एक गरीब का सपना होता है की उसका अपना आवास हो इसी को लेकर पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2022-23 में 80 लाख घरों को लोगों को मुहैया कराया जाने की योजना है। इस कार्य के लिए 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जायेगा ताकि जरुरतमंदों को आवास दिया जा सके।

हमारे देश के किसानों को रीढ़ की हड्डी कहा जाना अनुचित नहीं होगा इसलिए मा. वित्त मंत्री जी ने किसानों के कल्याण का विशेष ध्यान इस बजट में रखा है, वित्त मंत्री जी ने बजट में यह कहा कि कृषि में 2021-22 के दौरान गेहूं और धान की खरीद 12.08 लाख मीट्रिक टन होगी।

किसानों को एमएसपी के जरिए 2.37 लाख करोड़ रुपये दिए जायेगा जो किसानों के लिए हितकारी होगा। साथ ही बजट में यह घोषणा की गयी है की प्राकृतिक खेती को प्रमोट किया जाएगा जिसके लिए गंगा नदी के किनारे इसका पहला प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। तिलहनों के आयात को कम करने के लिए तिहलन के आयात की निर्भरता को कम किया जाएगा और घरेलू उत्पादन पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। किसानों को डिजिटल करने के प्रयास को तेज किया जाएगा। निजी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए पीपीपी मॉडल पर काम किया जाएगा। किसानों को खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव का इस्तेमाल करने के तरीको को बताया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाया जा सके इसके लिए राज्यों को बताया जाएगा, जिससे की वहां के

* Laid on the Table

किसान लाभान्वित हो सके । साथ ही नाबार्ड के जरिए खेती के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण के तरीको को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को मशीन किराए पर देने के लिए नई-नई सूचना किसानों को पहुंचाने के लिए तरीकों पर काम किया जाएगा । केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे की लोगों तक रसायन युक्त उत्पाद पहुँच सके । किसानों को कृषि से सम्बंधित उचित ज्ञान प्राप्त हो सके इसके लिए एग्री यूनिवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाएगा । रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए क्शल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा जिससे की वे अपनी फसल उत्पाद को आसानी से दुसरे स्थान तक ले जा सके | देश भर के किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके इसके लिए स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन बढ़ाने के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद" योजना शुरू की जाएगी । एससी-एसटी किसानों को एग्रो- फॉरेस्ट्री के लिए मदद दी जाएगी जिसका लाभ उस वर्ग की किसानों को अवस्य मिलेगा।

MSME सेक्टर में रोजगार क्षमता एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को और अधिक लाभान्वित किया जा सके, साथ ही फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किये जा सके इसके लिए सरकार एक व्यापक पैकेज को लागू करेगी । मझोले और छोटे उद्योगों के लिए स्कोप को बढ़ावा दिया जाएगा। MSME का दायरा अधिक से अधिक बढे इसके लिए उदयम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जायेगा | रोजगार के नए नए अवसर सृजित हों इसके लिए भी बजट में उचित प्रावधान किये गए हैं, वित्त मंत्री जी ने कहा है की PLI स्कीम को अच्छी सफलता मिली है इससे 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है एवं अगले पांच वर्षों में इसके अलावा 30 लाख रोजगार के सृजन होने की सम्भावना है । रोजगार के नए नए आयाम जनता को उपलब्ध हों और आर्थिक रूप से देशवासी सशक्त हो इन प्रयासों की निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए।

बजट में यह प्रावधान किया गया है की स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो पिछड़े इलाके और पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं उनको बिना रुकावट के गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त होती रहे इसके लिए उनको पीएम ई विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास, जिसको 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा के माध्यम से दी जाएँगी । कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी जिससे सभी राज्यों एक से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।

रेलवे भारत का एक मजबूत एवं सुरक्षित परिवहन का साधन है इसीको लेकर बजट में यथोचित प्रावधान किये गए है , अगले तीन वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन का विकास एवं विनिर्माण किया जायेगा साथ ही पीपीपी मॉडल के जरिए चार जगहों पर 2022-23 के दौरान रेलवे द्वारा नए उत्पादों को एक से दूसरे जगह पर पहुंचाया जा सके इसका काम किया जाएगा।

मा. वित्त मंत्री जी ने बजट में यह घोषणा की है की पीएम गतिशक्ति के जरिए राजमार्ग नेटवर्क और बढ़ाया जाएगा जिससे की आवागमन और अधिक सुगम हो पायेगा, इसके लिए 25

हजार किलोमीटर सड़क को और बनाया जाएगा । सामानों को जल्द से जल्द एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए उचित व्यवस्था की जाएँगी।

बजट में ग्रामीण विकास को लेकर भी कई घोषणाएं की गयी है और ग्रामीणों को उचित लाभ एवं बुनियादी सुविधाएँ मिले इसका भी प्रावधान किया गया है । देश के अत्यंत दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना सरकार का परम कर्तव्य है । इसलिए उनकी स्वास्थ्य, पोषण वित्तीय स्थिति और आधारभूत अवसंरचना की प्रगति की जा सके, इसके लिए 2022-23 के बजट में ऐसे स्थानों पर अधिक फोकस किया गया है । सीमावर्ती गाँव , जहाँ की जनसँख्या बहुत कम है उनकी शहरी क्षेत्रो के साथ कनेक्टिविटी हो और बुनियादी सुविधाओं को वहां के नागरिकों तक पहुँचाया जा सके इसका भी प्रावधान बजट में किया गया है |

मा. वित्त मंत्री जी बजट में घोषणा की है की भारत में आने वाले समय में कुल आबादी की आधी संख्या शहरी क्षेत्रों में निवास कर रही होगी और उसके लिए एक मजबूत शहरी तंत्र का विकसित होना अत्यंत आवश्यक है इसलिए पुराने ढर्रे पर शहरी प्लानिंग को आगे नहीं बढ़ाया जाए, इसके लिए उचित प्लानिंग एवं संस्थानों की जरूरत है। शहरी विकास को भारतीय जरूरतों के अनुसार बनाया जा सके, इसके लिए 5 मौजूदा संस्थानों को चिन्हित करके उन्हें सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का दर्जा दिया जाएगा। इन सभी संस्थानों को 2500 करोड़ का फंड दिया जाएगा। प्रदूषण मुक्त परिवहन के साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा। शहरों की इस तरीके की प्लानिंग होगी कि आवाजाही में आसानी होगी।

हमारे देश के किसान एवं ग्रामीणों को बैंकिंग का लाभ अब डाकघरों की मदद से भी मिल सकेगा ऐसा प्रावधान बजट में किया गया है मा. वित्त मंत्री जी ने कहा है की पोस्ट ऑफिस खातों के जरिए किसानों को सुविधा मुहैया कराई गई है। बजट में यह घोषणा की गयी है की वर्ष 2022 में शत प्रतिशत 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालु हो जायेगा साथ ही सरकार का प्रयास है कि डिजिटल बैंकिंग की सुविधा को देश के सभी इलाके में सही तरीके से पहुंचाए जा सके। इसके लिए देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैकिंग यूनिट स्थापित करेंगे ताकि लोग अधिक से अधिक डिजिटल भुगतान कर सके। पोस्ट ऑफिस और बैंक को आपस में जोड़ा जाएगा और इन दोनों के बीच आपस में पैसों का लेनदेन होगा। पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर होगा जिसका निश्चित लाभ ग्रामीणों एवं किसानों को मिलेगा ।

देश में सुरक्षा तंत्र मजबूत हो इसके लिए रक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा विशेष कार्य किया जा रहा है इसी को लेकर वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है की रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के बजट को 25 फीसदी आर.एंड.डी के लिए रखा गया है जिसके माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संस्थाएं तकनीक को विकसित कर सकती हैं । ये तमाम वे क्षेत्र हैं जहां भारतीय उद्योगों को और ज्यादा दक्ष बनाया जा सकता है।

रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान के लिए स्टार्टअप को मौका दिया जाएगा जिससे देश के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे । इस क्षेत्र के घरेलु उद्योग को बढ़ावा मिले इसके लिए इस क्षेत्र में 65 फीसदी स्वदेसी तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा।

वित्त मंत्री जी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश में डिजिटल रुपये की शुरुआत किए जाने का एलान किया है उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा "डिजिटल रुपये की शुरुआत करने से देश में करेंसी मैनेजमेंट में काफी सुधार होगा और इसके माध्यम से देश में एक और अधिक दक्ष और सस्ती करेंसी प्रबंधन व्यवस्था देखने को मिलेगी।

मा. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह बजट सिर्फ एक या 2 साल के लिए रोडमैप नहीं तैयार करेगा बल्कि इसमें अगले 25 साल के लिए ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। इस बजट से देश के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी । हम सब जानते है की देश ओमीक्रोन लहर से जूझ रहा है परन्तु इसका असर देश पर सशक्त नेतृत्व के कारण उतना नहीं पड सका, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था तेजी से मजबूत हो रही है यह हम सब भली भांति जानते ही है।

वित्त मंत्री ने कहा कि हम विश्वास आधारित कर व्यवस्था बनाने चाहते हैं। गलतियों को दूर करने के लिए करदाताओं को अतिरिक्त भुगतान की सुविधा के साथ इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा होगी। टैक्स सिस्टम में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब करदाता अपने रिटर्न को अगले दो वर्ष तक सुधार कर अपडेट कर सकता है जिससे देश के करदाताओं को राहत मिलेगी।

बजट में चमड़े के सामान सस्ता किया गया है, कपड़ा भी सस्ता होगा एवं मोबाइल चार्जर, मोबाइल लेंसेस सस्ते होंगे । इसके अलावा खेती का सामान सस्ता होगा। पॉलिश्ड हीरा सस्ता होगा। तराशे और पॉलिश किए गए हीरों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया जाएगा जिसका लाभ हीरा व्यापारियों एवं अन्य सम्बंधित व्यापारियों को मिलेगा।

अंत में मैं यह कहना चाहूँगा की यह बजट विकास की रफ्तार को मजबूत करेगा । जैसा की वित्त मंत्री जी ने कहा है की यह बजट अगले 25 साल का विजन पेश करता है। युवाओं, महिलाओं, एससी, एसटी, गरीब एवं किसान का बजट है, दूसरी भाषा में कहा जाये तो यह भारत के आम नागरिक का बजट है, भारत के कल्याण का बजट है । साथ ही हम कई दिशाओं में इस बजट के जरिए आगे बढ़ रहे हैं और मेरी पूरी आशा है की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह देश निरंतर प्रगतिशील रहेगा । मैं मा. वित्त मंत्री महोदया को साधुवाद एवं धन्यवाद देता हूँ की आपने देश के विकास का बजट पेश किया ।

(इति)

***श्री जनार्दन मिश्र (रीवा):** महोदय, आज देश ओमिक्रोन की तीसरी लहर से जूझ रहा है | इस से प्रभावित होने वालो की काफी संख्या के बावजूद इसके लक्षण मामूली है, यह इस कारण है कि हमने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जिस तेजी से टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर हम पहुँच रहे है |

विगत दो वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओ का जो आधार भूत ढांचा तैयार किया गया है उसका यह परिणाम है | यह सफलता इस दिशा की ओर इंगित करती है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आपदा को भी अवसर में परिवर्तित करने में सफल रहे है।

आज हम अमृत काल में है | आजादी के 75 वां वर्ष हम मना रहे है | आज आवश्यकता इस बात है कि आने वाले 25 वे वर्ष में जब हम आजादी के 100वे वर्ष में होंगे तब के लिए हमारी दृष्टि क्या है | हम देश को किस स्थिति में पहुँचाना चाहते है | उस समय तक पहुँचने के लिए देश के सामने कोनसी चुनोतियां है और उनके निराकरण के लिए हमारी क्या योजना होनी चाहिए हमारा रास्ता क्या है |

वर्तमान बजट इस यात्रा की बुनियाद है | हमे इसी दृष्टि से बजट का आकलन करना होगा। महोदय, इस अमृत काल में बजट में जो लक्ष्य है:

1. सूक्ष्म आर्थिक स्तर समग्र कल्याण पर व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना
2. डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रोद्योगिकी समर्थित विकास, उर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना तथा
3. सार्वजानिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरम्भ करने के प्रभावी चक्र से लोगो को निजी निवेश से सहायता उपलब्ध करना।

और इन उदेश्यों को प्राप्त करने के लिए बजट में चार प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई है।

1. पी एम गति शक्ति
2. समावेशी विकास
3. उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, उर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना
4. निवेशो का वित्त पोषण

अभीतक कई महत्वपूर्ण विभागों में आपसी तालमेल के अभाव के कारण योजनाओ के क्रियान्वयन में काफी टकराव व असस्म्बधता देखी जा रही थी जिसे एक सूत्र में बांधने का कार्य किया जाना है जो आर्थिक वृद्धि और स्तत विकास की दिशा में एक परिवर्तन कारी पद्धति साबित होगी अब सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पत्तन,सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, और लोजिस्टिक अवसरंचना ये सातों भाग एक साथ मिलकर के अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे | इससे उत्पादकता के बढ़ाने, आर्थिक वृद्धि एवं विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

---

* Laid on the Table

सड़क परिवहन में गत वर्षो में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है इसमें सभी राष्ट्रिय राजमार्ग नेटवर्क में 25000 किमी ओर जोड़े जायेंगे।

वस्तुओ और लोगो का निर्वाध बहुविधि मूवमेंट के लिए सभी माध्यमो के ओपरेटरो का डाटा एक्सचेंज ए पी आई के लिए अभिकल्पित यू एल आई पी पर लाया जायेगा इससे सभी हित धारको को रियल टाइम सूचना उपलब्ध होगी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा। साथ ही यात्रियों की निर्विघ्न यात्रा के लिए सामान को लाने ले जाने के लिए ओपन स्त्रोत की सुविधा भी दी जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 2000 किमी के नेटवर्क को कवच के अन्दर लाया जायेगा।

अगले तीन वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी की वन्दे भारत रेलगाड़ियो का विकास और विनिर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

साथ ही अगले तीन वर्षों के दौरान मल्टीमोडल लोजिस्टिक्स सुविधाओ के लिए एक सौ पी एम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किये जायेंगे।

खेती और किसानो की समृद्धि के लिए सरकार वचनबद्ध है और MSP के तहत रबी 2021-22 की खरीद और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानो से 1208 लाख मेट्रिक टन गेंहू खरीदान होगा जिसका MSP मूल्य 2.37 लाख करोड़ रूपये का भुगतान सीधे किसानो के खाते में किया जायेगा। रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देने मोटे अनाजो के लिए यह वर्ष समर्पित है। इनकी देशी खपत को बढ़ाने तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिग की जाएगी। तिलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर बने इसके लिए तर्क संगत व्यापक योजना का प्रस्ताव है।

कृषि फसलो का आकलन करने भू-दस्तावेजो का डिजिटाइजेशन करने , कीटनाशको का छिडकाब करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा देने की योजना है।

राज्यों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे अपने कृषि विश्व विद्यालयो के पाठ्यक्रमो में संशोधन कर सके जिससे प्राकृतिक, जीरो बजट और आर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य सवर्धन और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

फलो और सब्जियों की अच्छी किस्म अपनाने और उत्पादन तथा फसल कटाई की यथोचित तकनीक का प्रयोग करने के लिए किसानो की सहायता करने हेतु राज्य सरकारों के भागीदारी से एक व्यापक पैकेज दिया जायेगा जिससे खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा।

इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ई सी एल जी एस) के तहत 130 लाख से अधिक एम एस एम ई को अत्यंत जरुरी अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया है।

इन्हें अधिक मजबूती मिले ई सी एल जी एस को मार्च 23 तक बढ़ाया गया है और इसकी गारंटी के दायरे 50,000 करोड़ रूपये से बढाकर 5 लाख करोड़ रूपये तक कर दिया गया है। साथ ही आपेक्षित धन लगाकर क्रेडिट गारंटी ट्रांसफर माइक्रो एंड स्माल इंटर प्राइजेज स्कीम को पुनर्जीवित किया गया है। इससे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का 2 लाख करोड़ रुपयों का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

बहुप्रतीक्षित नदी जोड़ो परियोजना को जमीन पर उतारा गया है और केन बेतवा परियोजना जिस पर 44,605 करोड़ खर्च होंगे प्रारम्भ किया जा रहा है | जिसके लिए इस वर्ष 1400 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है।

इसके साथ ही पांच अन्य परियोजनाओ के क्रियान्वयन की प्रिक्रिया तेज की गई है। हर घर नल से जल 22-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को पेय जल मुहैया कराने हेतु 60,000 करोड़ का आवंटन किया गया है | इसी वर्ष पी एम आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख मकानों के निर्माण हेतु 48,000 करोड़ का आवंटन किया गया है।

2022 तक शत प्रतिशत 1.5 लाख डाकघरों में कर बैकिंग सिस्टम चालू हो जायेगा जिससे फाईनेशियल इनक्लूजन संभव होगा और नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना खाता खोला जा सकेगा। यहाँ मोबाईल बैंकिंग के साथ ही ए टी एम भी होगा।

शिक्षको को गुणवत्ताप्रद एवं सर्वभौमिकरण करने के लिए 12 टी.वी चेनलो से बढाकर 200 टी.वी. चेनलो तक पहुचाया जायेगा नेशनल डीजिटल हेल्थ ईको सिस्टम के लिए ओपन प्लेट फार्म तैयार किया गया है।

इससे चिकित्सा कर्मियों से लेकर रोगियों तक को सुविधाये डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सकेगी।

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दृष्टि से पूंजीगत खरीद बजट 21-22 में 58 प्रतिशत से बढाकर 22-23 में घरेलू उद्योग के लिए 68 प्रतिशत तक किया गया है।

संचार के क्षेत्र में 5G सुविधा को बढ़ाने के प्रयास का प्रावधान किया गया है।

इस प्रकार से देखे तो यह बजट आने वाले 25 वर्षों के भारत निर्माण व प्रगति की बुनियाद पर खड़ा बजट है। जिसके दूरगामी सु:खद परिणाम होंगे।

महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र रेल सुविधाओ की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ से मुंबई के लिए प्रतिदिन सेकड़ो लोग चिकित्सा एवं रोजगार के लिए जाते है पर कोई यात्री रेल गाड़ी का परिचालन न होने से उन्हें काफी परेशानी होती है। साथ ही हमारे यहाँ से बेंगलोर, पूना व कोटा के लिए भी रोजगार एवं शिक्षा के लिए नौजवान व छात्र जाते है परन्तु कोई रेल सेवा नहीं है। अतः इन क्षेत्रो से रीवा को जोड़ने हेतु नई यात्री गाड़ियों का संचालन कराया जाना चाहिए।

रीवा से मिर्जापुर रेल लाइन का सर्वे पूरा हो चुका है इस रेल लाइन के निर्माण से माल ढुलाई एवं यात्री सुविधाओ को भारी सुविधा होगी अत: इस रेल लाइन को स्वीकृत किया जाना उचित होगा।

रीवा हवाई संपर्क विहीन क्षेत्र है, हमारे यहाँ एक हवाई पट्टी है। रीवा में हवाई अड्डा का निर्माण विचाराधीन है उसे शीघ्र ही स्वीकृत प्रदान की जाये जिससे रीवा हवाई संपर्क से जुड़ सके।

महोदय,में वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

धन्यवाद

(इति)

***श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा):** माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी के लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा वर्ष-2022-23 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री महोदया दवारा देश के सर्वागीण विकास और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को आधार मानते हुए, जनकल्याणकारी बजट सदन में प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी व वित्त मंत्री महोदया का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।

आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के मूल भाव पर आधारित केंद्रीय बजट निश्चित रूप से देश को आत्मनिर्भर और सबल बनाने सहित अन्त्योदय की संकल्पना को साकार करने वाला है,मैं देख रहा हूँ, देश का हर वर्ग बजट का स्वागत कर रहा है, सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को फिर से उर्जावान बनाना, नवाचार और अनुसन्धान व विकास,न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन जैसे महत्वपूर्ण स्तंभों को बजट का आधार बनाकर देश के विकास की नींव रखने हेतु सदन में प्रस्तुत बजट का मैं हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ, अपना समर्थन देता हूँ।

माननीय महोदय,जैसा कि आपको विदित हैं, मैं लोकसभा में झारखण्ड राज्य के जनजाति बहुल, बाबा टांगीनाथ और भगवान हनुमान की पावन जन्मस्थली माता अंजना के आशीर्वाद से सिंचित रत्नगर्भा बॉक्साईट नगरी लोहरदगा संसदीय क्षेत्र अर्थात एक ग्रामीण अंचल का सदन में प्रतिनिधित्व करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के साथ-साथ,अच्छी शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के आभाव में भी वन सम्पदा व जनजातीय एवं ग्रामीण संस्कृति को संजोकर रखते हुए देश की प्रगति में अनवरत योगदान दे रहा है, अतः इस क्षेत्र को सम्पूर्ण विकास और आधारभूत सुविधाओं की महती आवश्यकता है, इसलिए मैं इस पूरे क्षेत्र की निम्नलिखित आवश्यकताओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, इन सभी मुद्दों को केंद्रीय बजट में सम्मिलित करने का निवेदन करता हूँ :-

1. किसान व ग्रामीणों की आय दोगुनी करने हेतु मेरे संसदीय क्षेत्र सहित पूरे झारखण्ड राज्य के ग्रामीण अंचलों में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की समस्त योजाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है।
2. यहाँ खनन अथवा बॉक्साईट आधारित उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता है।
3. इस पुरे क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में वनोत्पाद उपलब्ध होने के साथ-साथ बड़ी मात्र में सब्जियों की खेती होती है,यहाँ खाद्य प्रसंस्करण उदयोग अधिक से अधिक स्थापित किये जाएँ।
4. मेरे संसदीय क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, यहाँ पौराणिक बाबा टांगीनाथ मंदिर व भगवान हनुमान जी का जन्मस्थान आंजन ग्राम सहित निकट में ही

* Laid on the Table

रामरेखा धाम, प्राकृतिक सौंदर्य व ऐतिहासिक स्थलों के विभिन्न स्थान विदयमान हैं, जिन्हें पर्यटन हेतु विकसित करने से इन स्थानों का महत्व तो बढ़ेगा ही अपितु इनके एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने से यहाँ के स्थानीयजनों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा।

5. रेल सम्बन्धी:-

   * लोहरदगा रेलवे लाइन का दोहरीकरण अविलम्ब पूर्ण कर दिया जाये।

   * किसान एक्सप्रैस नाम से एक नई रेल सेवा प्रारंभ की जाये लोहरदगा से राउरकेला भाया रांची।

   *लोहरदगा से कोरबा भाया-गुमला,जशपुर नई रेलवे लाइन का निर्माण किया जाये।

6. देशभर में गुमला व लोहरदगा में खेलों के प्रति विशेष रुझान है इस क्षेत्र ने देश को कई राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी दिए हैं, अतः यहाँ की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम और विशेष आधारभूत सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिये।
7. जनजातीय अंचलों में सौर उर्जा सम्बन्धी प्रकल्पों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है।
8. इस पूरे क्षेत्र में पशुपालन, डेयरी, मतस्यपालन आदि को बढ़ावा देने हेतु विशेष कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता है।
9. गुमला में **"सेना व अर्धसैनिक भर्ती केंद्र"** स्थापित किया जाना चाहिए | परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का की भूमि के नाम से जाना जाने वाले इस पूरे क्षेत्र से भारतीय सेना व अर्धसैनिक बलों में कार्यरत होकर देश की सेवा कर रहे हैं,सेनाओं के प्रति एक विशेष रुझान यहाँ के युवाओं में रहता है, इनकी भावना को ध्यान में रखते हुए और पलायन को रोकने में एक विशेष भूमिका यह भर्ती केंद्र निभा सकता है।
10. जनजातीय बहुल ग्रामीण अंचल जैसे झारखण्ड,उड़ीसा व् छत्तीसगढ़ राज्यों के आपसी सीमावर्ती जिलों में बायो डीजल के उत्पादन अपार संभावनाएं हैं इसके लिए मैं गुमला में बायो फ्यूल का प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के सम्मुख रखता हूँ।
11. गुमला में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय" की स्थापना होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा लोहरदगा संसदीय क्षेत्र सहित झारखण्ड के समस्त जनजातीय बहुल व यहाँ के समग्र ग्रामीण अंचल की प्रगति हेतु मेरे द्वारा उठाये गए मुद्दे कल्याणकारी सिद्ध होंगे, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री महोदया से निवेदन करता हूँ, कि जनहित में मेरे द्वारा उठाये गए समस्त मुद्दों व योजनाओं को बजट में सम्मिलित करने का कष्ट करें।

(इति)

***श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद):** इस एतिहासिक बजट को पेश करने के लिए मैं अपने माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस बजट में आधुनिकता की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. सात वर्षों में जो फैसले लिए गए, नीतियां बनीं, पहले की नीतियों की गलतियां सुधारी गईं, उसकी वजह से आज अर्थव्यस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंदर मोदी जी के नेत्रत्व में देश में ये बजट, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर पैदा करने वाला एतिहासिक बजट है। ये बजट देश में अधिक तेज विकास, तेजी से बढ़ता नया बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश के नए स्रोत, अधिक नौकरियों की संभावनाओं से भरा हुआ है। सच में ये देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को भी सुनिश्चित करने वाला बजट है।

आज जब हम आजादी के बाद पहली बार पिछले दो सालो से करोना की भयंकर आपदा से गुजर रहे, ऐसी आपदा जिसमे जाने कितने अपनों को हमने खो दिया कितने लोगो का रोजगार बाधित हुआ और व्यपार में उतार चढाव देखे, ऐसे में ये बजट, विकास का नया विश्वास लेकर आया है।

भारत की आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर प्रत्येक भारतवासी अमृत महोत्सव मना रहा है, और भारतियों की यह संकल्पशक्ति, भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए ये बजट असीम विश्वास पैदा करता है। इसी विश्वास के साथ, प्रत्येक भारतवासी को इस बजट के लिए मेरा अभिनंदन और बधाई।

इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सभी हिस्सों से सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, बजट का लाभ युवा, मध्यम वर्ग, गरीब-दलित-पिछड़े, सभी वर्गों को मिलेगा, हर क्षेत्र को आधुनिकता, टेक्नोलॉजी, जैसे किसान ड्रोन, वंदेभारत ट्रेन, डिजिटल करेन्सी, banking के क्षेत्र में digital units , 5G services का रोल आउट,National Health के लिए digital ecosystem, सही मायने में ये डिजिटल बजट है।

यह सुनिश्चित होगा कि देश में कृषि में नये अवसर और भविष्य की कृषि लाभप्रद होगी । नए एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष फंड है फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज है, इससे किसानों की आय बढ़ेगी, MSP खरीद के माध्यम से सरकार किसानों के खाते में 2.37 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करेगी हैं इससे देश के किसानो की जिंदगी में बड़ा सुधर होगा और उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा।

इस बजट में गरीब के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। हर गरीब के पास पक्का घर, घर में नल से जल, राशन की आपूर्ति हो, रसोई गैस, शौचालय सुविधा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया गया है।

---

* Laid on the Table

माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के प्रयासों से आज देश में करीब-करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है. इसमें से करीब-करीब 5 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्ष में दिए गए हैं. अब करीब 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचने लगा है. इसमें से करीब 5 करोड़ से ज्यादा पानी के कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 2 वर्षों में दिए गए हैं. इस बजट में घोषणा की गई है कि इस साल करीब 4 करोड़ ग्रामीण घरों को पानी का कनेक्शन दिया जाएगा।

झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों के पास अपना घर है पहले के मुकाबले घरों के लिए मिलने वाली राशि भी बढ़ाई और घरों का साइज भी बढ़ाया है ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए जगह मिल जाए. ये लाभ पाने वालो में ज्यादातर घर महिलाओं के नाम पर है माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के प्रयासों से महिलाओं को घर की मालकिन भी बनाया है 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 44,000 करोड़ रुपये में 80 लाख किफायती घरों का निर्माण किया जाएगा

इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाएगा डिजिटल विश्वविद्यालय; हब और स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा। कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिए बच्चों को पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 1-कक्षा-1-टीवी चैनल लागू किया जाएगा। डिजिटल इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए देश स्टैक ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क शामिल होगा जिसमें निम्हंस नोडल केंद्र होंगे और आईआईआईटी बैंगलोर प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करेगा। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे

इस आम बजट में प्रस्तावित डिजिटल मुद्रा को नकदी में तब्दील किया जाएगा है और यह फाइनेंसियल टेक्नोलोजी (फिनटेक) क्षेत्र में नए अवसरों के द्वार खोलेगी। केंद्रीय बैंक की डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) या डिजिटल मुद्रा ऑनलाइन लेनदेन को और सुरक्षित बनाएगी तथा इसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा | इससे आने वाले समय में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। डिजिटल रूपया हमारी भौतिक मुद्रा का ही डिजिटल स्वरूप होगा और फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज (विनिमय) किया जा सकेगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित होगा। इस डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) से डिजिटल अर्थ-व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

किसान ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिए से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर चलेगी।

गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है गंगा किनारे, नैचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे मां गंगा की सफाई का जो अभियान है उसमे मां गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत बड़ी मदद मिलेगी

माननीय मोदी जी की सरकार ने कोरोना काल में MSME के अंतर्गत आने वाले छोटे उद्योगों की मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश ने लगातार अनेक निर्णय लिए है। 5 वर्षों में

MSMEs को रेट करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये का कार्यक्रम है इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 परसेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा। ये आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है। साढ़े 7 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही, छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए है।

'पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान' की घोषणा की और कहा कि यह प्लान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. इस प्लान के तहत सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और जलमार्गों के इंफ्रा को लेकर बड़ी योजनाओं पर काम करेगी और कई नए बदलाव किए जाएंगे।

इस बजट से साफ है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास फोकस रख रही है. वित्तमंत्री ने 'पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान' की घोषणा की और कहा कि यह प्लान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है. इस प्लान के तहत सरकार रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और जलमार्गों के इंफ्रा को लेकर बड़ी योजनाओं पर काम करेगी और कई नए बदलाव किए जाएंगे. वित्त मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 22-23 में 25 हजार किलोमीटर के हाईवे तैयार किए जाएंगे.अगले तीन सालों में 100 नए कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।

पीएम गतिशक्ति योजना आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए अहम होगी. इसके तहत रोड, रेलवे और वॉटरवेज़ के इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स विकास पर फोकस किया जाएगा. देशभर में 25,000 किमी सड़कें बनाने पर जोर रहेगा. रोड इंफ्रा और बेहतर किए जाएंगे। अगले 100 साल के लिए ढांचागत विकास की रूपरेखा पर काम किया जा रहा है. हाइवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. वित्त वर्ष 2022-23 में 8 नए रोपवे का ऑर्डर दिया जाएगा. रोपवे ऑर्डर पीपीपी मॉडल पर दिया जाएगा।

इस योजना के तहत नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें अगले तीन वर्षों में चलाई जाएंगी. 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी अगले तीन वर्षों में तैयार होंगे. इससे मेट्रो सिस्टम तैयार करने की नवोन्मेषी तरीका विकसित होगा।

44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन-बेतवा नदियों को जोड़ने का कार्य शुरू किया जाएगा 5 नदी लिंक के लिए डीपीआर के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है।

2022-23 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है।

रेलवे छोटे किसानों और एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा अगले वित्तीय वर्ष में 4 स्थानों पर मल्टी-मोडल पार्कों के ठेके दिए जाएंगे, ईसीएलजीएस योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपये बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा, 2,000 किमी रेल नेटवर्क को सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है गारंटीड कवर को 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर कुल कवर 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा

महामारी ने सभी उम्र के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए, एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, 112 आकांक्षी जिलों में से 95 प्रतिशत ने स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की है।

नॉर्थ ईस्ट के लिए पीएम विकास की पहल को नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के लिए लागू किया जाएगा। यह युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करेगा। यह योजना मौजूदा केंद्र या राज्य की योजनाओं का विकल्प नहीं है।उत्तर पूर्व के लिए पीएम विकास पहल नामक एक नई योजना शुरू की जाएगी, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत शामिल किया जाएगा

मेरे लोकसभा क्षेत्र दाहोद गुजरात के लिए यह बजट अमृत सामान है दहोद जो पहले से ही माननीय नरेंदर मोदी जी के द्वारा स्मार्ट सिटी घोषित है और एक महत्वाकांक्षी जिला भी है यहाँ के लोग प्राकर्मी और सेना में जाने की रूचि रखते है विगत दशकों से एक बड़ी संख्या में देश के सिपाही के रूप में सेना में गये हैं, अपनी वीरता और बलिदान के लिए उन्होंने ख्याति अर्जित की है। तो मै आपसे अनुरोध करूँगा है कि मेरे लोकसभा की जनता का सेना प्रेम और सेना मे कार्ये करने के जज्बे को देखते हुए दाहोद में सैनिक स्कूल की स्थापना करने की कृपा करें।

मेरे लोकसभा क्षेत्र की तालुका, दाहोद, झालोद, देवगढ़ (बरिआ), गर्भदा, लिमखेड़ा, फतेहपुरा, धनपुर, सांजेली, व सिंगवाद में बीएसएनएल के मोबाईल फोन के सिंग्नल में सुधार लेन के लिए ने मोबाइल टावर लगाने की जरुरत है मेरा अनुरोध है कि इन टावरो को लगवाने का प्रावधान करने की कृपा करे।

गुजरात तथा राजस्थान की सीमाओ से लगा हुआ है दाहोद जिले का कारोबार तथा व्यापार राजस्थान से होता है हमारे यहाँ खेडापा (गुजरात) तथा राजस्थान जाने के लिये कडाना डैम का पानी बीच में आता है जिस पर ब्रिज बन जाने पर यहाँ के लोगो का राजस्थान आना जाना 40 कि.मी. का सफ़र और सफ़र में लगने वाला समय बचेगा, मेरा अनुरोध है कि कृप्या खेडापा (गुजरात) तथा राजस्थान के बीच ब्रिज बनवाने का प्रावधान करने की कृपा करे।

माननीय मोदी जी की सरकार ने इस बजट के माध्यम से आने वाले 25 वर्षों की योजनाओं को धरातल पर लाकर उन्हें कार्यान्वित करने का बजट पेश किया है, जिसमें इज आफ लिविंग पर विशेष ध्यान दिया है भारत के प्रत्येक कोने से, दुर्गम पहाड़ो पे निवास करने वाले या मैदानी क्षेत्र में, किसान या स्टार्टअप करने वाले युवा उद्यमी या फिर औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो, इस बजट में हर परिप्रेक्ष्य को शामिल किया गया है।

देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला ये इतना अच्छा बजट पेश किया है इसलिए मैं वित्त मंत्री जी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ।

(इति)

***श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज):** माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष-2022-23 के आम बजट पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए,आपको धन्यवाद देता हूँ। आमजन को केंद्र बिंदु में रखकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु यशश्वी, कर्मयोगी, ईमानदार एवं दुनिया में भारत के नेतृत्व क्षमता की डंका बजाने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोदी जी की सरकार के द्वारा प्रस्तुत इस लोकप्रिय, ऐतिहासिक एवं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक आर्थिक विकास दर वाले इस बजट का समर्थन करते हुए कहना चाहूँगा कि आज हमारा देश कोविड-19 जैसे वैश्विक महा आपदा काल की चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर प्रत्येक भारतीयों की इच्छा शक्ति से भारत के उज्जवल भविष्य एवं चहुमुखी विकास के लिए एक आत्मनिर्भर एवं भारत को दुनियाँ में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए प्रस्तुत यह बजट हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय एवं हर्षदायक है। बजट में "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मन्त्र पर चलते हुए अगले 25 वर्षों के लिए एक ऐसे भारत का निर्माण जो मजबूत और आत्मनिर्भर हो, उससे सम्बन्धित की गई व्यवस्थाओं की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए मैं इस सदन के माध्यम से सभी भारतीय लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसे बजट से अपने-अपने हितों का शोधन करने का पुरजोर कोशिश करते हुए देश का विकास एवं अपना विकास करने का कष्ट करें| इस बजट से देश के विकास एवं समाज कल्याण सहित सर्वांगीण विकास सम्बन्धी मुख्य दूरदर्शी व्यवस्था निम्न प्रकार है :-

भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है,जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा | पीएलआई योजना में 30 लाख करोड़ रूपये के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। अगले 25 साल भारत के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया गया है। पीएम गतिशक्ति, समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा, संक्रमण और जलवायु कार्य, निवेश को वित्तीय मदद, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022 में 25000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए 20000 लाख करोड़ रुपये जुटाए जाएंगे। 2022-23 में चार स्थानों पर मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क बनाने के लिए पीपीपी प्रारूप के जरिए संविदाएं प्रदान की जाएंगी। स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना है। 2022-23 में देसी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और क्षमता वृद्धि कवय के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा।

महोदय, अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट बंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। अगले 3 साल के दौरान मल्टीमाडल लाजिस्टिक के लिए 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किये जाएंगें। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को पीपीपी प्रारूप में लाया

* Laid on the Table

जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए सविदाएं प्रदान की जाएंगी। उद्यम, ई-श्रम,एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया गया। ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा। ईसीएलजीएस के तहत गारंटी कवर को 50000 करोड़ रूपये बढाकर कुल 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के तहत 2 लाख करोड़ रूपये का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा | रेजिंग एंड एसिलेरेटिंग एमएसएमई पर्पोमेंस (आरएएमपी) प्रोग्राम 6000 करोड़ रूपए के परिव्यय से शुरू किया जाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिये नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिग़ एंड लिवलीहुड (डीईएसएच-स्टैक ई-पोर्टल) लाँच किया जाएगा | "ड्रोन शक्ति" की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन (डीआरएएएस) के लिए स्टार्टप्स को बढावा दिया जाएगा। पीएम ई-विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढावा देने के लिए वर्चुअल प्रयोगशाला और कौशल ई-प्रयोगशाला की स्थापना । डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई-कंटेंट विकसित किया जाएगा। व्यक्तिगत तौर पर पढाई करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविधालय की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय डिजीटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शरू किया जाएगा। 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। इसका नोडल सेंटर निम्हांस होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंग्लूरू इसे प्रौद्योगिक सहायता देगा। मिशन शक्ति, मिश्र वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। दो लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाडियों में उन्नयन किया जाएगा। हर घर नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रूपये आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48 हजार करोड़ रूपये आवंटित किए गए। शत-प्रतिशत 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यक बैंक 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (डीबीयू) स्थापित करेंगें | इम्बेडेड चिप और भावी प्रोद्योगिकी वाले ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगें | भवन उपनियमों शहरी नियोजन योजना,पारगमन उन्मुखी विकास का आधुनिकरण लागू किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बैट्री अदला-बदला निति लाई जाएगी। भूमि के रिकार्ड के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ठ भूमि पार्सल पहचान संख्या होगी। 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68% निर्धारित किया गया
जो 2021 में 58% के मुकाबले अधिक है। 25% रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ उद्योग स्टार्टप्स और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा। गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रूपये का सीधा भुगतान किया जाएगा। देश भर

में रसायनमुक्त प्राकृतिक खेती को बढावा दिया जाएगा । गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक की गलियारे वाले किसानों की जमीनों पर ध्यान दिया जाएगा। फसलों के आकलन भूमि रिकार्ड का डिजिटलीकरण,कीटनाशकों पोषक तत्वों के छिडकाव के लिए किसान ड्रोन। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस,भू-स्थानिक प्रणालीयों और ड्रोनों, सेमीकंडक्टर और इसके इको-सिस्टम अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिक्लस हरित ऊ र्जा और स्वच्छ गतिशीलता प्रणालियों जैसे सनराइज अवसरों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी योगदान उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रूपये की शरुआत 2022-23 में की।

अंत में मैं पुन: 2022-23 के लोकप्रिय बजट का समर्थन करते हुए अध्यक्ष महोदय के माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा के निम्न कार्यों को कराने का आग्रह करता हूं।

मेरे संसदीय क्षेत्र सारण जिला के जलालपुर में एक कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाए। मशरक जं. से महाराजगंज, दरौंदा, छपरा होते हुए पाटलीपुत्र या पटना जं. तक एक जोड़ी नई टेंन का संचालन किया जाए। लोकनायक जय प्रकाश की धरी सारण के छपरा जं. से जलालपुर, बनियापुर, भगवानपुर, मलमलिया होते हुए गांधी की कर्मभूमि चंपारण के मोतिहारी तक एक नई रेल लाइन बिछाई जाए। महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत महाराजगंज, गोरेयाकोठी, एकमा, मांझी, बनियापुर एवं तरैयां विधान सभा कक्षेत्र के अंतर्गत जल जमाव वाले चंवरों में जलीय कृषि एवं मत्स्य पालन को विकसित किया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाले NH-722 छपरा-मुजफ्फरपुर रोड से गडखा, पैगम्बरपुर,जनता बाजार,महाराजगंज होते हुए सिवान तक जाने वाले पथ को राष्ट्रीय राजमार्ग NH बनया जाये। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराया जाये। मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत एक बड़े स्तर का सौर ऊर्जा प्लांट का निर्माण कराया जाये। खेलो इंडिया के तहत खेल के क्षेत्र में ग्रामीण युवाओं को बढावा देने के लिए एक आधुनिक स्तर का स्टेडियम का निर्माण कराया जाये।

मैं पुन: महोदय, को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे बजट पर चर्चा का समय दिया गया |

(इति)

***कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर):** माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2022-23 बजट की चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

स्वतंत्रता के अमृत काल में कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न की गई कठिन चुनौतियों के बीच लगभग 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट देश के आगामी 25 वर्षों की विकास यात्रा के प्रारंभिक स्थल के रूप में इस वर्ष सदन में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 22-23 कारगर पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर लगभग 10.68 लाख करोड़ किया गया है, जो कि जीडीपी का लगभग 4.1% होगा। इस अभूतपूर्व व्यय से अर्थव्यवस्था को शक्ति मिलेगी और वह तेज गति से विकास कर सकेगी।

अमृत काल में तेज विकास के प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है, यथा-

- पी.एम. गतिशक्ति
- समावेशी विकास
- उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन, जलवायु कार्य योजना
- निवेशों का वित्त पोषण

गतिशक्ति के माध्यम से देश में अवसंरचना का बहुत तेज निर्माण होने वाला है, जिसमें न सिर्फ अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि नए रोजगारों का भी सृजन होगा। केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचनाओं के निर्माण पर अन्तर्विभागीय सहयोग के माध्यम से जोर देने से देश सहित बुंदेलखंड को लाभ होगा। वर्तमान में बुंदेलखंड में डिफेन्स कोरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण और केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का प्रारम्भ इत्यादि अवसंरचनात्मक विकास प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में हो रहा है। 44,605 करोड़ की लागत की केन-बेतवा रिवर लिंकिंग परियोजना हेतु वर्ष 21-22 के लिए 4300 करोड़ और वर्ष 22-23 के लिए 1400 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। इस परियोजना से बुंदेलखंड में 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी और 62 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा तथा 103 मेगावाट हाइड्रो व 27 मेगा वाट सोलर एनर्जी का भी उत्पादन होगा। हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत 8.7 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है। पिछले दो सालों में 5.5 करोड़ परिवारों को नल से जल मिला और वर्ष 22-23 में 3.8 करोड़ परिवारों के लिए 60,000 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है।

सभी के लिए घर योजना के अंतर्गत वर्ष 22-23 में 80 लाख घरों के लिए 48,000 करोड़ रुपयों का बजटीय आवंटन किया गया है। पी.एम. गतिशक्ति के माध्यम से देश में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाए जायेगें, रेलवे के द्वारा 2000 किमी. की नई रेल लाइन और 400 वन्दे भारत ट्रेन चलाए जाने का प्रावधान इस बजट के माध्यम से किया गया है। मै आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि

---

* Laid on the Table

- बुंदेलखंड में हो रहे तेज अवसंरचनात्मक विकास और इस क्षेत्र की यातायात के माध्यम से देश के अन्य स्थानों के साथ जुड़ने की क्षमता और विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण एक मल्टीमाडल लाजिस्टिक पार्क का निर्माण बुंदेलखंड में भी कराया जाए।
- बुंदेलखंड में स्थानीय संपर्कता को रेल द्वारा बढ़ाये जाने के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए और नई पैसेंजर व एक्सप्रेस ट्रेनों का भी संचालन किया जाए।

हमीरपुर-खजुराहो पैसेंजर ट्रेन तथा अयोध्या से उज्जैन वाया भोपाल-खजुराहो-बाँदा-महोबा-मौदहा सुमेरपुर-कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाये।

महोबा-चरखारी-राठ-उरई-भिण्ड-इटावा तक रेलवे लाइन की हमारी आवश्यकताओं को महत्व देते हुए स्वीकृत किया जाए, जिससे विस्तृत बुंदेलखंड क्षेत्र में आवागमन सुगम हो सके। महोदय मेरे द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने की मांग को अनेक बार सदन में उठाया है और आज पुन: आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि NH 86 (कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग) को कानपुर-कबरई के मध्य 8 लेन चौड़ा बनाया जाए, जिससे लगातार होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके।

कोरोना वायरस काल के समय देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को और भी मजबूत किया गया है। इस हेतु नेशनल डिजिटल हेल्थ इको सिस्टम – एक ओपन प्लेटफार्म प्रारम्भ किया जाएगा, साथ ही नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। यद्यपि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बुंदेलखंड में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, परन्तु फिर भी दिल्ली सहित बड़े महानगरों के एम्स अस्पतालों में इलाज के लिए इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए इन बड़े शहरों को जाते हैं, जिसमें समय और धन दोनों अधिक लगता है। अत: आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि महोबा उ०प्र० में एम्स संस्थान की स्थापना की जाए।

आपने मुझे वर्ष 2022-23 बजट चर्चा पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।

(इति)

***श्री संजय सेठ (राँची):** " नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग।

कुछ थे पहले के तरीके और कुछ है आज के ढंग।

रोशनी जाकर जो अंधेरों से टकराई है,

गांव की समस्याओं को भी बदलना पड़ा है रंग।"

बजट की जब बात आती है तो हमें यह भी समझना होगा कि आखिर बजट कैसा होना चाहिए? क्यों के लिए होना चाहिए? किसके लिए होना चाहिए?

महोदय, महात्मा गांधी जी ने 1930 में ही बजट की परिकल्पना की थी और वही परिकल्पना रामराज्य की परिकल्पना है। राम राज्य के बजट की परिकल्पना है। जब राम राज्य के बजट की परिकल्पना पूज्य महात्मा गांधी जी ने कही थी तो फिर आज के कांग्रेसियों को इस बजट से समस्या क्या होती है? यह समझ में ही नहीं आता है। गांधी जी ने रामराज्य का जो बजट बताया है, उसमें जब भगवान राम वनवास पर होते हैं तो भरत से पूछते हैं कि भरत बताओ कैसा बजट बना रहे हो अपने राज्य के लोगों के लिए? और तब भरत को यह सलाह दी जाती है कि बजट ऐसा होना चाहिए कि हर व्यक्ति राज्य में खुश रहे। बजट किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होना चाहिए। बजट उस बादल की तरह होना चाहिए जो हर जगह आवश्यकता अनुसार बारिश करवाएं। लोग खुश रहे। अच्छी फसल हो। अच्छी पैदावार हो।

महोदय, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारी यह सरकार का बजट उसी रामराज्य की परिकल्पना वाला बजट है।

यह बजट किसी एक को खुश करने के लिए नहीं है।

यह बजट पूरे देश को खुश करने के लिए है।

यह बजट किसी एक के लिए नहीं है।

यह बजट संपूर्ण भारत के नेक के लिए है। महोदय, आज भी गांव में जाता हूं। ग्रामीणों से मिलता हूं तो उनके चेहरे पर जो खुशी देखने को मिलती है, मैं उसे यहां शब्दों में नहीं कह सकता। गांव में बिजली है। और गांव में पानी पीने के लिए नल लगा हुआ है। गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्के घर बने हैं। उनका गांव में शौचालय है। उन गांव के किसानों के खाते में राशि आती है। उन गांव की बुजुर्गों, वृद्ध माताओं के खाते में हर महीने पेंशन आता है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अभी जब मैं अपने क्षेत्र घूम रहा था बजट सत्र से पहले, तो मैंने पूछा माताओं से, गांव के बुजुर्गों से कि बजट क्या होना चाहिए बताइए। आपके लिए हम प्रधानमंत्री जी को क्या कहे? उन सब ने यही बात कही कि प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत-बहुत आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी ने इतने साल में हमारे गांव में बिजली पहंचाई। हमारे गांव में पानी पहंचाया।

---

* Laid on the Table

हम सब को पक्का घर दिया। हम सब को शौचालय दिया। और सबसे बड़ी बात कि अब किसी को पेंशन के लिए ब्लॉक नहीं जाना पड़ता है। वह पेंशन उनके खाते में आता है।

महोदय, इससे सुकून वाली बात और क्या होगी कि देश के सुदूरवर्ती गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति, गांव में बैठे हुए बुजुर्ग, गांव में बैठी वृद्ध माता इस बात को महसूस कर रहे। वह इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारा उदय हो रहा है। नए भारत का उदय हो रहा है। अंत्योदय हो रहा है।

तब कहता हूं ....

कांग्रेस के घोटालों ने जब छुआ आसमान,

इस देश में एक नेता बनके उभरे महान।

कांग्रेस की खोली पोल,

बदल गया समाज का भूगोल।

जनता को छलने वाले,

घूम रहे हैं गोल-गोल।

महोदय, आजादी के अमृत काल में भारत सरकार द्वारा पेश किया गया यह बजट देश की 130 करोड़ जनता का बजट है। यह किसी क्षेत्र या राज्य का बजट नहीं है यह संपूर्ण देश का बजट है। हर देशवासी का बजट है।

महोदय, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी बात करते हैं तो वे हमेशा 130 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं। किसी राज्य, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय, पंथ की बात नहीं करते, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब इसमें एक कड़ी जुड़ी है सब का प्रयास। यह बजट सबके विकास के राह में सब के प्रयास और सब के विश्वास के लिए है। इसी राह पर चलते हुए हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमन जी संपूर्ण देश का बजट पेश किया है। किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं। किसी धर्म विशेष के लिए नहीं। किसी राज्य विशेष के लिए नहीं।

महोदय, पूर्व की सरकारों के बजट हम पढ़ते थे कोलगेट सस्ता नमक महंगा रेडीमेड कपड़ा सस्ता थान का कपड़ा महंगा वह बजट दरअसल जमाखोरी को बढ़ावा देने वाला बजट होता था जो चीजें महंगी होती थी उसकी जमाखोरी शुरू होती थी इसलिए मैं कहता हूं कि यह बजट कोलगेट का दाम घटाने के लिए और सीमेंट का दाम बढ़ाने के लिए नहीं है। यह बजट जमाखोरी बढ़ाने के लिए नहीं है। यह बजट संपर्ण देशवासियों को कदम से कदम मिलाकर चलाने के लिए बजट है।

यह बजट भारत के अमृत काल का बजट है। आने वाले 25 साल के भारत के नवनिर्माण का बजट है।

देश की रगों में दौड़ती है रेल,

देश के हर अंग को जोड़ती है रेल।

धर्म,जाति, पाती नहीं जानती है रेल,

छोटे बड़े सभी को अपना मानती है रेल।

इसलिए तो इस बजट में देशभर में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दिया गया। यह ट्रेन किसी एक राज्य में नहीं दौड़ेगी। संपूर्ण भारत को एक दूसरे राज्यों से जुड़ने के लिए दौड़ेंगी। एक दूसरे राज्य के नागरिकों को जोड़ने के लिए दौड़ेंगी। देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए दौड़ेंगी।

महोदय, आजादी के बाद से ही रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से हमारे देश की मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हुआ। जब देश की मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होगा तो भला इस देश के नागरिक का स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा। मैं मानता हूं कि एक बार में इस पर रोक लगाना संभव नहीं है, इसलिए इस बजट में प्राकृतिक खेती पर जोर दिया गया है। प्राथमिकता के आधार पर गंगा किनारे के क्षेत्रों में 5 किलोमीटर तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। इससे न सिर्फ गंगा प्रदूषण से मुक्त होगी बल्कि गंगा के किनारे रहने वाले लोगों की खेती में रुचि भी बढ़ेगी, उनकी आय बढ़ेगी। विविध फसलों की उपज भी होगी। और फिर अन्य क्षेत्रों के कृषक भी इससे प्रेरणा लेंगे। सरकार प्रोत्साहित करेगी और हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ चलेंगे। यह भारत को परम वैभवशाली भारत बनाने वाला बजट है। क्योंकि इस देश का खुशहाल किसान ही इस देश की मिटटी को खुशहाल रख सकता है। और किसान और मिट्टी मिलकर इस देश के हर नागरिक को खशहाल करेंगे। हर नागरिक को स्वस्थ करेंगे, ऐसा विश्वास मुझे है।

भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ सक्रिय है। दुनिया के लिए प्रारत करने वाली है। भारत विरोधियों की इच्छाओं पर कुठाराघात करने वाला है। जबकि कोरोना काल में दनिया की अर्थव्यवस्था चौपट और रुग्ण हा गई। अमेरिका और यूरोप तक की अर्थव्यवस्था लगभग चरमरा गई। भारत दनिया की इतनी बड़ी आबादी को कोरोना में भी सक्रिय रखना और उनके लिए सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को सक्रिय रखना बड़ा कठिन कार्य था। कोरोना बंदिशों के कारण उत्पादन कार्य प्रभावित था, आपूर्ति प्रक्रिया बाधित थी। इसके बावजूद इस दौरान महंगाई लगभग नियंत्रित रही और आपूर्ति कार्य भी सक्रिय रहा।

कोई बजट तब महत्वपूर्ण होता है, जब उसके अंदर जरूरतमंदों और गरीब तबकों के लिए कल्याण की बातें होती है, विकास की बातें होती हैं। हमारे देश में गरीबी हटाओ अभियान का नारा वर्षों पूर्व में दिया गया था पर आज तक गरीबी नहीं हटी। नरेंद्र मोदी जी के बजट और अन्य योजनाओं का विरोध करने वाली कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों से यह पूछा जाना चाहिए कि आज तक गरीबी क्यों नहीं हटी। उसके पीछे क्या कारण है। उन्होंने तो 50 वर्ष तक शासन किया था। लेकिन आज जब गरीबों के कल्याण के लिए व्यवस्था होती है, कोई मजबूत गरीबी उन्मूलन योजना

लाती है, तो भी विपक्ष विरोध करता है। इस बजट में गरीबों के लिए जितनी धनराशि दी गई है, उतनी धनराशि कभी भी नहीं दी गई थी। गरीबों को विकास के लिए कोई एक नहीं बल्कि कई योजनाएं चल रही हैं।

सबसे बड़ी बात है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी गांव में साफ पानी उपलब्ध नहीं है। गांव में अच्छी सड़कें ना होना, साफ पानी उपलब्ध ना होना चिंता की बात है। नरेंद्र मोदी जी ने यह बीड़ा उठाया है कि गांव में साफ पीने के पानी की समस्या को दूर करेंगे। देश का एक भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहना चाहिए। ऐसा तब संभव होगा जब गांव में घर घर पानी की आपूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाई जाए। बजट में प्रावधान किया गया है कि 4 करोड़ लोगों के घरों में पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। पानी की आपूर्ति पर पहले 40 हजार करोड़ रुपये खर्च होते थे, पर इस बजट में 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे 3.8 करोड़ घरों तक साफ पानी उपलब्ध कराया जायेगा। इस राशि को डेढ़ गुना करना यह दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए गांव को पानी पहंचाने की योजना कितना महत्व रखती है।

महोदय, यह बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में निवेश और राज्यों के विकास का गात दन के लिए 50 साल तक ब्याज मक्त ऋण का प्रावधान बजट में किया गया है। पीएम गति शक्ति से संबंधित इस परियोजना के तहत राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में एक लाख करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। ब्याज मुक्त ऋण मिलना ही अपने आप में अभी के समय में बहुत बड़ी बात है। हमारे विपक्षी बात बात पर सरकार का मजाक उड़ाते हैं। बैंकिंग सेक्टर व अन्य सेक्टर में सरकार कुछ नहीं कर रही है। यह बजट जवाब है कि राज्यों के विकास के लिए सरकार कितनी गंभीर है। राज्यों के विकास के लिए सरकार गंभीरता दिखा रही है, तभी तो ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है ताकि कोई भी राज्य विकास से अछूता नहीं रहे। किसी भी राज्य के नागरिक को यह महसूस नहीं हो कि सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। राज्यों को इतना अवश्य करना होगा कि केंद्र सरकार के साथ संबंध बेहतर हो सके, इस दिशा में राज्य की सरकारों को सोचना होगा। राज्यों को सोचना होगा और उन्हें सोचना ही चाहिए।

अमृत काल के इस बजट में संपूर्ण देश के हर नागरिक का विकास और उसकी योजनाएं समाहित है। 2.3 लाख करोड़ जीडीपी के साथ आज जब हमारा भारत दुनिया की चौथी मजबूत आर्थिक शक्ति बनने के लिए तैयार खड़ा है तो, ऐसे में यह जरूरी है कि हम जो भी काम करें, वह देश के लिए करें। 130 करोड जनता के लिए करें। और इस बजट में सरकार ने इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा है।

महोदय, 100 गीत शक्ति कार्गो टर्मिनल के माध्यम से जहां उत्पादों की ढलाई आसान होगी, वही "One Station-One Product" जैसी योजनाओं से विभिन्न राज्यों की उपज और उत्पाद को दुनिया से जुड़ने का अवसर मिलेगा। 25 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण से देश के विकास को नई गति प्रदान होगी। हर क्षेत्र एक दूसरे से आसानी से जुड़ सकेंगे। निश्चित रूप से यह बजट हर देशवासी का बजट है। हम सब के लिए यह बजट है। पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बजट पेश किया है, जो क्षेत्र और राज्य से ऊपर उठकर देश के लिए तैयार किया गया बजट है। हम सबको इस बजट का स्वागत करना चाहिए।

(इति)

***श्रीमती जसकौर मीना (दौसा):** माननीय अध्यक्ष जी समयाभाव के कारण वित्त विधेयक पर लिखित में अपने विचार रखते हुए अति प्रसन्नता का अनुभव करती हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सुंदर व संक्षिप्त में भारत के 2022-23 के बजट को प्रस्तुत किया, इसका समर्थन करती हूं। विश्व की सबसे बड़ी महामारी में देश की आर्थिक प्रगति को अच्छे तरीके से संभाला। इसी कारण दुनिया के देशों का भारत के प्रति नजरिया बदला है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूंगी यह नए अवसरों का, नए संकल्प सिद्धि का समय है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें भारत की 1.30 करोड़ आबादी को मूलभूत सुविधा ना मिलती हो।

9 करोड लोगों को नल से जल मिला 5 करोड को नए जल कनेक्शन मिले 4 करोड़ को और मिलेगा। 80 लाख पक्के घर देने का लक्ष्य, गांव व शहरों के गरीबों को मुहैया कराने का लक्ष्य है पिछले सालों में तीन करोड़ गरीबों को पक्का घर दिया जिसमें महिलाओं के नाम पर बनाया गया।

कृषि हो, शिक्षा हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संतुलित विकास की ओर ले जाने वाला बजट है। माननीय मंत्री जी मैं स्वयं एक किसान हूं। कृषि को राज्य का विषय बताने से हमारे छोटे किसान जो 80% की संख्या में जीवन यापन करते हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। मेरा संसदीय क्षेत्र जलाभाव से ग्रसित- डार्क जोन में आता है।

राजस्थान में चंबल बनास जैसे नदिया अपार जल प्रवाह को समुद्र में ले जाती है, यदि बनास व चंबल नदियों का जल राजस्थान के पूर्वी भाग में लाया जाए तो पूर्वी क्षेत्र के 14 जिलो को कृषि जल व पेय जल से तृप्त किया जा सकता है। मेरा संसदीय क्षेत्र राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगा हुआ होने के उपरांत भी लघु उद्योगों की दृष्टि से अभाव में है। बैंकों का सहयोग सकरात्मक नहीं है, युवाओं और महिलाओं को बैंकों द्वारा वित्तीय सुविधा प्राप्त नहीं होने से खाद्य तेलों में भारत को काफी मात्रा में आयात करना पड़ता है। दूसरी ओर राजस्थान तिलहन पैदा करने में नंबर एक पर है खादी ग्राम उद्योग से सहयोग लेकर कच्ची घानी का गांव- गांव में लघु उद्योग स्थापित कर राज्य का सहयोग करने में महिलाएं तैयार है, लेकिन बैंकों का सहयोग नहीं मिल पाता है।

मैं स्वयं इस अभियान को मेरे क्षेत्र में चला रही हूं लेकिन बैंक राशि ऋण देने में सहयोग नहीं करते। प्राकृतिक कृषि पर हमारी सरकार बहुत गंभीरता से निर्णय लेकर गंगा नदी तट को चिन्हित किया है। इसका दायद बढ़ाया जाए , ताकि हर लघु किसान प्रेरित हो सके।

महिला सशक्तीकरण की पहचान पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि कृषि श्रम में 80% महिलाओं का योगदान है। कृषि में कौशल विकास पर बल दिया जाए। मोटे अनाज की खरीद पर विशेष बल दिया जाए। किसानों के कृषि नलकूप और सौर ऊर्जा लगाने के लिए अनुदान राशि में वृद्धि की जाए।

वैसे तो बजट में संतुलित विकास पर बल दिया गया है। इसकी क्रियान्विति पर भी चौकसी रखना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद (इति)

---

* Laid on the Table

***श्री सुरेश कश्यप (शिमला):** महोदय मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला लोकसभा जो कि अनसूचित जाति आरक्षित सीट है, से आता हूँ।

महोदय, हिमाचल प्रदेश भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ देश, विदेश से सैलानी यहाँ की संस्कृति और प्राकृतिक सौन्दर्य देखने आते हैं। इसे देव भूमि भी कहा जाता है। संसद द्वारा दिसम्बर 1970 को हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पास किया गया तथा नया राज्य 25 जनवरी 1971 को अस्तित्व में आया। इस तरह हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18 वां राज्य बना। तब से लेकर आज तक हिमाचल प्रदेश ने एक लम्बी यात्रा तय की है। इस प्रदेश ने अनेकों सरकारें देखी हैं, परन्तु वर्तमान में पहली बार देश में मोदी सरकार और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक साथ मिलकर प्रदेश को विकास प्रगति की ओर अग्रसर कर रही है।

महोदय, मैं धन्यवाद करता हूँ श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और माननीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी का, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के रेलवे प्रोजेक्ट को गति देने के लिए 2022-2023 बजट में 1665 करोड़ रुपये की स्वीकृत प्रदान की। यह राशि सामरिक महत्व की भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन और दो अन्य परियोजनाओं के लिए जारी हुई है। हालांकि, हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इस बारे में अभी विस्तृत और आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन के लिए 1200 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर हुई है। नंगल-तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 335 और चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन के लिए 150 करोड़ रुपये मिले हैं। यह मालूम रहे कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेल लाइन को हिमाचल सरकार सामरिक महत्व की बताती रही है। यह 63.1 किलोमीटर लंबी है।

हर गरीब, दलित, पिछड़े को अपना पक्का मकान मिले, ऐसी सोच रखने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को कोटि-कोटि धन्यवाद। इस बजट में देश में चल रही प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत और नए 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक हिमाचल प्रदेश राज्य में 11943 मकानों की स्वीकृत की गयी है। मुझे बताते हुए गर्व है कि 8,578 पक्के मकान बनकर तैयार किये जा चुके हैं और शेष का कार्य तेज गति से चल रहा है। बारिश में बर्फ गिरने पर जो निर्धन लोग अपने आप तन्हा महसूस करते थे, आज वह अपने परिवार के साथ खुशहाली से पक्के मकानों में रह कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

वित्त मत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा वर्ष 2022-22 के बजट में इस योजना के अतर्गत 60 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसके माध्यम से प्रत्येक घर तक नल का साफ पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। पिछले 2 वर्षों में इस योजना के माध्यम से 5.5 करोड घरों तक नल का जल पहुंचाया गया है। इस योजना को 2019 में आरंभ किया गया था।

---

* Laid on the Table

हिमाचल प्रदेश, जो एक पहाड़ी राज्य है। वहां भी 15.5 लाख घरों को नल द्वारा जल पहुंचने का कार्य पूरा हो चुका है और इस बार 1.5 लाख को और स्वीकृत दी गयी है, जो कि इसी साल लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा।

कोविड-19 वैश्विक महामारी में जिस तरह माननीय प्रधान मंत्री जी ने योजना के तहत देश भर में 80 करोड़ गरीब, मजदूर, बेरोज़गार नागरिकों के लिए निशुल्क राशन मुहैया करवाया, यह मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि किसी गरीब का चूल्हा न बुझे, वह भूखा न सोए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का।

आज पर्वतीय क्षेत्रों में नए रोप वे बनाए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे न केवल वहां रह रहे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, बल्कि टूरिज्म को भी गति मिलेगी और रोजगार के अपार अवसर पैदा होंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में आज लगभग 51 % सड़कें प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना द्वारा बनाई गयी है। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ अक्सर लैंड स्लाइड हो जाती है। भारी वर्षा और बर्फबारी होने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अतः मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि इनके रखरखाव के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान की जाए।

महोदय, मैं यह भी संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में 5 हज़ार करोड़ एप्पल इकोनॉमी है, लेकिन देखा गया है कि विदेशी सेब, खास तौर पर ईरान और अन्य देशों से सेब को भारी मात्रा में आयात किया जाता है। ऐसे में भारतीय सेब के मूल्य में गिरावट देखी जाती है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी 100 % की जाए।

मैं केन्द्र सरकार के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि एक दर्जन से अधिक रोप-वे हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत किये गए हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए

तथा प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु इनकी संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए मैं और प्रदेश की जनता आभारी रहेगी। अटल टनेल की तर्ज पर टनल्स बनाने के लिए धन राशि स्वीकृत की जाए।

महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के पोंटा साहिब, काला अम्ब इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, इनको रेल लाइन के द्वारा हरियाणा राज्य के जगाधरी से जोड़ा जाए। देश

भर में 400 वन्दे भारत ट्रेन के लिए 40000 के बजट का प्रावधान दिया है।

अत: मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट देश को दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

(इति)

***श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा) :** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि कोरोना की लहर में माननीया सीतारमण जी, वित्त मंत्री ने देशहित में जो बजट तैयार किया है, उसका मैं पूर्णतया समर्थन करती हूँ। मेरे विचार से इस कोरोना काल में जबकि देश की आर्थिक स्थिति संभालना आसान नहीं था, उस परिस्थिति में उन्होंने ऐसा बजट पेश किया है, इसके लिए वे बधाई की पात्र हैं। इस बजट से देश का चहुंमुखी विकास होना निश्चित है। इसमें जहां एक ओर सड़कों के द्वारा गांवों से शहरों को जोड़ते हुए देश की सीमा पर स्थित दुर्गम स्थानों को जोड़ने की तैयारी में है तो दूसरी ओर रेलवे देश के अनेक भागों में नई रेल लाइन बनाकर और रेल लाइनों को चौड़ा करके अनेक स्थानों तक जाने का रास्ता सुगम बना रही है, जो देश के लोगों हेतु चहुमुखी विकास का अवसर प्रस्तुत कर रही हैं।

यह बजट भारत को आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही साथ ही यह बजट युवाओं, महिलाओं और गरीबों के हित में है।

कोरोना संकट के बीच आया यह बजट इसलिए भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि माननीय मोदी जी की सरकार ने देश के आर्थिक भविष्य को सुधारने पर ध्यान दिया न कि लोक लुभावन योजनाओं के जरिये फौरी वाहवाही पाने अथवा कोई राजनितिक लाभ उठाने की कोशिश की। यह स्पष्ट है कि सरकार ने चुनावी राजनीतिक हितों के आगे देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के दूरगामी लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित किया है, बल्कि यह भी रेखांकित किया कि उसका उद्देश्य 2047 तक भारत को एक समर्थ, सक्षम देश के रूप में सामने लाना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह बजट वृद्धि को रफ्तार देने वाला है।

आज के राजनीतिक माहौल में ऐसा बजट वही सरकार दे सकती है जिसमें आत्मविश्वास कूट-कूट कर भरा हो। इस बजट के द्वारा श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने यह साफ कर दिया है कि तत्कालीन लाभ देकर थोड़े अधिक वोट तो लिए जा सकते हैं, लेकिन काफी लम्बी राजनीति हेतु जनता के जीवन में बदलाव लाना जरूरी है। यह अर्थशास्त्र के द्वारा ही संभव हो सकता है।

हमारी सरकार ने अपने इस बजट में पांच बड़ी घोषणाएं की हैं :-

1. देश में रिजर्व बैंक ने पहली बार डिजिटल करेंसी जारी करने का निर्णय लिया है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री जी ने डिजिटल करेंसी जारी करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा की अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष में रिजर्व बैंक "डिजिटल रूपी" जारी करेगा। वर्चुअल संपत्ति और उससे होने वाली आय पर 30 प्रतिशत आयकर लगाया गया है, इससे यह लेन देन में आएगा।
2. 5-जी की लांचिंग: 5-जी मोबाइल सेवा शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी इसी वर्ष की जायेगी। पहले यह दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में प्रारंभ की जाएगी, इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी। 5-जी माडल के तहत सुदूर क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचेगा ताकि लोग शहरों की तरह ही इसका उपयोग कर सकें।

---

* Laid on the Table

3. 80 लाख सस्ते मकान: प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत देश में 80 लाख सस्ते मकान बनाये जायेंगे, इसके लिए 48 हजार करोड़ रूपये आवंटित किये गये हैं। शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी जबकि गाँवों के लिए आधुनिक मकान बनाये जायेंगे। केंद्र और राज्य इसे मिलकर पूरा करेंगे।
4. डिजिटल यूनिवर्सिटी का निर्माण: इस बजट वर्ष में डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित होगी जिसमे ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया जायेगा | इसमें अलग-अलग भारतीय भाषाओं में विश्व स्तर पर पढ़ाई होगी, साथ ही स्कूली शिक्षा और रोजगार के पाठ्यक्रमों को भी पढ़ाया जाएगा।
5. 68% रक्षा उपकरण देश में खरीदें जायेंगे: रक्षा क्षेत्र में “मेक इन इंडिया” अभियान के तहत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा।

इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू गरीब लोगों के कल्याण से जुड़ा हुआ है। इसी को ध्यान में रखकर गरीबों के लिए पक्का घर, नल से जल, शौचालय और रसोई गैस की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इन्टरनेट संपर्क पर भी जोर दिया गया है।

इस बजट में शामिल योजनाओं का लाभ युवा, मध्यम वर्ग, गरीब, दलित और पिछड़ों सहित सभी वर्गों को मिलेगा। यह बजट निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे “ग्रीन जॉब" का क्षेत्र भी खुलेगा। इस बजट से किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस बजट में गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल इन पांच राज्यों में गंगा किनारे प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

मेरे विचार से यह देश का पहला बजट है जिसमें न केवल जलवायु परिवर्तन से होने वाले खतरों को लेकर चिंता व्यक्त की गई है, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कई अहम् घोषणाएं भी की गई हैं।

हमारी सरकार पर्यावरण पर सकरात्मक प्रभाव डालने वाली और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने वाली योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए “ग्रीन बांड" जारी करने पर विचार कर रही है।

बजट से ऐसा प्रतीत होता है की सरकार स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में स्वीकार करती है।

हमारी सरकार ने मेट्रो और रैपिड रेल को और गति देने की तैयारी इस बजट के द्वारा की है। केंद्रीय सरकार द्वारा इसके लिए अधिक राशि आवंटित की गई है।

हमारे प्रधानमंत्री ने विकास के लिए "पी.एम. गतिशक्ति” को आधार माना है। इसके अंतर्गत सड़क, रेलवे, एअरपोर्ट, बंदरगाह ट्रांसपोर्ट, जलमार्गों और लोजिस्टिक्स तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे सात इंजन शामिल किये हैं। इस योजना की प्रगति के लिए इस बजट में 65% राशि अधिक

आवंटित की गई है। इस वर्ष 50 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे का निर्माण होगा और 22 नए सुपर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा।

अगले तीन वर्षों में 400 वन्दे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए भी पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक राशि आवंटित की गई है। एक क्लिक पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी हमारी सरकार द्वारा रखा गया है।

विषय: मेरे संसदीय मतक्षेत्र वडोदरा में डिजिटल बॅकिंग यूनिट स्थापित करने के विषय में

आदरणीय सभापति जी,

सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे मेरे संसदीय मतक्षेत्र वडोदरा के विषय में बोलने का अवसर प्रदान किया। आने वाले 25 वर्षों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए "आत्मनिर्भर भारत" के अभियान को आगे बढ़ाते हुए "आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था" का बजट देने के लिए मैं वडोदरा के नागरिकों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारामण जी का धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। यह आम बजट बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी जी और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

आदरणीय सभापति जी,

आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए बैंकिंग सुविधा को अधिक सुलभ बनाना था। आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद भारत देश की बैंकिंग आबादी कुल 80% से भी ज्यादा हो गई है। वर्ष 2021 आखिर तक प्रधान मंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों की संख्या करीब 43.81 करोड़ है एवं जन धन बैंक खातों में कुल जमा राशि करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है।

आदरणीय सभापति जी,

वर्ष 2021 में 73 लाख करोड़ की धनराशि के 3800 करोड़ से अधिक UPI लेनदेन दर्ज किए गए हैं। कुछ लोग डिजिटल इंडिया का मज़ाक बना रहे थे। ये उनको समझना चाहिए यह केंद्र सरकार की परियोजनाओं की महत्वपूर्ण सिद्धि है। वित्त वर्ष 2018 में भारत का डिजिटल ऋण 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और वर्ष 2023 तक पाँच गुना वृद्धि होने के अनुमान के साथ डिजिटल संवितरण 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है। इसके साथ ही वर्ष 2025 तक भारत का फिनटेक बाजार 6.2 ट्रिलियन रुपए तक पहुँचने की संभावना है।

आदरणीय सभापति जी,

इस आम बजट में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने देश के हर एक नागरिक को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने हेतु देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना करने की घोषणा की है। मैं आपको बताना चाहूंगी की देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय वडोदरा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना वर्ष 1908 मे महाराजा सयाजीराव गायकवाड तृतीय के द्वारा वडोदरा में की गयी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय

स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के बाद का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगी की वडोदरा जिला में भारतीय स्टेट बेंक के बचत खाता धारकों की कुल संख्या 13 लाख 10 हजार है और बैंक ऑफ बरोड़ा के बचत खाता धारकों की कुल संख्या ।। लाख 56 हजार 400 है। जो की सिर्फ इन दोनों बैंक बचत खाते वडोदरा जिले की कुल जनसंख्या के 56 प्रतिशत के करीब है।

आदरणीय सभापति जी, मैं आपश्री के सम्मानित माध्यम से वित्त मंत्री जी के समक्ष अपनी मांग रखना चाहूंगी कि इस आम बजट में 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है। उसके मुताबिक मेरे संसदीय मतक्षेत्र वडोदरा में भी डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित किया जाये, जिससे वडोदरा की जनता को डिजिटल बैंकिंग सुविधा का अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

विषय: मेरे संसदीय मतक्षेत्र वडोदरा की सावली विधान सभा में ईएसआई (ESI) हॉस्पिटल को मंजूरी देने के विषय में

आदरणीय सभापति जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे संसदीय मतक्षेत्र वडोदरा के सावली विधान सभा मे गुजरात की बड़ी GIDC ने समाविष्ट एक मंजूसर GIDC भी है, जिसमें करीब 30000 से 35000 कर्मचारी कार्यरत है। इन सभी कर्मचारियों को अगर अकस्मात होने पर 30 किमी का सफर करते हुए वडोदरा शहर आ कर इलाज करवाना पड़ता है। जिस वजह से अनावश्यक रूप से उनके धन और समय व्यर्थ होते है एवं इन सभी कर्मचारियों की आय मे से ईएसआई का भुगतान भी किया जा सकता है। ईएसआई (ESI) हॉस्पिटल के निर्माण होने से सभी कर्मचारी के आरोग्य विषयक सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी एवं ESI हॉस्पिटल के द्वारा कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को भी ESI हॉस्पिटल का लाभ मिल सकेगा।

आदरणीय सभापति जी,

मैं आपश्री के सम्मानित माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री जी से नम्र अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे संसदीय मतक्षेत्र वडोदरा की सावली विधानसभा में ईएसआई (ESI) हॉस्पिटल को मंजूरी देने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया की पहेल करे। अतः मैं एक बार पुनः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ।

(इति)

***श्री हँसमुखभाई एस. पटेल (अहमदाबाद पूर्व):** माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने संसद में जो केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। गांव, गरीब, किसान, महिला, दलित, पिछड़े, एवं आदिवासियों के लिए लाए हुए बजट के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, हमारी सरकार का नारा है "जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान" इसलिए इस बजट में ड्रोन की बात की गई है। आज यदि डिफेंस में ड्रोन की आवश्यकता है, सिविल एविएशन में ड्रोन की आवश्यकता है, तो किसानों को भी ड्रोन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। किसानों को भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे वे अपनी फसल की रक्षा कर पाएं, फर्टिलाइजर का सही उपयोग कर पाएं, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर पाएं और कीटकनाशक का उपयोग कर पाएं। ड्रोन का उपयोग आज शुरू हो गया है।

इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए ओपन प्लेटफार्म बनाया जाएगा। इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य केंद्रों की डिजिटल रजिस्ट्री, यूनीक आईडेंटिटी कंसेंट फ्रेमवर्क और स्वास्थ्य केंद्रों का यूनिवर्सल एक्सेस शामिल होगा। मेंटल हेल्थ की उत्तम दर्जे की काउंसलिंग और केयर सर्विस देने के लिए नेशनल दिल्ली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में काम कैसे किया जाएगा, इसका पूरा प्लान बनता है। जब बजट इंप्लीमेंटेशन का पेपर अगले साल आएगा तो हमने कहां-कहां क्या प्रोजेक्ट किए, वह भी बताया जाएगा।

इस बजट में विश्वस्तरीय आधुनिक अवसंरचना तथा लॉजिस्टिक के लिए पीएम गतिशक्ति के अंतर्गत 7 इंजनों यानी सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, सार्वजनिक परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक्स से संचालित राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। एक्सप्रेस वे के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का काम पूरा करना है। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफार्म तैयार करना, जिससे सभी ऑपरेट मोड ऑपरेटरों में डाटा विनिमय हो सके। यात्रियों की निर्बाध यात्रा के लिए ओपन सोर्स मोबिलिटी का भी निर्माण किया जाएगा। पीपीपी मॉडल के तहत चार मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी वह 2022-2023 में कार्यान्वित हो जाएगा।

पोस्टल एवं रेलवे नेटवर्क को एकत्रित किया जाएगा जिससे पार्सल प्रेषण में सुविधा होगी। मुझे बताने में गर्व होता है कि रेल बजट में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद डिविजन जो मेरे संसदीय क्षेत्र में है, वहां 1,659 करोड रुपए पुराने एवं नए विकास के कार्य में खर्च के लिए आयोजन किया गया है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का एवं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

---

* Laid on the Table

नई दिल्ली-मुंबई के बीच दौड़ने वाली ट्रेन की महत्तम स्पीड 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए 450 करोड़ रूपए खर्च किए जायेंगे। पालनपुर से समाख्याली रेल लाइन के लिए 400 करोड़ और हिम्मतनगर खेडब्रह्मा रेल लाइन मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित करने के लिए 370 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अहमदाबाद से बोटाद रेल लाइन के लिए 56 करोड़ का आयोजन किया गया है।

स्थानीय व्यवसाय और आपूर्ति श्रंखलाओ की मदद के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कांसेप्ट को लागू किया जाएगा अगले 3 वर्षों के दौरान 400 नई वंदे भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया जाएगा, इसके अतिरिक्त अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे।

इस बजट में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च, 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसका गारंटी कवर ₹50,000 किया गया है। अब कुल 5,00,000 करोड़ रुपए का गारंटी कवर है। 200000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की सुविधा के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हेतु क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को नया रूप दिया गया है।

सभापति महोदय, इस बजट में नेशनल इन्फ्राट्रक्चर पाइपलाइन में परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े प्रोजेक्ट को पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ा जाएगा, जिसको पिछले वर्ष शुरू किया गया था। पूर्वोत्तर में विकास योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद के जरिए प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनीशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट को लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में एक लाख करोड़ रुपए आबंटित किए जा रहा हैं। इस कोरोना काल में दूरंदेशी बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी एवं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र के विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं जिन्हें सरकार अपनी योजना में शामिल करती है तो मेरे संसदीय क्षेत्र का समुचित विकास हो पाएगा। मेरे संसदीय क्षेत्र अहमदाबाद पूर्व में बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में बड़े हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाय। आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

(इति)

***श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ (पंचमहल):** अध्यक्ष महोदय, मैं सामान्य बजट 2022-2023 पर चर्चा अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट 2022-2023 पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं माननीय नरेन्द्र भाई मोदी एवं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को बधाई देता हूं कि आपने इस वैश्विक महामारी के बावजूद भी इस बजट में सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का ध्यान रखा है।

इस वैश्विक महामारी में स्वास्थ्य जगत में विषेश ध्यान देते हुए आयुष्मान भारत को सुचारू रूप से सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच तैयार किया जा रहा है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य की डिजिटल रजिस्ट्रियां शामिल की जा रही है इसका सभी लोगों को असानी से लाभ मिल सकेगा।

माननीय प्रधान मंत्री जी का उद्देश्य अमृत काल में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके उस दृष्टिकोण को पूरा करना है। अमृत काल में निधारित लक्ष्य में सूक्ष्म आर्थिक स्तर–समग्र कल्याण पर जोर देते हुए व्यापक आर्थिक विकास में सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक, प्राद्योगिकी समर्थित विकास, उर्जा परिवर्तन तथा जलवायु कार्य-योजना को बढावा देना तथा सार्वजनिक पूंजी निवेश की सहायता से निजी निवेश आरंभ करने के प्राभावी चक्र से निजी निवेस से सहायता उपलब्ध करना है।

अगर हम पीएम गतिशक्ति की बात करते है तो इसमें आर्थिक वृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी पद्धति है। इस पद्धति का संचालन सात इंजनों से होता है। जिसमें – सड़क, रेलवे एयरपोर्ट, पतन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना जैसे सातो इंजन को महत्व देकर अर्थ व्यवस्था को आगे ले जाने का कार्य किया जा रहा है।

इसी प्रकार पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना में आर्थिक परिवर्तन के सात इंजन, निर्बाध बहुविध कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता शक्ति है। इसमें गतिशक्ति मास्टर प्लान के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा तैयार इन्फ्रास्ट्रक्चर भी शामिल करने का प्रावधान इस बजट के माध्यम से किया गया है, इसका लाभ सभी क्षेत्रों को मिल सकेगा।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी बधाई देता हूं, जिस प्रकार सड़क परिवहन के लिए वर्ष 2022-2023 में एक्सप्रेस मार्ग के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का प्रतिपादन किया जाएगा ताकि लोगों एवं वस्तुओं का अधिक तेज गति देने का कार्य किया है। वर्ष 2022-2023 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25000 कि.मी. जोड़े जा रहे है इससे सभी लोगों को फायदा मिल सकेगा। पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आने-जाने हेतु घंटों तक चलना पड़ता था लेकिन इस बजट में जिस प्रकार से पर्वतमाला : राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के माध्यम से आवागमन को और सुविधा जनक किया गया है जिससे काफी समय का बचत हो सकेगा।

---

* Laid on the Table

हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है वही पर माननीय मोदी जी की सरकार ने रबी 2021-2022 में गेहूं की खरीद और खरीफ 2021-2022 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं एवं धान होगा एवं एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रूपये का भुगतान सीधे किसानों के खाते में करने से हमारे अन्नदाताओं को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

कई इलाकों में पेय जल की बहुत ही कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था लेकिन माननीय मोदी जी के सरकार द्वारा हर घर नल से जल की परियोजना के माध्यम से सभी लोगों को पेय जल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।

इसी प्रकार केन बेटवा परियोजना और अन्य रीवर लिंकीग परियोजनाएं, खाद्य प्रसंसकरण, एमएसएमई कौशल विकास, गुणवक्ताप्रद शिक्षा का सार्वभौमिकता को प्रमुख महत्व देकर सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का ध्यान दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं एवं मै इस बजट 2022-2023 का समर्थन करता हूं।

(इति)

***श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार):** महोदय, बजट पर जो साधारण डिस्कशन चल रहे हैं, मैं अपना भाषण लिखित में दे रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय बजट 2022-23 साधारण डिस्कशन में आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र में ज्यादातर लोग किसान और गरीब है। उसमें इंडस्ट्री न के बराबर है और होने का उम्मीद भी कम है। देखा जाये तो पिछले बीजेपी सरकार आने के बाद आसाम में नए इंडस्ट्री बहुत कम आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देखे तो यह रेट 2018, 2019 और 2020 में 2.30 , 0.02 और 0.49 % है।

महोदय , इस बार का मनरेगा बजट सिर्फ 73000 करोड़ है जो पिछले वर्ष से भी कम है इसलिए इस राशि को और बढ़ानी चाहिए। असम के लिए मनरेगा का जो राशि आवंटित (2021 - 22) 1725.81 करोड़ किए हैं वो भी दूसरे राज्य के मुताबिक बहुत कम है इसलिए असम का राशि भी बढ़ानी चाहिए। हमने देखा है कि मनरेगा के फण्ड भी political fund जैसा हो गया है। rulling party के लोगों ने गरीब के job card को अपने हाथ में रखके labour badget बनाके ले लेता है और कार्ड धारक को कुछ कमीशन देता है। ऐसा बहुत केस थाने में दर्ज है।

महोदय, जल जीवन मिशन के अंदर जो महत्वकांक्षी योजना है उसको मैं दिल से स्वागत करता हूँ। परंतु मेरा संसदीय क्षेत्र के साथ साथ पूरे असम में शुद्ध पेयजल की किल्लत है। गुवाहाटी शहर में शुद्ध पेयजल के लिए एसियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा गत 10 वर्षों से चल रहे पेयजल योजना अभी सिर्फ 30 % तक ही पूरे हो पाए हैं और असम के कई जगहों में बहुत से प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों में ही सीमित रह गया है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि दोबारा ऐसा घटना न घटे इसके लिए सरकार ध्यान दे। राज्य सरकार को जो भी फण्ड आवंटित किया जाता है वह फण्ड सही तरीके से utilisation हो यह पक्का करना चाहिए। उसके लिए क्षेत्र के सांसद सहित सभी जनप्रतिनिधियों को कानूनन शामिल करनी चाहिए। इसमें बॉर्डर एरिया को भी शामिल करना चाहिए।।

महोदय, उत्तर पूर्वी राज्यों के नार्थ ईस्टर्न कौंसिल को 1500 करोड़ का जो बजट दिया है वह बहुत ही कम है। इस बजट से आठ राज्यों के आठ प्रोजेक्ट भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएंगे।

महोदय, अनुसूचित जनजातियों के लिए जहां, अनुसूचित जनजातियों की संख्या अधिक है उन सभी सब डिवीज़न लैवल में एकलवय मॉडल स्कूल बनाने की योजना है और

---

* Laid on the Table

ऐसे बहुत सब डिबिजन हैं जहां अनुसूचित जनजातियों की संख्या कम है वह पर भी एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का प्रयास करना चाहिए।

महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में मेरा संसदीय क्षेत्र सहित पूरे असम के लिए स्पेशल पैकेज देना चाहिए क्योंकि असम के बहुत से स्कूल provincialized नहीं हुए हैं। शिक्षकों की भी किल्लत है। बहुत से स्कूलों में स्टूडेंट के मुताबिक क्लासरूम नहीं हैं। राज्य सरकार के स्कूलों में Quality Education और Infrastructure अच्छा नहीं है जिसके चलते वहा के स्टूडेंट्स को क्वालिटी एडुकेशन नहीं मिल पाती है। इसके लिए एकलव्य मॉडल स्कूल के साथ Vocational School भी खुलने चाहिए ताकि समय से पहले युवा अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

महोदय , प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो स्किल ट्रेनिंग युवाओं को मिली, वे जॉब देने में असफल हुए इसलिए आईटीआई को सभी सब डिवीज़न लैवल पर स्थायी सेन्टर बना दिया जाए, इससे बैंकों द्वारा लिंकिंग करके लोगों को राजगार मिलने में सहायक होगी।

महोदय, हमारे क्षेत्र के ज्यादातर लोग किसान हैं और खेती पर ही निर्भर हैं। क्षेत्र के लोग एक खेती के ऊपर ही निर्भर हैं जिसके जरिये उनका जीवन यापन बहुत मुश्किल से चलता है। Irrigation का अगर सही प्रयोग किया जाये तो वहा के किसानों द्वारा मल्टी क्रॉपिंग करके उनकी दशा और दिशा बदलने में सहायक साबित होगा। असम के खेतों में Irrigation और electrification सुविधा न के बराबर है, अगर इस पर फोकस किया जाये तो किसानों की इनकम डबल हो सकती है।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के सरभोग विधान सभा में 1962 में स्थापित Ramie Research Station है, लेकिन वह किसी काम का नहीं है। वहा न कोई स्टाफ है न कोई साइंटिस्ट। Ramie एक अमूल्य रतन है जिसकी Promotion करेंगे तो मोदी जी का किसानों का डबल इनकम का सपना फोर फाइव टाइम तक बढ़ोतरी दे सकता है, क्योंकि Ramie से कपड़ा, थैली, रस्सी और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जा सकता है, ऐसी हमें जानकारी प्राप्त है, और तो और उसकी longibility 100 साल तक है। वह न टूटता है न फटता है। इस Ramie को केंद्र की ओर से प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रोग्राम बनाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद!

(इति)

***श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे (नासिक):** अध्यक्ष महोदय, मैं सन 2022-23 के सामान्य बजट के बारे में लिखित स्वरूप में अपनी बात रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हर साल बजट पेश किया जाता है, ताकि हर साल हमारे देश का नागरिक और देश एक कदम आगे चल कर आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर हो सके। आज हमारे देश को आजाद होकर 75 साल होने जा रहे है और हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे है। आगे चल कर आजादी के 100 साल मनाने वाला हमारा देश विश्व में सबसे पहला होगा। इसका भी सपना हम देख रहे है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के सामने बेरोजगारी, किसानों की समस्या और महिला सशक्तिकरण यह तीनों बातें बड़ी चुनौती हैं। उसी के साथ महंगाई रोक कर रखना और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना यह भी उतना ही जरुरी है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सरकारी नौकरी के लिए शून्य बजट है। प्राइवेट सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से मैन पॉवर कम लगता है, इसीलिए कौशल विकास के माध्यम से युवकों को स्वयं रोजगार निर्माण करना यही देश का अगला भावी कदम है। मै समझता हूं इस बजट में बेरोजगारी की संख्या को नजर रखते हुए इस साल कम बजट रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, किसानों की आमदनी सन 2022 तक दुगनी होगी। ऐसा इस सरकार ने वादा किया था। हमारा देश कृषि प्रधान देश करके जाना जाता है। लगभग 60% जनता खेती पर निर्भर है। किसान को 24 घंटे मेहनत करने के बाद भी वातावरण पर निर्भर होना पड़ता है। उनके नुकसान के हिसाब से उन्हें 10% भी पैसा नहीं मिलता है। उनकी आमदनी दुगनी होने के बजाए उनका उत्पादन खर्च दुगना हो गया है। ऐसा कैसे उनकी आमदनी दुगनी होगी ? उनका उत्पादन खर्च कैसे कम हो सकता है, इसके लिए नियोजन करना अपेक्षित था।

अध्यक्ष महोदय हमें अगर हर परिवार को सक्षम बनाना है तो हमें महिला सशक्तिकरण को बढावा देना जरुरी है। महिलाओं के लिए नई-नई योजना लाने की जरुरत है और उसमें सरकार से उन्हें मदद देने की जरुरत है। यह बजट महिलाओं की संख्या के हिसाब से बहुत कम लगता है।

अध्यक्ष महोदय, महंगाई हर परिवार के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। महंगाई रोकना भी जरुरी है। सरकार एक तरफ गैस की सब्सिडी दे रही है और दूसरी तरफ सरकार ने गैस का भाव दुगना कर दिया है। आज पेट्रोल डीजल के भाव लगभग 100 रू. से भी आगे जाने की संभावना है, जिससे सर्वसामान्य परिवार की जेब में फर्क पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से हम वैश्विक महामारी कोरोना का सामना कर रहे है। पिछले दो साल से हमें हमारी सांसद निधि रू.5 करोड़ रुपये भी नहीं दी गई है। हम सब लोकसभा और राज्य सभा के सदस्य मिलकर लगभग 8०० सांसद है। इसका मतलब रू.4००० करोड़ हर साल सांसदों को करोना की मदद के लिए दिया गया, लेकिन हम जब बजट की बात करते है कि 37 लाख करोड़ का बजट है तो उसमे रू.4००० करोड़ कम करके हम क्या दिखाना चाहते थे,

* Laid on the Table

क्योकि इसी कोरोना की महामारी के टाइम जनता भी हमसे इसी महामारी के लिए मदद की अपेक्षा कर रही थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह विनती करता हूं कि दो साल इस 17वीं लोकसभा के बाकी हैं। इन दो सालों के लिए रू.10 करोड़ रुपये दिए जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया जा रहा है जैसे रेल, राष्ट्रीय महामार्ग, लोगिस्टिक पार्क इत्यादि, लेकिन इसमें मेरे नासिक संसदीय क्षेत्र में नासिक शहर के लिए पिछले बजट 2021-22 में नई मेट्रो की घोषणा की गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए 20 % राज्य, 20 % केंद्र और 60% दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार ने 20 % को मान्यता दी है। 60 % समभाग भी मंजूर है , लेकिन 2021-22 बजट में घोषणा होने के बावजूद भी केंद्र सरकार की 20% राशी को अंतिम मान्यता नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह हमारे महाराष्ट्र राज्य के एक महत्वपूर्ण रेल प्रकल्प जो नासिक – पुणे को नई लाइन से जोड़ने वाला है, उसे भी रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय ने मान्यता दी है। इस प्रकल्प के लिए 20 % राज्य सरकार 20 % केंद्र सरकार और 60% समभाग ऐसा आर्थिक गणित है। इस प्रकल्प को भी राज्य सरकार ने 20 % की मान्यता दी है। 60 % समभाग भी मंजूर है और पिछले एक साल से केंद्र सरकार का 20% हिस्सा अभी तक मान्यता नहीं मिली है। मेरी आपके माध्यम से विनती है कि केंद्र सरकार उनके 20% हिस्से को नासिक पुणे नई रेल लाईन को जल्द से जल्द मान्यता दे।

धन्यवाद!

(इति)

***श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर):** अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं मा. वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ की उन्होंने कोरोना की चुनौतियों से उबरती अर्थव्यवस्था में वृद्धि को रफ़्तार देनेवाला दूरदर्शी और व्यावहारिक बजट पेश किया। साथ ही मैं उनका साधुवाद करना चाहूँगा की उन्होंने मा. प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने की दिशा में देश को अग्रसित करने वाला बजट प्रस्तुत किया। इस बजट का दीर्घकालीन लक्ष्य यह भी है की स्वतंत्रता के सौवें वर्ष तक समर्थ भारत के निर्माण की डगर पर तेजी से आगे बढ़ा जायेगा। महोदय, वर्ष 2022-23 के बजट में कृषि और किसान हितों, बुनियादी ढांचे की मजबूती , उद्योग कारोबार की गतिशीलता , निर्यात वृद्धि , शेयर बाजारों को प्रोत्साहन , रोजगार के नए अवसर, नई मांग का निर्माण टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढाने के साथ सामाजिक न्याय के लिए भी प्रभावी प्रावधान सुनिश्चित किये गए हैं | मा. वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किये गए बजट का एक दीर्घकालीन लक्ष्य यह भी की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक सशक्त और समर्थ भारत के निर्माण के लिए तेज गति से आगे बढ़ा जायेगा। मा. वित्त मंत्री जी ने अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन की बूस्टर डोज देते समय राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.4 फीसदी तक विस्तृत करने में कोई संकोच नहीं किया है। साथ ही इस बजट से अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी जा सकेगी। वर्ष 2022-23 के बजट का आकार यानि कुल व्यय 39.45 लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। यदि हम विनिवेश लक्ष्य की बात करें तो यह लक्ष्य 65,000 करोड़ रूपये का रखा गया है। साथ ही क्रिप्टोकरेंसी के लाभ पर 30 प्रतिशत का कर लगाया गया है। निःसंदेह नए बजट में खेती और किसान के हितों को उच्च प्राथमिकता दी गयी हैं एवं कृषि की विकास दर बढाने और छोटे किसानों की आमदनी बढाने के लिए कृषि सुधारों को व्यापक प्रोत्साहन भी बजट में दिया गया है। खाद्य और उर्वरक सब्सीडी पर इस बजट में जोरदार इजाफा किया गया है। कृषि में निजी निवेश बढ़ाने के लिए अनेकों प्रोत्साहन दिए गए हैं। नए बजट में प्राकृतिक खेती और मांग आधारित खेती को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष घोषणा की गयी है साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाने वाली सरकारी खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एमएसपी की रकम सीधे किसानों के बैंक खातो में हस्तांतरित करने का महत्वपूर्ण कदम भी बजट में आगे बढ़ाया गया है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के मद्देनजर खाद्य प्रसंस्करित क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाने का प्रावधान भी बजट में किया गया है | बजट में सरकार द्वारा एग्री फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा भी दिया गया है। कृषि उत्पादों की मार्केटिंग , ब्रांडिंग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान किये गए हैं निःसंदेह इस बजट में मा. वित्त मंत्री जी ने बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय बढाकर आर्थिक गतिविधियाँ, खपत और नौकरियों के सृजन को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई गयी है। साथ ही इस बजट में वर्ष 2022-23 के लिए 7.5 लाख करोड़ रूपये पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है वर्ष 2022-23 में यह जीडीपी का 2.9 फीसदी है।

* Laid on the Table

महोदय, नए बजट से अर्थव्यवस्था में सुधार का मजबूत रास्ता बना है साथ ही रोजगार के नए मौकों की राह भी प्रशस्त हुई है। बजट में सौर ऊर्जा सेक्टर को लेकर भी बड़ी घोषणा हुई है। किफायती आवास, रियल एस्टेट और निर्माण (कंस्ट्रक्शन) पर सरकार ने ज्यादा जोर दिया है। वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48 हजार करोड़ रूपये आबंटित किये गए हैं। महोदय. मा. प्रधानमंत्री जी का संकल्प है की आने वाले वर्षों में दुनियाभर में भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर ऐसे में इस परिपेक्ष्य में मा. वित्त मंत्री जी ने नए बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किये हैं। साथ ही श्रम आधारित कृषि उद्योग क्षेत्र और सूती वस्त्र उद्योगों को बड़े प्रोत्साहन दिए गएँ हैं। इससे चीन और अन्य देशों से कच्चे माल और विभिन्न वस्तुओं के आयात को कम किया जा सकेगा। नए बजट में वित्तमंत्री जी ने रिकॉर्ड निर्यात का लक्ष्य रखते हुए विभिन्न कच्चे मालों पर घटायें हैं जिनका पीएलआई क्षेत्र के उद्योगों में उपयोग होता है। इस बजट में वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन देने के कदम भी दिखाई दे रहें हैं। बजट में मा. वित्तमंत्री जी ने देश में खुदरा कारोबार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने और कारोबार करने के लिए आवश्यक लाइसेंस की संख्या घटाकर उनका अनुपालन बोझ हल्का करने के तरीके भी सुनिश्चित किये हैं। स्टार्टअप के लिए टैक्स छुट 31 मार्च 2023 तक के लिए बढाई गयी है साथ ही एमएसएमई के लिए दो लाख करोड़ रूपये का विशेष राहत पैकेज दिया गया है।

महोदय, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को अधिक उपयोगी बनाए के लिए नए बजट में विशेष घोषणा की गयी है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है | गारंटी कवर को पांच लाख करोड़ रूपये तक विस्तारित किया गया है इससे पूँजी की राह आसान होगी। वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट में नव सृजित केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किये गए हैं। बजट में को-ओपरेटिव सोसाइटी के लिए मैट की दर को भी 15 फीसदी तक घटने का प्रावधान किया गया है। देश की सीमा पार चीन और पकिस्तान के कारण गहराए तनाव और तनातनी के लम्बे दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों के कारण नए आम बजट के तहत रक्षा बजट और रक्षा अनुसन्धान में भी बड़ा इजाफा किया गया है।

महोदय, हमारे देश में नारी और अधिक सशक्त हो और उनका भविष्य उज्जवल हो इसके लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, पोषण 2.0 को लॉन्च किया गया है, ताकि महिलाओं और बच्चों की योजनाओं को सक्षम तरीके से उन तक पहुंचाया जा सके। 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसके माध्यम से उन्नत किया जाएगा।

देश में प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ जल मिले इसके लिए बजट में उचित 60 हजार करोड़ रुपये का प्रावाधान किया गया है, जिसके माध्यम से वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जायेगा। हमें निश्चित रूप से सरकार की सराहना करनी होगी की पिछले 2 वर्षों में हर घर नल से जल को 5.5 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है।

हर एक गरीब का सपना होता है की उसका अपना आवास हो इसी को लेकर पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2022-23 में 80 लाख घरों को लोगों को मुहैया कराया जाने की योजना है। इस कार्य के लिए 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया जायेगा ताकि जरुरतमंदों को आवास दिया जा सके।

बजट में यह प्रावधान किया गया है की स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो पिछड़े इलाके और पिछड़े वर्ग से संबंध रखते हैं उनको बिना रुकावट के गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त होती रहे इसके लिए उनको पीएम ई विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास, जिसको 12 से 200 टीवी चैनल तक बढ़ाया जाएगा के माध्यम से दी जाएँगी। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी जिससे सभी राज्यों एक से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा प्रदान कर सकेंगे।

रेलवे भारत का एक मजबूत एवं सुरक्षित परिवहन का साधन है इसीको लेकर बजट में यथोचित प्रावधान किये गए है , अगले तीन वर्षों के दौरान 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन का विकास एवं विनिर्माण किया जायेगा साथ ही पीपीपी मॉडल के जरिए चार जगहों पर 2022-23 के दौरान रेलवे द्वारा नए उत्पादों को एक से दूसरे जगह पर पहुंचाया जा सके इसका काम किया जाएगा।

मा. वित्त मंत्री जी ने बजट में यह घोषणा की है की पीएम गतिशक्ति के जरिए राजमार्ग नेटवर्क और बढ़ाया जाएगा जिससे की आवागमन और अधिक सुगम हो पायेगा, इसके लिए 25 हजार किलोमीटर सड़क को और बनाया जाएगा। सामानों को जल्द से जल्द एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए उचित व्यवस्था की जाएँगी।

अंत में मैं पुनः मा. वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा की उनके द्वारा पेश किये गए बजट से अर्थव्यस्था में सुधार का मजबूत रास्ता बना है साथ ही रोजगार के नए मौकों की राह भी प्रशस्त हुई है । यह स्पष्ट दिख रहा है की मा. वित्त मंत्री जी ने कोरोना से उभरती अर्थवयवस्था को गति प्रदान करने के लिए जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है।

धन्यवाद

(इति)

***श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर):** माननीय अध्यक्ष जी. हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री आदरणीया निर्मला सीतारमण जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिसमें लोक-लुभावन घोषणाओं के स्थान पर बजट को कृषि एवं किसानों, गरीब एवं मध्यम वर्गीय लोगों पर केन्द्रित किया गया है तथा समाज के गरीब तबकों का भी विशेष ध्यान रखा गया है और आगामी 25 वर्षों की मजबूत नींव स्थापित की गई है।

माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार किए जाने, हर घर नल योजना की व्यवस्था किए जाने तथा मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां सृजित किए जाने का प्रावधान किया है और किसानों के हित में भी अनेक योजनाएं संचालित की गई है, जिनमें कृषि वानिकी को बढ़ावा देने, खेती का सामना सस्ता करने, किसानों के लिए नए संस्थानों का गठन करने, किसानों को MSP के लिए 2.7 Lk Cr और किसान ड्रोन को बढ़ावा देने, उनकी आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिये 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करने, फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए पैकेज दिए जाने इत्यादि का प्रावधान किया है।

श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल केन्द्रीय नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने गांवों तक ब्रॉडबेण्ड सर्विस डिजिटल बैंकिंग पहुंचाने, जिलों में बेहतर जीवन की सुविधाएं बढ़ाने, शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने, देश में 25 हजार कि0मी0 हाईवेज का विस्तार किए जाने, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, सेज (एसईजेड) की जगह नया कानून बनाने, निजी उद्योग को प्रोत्साहन दिए जाने, तीन वर्षों में 400 बंदेमातरम रेलगाड़ियां प्रारम्भ करने, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को लागू किए जाने, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना पर जोर दिये जाने, कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई किए जाने, छात्रों के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने, महिला शक्ति के लिए 3 नई योजनाएं चालू करने, रक्षा क्षेत्र में 68 प्रतिशत घरेलू उत्पादन शुरू किए जाने, वर्ष 2022 में 5जी सर्विस शुरू करने, एम०एस०एम0ई0 को बढ़ावा देने, देश में टीकाकरण कार्यकम और तेजी से किए जाने, राज्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक लाख करोड़ रू0 की मदद दिए जाने का प्रावधान इस केन्द्रीय बजट में किया है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में कोविड जैसी विश्वव्यापी महामारी के बाद भी अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है और जी0एस0टी0 में भी बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। सरकार टैक्स सिस्टम में भी सुधार की प्रकिया के लिए प्रतिबद्ध है और नया टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना का आह्वान इस बजट में किया गया है।

इस वित्तीय बजट में दिव्यांग जनों के माता-पिता को आयकर में छूट दिए जाने, कॉआपरेटिव सोसायटी के लिए कर दर में छूट दी गई है और कर्मचारियों को भी पैंशन में कर पर छूट का प्रावधान किया गया है तथा स्टार्टअप को भी मार्च, 2023 तक टैक्स इंसेन्टिव देने, केपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट दिए जाने, राज्य व केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बीच

* Laid on the Table

टैक्स में समानता लाने, टैक्स फाईलिंग में सुधार हेतु 2 वर्ष का दिए जाने तथा कॉर्पोरेट को आयकर में छूट देने तथा विदेश से आने वाली मशीनें इत्यादि से आयात ड्यूटी कम किए जाने का प्रावधान किया गया है, जिनसे कपड़ा, हस्तशिल्प, चमड़ा, इलैक्ट्रॉनिक आईटम्स, मोबाईल आदि सस्ते होंगे।

यह हम सभी देशवासियों के लिए खुशी की बात है कि हमारा देश इस वर्ष स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है तथा इस वर्ष अमृत महोत्सव के अवसर पर सरकार ने देश के महापुरूषों को सम्मान देने की दृष्टि से राष्ट्र के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को विकसित किए जाने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिन महापुरूषों ने अपना सबकुछ न्यौछावर कर दिया तथा देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया, ऐसे महापुरूषों को सम्मान देने का कार्यहमारे ऋषितुल्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशाल व्यक्तिव्य के अनुरूप विश्व का सबसे बड़ा स्मारक बनाने का कार्य केवडिया में किया गया और नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का एक भव्य स्मारक राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट के पास बनाया जा रहा है। सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने का अभूतपूर्व कार्य कर रही है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है कि देश के प्रत्येक गरीब परिवार के घर में बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बनाकर हर गांव तक विद्युत पहुंचाने का कार्य सरकार ने किया है तथा करोड़ों गरीब परिवार के घर में "सौभाग्य योजना संचालित करके मुफ्त विद्युत का कनेक्शन और मीटर देने का अभूतपूर्व कार्य किया गया है तथा गरीब परिवारों के लिए मुफ्त आवास योजना बनाकर उन्हें घर का आश्रय दिया है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि काफी मुश्किल समय में यह बजट पेश किया गया है तथा इसमें मूलतः आधारभूत संरचना पर जोर दिया गया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मूल मंत्र "सबका साथ-सबका विकास, सबका प्रयास" को दृष्टिगत रखते हुए इस बजट में जरूरी सुविधाओं को देश के दूरदराज गांवों, गरीब परिवारों तथा मजदूरों तक पहुंचाए जाने के लिए धन का आवंटन किया गया है।

देशवासियों ने इस बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें जताई थीं, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री महोदया ने पूरा किया है। वास्तव में यह बजट भारत की वृद्धि पर केंद्रित है और विकास दर में तेजी लाने के लिए पूर्णतः अनुकूल है। यह बजट 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए है, इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

अंत में, मैं पुनः माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत वित्त बजट का पूरजोर समर्थन करता हूं।

धन्यवाद

(इति)

***डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज):** माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय बजट-2022 पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। देश की अर्थव्यवस्था महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से उबरकर जिस तरह से समग्र रूप से बड़ी तेजी के साथ रिकवर कर रही है, वह हमारे देश की दमदार मजबूती दर्शाती है। जैसा कि अनुमान है कि देश की आर्थिक विकास दर Current Year में 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

महोदय, कोरोना के दरम्यान देश ने जिस प्रकार से आपने-आपको संभाला और दूसरे देशों को संभलने में मदद की है, वह 'सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया' की भावना को दर्शाता है। यह भावना हमारे वेदों में भी है और यह भावना बाबा साहेब अम्बेडकर जी की भी थी। बजट-2022-23 में देश के विकास के लिए जिस प्रकार से एक के बाद एक ठोस कदम उठाए गए हैं, उससे जनसामान्य का विकास होगा तथा देश आगे बढ़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह कह सकते हैं कि कोरोना पीरियड या कोरोना की समाप्ति के बाद विश्व में एक नया World Order तैयार हो रहा है। उसमें यह आवश्यक है कि बदलती हुई इस दुनिया में देश को मजबूती के साथ दुनिया के सामने लाया जाए। बजट 2022-23 में माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है, वह वृहद् अर्थव्यवस्था के विकास पर फोकर करने के साथ-साथ छोटी-छोटी अर्थव्यवस्था के विकास पर फोकस किया गया है। डिजिटल अर्थव्यवस्था, फिनटेक और Technology आधारित विकास के साथ-साथ सार्वजनिक Capital Investment के बल पर निवेश जुटाने का प्रयास किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी ने सभी आयु वर्ग के लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ा दी हैं, लेकिन केन्द्रीय बजट 2022-23 आयुष्मान भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिवेश तैयार करेगा, जिससे चिकित्साकर्मी और स्वास्थ्य सुविधाओं, Unique Health Identity कन्सेन्ट फ्रेमवर्क और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को डिजिटल रूप में दर्ज किया जाएगा।

महोदय, भारत आज फार्मेसी में आत्मनिर्भर है। देश जितना सामर्थ्यवान होगा, उतना ही हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव कल्याण के साथ-साथ विश्व कल्याण की भूमिका अदा कर सकेंगे। इस बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एकीकृत ढांचा मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शुरू करने पर बल दिया गया है तथा 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस बजट से देश प्रगति करेगा और 130 करोड़ देशवासियों का जीवन खुशहाल होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब यह जानते हैं कि जो ठहरा हुआ पानी होता है, वह बीमारी पैदा करता है। जो बहता हुआ पानी है, वह जीवन में उमंग भर देता है। देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय होना चाहिए, जो कि इस बजट में है। बजट 2022-23 में कृषि के क्षेत्र में 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य के भुगतान से

* Laid on the Table

लेकर पूरे देश में Chemical Free और Natural Farming को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं। 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए केन-बेतवा लिंक से सिंचाई की व्यवस्था सराहनीय है। इस लिंकिंग की बिहार को बहुत जरूरत है, क्योंकि बिहार बाढ़ एवं सूखा, दोनों का सामना करता है।

महोदय, हमारे यहां कृषि या खेती हमारी संस्कृति की पहचान है। हमारे ऋषि-मुनियों ने कृषि पर बहुत-कुछ लिखा है। देश में कृषि पर ग्रंथ है। हमारे राजा भी खेतों में हल चलाते थे। राजा जनक और कृष्ण भगवान के भाई बलराम इसके उदाहरण हैं। हमारे पर्व हों, त्यौहार हों, गीत हों, सभी चीजें फसल बोने के समय के साथ या फसल काटने के समय से कृषि से जुड़ी हुई हैं। दस साल पहले जो Census हुआ, उसके अनुसार देश में 55 प्रतिशत खेतिहर मजदूरों की संख्या है। यह एक चिंता का विषय है और मेरा सुझाव है कि इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जमीन कम होने से खेती से रिटर्न कम मिलता है और उनका जीवन कठिन बनता जाता है। किसी और के खेत में जाकर मजदूरी करने पर वे मजबूर हो जाते हैं।

महोदय, कृषि में निवेश बढ़ाने से एग्रीकल्चर सेक्टर ताकतवर होगा। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में देश एवं बिहार राज्य मजबूती के साथ क्रमश: आगे बढ़ रहा है। पिछले 2 वर्षों से देश का आर्थिक विकास कोरोना महामारी के चलते प्रभावित रहा है। देश के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 के माध्यम से विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो सराहनीय है। केंद्रीय बजट में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है।

महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से गंगा नदी के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 2022-23 में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय सराहनीय है। इस बजट में धान एवं गेहूं की अधिप्राप्ति को बढ़ाने के निर्णय से किसानों को काफी फायदा होगा। प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख नए मकानों के निर्माण का निर्णय स्वागत योग्य है। राज्य सरकारों को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में इस वर्ष एवं अगले वर्ष अधिक राशि प्राप्त होगी। इससे राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाइयां कम होंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 21वीं सदी के इस दशक में देश में ब्लू इकोनॉमी के अपने प्रयासों में तेजी आई है। एक्वाकल्चर के साथ-साथ SEAWEED की खेती में जो नई संभावना बनी है, उन संभावनाओं का पूरा लाभ उठाना जरूरी है। डीप ओशियन मिशन समंदर की असीम संभावनाओं को तलाशने का हमारा प्रयास और जो खनिज समंदर में छुपे हुए हैं, जो थर्मल एनर्जी समंदर के पानी में है, वह देश के विकास को नई बुलंदी दे सकती हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 में मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी के लिए 6,407.31 करोड़ रुपये का आवंटन, जो कि 44% की वृद्धि को दर्शाता है, यह निश्चित ही इस सेक्टर को मजबूती देगा

महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इंस्ट्रूमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। केंद्रीय बजट 2022-23 में यह प्रयास किया गया है कि जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता आए ,टेक्नोलॉजी आए जैसे किसान ड्रोन हो, वंदे भारत ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो। इनका लाभ हमारे युवाओं, मध्यमवर्ग, गरीब, दलित, पिछड़े सभी वर्गों को मिलेगा। इस बजट का महत्वपूर्ण उद्देश्य गरीबों का कल्याण करना है। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट के प्रावधान यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि कृषि लाभप्रद हो एवं नए अवसर का सर्जन हो। एमएसपी खरीद के माध्यम से किसानों के खाते में सवा दो लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं जो कि इस बजट का सराहनीय पहलू है। देश में सभी जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ इस बजट में किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय बजट 2022-23 सराहनीय है। इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।

(इति)

***श्री राकेश सिंह (जबलपुर):** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आम बजट 2022 -23 पर मुझे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसके लिए मै आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

सबसे पहले मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति अपना सम्मान और आभार प्रकट करता हूँ जिनके दूरगामी सोच, कुशल नेतृत्व और समर्पण भाव ने देश को एक नई उंचाई पर पहुंचाया है।

महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मानीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसने देश में एक इतिहास रचा है। ऐसा पहली बार इस बजट में हुआ है जिसमें आजादी के 100 साल बाद के भारत की तस्वीर की कल्पना की गई है तथा अगले 25 वर्षों की नींव रखी गई है।

इस बजट को यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गति शक्ति योजना के साथ जोड़कर तैयार किया गया है जो भारत की तीव्र आर्थिक विकास को गति देगा। ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भारत की विकास दर विश्व के अग्रणी देशों के बराबर होगी।

बजट का सबसे ख़ास पहलू यह है कि, यह भारत की संस्कृति और पर्यावरण के सोच को भी दर्शाती है। आज दुनिया के सभी देश पर्यावरण की बात तो करते है, लेकिन किसी भी देश का बजट पर्यावरण को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने इस नई पहल से पूरे विश्व समुदाय के सामने आज एक रोडमैप प्रस्तुत किया है।

महोदय, बजट में पर्यावरण और धारणीय विकास को प्रमुखता देते हुए समाज के सभी वर्गों, किसानों के हितों की चिंता की गई है और यह बजट हर क्षेत्र में विकास के प्रति केन्द्रित है।

बजट में किये गए प्रावधान प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ कदम ताल करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को तीव्र गति से बढायेगी, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर सृजित होंगे। मेक इन इंडिया के तहत करीब 60 लाख नए रोजगार सृजित होंगे।

इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के तहत भी 16 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। बजट में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत अन्य कई प्रावधानों के साथ ही अगले कुछ वर्षों में 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

सड़क अवसंरचना के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 25 हजार किलोमीटर बढाने हेतु बजट में 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान तथा प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहरी में गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाने हेतु 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

कृषि और किसानों के व्यापक हितों की चिंता करते हुए बजट में कई प्रावधान किये गए हैं। अब एमएसपी सिस्टम में किसानों को उनकी खरीद का 2.37 लाख करोड़ रुपये का पेमेंट्स सीधे उनके बैंक खाते में किया जाएगा। खेती को और अधिक लाभप्रद बनाने के उद्देश्य से रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही किसानों की आय और अधिक बढाने के लिए पीपीपी मोड़ में योजनाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। जिससे किसानों की न केवल आय बढ़ेगी बल्कि उनकी समृद्धि के साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।

प्राकृतिक खेती, शून्य बजट खेती, जैविक खेती और कृषि की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को अद्यतन किये जाने की घोषणा इस बजट में की गई है। निश्चित रूप से यह कृषि क्षेत्र में आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर कदम है। इसके अलावा

---

* Laid on the Table

किसानों को और अधिक सुविधा हो इसके लिए कीटनाशकों व पोषक तत्वों के छिडकाव के लिए ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दिए जाने की बात कही गई है। इसी के साथ ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्ट एप को प्रोत्साहन देने का भी प्रावधान किया गया है। यह किसानों की सुविधा के साथ ही युवाओं के रोजगार की नई संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा।

नई शिक्षा नीति को लागू करने के साथ ही देश में डिजिटल शिक्षा को गति देते हुए प्रधानमंत्री ई-विद्या के वन क्लास, वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। इस कदम से कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा।

महिलाओं और बच्चों के विकास को केन्द्रित 2 लाख सक्षम आंगनबाडी केंद्र बनाने की घोषणा भी बजट में की गई है। स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हर घर नल योजना के लिए 60 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

ऐसे अनेक प्रावधान के साथ यह बजट देश के तीव्र आर्थिक विकास का खाका तैयार कर रहा है। जो न केवल आर्थिक विकास बल्कि धारणीय विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह न केवल भारत के विकास की दिशा निरुपित करने वाला बजट है बल्कि यह विश्व के अनेक देशों के लिए भी एक सन्दर्भ के रूप में स्थापित हुआ है।

महोदय, देश का यह बजट ऐसे समय में भी आया है जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की वजह से चरमरा गई है। विश्व के अधिकाँश विकसित देशों जिन्हें वैश्विक महाशक्ति समझा जाता रहा है उनकी अर्थव्यवस्था और सप्लाई चेन ध्वस्त हो चुकी है, यहाँ तक कि कोरोना महामारी के संकट के बीच अमेरिका और OECD देशों तक की महंगाई दर 7% से अधिक हो चुकी है।

इन सबके बीच भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने आज विश्व में सबसे तेजी से आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। देश ने इस कठिन घड़ी में भी महंगाई दर को **5%** से अधिक नहीं होने दिया। यह सब केवल दूरदर्शी और समर्पित सेवक की वजह से संभव हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सतर्कता और संवेदनशीलता से महंगाई नियंत्रण के उपाय किये।

कोरोना काल में भी हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को अत्यंत बेहतर तरीके से आगे बढाया। एक तरफ जहां दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है वहीं भारत के किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया और सरकार ने भे रिकॉर्ड खरीद की। देश ने भूख से किसी को मरने नहीं दिया।

यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत विभिन्न क्षेत्रो में मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और विश्व नेतृत्व की क्षमता प्राप्त की है। आज देश में गरीब का घर बन रहा है, सड़कें बन रही है, गरीबों के घर रौशन हो रहे हैं, माताओं - बहनों को चूल्हों के धुएं से राहत मिल रहे है। देश कृषि एक्सपोर्ट, मोबाइल, डिफेन्स एक्सपोर्ट में आगे बढ़ा है। रक्षा उत्पादन में न केवल आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि रक्षा एक्सपोर्ट की श्रेणी में भी आया है।

महोदय, आज देश का प्रत्येक भाग विकास की नई उंचाई पर पहुंच रहा है और हर भारतीय को देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर गर्व हो रहा है।

(इति**)**

***श्रीमती रमा देवी (शिवहर):** मा० मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण जो बजट प्रस्तुत की हैं उनके लिये दो पंक्तियां बोलती हूँ, तेजस्वी सम्मान पाते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं प्रशस्ती अपना कर्तव्य दिखलाकर। हम सभी जानते है कि यह बजट' ऐसे मुश्किल समय में तैयार किया गया है जब पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जुझ रही है। माननीय वित्त मंत्री जी ने चुनौतियों को अवसरों के रूप में बदलने की कोशिश की है। वर्ष 2020 से जारी कोरोना महामारी के दौरान किन-किन मुसीबतों का सामना देश को करना पड़ा इससे हम सभी अवगत है। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई अभी भी जारी है और कोविड के बाद जब दुनिया में राजनैतिक, आर्थिक, और सामाजिक संबंध बदल रहे है, इतिहास का यह क्षण नये युग का सवेरा है और ऐसा युग जिसमें विश्व पटल पर भारत एक उम्मीद की एक किरण के रूप में उभरा है। असाधारण परिस्थितियों में तैयार किया गया यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने वाला है। "सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास" के मंत्र पर चलते हुये 130 करोड़ देशवासियों का जीवन सुधारने, कुशासन से पैदा हुई उनकी मुसीबतें दूर करने और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक को सभी जरुरी सुविधाओं को पहूँचाने के लक्ष्य के लिए यह सरकार पूरी तरह से संकल्पित है। इस बुनियाद का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प एक सर्व-समावेशी, सर्व-हितकारी, सशक्त भारत का निर्माण और देश की आत्म-निर्भरता है।

किसी भी सरकार की परीक्षा मुश्किल समय में लिये गये उनके ठोस एंव कल्याणकारी निर्णयों से होती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में इस सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये है जिसके कारण हम कोविड से उबरने में सक्षम हो सकें है। हमारे टीकाकरण अभियान की गति और कवरेज इसका उदाहरण है।

विगत दो वर्षों में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं में तेजी से सुधार के कारण ही हम इस इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर पाये है।

मोदी सरकार देश के किसानों के कल्याण एंव उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसलिए उनके विकास एंव सशक्तिकरण के लिए सतत प्रयत्नशील है। आम बजट में एक ऐसे आधुनिक भारत के निर्माण का स्वप्न झलकता है, जो दुनिया में विकसित हो रही नवीनतम तकनिक को हर स्तर पर अपनाने में सक्षम हो। इसी कड़ी में सरकार का लक्ष्य है कि किसान खेती के पारम्परिक तरीकों से बाहर निकलें और कृषि कार्य में आधुनिक तकनिक का इस्तेमाल करें। देशभर में रसायनमुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा इस बजट में ड्रोन प्रणाली सहित कई प्रावधान किये गये है जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार आयेंगे। इस बजट में भी किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेंहू और धान खरीद का लक्ष्य है। इसके लिए किसानों को एमएसपी के सीधा भुगतान के लिए 2 लाख 37 हजार करोड़ रूपये इस बजट में आवंटित किये गये है। मैं इसके लिए आदरणीय वित मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं।

---

* Laid on the Table

प्रधानमंत्री मोदी जी अपने सेवाकाल के प्रारम्भ से ही लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने एंव गरीबों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। मोदी सरकार गरीबों तथा हाशिये पर रह रहे लागों को सशक्त बनाने पर जोर देती रही है। पिछले वर्षों के अनवरत प्रयासों का नतीजा है कि सभी के लिए आवास के लिए "प्रधानमंत्री आवास योजना" से अब तक दो करोड़ से अधिक पक्के मकान गरीबों को मिल चुके है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48 हजार करोड़ रूपये इस बजट में आवंटित किये गये है जो मोदी सरकार की समाज के कमजोर वर्ग के कल्याणकारी नीतियों को दर्शाता है।

मोदी सरकार की यह भी प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक घर में शुद्ध जल कैसे पहुंचायी जाये इसके लिए “हर घर, नल से से जल योजना के तहत इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। वर्ष 2022-23 में देश के 3 करोड़ 80 लाख परिवारों को शामिल करने के लिए 60 हजार करोड़ रूपये इस बजट में आवंटित किये गये है। इससे निश्चित रूप से समाज के गरीब, पिछड़े एंव वंचित वर्ग के जीवनशैली में सुधार आयेगा, उनकी जीवनशैली सुविधाजनक हो सकेगी।

नारी शक्ति को उज्जवल भविष्य के अग्रदूत के रूप में महत्व देते हुये माननीय वित मंत्री जी ने महिला आधारिम विकास कार्य को पुनर्जीवित करने के जो उपाय इस बजट में किये है वे स्वागतयोग्य है। ग्रामीण स्तर पर नौनिहालों की बेहतर देख-भाल एंव उनके समुचित विकास के लिए दो लाख आंगनबाड़ी केन्द्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नयन किये जाने का लक्ष्य इस बजट में किया गया है। यह एक स्वागतयोग्य कदम है क्योंकि, इससे महिलाओं एंव गरीब परिवार के बच्चों को और अधिक बेहतर सुविधाएं दी जा सकेंगी।

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए देश के 75 जिलों में 75 अनुसूचित डिजिटल वाणिज्यिक बैंक स्थापित करने का लक्ष्य भी इस बजट में रखा गया है। इसके साथ देश के डेढ़ लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अब ये योजना पूरे देश में लागू हो रही है।

वर्ष 2014 से ही मोदी सरकार निर्यातों को कम करने और सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। घरेलू उद्योग के लिए पूंजीगत खरीद बजट के 2021-22 में 58 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 68 प्रतिशत किया गया है। उद्योग के लिए कोयला से गैस बनाने के लिए चार पायलट परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। देश के सभी गांवों को भारतनेट के तहत ऑप्टिकल फाइबर नेट से जोड़ा जाएगा। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र को भी डिजिटल किये जाने में मदद मिलेगी।

मोदी सरकार में रेलवे के क्षेत्र में देश में काफी सुधार हुये है। लोगों को रेलवे के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाये जाने का लक्ष्य इस बजट में निर्धारित किये गये है। इससे लोगों का रेलवे से यात्रा ज्यादा सुविधाजनक हो सकेंगी।

वर्ष 2022-23 में 25 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवेज का विस्तार किया जायेगा। यह देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला है। मुझे इस बात कि खुशी है कि लगभग 2100 करोड़ रूपये की लागत से मेरे संसदीय क्षेत्र चकिया से भीट्ठामोड़ तक गुजरने वाली राम जानकी मार्ग के 4 लेन निर्माण की स्वीकृति भी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। मैं इसके लिए माननीय सड़क, परिवहन एंव राजमार्ग मंत्री श्री नीतिन गडकरी जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं।

कोरोना महामारी के दौरान लगी पाबंदियों से शिक्षा को हुये नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने पीएम ई-विद्या के तहत "एक क्लास-एक टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनल की व्यवस्था लागू की जाएगी तथा एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का भी प्रस्ताव इस मौजूदा बजट में है।

सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधा के विस्तार के लिए "जीवंत ग्राम कार्यक्रम' की घोषणा इस बजट में किया गया है। इससे मेरे क्षेत्र के भारत-नेपाल सीमावर्ती प्रखंड सुप्पी, बैरगनिया, ढाका एंव घोड़ासहन के ग्रामों के विकास में भी मदद मिलेगी।

मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित मंत्री जी द्वारा 39 लाख 45 हजार करोड़ रूपये का पेश किया गया यह कल्याणकारी बजट सरकार की दूरदर्शी सोच को दर्शाता है। यह देश की अर्थव्यवस्था को बदलने वाला सिद्ध होगा तथा यह बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। इस बजट में हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश है जो युवाओं, निवेशकों एंव उद्योग के लिए नई सम्भावनाओं को अवसर प्रदान करने वाला है तथा इस बजट में आत्मनिर्भर भारत की नींव बजट में रखी गई है। मैं इस बजट का समर्थन करती हूं।

(इति)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 को सांय चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

2304 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 / 21 माघ, 1943 (शक)
के सोलह बजे तक के लिए स्थगित हुई।